खण्ड-480, अंक-3
बुधवार, 24 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(14 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 480 में 10 अंक है)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

data-7 180 LA (14-23)

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
-प्रश्नोत्तर .....(जारी)	7-11
-तारांकित प्रश्न संख्या-1 (नत्थी 'ख') को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न..... (जारी)	11-16
-प्रश्नोत्तर	16-33
-तारांकित प्रश्न संख्या-1 (नत्थी 'ख') को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	33-34
-कारागार में जनप्रतिनिधियों को विशेष सुविधायें प्रदान किये जाने विषयक पूर्व में दिये औचित्य के प्रश्न पर स्पष्टीकरण	34
-नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	34-36
-प्रदेश के सभी पालीटेक्निकों के डी फ्रीज बजट को समाप्त कराने, आई0ई0आर0टी0 इलाहाबाद को राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान बनाने तथा अध्यापकों-कर्मचारियों की मांगों को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36-37
-जनपद हाथरस (महामायानगर में अलीगढ़-आगरा रोड पर तालाब चौराहे के निकट फ्लाई-ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
-जनपद प्रबुद्धनगर के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37-38
पूर्वी उ0प्र0 में आर्थिक जोन के अन्तर्गत गोरखपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	38-39
-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा में विकास खण्ड मिहीपुरवा तथा बलहा के जंगलों के मध्य सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
-जनपद कानपुर महानगर में पीने के पानी हेतु तैयार खड़े ओवर हेड वाटर टैंकों का चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39-40

विषय	पृष्ठ संख्या
-लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था सुधारे जाने एवं जाम से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	40
-जनपद अमेठी में ट्रकों की ओवरलोडिंग रोकने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	40-41
-मथुरा-आगरा के बीच में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41-42
-जनपद गोरखपुर के विधान सभा चौरी-चौरा में सरैया डिस्टलरी फैक्ट्री से निकलने वाले गन्दे पानी को फरेन नाले में गिराने से रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42
-जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी में ए0बी0सी0 कम्पनी से निकलने वाले दूषित जल से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42-43
-जनपद बागपत शहर के श्मशान घाट पर टीन शेड लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43
-जनपद पंचशील नगर में गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत एन0एच0-24 पर हापुड़ व ब्रजघाट पुल के बीच बने ओवर ब्रिज से सटी सर्विस लेन की विशेष मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43-44
-विधान सभा जहानाबाद फतेहपुर में विकास खण्ड अमौली अन्तर्गत दपसौरा पम्प कैनाल तथा खजुआ के अन्तर्गत पम्प कैनाल को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	44
-जनपद बुलन्दशहर में नया विकास खण्ड ककोड़ सृजित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के ग्राम दौलतपुर में निर्माणाधीन यमुना नदी के पुल तक जाने वाली सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
-औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	45
-उत्तर प्रदेश की विधान सभा में परिसीमन के आधार पर 500 सदस्य किये जाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र भेजकर लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	45-48

विषय	पृष्ठ संख्या
-परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 1572/30-4-10-167-91 टी0सी0, दिनांक 05 अगस्त, 2010 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (सातवां संशोधन) नियमावली, 2010 ...	48
(सदन के पटल पर रखी गयी)	
-उत्तर प्रदेश आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 की वार्षिक रिपोर्ट	49
(सदन के पटल पर रखी गयी)	
-उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन..	49
(सदन के पटल पर रखा गया)	
-लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-8/2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)	49-50
(सदन के पटल पर रखा गया)	
-लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 ..... (पुरःस्थापित)	50
-जनपद बांदा के खपिटिहा कलां गांव में लगी आग से प्रभावित लोगों को राहत सम्बन्धी चेक पूर्व सांसद द्वारा बांटे जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी विरुद्ध कार्यवाही की मांग	50-52
-मा0 सिंचाई मंत्री द्वारा दिये गये भोज की सूचना	52-53
-नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	53-66
-बजट अनुदानों को एक साथ रखे जाने का सुझाव	66-67
-वित्तीय वर्ष 2012-2013 की आय-व्ययक के अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) एवं अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)..... (स्वीकृत)	67-128
-वित्तीय वर्ष 2012-2013 की आय-व्ययक की अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग की मांग पर चर्चा एवं मतदान)..... (स्वीकृत) ...	128-140
-बजट अनुदानों को एक साथ लिए जाने के सम्बन्ध में सुझाव ...	140-141

विषय	पृष्ठ संख्या
-वित्तीय वर्ष 2012-2013 की आय-व्ययक की अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) तथा अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)..... (स्वीकृत)	141-171
-नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	171-172
-जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना के कतिपय गांवों में कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा प्रजापति, यादव व आदिवासी समाज के लोगों को उनके मूल निवास स्थान से अन्यत्र विस्थापित करने का दबाव बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	172-174
-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में घाघरा नदी के किनारे तेजी से हो रहे कटान को तत्काल रोके जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	174
-जनपद महराजगंज के क्षेत्र पंचायत नौतनवां अन्तर्गत महाव नाला में बाढ़ आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कुंवर कौशल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	174-176
-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यू0पी0टी0ई0टी0 में संस्कृत भाषा को विकल्प के रूप में रखे जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	176
-जनपद पीलीभीत में स्टेट फार्मेसी के पद पर तैनात अधीक्षक द्वारा अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र एवं फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	177
-जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रजनी तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	178-181

विषय	पृष्ठ संख्या
-जनपद मिर्जापुर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत जिगना, लालगंज व हलिया के पावर हाउसों की जर्जर स्थिति के कारण बिजली सप्लाई की समस्या के सम्बन्ध में श्री भाई लाल कोल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	182
-जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के बलसर रिगौली बाँध से धानी बाजार को बाढ़ से सुरक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बजरंग बहादुर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	183
-जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में किसानों के हित में उपमण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	183
-जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय मिश्र 'टेनी' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	183
-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत पड़ने वाले कस्बे नकुड़, सरसवां एवं सुल्तानपुर चिलकाना में विद्युत सप्लाई के सम्बन्ध में डा. धर्म सिंह सैनी द्वारा नियम-51-के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	184
-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के ब्लाक सैंया में ग्वालियर नेशनल हाइ-वे रोड पर बी0टीसी0 प्रशिक्षण हेतु बने सरकारी कालेज में प्रशिक्षण बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	184-186
-नत्थियाँ	187-217

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 14 जून, 2012

(विधान.सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-335

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
9. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
13. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
20. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
21. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
22. अमित गौरव, श्री — एटा
23. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
26. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
28. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
29. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
30. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
31. अविनाश, श्री — सोनभद्र
32. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
33. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
34. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
35. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
36. आलोक कुमार, श्री — मैनपुरी
37. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
38. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
39. आशीष यादव, श्री — बदायूं
40. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
41. इकबाल, श्री — बिजनौर
42. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
43. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
44. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
45. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
46. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
47. उदयराज, श्री — उन्नाव
48. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी

49. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
50. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
51. उमाशंकर, श्री बलिया
52. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
53. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
54. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
55. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
56. कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
57. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
58. कामेश्वर, श्री देवरिया
59. काली चरन सुमन, श्री आगरा
60. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
61. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
62. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
63. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
64. केशव प्रसाद, श्री कौशाम्बी
65. कैलाश, श्री गाजीपुर
66. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
67. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
68. गंगा, श्री कुशीनगर
69. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
70. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
71. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
72. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
73. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
74. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
75. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
76. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
77. गोमती यादव, श्री लखनऊ
78. गोरख पासवान, श्री बलिया
79. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
80. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
81. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
82. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
83. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
84. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
85. जगपाल, श्री सहारनपुर
86. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
87. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
88. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
89. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
90. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
91. जय प्रकाश, श्री गोरखपुर
92. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
93. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
94. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
95. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
96. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
97. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
98. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
99. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
100. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
101. दलजीत सिंह, श्री बांदा
102. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
103. दिलवाज खान, श्री बुलन्दशहर
104. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
105. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
106. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
107. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
108. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
109. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली

110. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
111. धर्मराज, श्री बाराबंकी
112. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
113. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
114. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
115. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
116. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
117. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
118. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
119. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
120. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
121. नारद राय, श्री बलिया
122. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
123. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
124. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
125. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
126. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
127. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
128. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
129. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
130. पीतमराम, श्री पीलीभीत
131. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
132. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
133. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
134. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
135. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
136. प्रदीप कुमार, श्री औरैया
137. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
138. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
139. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
140. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
141. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
142. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
143. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
144. बंशी सिंह पहड़िया, श्री बुलन्दशहर
145. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
146. बदलू खां, श्री उन्नाव
147. बाबू खां, श्री हरदोई
148. बाबूलाल, श्री गोण्डा
149. बावन सिंह, श्री गोण्डा
150. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
151. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
152. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
153. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
154. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
155. बैजनाथ, श्री मऊ
156. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
157. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
158. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
159. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
160. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
161. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
162. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
163. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
164. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
165. मनबोध, श्री देवरिया
166. मनीष रावत, श्री सीतापुर
167. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
168. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
169. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
170. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
171. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
172. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
173. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर

174. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
175. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
176. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
177. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
178. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
179. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
180. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
181. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
182. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
183. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
184. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
185. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
186. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
187. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
188. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
189. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
190. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
191. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
192. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
193. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
194. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
195. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
196. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
197. यासर शाह, श्री बहराइच
198. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
199. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
200. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
201. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
202. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
203. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
204. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
205. रणजीत सुमन, श्री एटा
206. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
207. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
208. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
209. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
210. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
211. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
212. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
213. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
214. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
215. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
216. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
217. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
218. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
219. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
220. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
221. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
222. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
223. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
224. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
225. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
226. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
227. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
228. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
229. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
230. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
231. राम करन आर्य, श्री बस्ती
232. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर

233. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
234. राम गोविन्द, श्री बलिया
235. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
236. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
237. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
238. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
239. राम मगन, श्री बाराबंकी
240. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
241. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
242. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
243. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
244. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
245. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
246. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
247. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
248. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
249. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
250. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
251. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
252. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
253. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
254. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
255. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
256. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
257. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
258. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
259. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
260. विजय पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
261. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
262. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
263. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
264. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
265. विजय सिंह, श्री रामपुर
266. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
267. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
268. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
269. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
270. वीरपाल राठी, श्री बागपत
271. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
272. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
273. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
274. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
275. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
276. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
277. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
278. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
279. शाकिर अली, श्री देवरिया
280. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
281. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
282. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
283. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
284. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
285. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
286. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
287. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
288. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
289. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
290. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
291. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
292. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
293. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़

294. संजय कपूर, श्री रामपुर
295. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
296. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
297. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
298. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
299. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
300. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
301. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
302. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
303. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
304. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
305. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
306. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
307. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
308. सियाराम सागर, डा0 बरेली
309. सीमा, श्रीमती जौनपुर
310. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
311. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
312. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
313. सुधाकर, श्री मऊ
314. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
315. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
316. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
317. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
318. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
319. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
320. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
321. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
322. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
323. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
324. सुल्तान बेग, श्री बरेली
325. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
326. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
327. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
328. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
329. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
330. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
331. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
332. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
333. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
334. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोटः- मुख्यमंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुर्नवास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा में मनमानी फीस के निराकरण के दिशा निर्देश

**1–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा में प्रबन्धतन्त्र द्वारा विभिन्न प्रकार की मनमानी फीस विद्यार्थियों से ली जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त समस्या के निराकरण के लिए कोई कारगर योजना बनायी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्या ?

मुख्य मंत्री (अखिलेश यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र में स्थापित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में फीस निर्धारण हेतु शासन द्वारा शुल्क निर्धारण समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा सभी संस्थाओं का शुल्क निर्धारण किया जाता है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण/व्यवसायिक संस्थाओं में शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार शुल्क लिये जाने को सुनिश्चित कराने तथा मण्डलीय समिति गठित कर संस्थाओं की चेकिंग कराने हेतु सभी मण्डलायुक्तों को शासनादेश संख्या 3615/सोलह-1-2010-13(34)/2007 दिनांक 18-10-2010 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि प्रदेश के तकनीकी शिक्षा में विद्यार्थियों से मनमानी फीस नहीं ली जाती है। क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पिछले दो वर्षों के दौरान प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र के डिग्री/डिप्लोमा तथा अभियंत्रण, व्यवसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों से धन वसूलने के कितने मामले संज्ञान में आए हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई है?

(लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री) श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो समिति बनी हुई है और मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को सीधे निर्देश हैं कि कहीं भी अधिक फीस ली जा रही हो तो चेकिंग करके, इन स्कूलों की मान्यता खत्म की जाए, और ज्यादा वसूली हो रही है तो मुकदमा लिखा जाए। जहां तक इस

तरह के मामले आने का सवाल है तो चार केस आए थे आजाद इंजीनियरिंग कालेज, लखनऊ, रामस्वरूप इंजीनियरिंग कालेज लखनऊ दयानन्द दीनानाथ इंजीनियरिंग कालेज उन्नाव, एम0सी0 सक्सेना इंजीनियरिंग कालेज लखनऊ इनके खिलाफ कार्यवाही कर दी गई है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान प्रदेश के तकरीबन अधिकांशतः इंजीनियरिंग कालेज में जो फीस को लेकर घोटाला चल रहा है और अरबों का घोटाला होगा यह, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के फर्जी एडमीशन, फर्जी रिकार्ड और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से पैसे का उनके नाम से विद्यालय में लिया जाना और उसकी वापसी छात्रों को वापस न किया जाना यह बहुत लम्बा और बहुत बड़ा घोटाला है। चूँकि फीस का यह मामला है और यह फीसें उनको लौटाई जानी चाहिए थीं अगर हम यह कहते हैं कि उनको हम फ्री एजूकेशन दे रहे है। पूर्ववर्ती पांच साल में यह कार्य बहुत धड़ल्ले से हुआ है। क्या मंत्री जी के संज्ञान में यह मामला है, अगर नहीं है तो मा0 मंत्री जी इसका संज्ञान लेते हुए जिन लोगों ने प्रतिपूर्ति घोटाला किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, फीस के बारे में पूरी तरह से सूची लगी हुई है बी0टेक0 की फीस निर्धारित है। एम0टेक0 की फीस निर्धारित है निजी कालेजों की फीस निर्धारित है और सरकारी इंजीनियरिंग कालेज की फीस निर्धारित है अगर उससे ज्यादा फीस ली जाती है तो मंडलायुक्तों और जिलाधिकारी को सीधे निर्देश हैं कि उनकी जाँच करें मौके पर जाएं और कार्यवाही करें। और सदस्य जी को अगर इस तरह की कोई सूचना है तो मेरी जानकारी में दें, हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा सवाल अधिक फीस लेने का नहीं है। मेरा सवाल है कि शासन और प्रशासन ने व्यवस्था की है समाज के अनुसूचित जाति और अनुसूचित-जनजाति के बच्चों को निःशुल्क या कम शुल्क पर शिक्षा देने की। जब वह टेक्निकल कालेजों में एडमिशन लेते हैं, नियमतः उनकी फीस जमा भी नहीं होनी चाहिए। उनके एडमिशन बिना पैसे के होने चाहिए। यदि पैसा लेकर उनका एडमिशन कराया गया है तो समाज कल्याण विभाग उस फीस की प्रतिपूर्ति करता है। मेरा प्रश्न यह है कि लोगों ने फर्जी इनरोलमेंट दिखाया, फर्जी एडमिशन दिखा करके समाज कल्याण विभाग से पैसा ले लिया और छात्रों को वापस नहीं किया, हमारी लड़ाई यहाँ है। यह बहुत बड़ा घोटाला है, अरबों तक जायेगा। आप इसकी जाँच करा लीजिए,

पूरे प्रदेश में यह खेल जो हुआ है, पिछली बार, सब सामने आ जायेगा, मेरा प्रश्न बस इतने से है।

श्री अध्यक्ष-

आप स्पेशिफिक पूछ लीजिए। स्पेशिफिक कालेज तो बता दीजिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैंने बता दिया, यह पूरे प्रदेश का मामला है। अगर कोई एक कालेज हो तो मैं बताऊँ।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, ऐसी कोई सूचना या जानकारी मुझे मिली नहीं है। पिछली सरकार की जानकारी तो मुझे है नहीं, दिया ही नहीं गया और ऐसा है तो समाज कल्याण विभाग से सूचना अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है और कोई सूचना यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं समाज कल्याण विभाग से मँगा कर दे दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है माननीय हुकुम सिंह जी, आप सवाल करें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय मंत्री जी की भी अपनी सीमाएँ है और सीमाओं के बारे में उन्होंने कहा कि जब कोर्ट शिकायत आयेगी, तब उसकी जाँच करायेंगे, बिना शिकायत के कार्यवाही कैसे कर लें। यह व्यवस्था बनाई हुई है, मण्डलायुक्त इन्चार्ज हैं, उनके पास शिकायत जायेगी, वह जाँच करेंगे, व्यवस्था सारी है। मान्यवर, यह विडम्बना है, एक शब्द है, ''विशेष सर्किल'', यह विशेष सर्किल बना हुआ है। हम लोग वहाँ तक पहुँच भी नही पाते और सब सीमा में बँधे हुए हैं लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, सिवाय इसके कि हम सरकार से आग्रह करें, आपसे आग्रह करें तो यह विडम्बना है, इसे दूर करने का प्रयास किया जाए। यह बात सहीं है फीस का प्रकरण तो पहले दिन से शुरू होता है, यह तो बाद की बात है। डोनेशन अनुमन्य तो नहीं है कहीं? जब अनुमन्य नहीं है, जैसे जुडीशियल नोटिस होता है, इनको तो जुडीशियल नोटिस दिया जा सकता है। डोनेशन के बिना किसी भी नामी-गिरामी स्कूल में एडमिशन नहीं होते। अब वह बच्चा तो शिकायत करेगा नहीं, उसके कैरियर का सवाल है, उसके माँ-बाप शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन इसका निराकरण क्या हो, समाधान क्या हो यह सोचने की बात है। अब हम आपके पास आए है आप बता रहे है और आप भी कहीं न कहीं इसके भुक्तभोगी होंगे। आपके पास भी लोग आते होंगे कि हमसे 10 लाख की मांग की जा रही है, 5 लाख की मांग

की जा रही है, 5 लाख करा दीजिए, 2 लाख करा दीजिए। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या मिलेगा, कोई माननीय मंत्री ऐसे नहीं होंगे जिनके पास सिफारिश न आती हो कि इसे कम करा दीजिए। हम सब जानते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे है, ऐसा निःसहाय भाव हमारे मन में आता है। करने का उपाय आप ढूँढिये, आपके पास बहुत फोर्स है, इसे करने के लिए। दूसरा प्रश्न मान्यवर, इससे जुड़ा हुआ यह है, फीस भी हो गई, डोनेशन भी हो गया, पढ़ाई के नाम पर क्या है वहाँ? 90 प्रतिशत जो इंजीनियरिंग कालेज है, टेक्निकल एजूकेशन के कालेज है, आज वह बड़े-बड़े नामो का उल्लेख करते है, अपने शिक्षकों के नाम के आगे। जो है ही नहीं वहाँ पर। आप 2-4 कालेज छांट लीजिए, जिनके नाम बहुत बड़े-बड़े है और वहाँ पर जा करके कभी परीक्षण करा लीजिए कि वह लोग जिनके नाम लिखे है, वह वास्तव में पढ़ाने आते है या नहीं आते है। उनके केवल नाम है और नाम के लिए उन्हें वेतन दे दिया जाता है। मान्यवर, उन्हीं कालेजों से पढ़कर जिन छात्रों ने बी0टेक किया, एम0टेक किया है, जब उन्हें जॉब नहीं मिलता तो वही छात्र 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार में काम कर रहे है। आज शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, अगर इसकी चिन्ता हमें नहीं होगी तो और किसी को क्यों होगी ? मैं भाषण पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मान्यवर मैं आपसे आग्रह करता हूं, करने की अगर इच्छा है तो सब हो सकता है। इसलिए विल पावर चाहिए और विल पावर होनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया बढ़ी हुयी फीस का, डोनेशन का और गिरते हुए शिक्षा के स्तर का, इन तीनों बिन्दुओं पर अभियान के रूप में कार्यवाही करें तो निश्चित रूप से संदेश जाएगा। यह मेरा आपसे प्रश्न है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो चिंता व्यक्त की है। उनकी चिंता सही है। लेकिन हमारे सामने कुछ दिक्कतें है। अध्यक्ष जी, आप भी समझ रहे होंगे कि कुछ छात्र बड़े-बड़े कालेजों में पढ़ना पसन्द करते हैं। अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छी सुविधायें हों। आप रोज देख रहे होंगे कि प्राइमरी स्कूल में तो अब किसी गरीब का बच्चा भी नहीं पढ़ना चाहता। यह समस्याएँ हैं। वैसे तो जब शिकायत मिली है तो सरकार ने कार्यवाही की है। जो बड़े कालेज चला रहे हैं कभी-कभी वह कोर्ट का भी सहारा ले लेते हैं इसकी वजह से भी उनको फायदा मिल जाता है। लेकिन हम हुकुम सिंह जी को आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर कोई शिकायत आएगी तो हम उस पर जांच कराकर कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है लेकिन इसकी दो तस्वीरें हैं। एक तो डोनेशन की और दूसरी मुलायम सिंह यादव की सरकार ने एक नीति बनायी थी कि एक जनपद में चार से ज्यादा इंजीनियरिंग कालेज नहीं खुलेंगे। लेकिन पिछले पांच सालों में

एक-एक जनपद में 30-35 कालेज हो गये। डोनेशन तो आप छोड़ दें। 70 हजार सीटें इंजीनियरिंग कालेज में खाली हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि दो वजहों से सीटें खाली हैं, एक काकस काम कर रहा है। ए0आई0सी0टी0ई0 और यूनिवर्सिटी 45 प्रतिशत मार्क्स रखते हैं लेकिन यहाँ जो बाहर के प्रदेश के कालेज हैं उन्होंने 60 प्रतिशत कर रखा है। यानी ए0आई0सी0टी0आई0 जो भारत सरकार की संस्था है वह 45 प्रतिशत, जो यूनिवर्सिटी है वह 45 प्रतिशत और प्राइवेट कालेजों ने 60 प्रतिशत कर दिया है। मेरा सीधा सा सवाल है कि जो एडमीशन का युनिवर्सिटी का 45 प्रतिशत है वह हो, तो डोनेशन का झगड़ा खत्म हो जाएगा। दूसरा मेरा सुझाव है कि मुलायम सिंह यादव जी ने जो प्रतिबंध लगाया था उस प्रतिबन्ध को फिर से लगाया जाये और एक जिले में मशरूम गोट की तरह से यह जो बॉटे जा रहे हैं यह बंद हो और आवश्यकता के अनुरूप जितने विद्यार्थी हैं उन्हें एडमीशन दिया जायें। सैकेड़ों इंजीनियरिंग कालेज बंद हो गये हैं। इस पर विचार किया जाये। आप देखें कि जो विद्यालय नहीं चल पा रहे हैं उन्हें कैसे चलायें और भविष्य में देने के पहले 70 हजार खाली सीटों के बारे में सोच लें। और 45 प्रतिशत जो पासिंग मार्क्स ए0आई0सी0टी0आई0 का है और जो पासिंग मार्क्स युनिवर्सिटी का है वह रखें और जो दो युनिवर्सिटी बनायी गयी है। एक तो यहाँ लखनऊ में और दूसरी गाजियाबाद में बनायी गयी, खास नाम दिया गया। एक प्रदेश में दो युनिवर्सिटी और दोनों के मानक अलग-अलग। स्टैण्डर्ड का फर्क। पूरब पश्चिम का बटवारा कर दिया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक मानक होना चाहिए एक युनिवर्सिटी होनी चाहिए और उतने ही कालेजों को अनुमति देनी चाहिए जितने आपके यहाँ छात्र उपलब्ध हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय तिवारी जी ने कहा उससे हम सहमत हैं और जो विचार आये हैं उस पर विचार करेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री हुकुम सिंह, श्री सतीश महाना तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

[4थे बुधवार के तारांकित प्रश्न सं0-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

तारांकित प्रश्न संख्या-1 (नत्थी 'ख') को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*2–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मा0 अध्यक्ष जी, तारांकित प्रश्न-1 पर हम लोगों के प्रश्न को आपने चौथे बुधवार को नत्थी कर दिया है, जबकि चौथे बुधवार को तो सदन ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

वह हम देख लेंगे, वह किन्हीं परिस्थितियों में किया होगा।

प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम रोकने के उपाय

*3-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम को रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नही तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में घटित साइबर अपराधों की जांच। गहन विवेचना हेतु पुलिस महानिदेशक के आदेश दिनांक 26-8-2011 द्वारा प्रदेश में एक-एक साइबर यूनिट जनपद-आगरा एवं लखनऊ में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के परिक्षेत्रों यथा मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, अलीगढ़ व सहारनपुर में पंजीकृत साइबर क्राइम की विवेचना आगरा स्थित यूनिट करेगी, जबकि इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़, चित्रकूटधाम, देवीपाटन, फैजाबाद, बस्ती, झाँसी एवं मिर्जापुर में पंजीकृत अपराधों की जांच लखनऊ यूनिट करेगी।

संबंधित इकाईयों को आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत जाँचकर्ता/विवेचक को विवेचना में तथा वैज्ञानिकों को विवेचना में सहयोग हेतु दक्ष बनाने के प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ई0ओ0 डब्लू) को साइबर अपराधों हेतु नोडल इकाई बनाया गया है। प्रदेश में तकनीकी सेवाओं के अधीन ए0टी0एस0/एस0टी0एफ0 के अधीन गौतमबुद्ध नगर, आगरा एवं लखनऊ में साइबर लैब स्थापित है। किसी भी आकस्मिक साइबर अटैक की चुनौतियों का सामना करने हेतु पुलिस बल में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन हो चुका है। प्रत्येक जोनल स्तर पर एक-एक साइबर इकाई/थाना स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। गृह विभाग के माध्यम से साइबर अपराध घटित होने के उपरान्त घटना स्थल से संबंधित थाने पर संगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराकर दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश के साइबर क्राइम के माध्यम से होने वाले अपराधों को नियंत्रित किये जाने हेतु प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी (उत्तर प्रदेश) नियमावली बनाया जाना प्रस्तावित है। उक्त

नियमावली में साइबर कैफें के स्वामी द्वारा पर्याप्त सावधानियाँ बरते जाने का प्राविधान है, जिससे साइबर कैफे का उपयोग किसी भी तरह के अवैधानिक एवं आपराधिक कृत्यों के लिये न हो सके।

प्रश्न ही नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, देश की सर्वोच्च संस्था सर्ट की रिपोर्ट के अनुसार चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। सर्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2008 में देश में जहां साइबर क्राइम की 25 सौ घटनाएं दर्ज की गई, वह 2010 में बढ़ कर 10500 हो गई। सर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हिन्दुस्तान की दस हजार वेबसाइटों पर हमला किया गया 2010 में। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक प्रदेश की बात है 2008 में जहां 70-80 साइबर क्राइम की घटनायें दर्ज की गई वह एक साल में बढ़ साढ़े तीन सौ तक पहुंच गई। मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में केवल दो ही साइबर क्राइम यूनिट थी, एक यहां लखनऊ में थी, दूसरी आगरा में थी। मा0 मंत्री जी ने कहा है कि वह प्रत्येक जोन स्तर पर साइबर यूनिट खोलने पर विचार कर रहे है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो साइबर यूनिट जोन स्तर पर खुलनी है वह कब तक खुल जायेंगी, कितने समय तक जोर स्तर पर साइबर यूनिट आप स्थापित कर देंगें। मा0 अध्यक्ष जी, दूसरा मेरा सवाल हैं, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आई0टी0 ऐक्ट 2000-2008 के अनुसार साइबर क्राइम के ब्योरे रखना, केवल इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी कर सकता था, माननीय अध्यक्ष जी, 2000 ऐक्ट के अनुसार डिप्टी एस0पी0 करता था, तो 2008 में उस ऐक्ट में संशोधन हुआ तो उसके अनुसार केवल इंस्पेक्टर लेबिल का ही अधिकारी इस क्राइम की विवेचना कर सकता है। मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया है कि प्रशिक्षण शिविर चलाये जा रहे हैं तो मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कितने इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका हैं। मान्यवर, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में केवल साइबर क्राइम के लिए, साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब की स्थापना पर विचार करेगी और उस लैब में डाटा रिकवरी, मोबाइल डाटा रिकवरी, डाटा फोरेंसिक और नेटवर्क फोरेंसिक के लिए उच्च स्तरीय आधुनिक तकनीक के साफ्टवेयर और हार्डवेयर उपलब्ध करायेगी?

प्रोटोकाल राज्य मंत्री श्री अभिषेक मिश्र-

मा0 अध्यक्ष महोदय, टोटल आठ जोन बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें से कुछ प्रस्ताव आलरेडी पीएचक्यू पुलिस हेड क्वाटर्स द्वारा मंगाये जा चुके हैं, कुछ प्रस्ताव रिसीव भी हो चुके है, जल्दी से जल्दी बाकी प्रस्ताव भी आ जायेंगे और इनको बहुत ही जल्द यथाशीध्र क्रियान्वित

किया जायेगा। दूसरा सवाल इनका था कि टोटल कितने लोगों को ट्रेन्ड किया गया है, उसमें साइबर क्राइम इंवेस्टिगेशन में जो हाई लेविल ट्रेनिंग दी जा चुकी है, वह 20 लोगों को दी जा चुकी है और बेसिक साइबर क्राइम ट्रेनिंग 45 लोगों को दी जा चुकी है और यह कार्यक्रम रोज के हिसाब से स्पीड पकड़ रहा है।

ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा इमफेसिस दिया जा रहा है। तीसरा इन्होंने सवाल पूछा कि किस चीज से रिलेटेड होगी, चाहे डेटा नेटवर्किंग हो चाहे फिशिंग हो। बहुत सारी चीजों की एक लंबी लिस्ट है पढ़ देता हूँ, मैं जिनके बारे में इस एक्ट के तहत प्रोविजन किया जायेगा और इस एक्ट के तहत जिनको कन्ट्रोल और रेगुलेट करने का प्रयास किया है जो क्राइम उसमें है साइबर स्टोकिंग, मोनोग्राफी, सलामी अटैक, ई-मेल स्पेसिंग, फिसिंग, पर्सनल डेटा थेम्ट, आइडेन्टी थेप्ट वगैरह-वगैरह इन्होंने जितने भी नाम लिए है, वह सारे के सारे कवर्ड है और जिनके लिए प्रीप्रेयरी भी चल रही है और इनका इनवेस्टीगेशन भी होगा।

डा0 धर्मपाल सिंह -

मैंने मा0 मंत्री से जानना चाहा था कि एक्ट के अनुसार केवल इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी इसकी जाँच कर सकते है, उत्तर प्रदेश के कितने थानों के इंस्पेक्टरों को अभी तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है? मैं यह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

बताया तो उन्होंने।

डा0 धर्मपाल सिंह-

उन्होंने बताया कि केवल 20 लोगों को। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या थाने के इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण दिया गया है?

श्री अभिषेक मिश्र-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैने टोटल 67 का नंबर इनको बताया है ˙ अभी तक सिर्फ 67 को ट्रेन्ड किया जा चुका है। बाकी हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी को जानकारी होगी कि ई0ओ0डब्लू के पास ही पेण्डेन्सी बहुत ज्यादा है। उनके पास न तो स्टाफ है और न ही वर्किंग इफीशिएन्सी है। मान्यवर, और न वे लोग इतने ज्यादा प्रशिक्षित है। मान्यवर, उनके पास जानकारी भी नहीं है, यह मेरी निजी जानकारी है। मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या मा0 मंत्री जी, ई0ओ0डब्ल्यू0 को पूरी तरीके से इस क्राइम को रोकने के लिए, इसके प्रापर इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी तरीके से मान्यवर, इसे स्ट्रेन्थन करेंगे? मैं यह आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानकारी चाहता हूँ, क्योंकि ई0ओ0डब्ल्यू0 में मान्यवर, 4-4 साल

की 8-8 साल की पेण्डेन्सी वहाँ पर। तो यह ई0ओ0डब्ल्यू0 पर जो और अतिरिक्त वर्क डाल दिया है और न ही वह वेल इक्यूप्ड है और न ही उनके पास तकनीकी प्रशिक्षण है और उनके ऊपर अलग से एक काम दे दिया।

श्री अभिषेक मिश्र-

मा0 अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने ई0ओ0डब्ल्यू0 से जुड़ा हुआ सवाल उठाया है। उसमें कहना है कि ई0ओ0डब्ल्यू0 सिर्फ नोडल एजेन्सी बनायी गयी है। इसके तहत एक साइबर क्राइम, एक साइबर अटैक एवं साइबर आतंकवाद की चुनौतियों को सामना करने के लिए पुलिस विभाग में डी0जी0 साहब के आर्डर के अनुसार एक समिति का गठन किया गया है जो कि एक्चुअल कनविनिंग कमेटी है, जिसमें एडीशनल डी0जी0 इसके अध्यक्ष हैं और कई सारे आई0जी0 है, जो इसमें रिस्पॉन्सबल है।

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं चाह रहे है, वह कह रहे है कि आदमियों की कमी है, उससे काम पूरा नहीं होगा।

श्री अभिषेक मिश्र-

उसी का जवाब है, मा0 अध्यक्ष जी,कि एक्चुअली यह ई0ओ0डब्ल्यू0 का काम नहीं है। ई0ओ0डब्ल्यू0 केवल नोडल एजेन्सी बनाई गयी है। यह कमेटी है जो कि कांम्पीटेन्ट लोग है और ये लोग उसको कन्वीन करेंगे उसको हेड करेंगे और क्रियान्वित करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अभिषेक मिश्र-

मान्यवर, इसके अलावा जो इन्होंने ट्रेनिंग का सवाल उठाया है। नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सीनियर आफिसर्स की भी ट्रेनिंग की जा रही है रेगुलरली और सीनियर आफिसर्स उसमें इक्यूप्ड किये जा रहे है। इन फैक्ट इस समय उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम से जुड़े हुए कुछ बहुत ही अच्छे एक्सपर्टस् मौजूद है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल कान्फ्रेस में भी बोलते है, तो यह कहना कि उनके पास स्किल नहीं है, यह मेरी जानकारी जितनी है उसके तहत गलत हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब तो पूरे प्रश्न का उत्तर आ गया है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो भी इन्वेस्टीगेशन हुए है साइबर क्राइम के क्षेत्र में उनमें जो अपराधी प्रकाश में आए है। उनकी आयु 18 वर्ष से 25 के बीच में है। तो क्या सरकार सुरक्षित इंटरनेट के लिए स्कूलों और कालेजों में जागरूकता अभियान चलायेगी ?

श्री अभिषेक मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है मा0 सदस्य जी ने। बहुत सारे स्कूल अपने पर्सनल लेवल पर पर्सनल इनीसिएटिव पर ऑलरेडी चला रहे है और फिसिंग अटैक्स के लिए बहुत सारे बैंकिग संस्थान काम कर रहे है, रेगुलरली आप अखबारों में, न्यूज मैगजींस में आप देखते होंगे, ये निकलते रहते है। सरकार की तरफ से आई0टी0 अवेयरनेस और बाकी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं और स्पेशिफिक सुझाव मैं मा0 सदस्य जी से लेकर के उसे और अधिक मजबूत करने का काम करूंगा।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में मेधावी गरीब छात्रों को आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 की मुफ्त कोचिंग हेतु संचालित योजना

***1**-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) (अनुपस्थित)-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेघावी गरीब छात्रों को भी आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 की मुफ्त कोचिंग दिये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी हॉ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के छात्रों/अभ्यर्थियों के लिए आई0ए0 एस0, पी0सी0एस0 एवं अन्य सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण/कोचिंग दिये जाने की योजना संचालित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री श्याम देवराय चौधरी जी उपस्थित नहीं हैं।

*2-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[दिनांक 12-6-2012 के तारांकित प्रश्न सं0-5 द्वारा उत्तरित]

वायु मण्डल से आक्सीजन लेकर औद्योगिक/व्यापारिक उद्देश्यों हेतु आक्सीजन गैस बनाये जाने पर रोक की मांग

*3-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वायुमण्डल से सीधे आक्सीजन लेकर औद्योगिक/व्यापारिक उद्देश्यों हेतु आक्सीजन गैस बनाई जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार पर्यावरण संतुलन हेतु वायुमण्डल से सीधे आक्सीजन लेने पर रोक लगायेगी? क्या सरकार पर्यावरण शुद्धता, वातावरण में आक्सीजन की कमी की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए अतिशीघ्र अधिनियम में संशोधन हेतु केन्द्र सरकार को संदर्भित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

वायुमण्डल से सीधे आक्सीजन न लेकर अपितु हवा लेकर कूलिंग, हीटिंग एवं डिस्टीलेशन द्वारा शुद्ध आक्सीजन बनाई जाती है, जिसका प्रयोग चिकित्सा सेवाओं, औद्योगिक गतिविधियों आदि में किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है तथा पर्यावरण में आक्सीजन की कमी के कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रासंगिक अधिनियम में संशोधन किये जाने की आवश्यकता नहीं है एवं अधिनियम में संशोधन हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है अपितु केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित संगत अधिनियमों के प्राविधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, पर्यावरण प्रदूषण आज पूरे विश्व के और मानवता के जीवन की रक्षा के लिये एक चिन्ता का विषय है। मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वायुमंडल से सीधे आक्सीजन लेकर औद्योगिक/व्यापारिक उद्देश्यों हेतु आक्सीजन गैस बनाई जा रही है? मान्यवर, पर्यावरण की रक्षा के लिये भारतीय संविधान में भी आर्टीकिल 51ए में प्राविधान है कि हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग पर्यावरण की रक्षा करें। उसमें जल, जमीन, वायु, वन्यजीव, वन आदि सब आते हैं। मान्यवर, पर्यावरण में हम लोग रोज इधर देख रहे है कि यह चर्चा का विषय है कि खदानों पर रोक, जल में प्रदूषण पर रोक सहित दुनिया भर के उपाय किये जा रहे हैं। मान्यवर, आज जो आक्सीजन गैस व्यापारिक उद्देश्य के लिये बनाई जा रही है, वह वायुमंडल से सीधे पूरे वायु को अवशोषित करते हैं जिसमें तमाम तरह की गैसें होती है। इसमें आक्सीजन की मात्रा 20.99 है, 78.03

नाइट्रोजन है, 0.4 कार्बन है, 0.93 आर्गन है। इसको लेकर फिर यह इलेक्ट्रोरेसिस से उसको विच्छेदित करके गैस बना रहे है। हम लोग भी वायुमंडल से आक्सीजन लेकर साँस ले रहे हैं लेकिन जब हम गैस लेते हैं और उसकी मैन्यूफैक्चरिंग करते हैं उसका व्यापारिक प्रयोग करते हैं तो जिस प्रकार से जब आप खदानों की खुदाई करते हैं तो आप पट्टा देते हैं और पैसा लेते हैं, जल, जमीन के लिये, वन के लिये जब आप कोई लाइसेंस देते हैं, पट्टा देते हैं तो आप पैसा लेते हैं। लेकिन मान्यवर, इसमें आक्सीजन लेने के मामले में कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है और आक्सीजन गैस के लिये बेचारा गरीब अस्पताल में दम तोड़ देता है। वह इतनी महंगी भी है। आज 100 पौंड आक्सीजन गैस का मूल्य 200 रुपया है। मान्यवर, यह पर्यावरण का शोषण तो है ही। जहाँ तक नियमों और कानूनों का सवाल है, तो वायु प्रदूषण में वायु की गुणवत्ता संतुलन के रूप में व्याख्या की जा सकती है। यह इस कारण खराब प्रभाव डाल रहा है। हमारा जो सेन्ट्रल इन्वायरन्मेंटल एक्ट, 1986 है, उसमें भी प्राविधानित है कि उसके धारा-3 में केन्द्र सरकार को वायु के संरक्षण, संवर्धन हेतु उपाय करने की शक्ति प्रदान की गयी है। धारा 6-1ए में पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु नियम बनाने का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार धारा 6 की उपधारा 6-2ए में केन्द्र सरकार को वायु, जल, जमीन के विभिन्न क्षेत्रों और उद्देश्यों में गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने का प्राविधान किया गया है। वह सारे प्राविधान हैं लेकिन इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। हम वायुमंडल में आक्सीजन बढ़ाने के लिये पेड़ लगाते है, दुनिया भर के कार्बन मोनोआक्साइड, डीजल को नियंत्रित करने के लिये हम परिवर्तन कर रहे है, सी0एन0जी0 गैस ला रहे हैं, ताकि वायु प्रदूषित न हो। दूसरी तरफ वायु मे जो आक्सीजन है, उसको लेकर व्यापारिक रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है। मान्यवर, इसमें मेरे दो सवाल है पहली बात तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पर्यावरण में आक्सीजन की कोई कमी की सूचना नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस संबंध में इन्होंने कोई जाँच कराई है कि जो आक्सीजन हम वायुमंडल से ले रहे हैं, जिसका व्यापारिक प्रयोग कर रहे हैं, क्या उससे कोई कमी हो रही है, पहला सवाल तो यही है कि क्या इस संबंध में इन्होंने कोई जाँच कराई है और दूसरा यह कि जो इसका कामर्शियली प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से हम खदान की खुदाई का पैसा लेते हैं, मछली पालन उद्योग से पैसा लेते हैं, उसी प्रकार जो इसका व्यापारिक प्रयोग कर है क्या उनसे आप पैसा लेंगे ?

श्री अभिषेक मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, हवा का पैसा कितना लिया जाना चाहिए इस बारे में अभी तक कोई सोच सरकार की नहीं है क्योंकि हवा तो बहुमूल्य है, बहुत कीमती चीज है, जिन्दगी और मौत की चीज है। जैसे इंसान सांस लेता है अगर वायु में ऑक्सीजन की जरा भी कमी होगी तो आपको तुरन्त महसूस हो जाएगा, हम सभी को प्रेशर बढ़ने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। चूँकि मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक ऐसी बात किसी के सामने नहीं आई है न

इस सदन में और न किसी और सदन में, तो अभी तक इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण या टेस्टिंग नहीं हुई है कि क्या ऑक्सीजन की कमी आ रही है? और जहॉ तक इसकी प्राइसिंग की बात है क्योंकि हवा जिन्दगी का पर्यायवाचक है, यह एक दूसरा शब्द है जिन्दगी के लिए, तो अगर मा0 सदस्य कोई प्राइसिंग सजेस्ट करें, अगर उसकी कोई कीमत बतायें तो उस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, ऑक्सीजन जो आई0सी0यू0 में या अन्य जगह पर मरीजों को दी जाती है, 100 पाउन्ड का जो ऑक्सीजन सिलेन्डर होता है 24 घण्टे में एक सिलेन्डर लगता है जो लगभग 600 रुपया प्रतिदिन का हो जाता है, अगर इसको कैलकुलेट करें तो प्रतिदिन हम लोग 600 रुपए की ऑक्सीजन वायुमण्डल से लेते हैं, अगर इसको महीने में और वर्षो मे देखें तो करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। मान्यवर, इस प्रकार से ऑक्सीजन का कितना प्रयोग होता है तो जो फैक्ट्रियों, जो कारखाने ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं उसमें उनकी मैनुफैक्चरिंग कास्ट को अलग करके क्या ऐसी कोई नीति बनायेंगे कि उनसे कुछ लिया जाए?

श्री अभिषेक मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले टू-जी स्पेक्ट्रम में हवा बेची गई है लेकिन वह कॉग्रेस ने ही बेची है तो हवा की क्या कीमत लगनी चाहिए यह तो वही बता सकते हैं। अगर हवा बेचने का कोई और तरीका निकाल सकें तो सरकार को कुछ और बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न था और ऑक्सीजन मूलतः इस प्रश्न की आत्मा है, क्योंकि माननीय सदस्य इसको ले आये हैं और मैं इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हवा का दाम नहीं लिया जा सकता, हवा उपलब्ध है, यह सारी बातें आ चुकी हैं लेकिन जब हवा का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है और उसे व्यावसायिक रूप से बेचा जा रहा है, अगर वह फैक्ट्री में जा रहा है वेल्डिंग में जा रहा है, मिल्टिंग में जा रहा है, रासायनिक फैक्ट्री में जा रहा है तो जाने दीजिए लेकिन यह जो मेडिकल का हिस्सा है जहाँ हम ऑक्सीजन की कमी को पूरा करके मरते हुए मरीजों का इलाज करते हैं और बहुत कायदे से उनसे धन लेते हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि अगर हवा निःशुल्क मिल रही है, कम्पनियां बहुत सारे अन्य कामर्शियल उत्पाद बना करके बेच रही हैं वह बेचें क्या उन्हें हम इस बात के लिए बाध्य कर करते हैं कि ऐसी जीवनोपयोगी महत्वपूर्ण चीज जिसके बिना मनुष्य जी नहीं सकता और मरते हुए व्यक्ति के लिए आवश्यक है क्या हम एक निश्चित कोटा बना सकते हैं कि आप इतना ऑक्सीजन कामर्शियली इस्तेमाल

कीजिए लेकिन इसका इतना हिस्सा आप मेडिकली इस्तेमाल कीजिए और उसे सरकारी अस्पतालों में आप निःशुल्क दीजिए, हम आपको छूट देते हैं क्या यह व्यवस्था आप कर सकते हैं?

श्री अभिषेक मिश्र-

पहला तो क्या हम कोई ऐसी लेबी बना सकते हैं तो मान्यवर, सदन स्वयं में ताकतवर है और सदन कोई भी नियम कानून बना सकता है कोई भी लेबी किसी भी चीज पर लगा सकता है पहला इसका यह जवाब है। दूसरा जो उसका मूल्य ले रहा है, उत्तर प्रदेश में 38 ऐसी इकाइयां है जो ऑक्सीजन के सिलेण्डर बना रही हैं वह उसका जो भी मूल्य लेती हैं, वह जो अपना उपक्रम कर रही हैं, अपना इण्टरप्राइज डाल रही हैं, अपना एफर्ट है, टाइम और मनी का जो इन्वेस्टमेंट है, उसका बड़ा लम्बा प्रॉसेज है, आप कहें तो मैं बता सकता हूँ कि एयर को लिया जाता है उसको कम्प्रेस करते हैं, कूल करते हैं, एब्जार्ब होती है, मॉलीक्यूलर सील लगाया जाता है, फिर एक्सपाइन्शन कराया जाता है फिर लिक्वडीफिकेशन किया जाता है फिर डिस्ट्रलेशन किया जाता है तब जाकर कहीं लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन अलग-अलग पैदा होती है माइनस 186 डिग्री सेंटीग्रेट पर।.....

श्री अभिषेक मिश्र-

और कोई भी आदमी आगे बढ़ करके इन्वेस्टमेण्ट नहीं करेगा, अगर उसको उस पर रीजेनेबिल रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन यह पॉसिबिल है, मा0 सदस्य ने जो कहा इस पर सरकार जरूर विचार कर सकती है कि जो ऐसी जरूरी चीजें है सांस लेने के लिए, उनको सरकार सब्सिडाइज कर दे, यह विचार किया जा सकता हैं।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 साहब अब बैठिये, पूरी बात आ गयी।

श्री अभिषेक मिश्र-

अध्यक्ष जी, इस पर मुनाफा ज्यादा न लिया जाए, एक रीजेनेबिल रेट ऑफ रिर्टन ही लिया जाए इस पर सरकार विचार कर सकती है।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अपने बंगले के अनुरक्षण पर व्यय की जाँच एवं कार्यवाही की मांग

*4-श्री रविदास मेहरोत्रा (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सरकार के मुख्य मंत्री ने अपने कार्यकाल के वर्ष 2007 से 2012 तक सरकारी कोष से अपने बंगले के अनुरक्षण में कितने

---

*नोटः-तारांकित प्रश्न संख्या-4 के बाद प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

करोड़ रुपये व्यय किये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पूर्व मुख्य मंत्री के बंगले के निर्माण में वित्तीय अनियमिततायें हुयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अभिषेक मिश्र-

वर्ष 2007 से 2012 तक पूर्व मुख्यमंत्री के आवास संख्या 13ए माल एवेन्यू में अनुरक्षण पर विद्युत अनुरक्षण खण्ड 2 द्वारा रू0 11.49 लाख एवं सिविल अनुरक्षण खंड 2 द्वारा रु0 8.66 लाख की धनराशि, अनुरक्षण कार्यों हेतु व्यय की गयी है तथा अन्य निर्माण कार्यों पर रु0 8656.20 लाख व्यय किया गया है। मामले में वित्तीय अनियमितता संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण कोई जाँच नहीं हुयी है तथा व्यय की गयी धनराशि का आडिट न होने के कारण वित्तीय अनियमितता संबंधी बिन्दु पर अभी टिप्पणी किया जाना सम्भव नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब तारांकित प्रश्न संख्या 4, मा0 रविदास मेहरोत्रा जी (मा0 सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

इस प्रश्न में किसी की रूचि है?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरी रूचि है।

(मा0 मंत्री श्री अभिषेक मिश्र द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पढ़ा गया।)

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, लिखित उत्तर में सारी चीजें स्पष्ट हो गयी है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, एक प्रश्न मेरा भी इसी से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब अब छोड़िये।

अतारांकित प्रश्न

1-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[दिनांक 13.06.2012 के अतारांकित प्रश्न सं0 14 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी में मण्डी परिषद् द्वारा अधूरी सड़कों का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

2-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में मण्डी परिषद् के द्वारा बन रही कितनी सड़के अधूरी हैं तथा कितनी प्रस्तावित हैं? क्या सरकार अधूरी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

4-श्री अखिलेश यादव-

सड़कें अधूरी हैं तथा कोई भी नई सड़क प्रस्तावित नहीं है।

जी हॉ।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के जनपदों की माँग जनपद बहराइच में ओल्ड एज होम स्थापित कराये जाने की मांग

3-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में ओल्ड एज होम स्थापित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? क्या सरकार जनपद बहराइच में ओल्ड एज होम खोलने की स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हाँ।

राज्य सरकार द्वारा पुरूषों हेतु लखनऊ में तथा महिलाओं हेतु वाराणसी में एक-एक राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह संचालित हैं। निराश्रित वृद्ध महिलाओं के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रदेश के 17 मण्डल मुख्यालय जनपदों में एक-एक वृद्धाश्रम संचालित हैं।

जनपद बहराइच में ओल्ड एज होम खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में मण्डी परिषद् द्वारा सड़कों के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

4-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के प्रयागपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में मण्डी परिषद की कौन-कौन सी सड़कें पिच हेतु प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार का उक्त सड़कों के डामरीकरण हेतु विधायकों से भी प्रस्ताव लेने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में कोई रोड प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के गांवों में आग लगने से फसलों के हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग

5-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के किन-किन ग्रामों में वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में आग लगने से गेहूं तथा गन्ने की फसल का नुकसान हुआ है ? क्या सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की गई है ? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति पाने वालों का नाम व पता क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आग लगने से वर्ष 2011-12 में ग्राम गंगा जमुनी धौली, शिवदहा, बसनेरा, सचौली एवं पिपरा पदारथ में गेहूँ की फसल तथा ग्राम नरायनपुर, पयागपुर एवं लखवापुर बहरैचा में गन्ने की फसल का नुकसान हुआ है। आग लगने से वर्ष 2012-13 में ग्राम चन्दईपुर, खानपुर नल्लोह, जलालपुर, ककरा मोहम्मदपुर, सेमरौना, कांधभारी, गनेशपुर, कुरसहा, बसनेरा, जैसौरा, सोहरियांवा, शेखापुर, चैसार निगोह अकरौरा, नेटिया, रायगढ़ बेहडा, इटहुवा, लखवापुर बहरैचा, धनपारा एवं बौंवा में गेहूँ की फसल की नुकसान हुआ है।

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण आपदा राहत निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार देवी आपदा से आच्छादित न होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा सहायता नहीं दी गयी है।

जनपद बहराइच की कतिपय तहसीलों में कृषकों को सही मूल्य दिलाये जाने हेतु उप मण्डियों की स्थापना कराये जाने की मांग

6-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादों का सही मूल्य कृषकों को दिलाने के लिए जनपद बहराइच की कैसरगंज तथा सदर तहसीलों में उप मण्डियों की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच की कैसरगंज तहसील में लघु मण्डी स्थल कैसरगंज तथा सदर तहसील में नवीन मण्डी स्थल बहराइच निर्मित है एवं व्यापार पूर्ण रूप से स्थानान्तरित है।

प्रदेश में कृषको के हितार्थ किसान मित्रों की पुनः नियुक्ति किये जाने की मांग

7-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007 में कृषकों के उत्थान तथा वैज्ञानिक ढ़ग से कृषि किये जाने के लिए प्रत्येक गांव पंचायत में एक-एक किसान मित्र की नियुक्ति की गयी है? क्या दिनांक 31 मार्च, 2010 को इस योजना को समाप्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार कृषकों के हितार्थ किसान मित्रों की पुनः नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

7-कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धमार्थ कार्य मंत्री (श्री आनन्द सिंह) धमार्थ-

वर्ष 2007-08 में 52 हजार किसान मित्र नियत मानदेय पर चयनित किए गए थे। वर्ष 2009-2010 में किसान मित्र योजना की समीक्षा एवं पुनर्गठन पर सम्यक विचारोपरान्त योजना को उपयोगी न पाये जाने के कारण शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा समाप्त कर दी गयी है। इस योजना को पुनः संचालित करने की अभी कोई योजना नहीं है।

जनपद शाहजहाँपुर की तहसील सदर के कतिपय गांवों में ग्राम समाज की भूमि को भूमिहीनों को पट्टे पर देने की कार्यवाही

श्री सुरेश कुमार खन्ना

8-क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बड़ावन व वारापुर, तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर में ग्राम समाज की खाली कृषि भूमि पर दबंगों द्वारा नवजात कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे खाली कराकर भूमिहीन किसानों को पट्टे पद देने की कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

खाली कृषि भूमि भूमिहीन किसानो को पट्टे पद देने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर एवं लखनऊ को आई0टी0 हब केन्द्र बनाये जाने की मांग

9-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर एवं लखनऊ को आई0टी0 हब केन्द्र बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विकास हेतु निर्धारित एजेण्डे में सर्वप्रथम लखनऊ में आई0टी0 हब केन्द्र बनाये जाने की योजना है। जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा में कई आई0टी0 हार्डवेयर एवं साफ्टवेंयर उद्योग पूर्व से स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नोयडा में वेव रियल स्टेट कम्पनी को बिना नीलामी कम रेट पर बेचने की जाँच की मांग

10-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सरकार ने नोयडा के सेक्टर-25 एवं 32ए में वेव रियल स्टेट कम्पनी को 6 लाख स्क्वायर मीटर जमीन नियम विरूद्ध बिना नीलामी करायें मार्केट रेट से बहुत कम रेट पर बेचकर वित्तीय अनियमितता की गयी? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर की सरैया डिस्टलरी/शुगर मिल के प्रदूषित जल की जाँच कर प्रदूषण रोकने की माँग

11-श्री जय प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि सरदारनगर, जनपद गोरखपुर में स्थापित सरैया डिस्टलरी/शुगर मिल्स से निकलने वाला प्रदूषित जल पशुओं एवं सिंचाई हेतु उपयुक्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जल की जांच कराकर प्रदूषण को रोकने हेतु आवश्यक उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

उद्योग मै0 सरैया डिस्टलरी को विगत वर्ष जांचोपरान्त कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था, जिसके पश्चात उद्योग ने उत्प्रवाह शोधन व्यवस्था में सुधार (रिवर्स ओसमोसिस प्लांट एवं नैनो फिल्टेशन की स्थापना) का कार्य किये जाने का प्रस्ताव दिया है तथा उद्योग द्वारा रु0 10.00 लाख की बैंक गारंटी प्रेषित करने के बाद उक्त कार्य को जून, 2012 तक पूर्ण करने का समय प्रदान किया गया है।

मै0 सरैया शुगर्स मिल लि0, सरदार नगर, गोरखपुर के जांचोपरान्त पूर्व में दिनांक 23-08-2011 को जल अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी किया जा चुका है। तत्पश्चात उद्योग का जल सहमति आवेदन पत्र दिनांक 26-03-2012 को अस्वीकृत करते हुए चार्टर का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उद्योग वर्तमान में आफ सीजन के कारण बंद है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विकास खण्ड पसगंवा में डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

12-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विकास खण्ड पसगंवा में कोई डिग्री कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

जनपद खीरी में 01 राजकीय महाविद्यालय, 03 अनुदानित महाविद्यालय एवं 16 स्ववित्त पोषित/अनानुदानित महाविद्यालय संचालित हैं।

राज्य कर्मचारियों की भांति मण्डी समिति के कर्मचारियों को छठे वेतन समान लाभ दिये जाने की मांग

13-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01-01-2006 से छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण के उपरान्त अवशेष वेतन का भुगतान सरकार द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि मण्डी परिषद्/मण्डी समिति लाभ में होने के वाद भी इनके कर्मचारियों को दिनांक 01-01-2006 से लाभ न देकर शासनादेश जारी होने के दिनांक 18-03-2011 से छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार लाभ में चलने वाले मण्डी परिषद्/मण्डी समिति के कर्मियों को भी दिनांक 01-01-2006 से ही राज्य कर्मियों के समान छठे वेतनमान का लाभ देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

मण्डी समिति के कर्मचारियों को दिनांक 01-01-2006 से प्रकल्पित आधार पर तथा 18-3-2011 से वास्तविक आधार पर नये वेतनमान वित्त विभाग की सहमति से दिये गये है।

14-श्री अमर पाल शर्मा-

[दूसरे सोमवार के अंताराक्ति प्रश्न सं0-116 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच की कतिपय शुगर मिलों द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण की जांच कर कार्यवाही की मांग

15-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच में स्थित सिम्भावली शुगर मिल्स लि0 चिलवरिया तथा पारले शुगर फैक्ट्री, परसेन्डी मिलों ने जल एवं वायु प्रदूषण रोकने हेतु पुख्ता उपाय किये हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन मिलों की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

मेसर्स सिम्भावली शुगर्स लि0 (शुगर इकाई) विलवरिया बहराइच में उद्योग में प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु बार स्क्रीन, आयल ग्रीस टैप, केमिकल डोजिंग टैंक, इक्वालाइजेशन टैंक, एरेशन टैंक, सेकेण्डरी कलेरीफायर एवं स्लज डाइंग बेड्स आदि इकाईयां स्थापित की गई हैं। उद्योग में वायु प्रदूषण श्रोत के रूप में 77 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता व 80 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता के ब्वायलर स्थापित हैं 77 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता का ब्वायलर वर्तमान में कार्यरत नहीं है। उक्त दोनों ब्वायलर में संयुक्त रूप में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में 52 मीटर ऊँची चिमनी के साथ मल्टी साइक्लोन एवं इलेक्ट्रोइस्टेटिक फ्रिसीप्रीटेटर (इ0एस0पी0) की व्यवस्था की गयी है। उक्त के अतिरिक्त उद्योग के कैप्टिवपावर प्लान्ट में एक 80 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता का ब्वायलर स्थापित है जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु इलेक्ट्रोइस्टेटिक प्रिसीप्रीटेटर की व्यवस्था की गई है।

उद्योग की आसवनी इकाई जिसमें 60 किलोमीटर प्रतिदिन क्षमता से अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। उद्योग से जनित उत्प्रवाह (स्पेण्टवाश) के शोधन हेतु बायोगैस डाइजेस्टर, मल्टीइफेक्ट इवापरेटर के साथ उत्प्रवाह का निस्तारण शून्य किये जाने हेतु बायो कम्पोस्ट यार्ड की की स्थापना की गयी है। उद्योग की आसवनी इकाई में कोई ब्वायलर स्थापित नहीं है।

मेसर्स पारले बिस्कुट प्रा0लि0 (शुगर डिवीजन) परसेन्डी द्वारा उद्योग में जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में बार स्क्रीन, आयल, एण्ड, ग्रीस टैप, केमिकल डोजिंग टैंक, इक्वालाइजेशन टैंक, प्राइमरी क्लेरीफायर, एरेशन टैंक, सेकेण्डरी क्लेरीफायर एवं स्लज डाइंग बेड्स आदि इकाईयाँ स्थापित की गई हैं। उद्योग में वायु प्रदूषण स्रोत के रूप में 32 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता का दो एवं 45 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता का एक ब्वायलर स्थापित किये गये हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 60 मीटर ऊँची दो चिमनियों के साथ वेन्चुरी स्क्रबर एवं इलेक्ट्रोइस्टेटिक प्रिसीप्रीटेटर संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा को तहसील बनाये जाने की मांग

16-श्री विजय कुमार दुबे-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के खड्डा को तहसील बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रस्तावित तहसील खड्डा में लेखपाल क्षेत्रों की कुल संख्या 48 है, जो कि निर्धारित मानक से कम है।

17-श्री वीरपाल राठी-

[दिनांक 13-6-2012 को अतारांकित प्रश्न सं0-110 द्वारा उत्तरित]

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में मण्डी परिषद की ओर से अनेक मार्गों का निर्माण

18-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर तहसील हेतु स्वीकृत हुये मण्डी परिषद् की ओर से मार्ग बीसलपुर-खुदागंज मार्ग से गांव बसारा तक, बीसलपुर खुदागंज मार्ग से गांव बढ़ैपुरा धारम तक, रसयांखानपुर मार्ग से गांव दौलतपुर हीरा तक तथा कनपरा माइनर से गांव कनपरा तक का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा देगी ?

श्री अखिलेश यादव-

उपरोक्त चारों मार्गों का निर्माण कार्य वर्ष 1996-97 में पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर के उद्योगों के प्रदूषित कचरे को हिण्डन नदी में गिराने पर रोक की मांग

19-श्री अमर पाल शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के उद्योगों के प्रदूषित पदार्थ और कचरे को गाजियाबाद से पूर्व ही हिन्डन नदी में गिराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार हिण्डन नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हिण्डन एवं हिण्डन की सहायक नदियों के कैचमेंट एरिया में जनपद बागपत, मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर के 54 प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योगों में से 10 उद्योगों का शुद्धिकृत उत्प्रवाह सीधे हिण्डन नदी में, 11 उद्योगों का शुद्धिकृत उत्प्रवाह कृष्णा नदी के माध्यम से, शेष 33 उद्योगों का शुद्धिकृत उत्प्रवाह काली नदी (पश्चिमी) के माध्यम से हिण्डन नदी में निस्तारित किया जाता है। उक्त समस्त 54 इकाइयों में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। 54 उद्योगों में से 12 चीनी मिल, 06 आसवनी इकाईयां, 32 पेपर उद्योग, 01 टैनरी, 01 पशुवधशाला, 01 मीट प्रोसेसिंग तथा 01 डेरी इकाई हैं। वर्तमान में आफ सीजन होने के कारण समस्त चीनी इकाईयां बन्द है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की ग्राम सभा व चौबेपुर में शमशान की भूमि को दबंगों से मुक्त कराये जाने की मांग

20-श्री उमाशंकर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत ग्राम सभा चौबेपुर, परगना-को0 गर्वी, तहसील-रसड़ा के खाता संख्या-00167, खातेदार का नाम-मरघट, खसरा संख्या 39, क्षेत्रफल-0.506 हेक्टेयर, श्रेणी-कब्रिस्तान और शमशान (मरघट) पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण का निर्मित निजी स्कूल के छात्रावास एवं निजी

व्यवसायिक दुकानों (कटरा) को खाली कराकर सरकार कब्रिस्तान एवं शमशान को अतिक्रमण मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम चौबेपुर परगना को0 गर्वी तहसील रसड़ा स्थित खाता संख्या-167, खसरा संख्या-39 क्षेत्रफल 0.506 हे0 श्रेणी-6-3 कब्रिस्तान एवं शमशान (मरघट) के रूप में दर्ज है। इसका पूरा भू-भाग मौके पर खाली है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कोल जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाये जाने की मांग

21-श्री राजबली जैसल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोल जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या उनकी स्थिति को देखते हुये अनु0 जनजाति में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के परगना लोनी में डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

22-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका की आबादी लगभग 12 लाख है परन्तु वहां पर एक भी सरकारी डिग्री कालेज नहीं है, यदि हां, तो क्या सरकार उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कालेज बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

जनपद गाजियाबाद के परगना-लोनी (सद्दीकनगर) में मा0 कांशीराम राजकीय महाविद्यालय अवस्थित है, जिसकी दूरी लोनी नगर पालिका से लगभग 25 कि0मी0 है। इसके अतिरिक्त लोनी विकास खण्ड में 03 अनानुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं।

प्रदेश के जनपदों में भिक्षुक गृहों का संचालन

23-श्री वीरपाल राठी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में विभाग द्वारा भिक्षुक गृहों का संचालन किया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि भिक्षुक गृहों में फरवरी, 2012 से मई, 2012 तक कितने भिक्षुक निरुद्ध हैं तथा इसमें से कितने को पुनर्वासित करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा एवं फैजाबाद में भिक्षुक गृहों का संचालन किया जा रहा है।

प्रश्नगत अवधि में 01 भिक्षुक निरुद्ध रहा है, जिसको पुनर्वासित करने का यथासम्भव प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के ग्राम समेसी में चल रही चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने की मांग

24-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के ग्राम समेसी में चकबन्दी का कार्य पिछले पांच वर्षों से हो रहा है ? यदि हां, तो क्या चकबन्दी पूर्ण कराने की कोई अवधि निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। ग्राम समेसी, तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में दिनांक 13-06-2008 से चबन्दी प्रक्रिया चल रही है।

जी हां।

60 माह।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमि पट्टे पर दिये जाने की नीति अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में पट्टा देने की कार्यवाही की मांग

25-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा की खाली भूमि तथा कृषि भूमि को पट्टे पर दिये जाने की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम

बडावन, ब्लाक भावलखेड़ा जिला शाहजहांपुर में खाली कृषि भूमि का पट्टे पर भूमिहीनों को देने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

ग्राम बड़ावन, ब्लाक भावलखेड़ा में रिक्त भूमि का पट्टे पर भूमिहीनों को देने की कार्यवाही प्रचलित है। यह कार्यवाही दो माह में पूर्ण होगी।

जनपद गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली एवं व्यवस्था सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

26-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक मात्र विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली एवं व्यवस्था की सुचिता तार-तार होने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-4 नं0 035419 दिनांक 16-4-2012 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराये जाने का आदेश दिनांक 17 मई, 2012 को निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में मण्डी समिति के भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

27-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड-पयागपुर में मण्डी समिति के लिये भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? यदि हां, तो क्या मण्डी समिति पयागपुर के भवन का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

मण्डी समिति पयागपुर का नवीन मण्डी स्थल निर्माणाधीन है, जिसमें बाउण्ड्रीवाल का निर्माण हो चुका है। शेष निर्माण कार्य शीघ्र ही कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की तहसील भानपुर में राजकीय डिग्री कालेज बनाये जाने की मांग

28-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भानपुर, जनपद बस्ती में राजकीय डिग्री कालेज बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में 04 राजकीय महाविद्यालय, 04 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 30 स्ववित्त पोषित/अनानुदानित महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें से 05 महाविद्यालय तहसील भानपुर से लगभग 15 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत अवस्थित हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या-1 (नत्थी 'ख') को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (व्यक्तिगत)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज नत्थी-ख में पहला तारांकित प्रश्न उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त है। यह प्रश्न मैने दिनांक 22-05-2012 को दिया था और इसमें कई मा0 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं। यह आज के लिये निर्धारित था, उसको आगे बढ़ाकर चौथे बुधवार को कर दिया गया। पूरे प्रदेश को और हम लोगों को मालूम है कि गेहूं की खरीद की अंतिम तिथि 30 जून है।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी बात समझ गया, अब बैठ जांए। मा0 खन्ना जी आप तो मंत्री रहे हैं आप भी जानते हैं कि कैसे जवाब आता है। कहीं न कहीं कोई बात होगी इसीलिये चौथे बुधवार के लिये स्थानान्तरित किया गया है। कभी-कभी विभाग से यह लिखकर आ जाता है कि अभी सूचना नहीं मिली है तब स्थानान्तरित कर दिया जाता है। आप तो खुद मंत्री रहे हैं, सब जानते हैं, पूछने की क्या जरूरत है ? आप मुझसे मिलिये मैं सब कारण बता दूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पूरी बात सुन लें। आज पूरे प्रदेश में गेहूं का उठान रूका हुआ है। 15-20 दिन से ट्रक गोदामों के बाहर खड़े हैं और गेहूं की खरीद हो नहीं रही है, बिना सिफारिश के कोई भी खरीद नहीं हो रही है। मान्यवर, महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब आज नहीं जब चौथे बुधवार को आयेगा तब आप पूछियेगा। अब बैठिये। व्यवस्था के प्रश्न में इतना कह गये, बहुत है।

कारागार में जनप्रतिनिधियों को विशेष सुविधायें प्रदान किये जाने विषयक पूर्व में दिये औचित्य के प्रश्न पर स्पष्टीकरण

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक व्यवस्था दी है कि अगर किसी व्यक्तिगत सदस्य का, व्यक्तिगत प्रकरण हो तो उसे प्रश्न काल के बाद आपने उठाने की अनुमति दी है मैं उसी को उठाना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी कल नियम 300 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी थी कि कारागार जो माननीय विधायक या सांसद अण्डर ट्रायल के रूप में जायं उन्हें विशेष सुविधा दी जाय अभी भी दी जाती है परन्तु मजिस्ट्रेट की अनुमति के साथ। उस समय कारागार मंत्री जी ने मेरी सारी बातों को मानते हुए यह कहा था कि बेहतर यह होता कि इसे पिछली सरकार में उठाया गया होता या पहले उठाया गया होता, मैंने उस समय कह दिया था कि हाँ मैंने उठाया था और उस समय मैंने कहा था आपको कदाचित स्मरण होगा पूरे सदन को स्मरण होगा लेकिन उस समय मेरे पास तारीख नहीं थी कि कब मैंने उठाया था मैं स्पष्टीकरण के रूप में तारीख और सूचना देना चाहता हूँ, मैंने 21 फरवरी, 2011 को यही प्रश्न उठाया था जब यह प्रश्न उठाया था तो वह अंकित है विधान सभा की कार्यवाही के पृष्ठ संख्या-128 पर अंक 8 में अंकित है। मैं यह सिर्फ स्पष्टीकरण के माध्यम से देना चाहता था कि यह प्रश्न आज ही नहीं उठा है यह प्रश्न जब बसपा की सरकार थी उस समय जब विधायकों की प्रताड़ना हो रही थी उस समय मैंने उठाया था और जो जवाब उस समय आया था वह बहुत ही नकारात्मक आया था यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ और मैंने माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से सूचना भी दे दी है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 जून, 2012 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 15 सूचनाएं स्वीकार हुईं। पहली सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह की प्रदेश के सभी पालीटेक्निकों के डी फ्रीज बजट को समाप्त कराने, आई0ई0 आर0टी0 इलाहाबाद को राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान बनाने तथा अध्यापकों-कर्मचारियों की मांगों का पूरा किये जाने के सम्बन्ध में है, (दूसरी सूचना पर श्री राधेलाल रावत का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर) तीसरी सूचना श्री गेंदालाल चौधरी की जनपद हाथरस (महामायानगर) में अलीगढ़-आगरा रोड पर तालाब चौराहे के निकट फ्लाई-ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद प्रबुद्धनगर के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पाँचवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की पूर्वी उ0प्र0 में आर्थिक जोन के अन्तर्गत गोरखपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है। (डा0 राधामोहन दास अग्रवाल ने अपनी सूचना को सदन के समक्ष पढ़कर सुनाया) छठी सूचना साध्वी सावित्री बाई फूले की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा में विकास खण्ड मिहीपुरवा तथा बलहा के जंगलों के मध्य सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है। (साध्वी सावित्री बाई फूले ने अपनी सूचना को सदन के समक्ष पढ़कर सुनाया)। सातवीं सूचना श्री सलिल विश्नोई की जनपद कानपुर महानगर में पीने के पानी हेतु तैयार खड़े ओवर हेड वॉटर टैंकों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री अविनाश कुशवाहा (अनुपस्थित),

नौवीं सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ल की लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था सुधारे जाने एवं जाम से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री गायत्री प्रसाद की जनपद अमेठी में ट्रकों की ओवरलोडिंग रोकने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की मथुरा-आगरा के बीच में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में सरैया डिस्टलरी फैक्ट्री से निकलने वाले गन्दे पानी को फरेन नाले में गिराने से रोके जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी में ए0बी0सी0 कम्पनी से निकलने वाले दूषित जल से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्रीमती हेमलता चौधरी की जनपद बागपत शहर के शमशान घाट पर टीन शेड लगवाये जाने के सम्बन्ध में है तथा पन्द्रहवीं श्री मदन चौहान की जनपद पंचशील नगर में गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत एन0एच0-24 पर हापुड़ व ब्रजघाट पुल के बीच बने ओवर ब्रिज से सटी सर्विस लेन की विशेष मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में है।

<u>निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :-</u>

1-श्री मदन गोपाल वर्मा,

2-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी,

3-श्री अजय मिश्रा टेनी,

4-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

5-श्री जगराम पासवान,

6-श्री प्रदीप चौधरी,

7-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

8-श्री पूरन प्रकाश,

9-श्री दलवीर सिंह,

10-श्री वीरपाल राठी,

11-श्री जय प्रकाश अंचल,

12-श्री उमेश पाण्डेय,

13-श्री रामहेत भारती,

14-श्री ममतेश शाक्य तथा

15-श्री अनीसुर्रहमान।

श्री अध्यक्ष-

अनुपस्थित सदस्यों के स्थान पर मैं श्री मदन गोपाल वर्मा तथा श्री प्रदीप चौधरी की सूचनाओं को ले लेता हूँ। श्रीमती विमला सिंह सोलंकी का नम्बर दो पर नाम है मैं इनकी सूचना को अलग से ले लेता हूँ, स्वीकृत करता हूं। (स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं।)

प्रदेश के सभी पालीटेक्निकों के डी फ्रीज बजट को समाप्त कराने, आई0ई0आर0टी0 इलाहाबाद को राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान बनाने तथा अध्यापकों-कर्मचारियों की मांगों को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय, उ0प्र0 के 18 सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक तथा इलाहाबाद की आई0ई0आर0 टी0 के लगभग 1200 शिक्षक, कर्मचारी 1998 में शासन द्वारा गलत ढंग से बजट फ्रीज करने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। समय से वेतन, छठें वेतनमान के एरियर तथा 2010 से ए0सी0पी0 लागू करने आदि के लिये उ0प्र0 पॉलीटेक्निक कर्मचारी महासंघ लगातार संघर्षरत है। 8 दिसम्बर, 2009 को संघ के साथ उच्चस्तरीय बैठक में गलत बजट फ्रीज तथा माँगों को स्वीकार करने के बाद भी लागू न करने से आक्रोश, असंतोष व्याप्त है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1954 में स्थापित आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। इस समय लगभग 1110 डिग्री तथा 1290 डिप्लोमा कोर्स में छात्र अध्ययनरत हैं। शासन में इसको राज्य स्तरीय संस्थान बनाने का प्रकरण लंबित है। मंडलायुक्त इलाहाबाद प्रबन्धतंत्र का कार्यभार देख रहे हैं। वर्तमान में यहाँ राज्य का कोई इंजीनियरिंग कालेज नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सभी पॉलीटेक्निकों के डी फ्रीज बजट को समाप्त कराने, आई0ई0आर0टी0 इलाहाबाद को राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान बनाने तथा अध्यापकों-कर्मचारियों की माँगों को पूरा किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद हाथरस (महामायानगर) में अलीगढ़-आगरा रोड पर तालाब चौराहे के निकट फ्लाई-ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री गेदालाल चौधरी-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जनपद हाथरस (महामायानगर) में अलीगढ़-आगरा रोड पर रेलवे फाटक जो कि नगर का एक व्यस्ततम क्षेत्र है वहां पर अधिकांशतः ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में कई सरकारी प्रतिष्ठान, स्कूल एवं बाजार भी है। जिससे प्रतिदिन हजारों व्यक्ति प्रभावित होते हैं।

अतः ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अलीगढ़-आगरा रोड पर रेलवे फाटक पर यथाशीघ्र एक फ्लाई-ओवर बनाये जाने की मांग करता हूँ ताकि हजारों लोग लाभान्वित हो सकें।]

जनपद प्रबुद्धनगर के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री हुकुम सिंह-

[महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष गांवों के विद्युतीकरण हेतु बजट में प्राविधान किया जाता है। जनपद प्रबुद्धनगर को विद्युत विभाग ने विद्युतीकरण के संतृप्त गांवों में दर्शाया है। परन्तु केवल एक विधानसभा क्षेत्र सं0-8 कैराना में जन सम्पर्क के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि निम्न गांव अभी भी विद्युतीकरण की सुविधा से वंचित हैं। यह सभी गांव अति पिछड़े एवं शोषित वर्ग के हैं। अधिकांश लोग मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। विद्युतीकरण के अभाव में गांववासियों को अत्याधिक कष्ट का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। गांवों के नाम हैं डेरा सिंगापुर ग्राम पंचायत काला माजरा, प्रधान

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर मजरा गढ़ी हसनपुर, दाड़ी नगर मजरा गढ़ी हसनपुर, बलेहड़ा वि0ख0 ऊन, डोगपुरा, पुरवियान मजरा गागौर, खजूरवाला मजरा पटनी परतापुर, डेरा नाई नगला (सिरसागढ़) पूरबियों का, मंदिर वाला मजरा पटनी परतापुर, रामगढ़ मजरा गागौर (पूरबियों का), ऊदपुर (अधूरा विद्युतीकरण), डेरा सुन्दरनगर (सिवसाने के पास) सरदारों का, असरपुर (पूरबियों का डेरा बलेड़ा के पास), श्यामनगर मजरा बीपुर रोटन, चंडीगढ़ मजरा बीपुर, डेरा साकमाल (हरसाने के पास), रेडा हरसाना (आधे में विद्युतीकरण-बंजारों का गांव), गूजरपुर (कमालपुर के पास) तथा डोंवपुरा। यह सभी गांव विद्युत वितरण खण्ड-1, शामली के अन्तर्गत आते हैं।

माननीय सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन सभी गांवों का विद्युतीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय।]

पूर्वी उ0प्र0 में आर्थिक जोन के अन्तर्गत गोरखपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[भूमि, मौसम, जैव विविधता, फसलों के विविध आयाम, टोपोग्राफी, वर्षा तथा सिंचाई की सुविधाओं के आधार पर पूरे प्रदेश को 9 एग्रो-क्लाइमेंटिक जोन में बांटा गया है। इनमें से एक नार्थ-ईस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अन्तर्गत गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बहराईच, बलरामपुर तथा श्रावस्ती आदि जिले आते हैं।

इन जिलों की मिट्टी की रासायनिक गुणवत्ता, जल जमाव, अम्लीकरण या क्षारीयकरण अन्य एग्रोक्लाइमेटिक जोन से अलग प्रकार के हैं, इसलिये कृषि उत्पादन करने के उद्देश्य से प्रदेश के अन्य हिस्सों में कृषि विश्वविद्यालयों में दिये जाने वाले अनुसंधानों की उपलब्धियां इस नार्थ-ईस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन के जिलों पर हू-बहू लागू नहीं की जा सकती है।

यही कारण है कि गन्ना उत्पादन क्षेत्र होने के बावजूद न सिर्फ गन्ना की उत्पादकता कम होती है बल्कि चीनी की उपलब्धता का प्रतिशत भी कम होता है। विभिन्न खाद्यान्न की उत्पादकता भी प्रदेश में सबसे कम होती है। पूरा क्षेत्र हर वर्ष भीषण बाढ़ का शिकार होता है। इसलिये हम बाढ़ का नुकसान तो सहते हैं लेकिन उच्चस्तरीय शोध न होने के कारण इस बाढ़ को अपनी ताकत बनाने की तकनीकी विकसित नहीं कर पाते हैं।

अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि नार्थ-ईस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन भू-भौगोलिकी तथा परिस्थियों को देखते हुये पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों की खुशहाली के नये रास्ते खुल सकें।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय की नियम-301 के तहत उठाने की अनुमति दें।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा में विकास खण्ड मिहीपुरवा तथा बलहा के जंगलों के मध्य सम्पर्क बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

साध्वी सावित्री बाई फूले-

महोदय, जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा में विकास खण्ड मिहीपुरवा तथा विकास खण्ड बलहा का क्षेत्र जंगल व नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। सैकड़ों गाँव के लोग 5-25 किमी0 जंगल के रास्ते चलकर सड़क पर आकर साधन पकड़ते हैं। इस क्षेत्र में अधिकतर जनजाति थारू, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लोक निवास करते हैं। गाँव तक पहुँचने हेतु कोई मार्ग न होने के कारण लोग जंगल के रास्ते पैदल ही आने-जाने के लिए मजबूर हैं तथा कई बार जंगली जानवरों का भी शिकार होना पड़ा है। शासन एवं प्रशासन की उदासीनता के कारण लोग जंगल के रास्ते आने को मजबूर हैं। इससे क्षेत्र जनता में भय एवं आक्रोश व्याप्त है। काफी समय से जंगल से आवागमन हेतु मार्ग बनाये जाने की मांग की जाती रही है परन्तु वन विभाग के द्वारा मना कर दिये जाने की बात कहकर प्रकरण को दबा दिया जाता है। व्यापक जनहित में जंगल से आवागमन हेतु मार्ग का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मार्ग निर्माण हेतु कार्यवाही की मांग करती हूँ।

जनपद कानपुर महानगर में पीने के पानी हेतु तैयार खड़े ओवर हेड वाटर टैंकों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री सलिल विश्नोई-

महोदय, कानपुर महानगर में इस भीषण गर्मी में पीने के पानी की समस्या अत्यन्त गम्भीर हो गयी है। चारों ओर पानी के लिए मारामारी है। जलस्तर नीचे उतर जाने के कारण हैण्डपम्पों से पानी मिलना बन्द हो गया है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत बनाई गयी पानी की टंकिया (ओवर हेड टैंक) के कनेक्शन गंगा वैराज की मेन लाइन से न होने के कारण फूलबाग सहित कानपुर में बनाई सभी पानी की टंकियां खम्बे की तरह खड़ी हैं जिस कारण से वाटर लाइनों में पानी का प्रेशर भी खतम हो गया है जिससे पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है। पीने के पानी का गम्भीर संकट खड़ा हो गया है अगर तुरन्त तैयार खड़े ओवर हैड वाटर टैंकों को चालू नहीं किया गया तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। शासन के द्वारा इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूँ।

लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था सुधारे जाने एवं जाम से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

मान्यवर,

अवगत कराना है कि अम्बेडकर बस अड्डा आलमबाग, लखनऊ जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा रेलवे की जमीन पर पूर्व में बसपा सरकार द्वारा निर्माण कराया गया था। मेरे संज्ञान में आया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर रेलवे विभाग ने न्यायालय में अपनी जमीन खाली कराने के लिये मुकदमा दायर किया था। यह भी ज्ञात हुआ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा हार गये तथा उस जमीन को खाली करना होगा। उक्त के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि रायबरेली रोड लखनऊ की वृन्दावन योजना में पूर्व सरकार में वाहनों को खड़ा करने के लिये 25 एकड़ में एक पार्किंग स्थल बनाया था जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है जिस पर रायबरेली, फैजाबाद रोड व सुल्तानपुर रोड से आने वाली बसों को शहीद पथ (हाईवे) होकर यहां पर रोक कर बस अड्डा बनाया जा सकता है। साथ ही कानपुर रोड से आने वाली बसों के लिये स्कूटर्स इण्डिया पेट्रोल पम्प के सामने 57 बीघा भूमि जिसे श्री राज कुशवाहा जो श्री बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री के भाई हैं को पूर्व विधायक श्री श्याम किशोर यादव ने उक्त भूमि को मैनेज कराया था जिस पर अन्तर्राज्यीय बस अड्डा प्रस्तावित था जो आज भी प्रस्तावित है। सरकार से उक्त दोनों स्थानों पर जनता की सुविधा एवं शहर की जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिये अम्बेडकर बस अड्डा आलमबाग, लखनऊ उक्त भूमि पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त दोनों स्थानों पर जनहित में जनता के हितार्थ बस अड्डे बनाने की मांग करता हूं।

जनपद अमेठी में ट्रकों की ओवर लोडिंग रोकने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गायत्री प्रसाद

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद अमेठी की ए0सी0सी0 सीमेंट फैक्ट्री टिकरिया की तरफ ले जाना चाहता हूं। सीमेन्ट फैक्ट्री से सीमेंट लादकर ट्रकों द्वारा ओवर लोडिंग की जा रही है जिससे वहां की सड़कें अत्यंत जर्जर हो गयी हैं। जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रकों की ओवर लोडिंग रोकने के साथ क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराना अत्याधिक आवश्यक है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

मथुरा-आगरा के बीच में पर्यटन को बढ़ाया देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर ताज की नगरी आगरा एवं श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली मथुरा दोनों ही विश्व प्रसिद्ध हैं, जिसे देखने के लिये देश-विदेश से पर्यटक आगरा व मथुरा आते हैं। मथुरा में मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, नन्दगांव, बरसाना व गोबर्द्धन आदि स्थान ऐसे हैं, जहां वर्ष पर्यन्त देश-विदेश के करोड़ों तीर्थ यात्री आते हैं। लम्बे अर्से से मथुरा आगरा के बीच एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आवश्यकता महसूस की जा रही है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रदेश के वर्तमान नौजवान मा0 मुख्यमंत्री जी की इच्छाशक्ति को आकर्षित करना चाहता हूं पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तावित जेवर में बनने वाले हवाई अड्डे को निरस्त किया। भारत सरकार के मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री जी ने भी हाल में घोषणा की है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मथुरा आगरा के बीच में बने। इस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये भूमि चयन का स्थान ऐसा होना चाहिये, जोकि यमुना एक्सप्रेस हाइवे पर मथुरा आगरा के बीच में हो और जहां से आगरा की दूरी 25 मिनट, मथुरा की दूरी 20 मिनट की हो, अलीगढ़ की दूरी 45 मिनट, हाथरस की दूरी 25 मिनट, जनपद फिरोजाबाद की दूरी 60 मिनट, एटा की दूरी लगभग 60 मिनट, राजस्थान राज्य में भरतपुर, बयाना व अन्य जगहों की दूरी भी एक या डेढ़ घण्टे की हो। उधर हरियाणा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की दूरी 70 से 75 मिनट की हो और यहां तक कि दूरस्थ पंजाब, हरियाणा राज्य के लोग भी इस बनने वाले हवाई अड्डे से प्लेन की सुविधा प्राप्त कर सकें। मान्यवर, ऐसा स्थान मथुरा आगरा के बीच में यमुना एक्सप्रेस हाइवे पर पड़ता है। प्रदेश सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और केन्द्र सरकार की इच्छाशक्ति के अनुसार ही इस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जन्म देगी। यह बहुत पुरानी मांग है कि इस हवाई अड्डे के बनने के तदोपरान्त जहां इस क्षेत्रों का समुचित विकास होगा, वहीं दूसरी ओर मथुरा, आगरा व भरतपुर में पर्यटन की अपार संभावनायें बढ़ जायेंगी।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि प्रदेश सरकार इस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाने हेतु मथुरा आगरा के बीच भूमि चिन्हित कराकर उसका प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने का कष्ट करें, जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सोच और सपने को क्रियान्वित किया जा सके।

मैं लोक महत्व के इस विषय पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में सरैया डिस्टलरी फैक्ट्री से निकलने वाले गन्दे पानी को फरेन नाले में गिराने से रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-गोरखपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत सरदार नगर में सरैया डिस्टीलरी फैक्ट्री स्थित है जिससे निकलने वाला दूषित जल फरेन नाला में गिरता है। जिससे फरेन नाला का पानी प्रदूषित हो गया है, दूषित पानी पशुओं के पीने एवं सिंचाई के लिये उपयुक्त नहीं रह गया है। उक्त दूषित पानी के प्रयोग से कई जानवरों की मृत्यु हो गयी है उक्त नाले का पानी दूषित हो जाने से नाले के 50 कि0मी0 के परिक्षेत्र में पेय जल भी दूषित हो गया है। पेय जल भी दूषित हो जाने से क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त पानी के उपयोग से उन्हें कई प्रकार की गम्भीर बीमारी हो गयी है। दूषित पानी के उपयोग से क्षेत्रीय जनता में कई प्रकार अन्य गम्भीर रोग उत्पन्न हो गये हैं। उक्त नाले के परिक्षेत्र में बसे लोगों को सबसे ज्यादा मस्तिष्क ज्वर रोग से पीड़ित होना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता ने उक्त नाले में गिराये जा रहे दूषित पानी को रोके जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये सरैया डिस्टलरी फैक्ट्री से निकलने वाले गन्दे पानी को फरेन नाले में गिराने से रोके जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी में ए0बी0सी0 कम्पनी से निकलने वाले दूषित जल से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जनपद-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड-सीटी के अर्न्तगत ग्राम-नकहरा में ए0बी0सी0 कम्पनी स्थित है। जिससे निकलने वाला दूषित जल लोहदी नदी में गिरता है। जिससे लोहदी नदी का पानी प्रदूषित हो गया है, दूषित पानी पशुओं के पीने एवं सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है। उक्त दूषित पानी के प्रयोग से कई जानवरों की मृत्यु हो गयी है उक्त नदी का पानी दूषित हो जाने से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नदी के परिक्षेत्र में पेय जल भी दूषित हो गया है। पेय जल भी दूषित हो जाने से क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त पानी के उपयोग से उन्हें कई प्रकार की गंभीर बीमारी हो गयी है। दूषित पानी के उपयोग से क्षेत्रीय जनता में कई प्रकार अन्य गंभीर रोग उत्पन्न हो गये हैं। उक्त नदी के परिक्षेत्र में बसे लोगों को सबसे ज्यादा मस्तिष्क ज्वर रोग एवं कैंसर जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित होना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता ने लोहदी नदी में गिराये जा रहे दूषित पानी को रोके जाने एवं ए0बी0सी0 कम्पनी को बन्द करने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ए0बी0सी0 कम्पनी से निकलने वाले गन्दे पानी को लोहदी नदी में गिराने से रोके जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बागपत शहर के शमशान घाट पर टीन शेड लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती हेमलता चौधरी-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-बागपत, शहर के शमशान घाट की तरफ कोई भी टीन शेड न होने के कारण गर्मी व बरसात के दिनों में जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों में काफी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन से उक्त शमशान घाट पर टीन शेड लगवाने की वक्तव्य/कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

जनपद पंचशील नगर में गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत एन0एच0-24 पर हापुड़ व ब्रजघाट पुल के बीच बने ओवर ब्रिज से सटी सर्विस लेन की विशेष मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, नेशनल हाइवे (NH-24) पर हापुड़ से ब्रजघाट गंगा पुल तक कई फ्लाई ओवरों का निर्माण पिछले कई वर्षों से चल रहा है। एक छोड़कर गढ़स्याना चौराहा सभी पूर्ण हो चुके हैं। जो ग्राम उपैड़ा, कुचेसर चौवला, सिम्भावली, बक्सर, अटसैनी व गढ़स्याना चौराहा पर बने हैं। इनके साथ सर्विस रोड का निर्माण भी अनुबंधित है। लेकिन इनका निर्माण न कराये जाने से जनता के आवागमन में भारी बाधा है। क्योंकि यह सर्विस रोड़ पूर्णतया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षतिग्रस्त है। यह सूचना अत्यन्त लोक महत्व व अविलम्बनीय जनहित से जुड़ी है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। अतः NH-24 हाइवे अथार्टी को तुरन्त निर्माण के निर्देश देने की कृपा करें।]

विधान सभा जहानाबाद फतेहपुर में विकास खण्ड अमौली अन्तर्गत दपसौरा पम्प कैनाल तथा खजुआ के अन्तर्गत पम्प कैनाल को उच्चीकृत किये जाने के सम्बध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन गोपाल वर्मा-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र 238, जहानाबाद फतेहपुर में विकास खण्ड अमौली अन्तर्गत दपसौरा पम्प कैनाल तथा विकास खण्ड खजुआ के अन्तर्गत बहादुर पम्प कैनाल से टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा है। जिससे स्थानीय/कृषकों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अतः आवश्यक है कि उक्त दोनों कैनाल को उच्चीकृत करके जनहित में कृषकों को टेल तक पानी पहुँचाया जाये ताकि गरीब व निर्धन कृषकों को पानी सुगमता से उपलब्ध हो सके और वे अपना जीवकोपार्जन कर सकें।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त जनहित उक्त कार्य को तत्काल कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर में नया विकास खण्ड ककोड़ सृजित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, जनपद बुलन्दशहर का विकास खण्ड सिकन्दराबाद क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से काफी बड़ा है। इसके अंतर्गत 91 ग्राम पंचायत, 116 क्षेत्र पंचायत सदस्य 133 राजस्व ग्राम तथा लगभग 160 के करीब ग्राम व मजरे हैं। यह विकास खण्ड लगभग 25 किमी0 लम्बाई तथा लगभग 30 किमी0 चौड़ाई में फैला हुआ है। प्रदेश के बड़े विकास खंडों में इसकी गिनती होती है। बहुत बड़ा विकास खण्ड होने के कारण जनता को विकास से संबंधित अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से जनता का मिलना असंभव हो जाता है। जिससे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। अधिकारी भी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते हैं। उनका काफी समय विभिन्न गांवों तक पहुँचने में ही निकल जाता है। क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए जनहित में इस विकास खंड का विभाजन कर नया विकास खंड ककोड़ बनाना अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के ग्राम दौलतपुर में निर्माणाधीन यमुना नदी के पुल तक जाने वाली सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद-सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र-गंगोह के ग्राम दौलतपुर में निर्माणाधीन यमुना नदी के पुल तक जाने वाली सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त हैं। क्या सरकार इन सड़कों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकारण करने हेतु कोई योजना बना रही है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 जून, 2012 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 (1) के उपबन्ध 333 के अधीन उत्तर प्रदेश की विधान सभा में परिसीमन के आधार पर 500 सदस्य किये जाने हेतु प्रस्ताव भेजकर लाभ दिलाये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की प्रदेश के 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्रों का स्नातक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में है। यह सूचना दिनांक 12 व 13 जून, 2012 को निरस्त की जा चुकी है अतः नहीं सुनी जायेगी। तीसरी सूचना श्री दलजीत सिंह जी की है जो जिलाधिकारी बांदा द्वारा शिष्टाचार एवं प्रोटोकॉल संबंधी शासनादेश का उल्लंघन किये जाने के संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। चौथी सूचना श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य की है जो विधान सभा के प्रथम सत्र 2012 के तीसरे बुधवार को उत्तरित अतांराकित प्रश्न संख्या 88 का पूर्ण उत्तर संबंधित विभाग से दिलाये जाने के संबंध में है। इसमें प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 167/168 एवं नियम 63 के अन्तर्गत आप हमें सूचना दे सकते हैं। मा0 सदस्य हाउस में हैं। नहीं हैं। तो इनको क्या बतायें।

उत्तर प्रदेश की विधान सभा में परिसीमन के आधार पर 500 सदस्य किये जाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र भेजकर लाभ दिलाये जाने में सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 170के अन्तर्गत यह है कि अनुच्छेद 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन

क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए पाँच सौ से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी।

मान्यवर, जब भी कोई विधान सभा बनेगी तो उसमें कम से कम 60 सदस्य होंगे और ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य होने चाहिए। मान्यवर पहले विधान सभा में 425मा0 सदस्य चुनकर आते थे लेकिन जब से उत्तराखण्ड बन गया है तो 22से अधिक सदस्य हमारे यहाँ के वहाँ चले गये हैं और इससे हमारी संख्या घट कर 403हो गयी है।

मान्यवर, आश्चर्य की बात है कि उत्तराखण्ड में 30 से 40 हजार पर विधान सभा के सदस्य चुने जाते है, नागालैण्ड में सिर्फ 10 हजार पर चुने जाते है बहुत से प्रदेशों में 20 हजार, 25 हजार, 15 हजार पर विधानसभा के सदस्य बनते है और उत्तर प्रदेश में विधान सभा का सदस्य बनने के लिए 3 लाख मतदाता चाहिए कम से कम। संविधान की बात कर रहा हूँ 3 लाख से लेकर 4 लाख तक और अभी तो गाजियाबाद बगैरा में जहाँ 6, 7 लाख पर था कानपुर गोविन्द नगर में 6 लाख 7 लाख था। मान्यवर, 425 की विधान सभा रह चुकी है, 500 तक हम कर सकते हैं। होता क्या है कि हमको भी 3 से 5 लाख लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है और बगल में हमारा ही हिस्सा है उत्तरांचल मे वहाँ 10 हजार में काम चल जाता है। तो जो संसाधन हमें मिलता है वह बहुत महत्वपूर्ण है उस संसाधन से हमें 3 लाख को संतुष्ट करना पड़ता है, मतदाता के अगर परिवार को जोड़ ले तो यह संख्या 15 से 20 लाख हो जाती है, 25 लाख हो जाती है। तो मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि जब भारत के संविधान में एक प्राविधान है और 2001 की जनगणना हो गयी है तो मान्यवर, अगर हम इस संख्या को 430 से बढ़ाकर 500 तक करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजें तो मान्यवर, हमारे लिये 2 लाख ढ़ाई लाख मतदाताओं पर हमारा निर्वाचन होगा और हमें छोटा क्षेत्र मिलेगा। मैं जो कह रहा हूँ कृपापूर्वक मेरी बात सुन लें। मान्यवर, मैं दो सुझाव दे रहा हूँ मैं पूरी तरह से बारगेन करने को तैयार हूँ, समझौता करने को तैयार हूँ, सौदा करने को तैयार हूँ, जब तक इसको सदस्य संख्या 500 तक नहीं बढ़ाई जायेगी तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे हर विधान सभा सदस्य को 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मतदाता को संतुष्ट करना पड़ता है यानि यह तो आपने स्वीकार कर ही लिया कि हमारे पास ज्यादा बड़ा क्षेत्र है सेवा करने के लिए तो हमें सेवा करने लायक तो बनायें आप। अगर मुझको एक विधान सभा क्षेत्र में जो सुविधाएँ और संसाधन मिलते है, उनको सिर्फ 10 हजार को संतुष्ट करना पड़ता है, उत्तरांचल को 20 हजार को संतुष्ट करना पड़ता है हमें 5 लाख को संतुष्ट करना पड़ता है, मैं कुछ नहीं चाहता कृपापूर्वक आप हमारे संसाधन बढ़ा दीजिए।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के 170 के अनुसार यहाँ 500 होने चाहिए 500 नहीं है 425 थे वह भी अब 403 रह गये है तो 500 के हिसाब से जो संसाधन मिलना चाहिए वह 403 में बांट दीजिए मैं यही कह रहा हूँ इसके अलावा और कुछ नहीं कह रहा हूँ और जो कह रहा हूँ यह भारत के संविधान के अनुसार कह रहा हूँ। और अगर नहीं बांटेंगे तो संविधान को खतरा उत्पन्न हो जायेगा तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आप जैसा सुशील, मिलनसार, अच्छा मुख्य मंत्री, एकआध और हो तो बताओ, जो जो मैं कह सकता हूँ जो अच्छा अवसर है, उसका सहारा लेते हुए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके भी हित की बात कर रहा हूँ अपने भी हित की बात कर रहा हूँ और 403 सदस्यों के हित की बात कर रहा हूँ। जल्दी से हमारे संसाधन बढ़ा दीजिए मैं यह बिलकुल नहीं कह रहा हूँ कि विधान सभा क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दीजिए नहीं कह रहा हूँ यह मेरे बगैर कहे आप समझ रहे होंगे। मैं सड़कों की बात करूंगा बिजली की बात करूँगा गांव की सिर्फ भारत के संविधान 170 का उल्लंघन माननीय मंत्री जी न हो या तो सदस्य संख्या 500 करिये या विधान सभा के संसाधन बढ़ाइये। इस पर माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कृपापूर्वक माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार ले लें। पहले शासन का विचार ले लें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी जो कहते हैं फायदे की ही बात कहते हैं कभी घाटे की बात कही नहीं, चाहे अपना हो, हमारा हो, सबका हो लेकिन वह सारी बाल उनकी ही गोल में है, जैसा चाहें तय कर दें, आप तय कर दीजिए हम मान लेंगे। पहले तो राष्ट्रपति की तय कर लें उसके बाद आगे बात करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, केन्द्र की सरकार भी तभी चलेगी जब आप समर्थन देंगे। राष्ट्रपति तब ही चुना जायेगा जब आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी जिसको चाहेंगे। यही मैं भी चाहता हूँ हमारी रोजी रोटी भी तभी चलेगी जब आप चाहेंगे। राष्ट्रपति तो कोई एक बनेगा छोड़ दो उसको हमारे 3 लाख की फिक्र कर लो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरे ख्याल से अगर प्रदीप जी का नाम राष्ट्रपति के लिये जाय तो सबसे खुश प्रमोद तिवारी जी होंगे। (हँसी)

श्री अध्यक्ष-

चलिये हो गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब जब चल ही रहा है तो चलने दीजिये थोड़ी देर। इसमें क्या दिक्कत है? अगर प्रदीप जी का नाम लेने पर अगर मैं प्रसन्न हूँगा और आजम साहब का नाम अगर राष्ट्रपति के लिये चला जाय तो पूरा सदन प्रसन्न होगा। (हँसी)

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय तिवारी जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। माननीय तिवारी जी इसमें लिखा है अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए पाँच सौ से अनधिक नहीं होगी। यह 500 से अनधिक नहीं होगी, उससे कम हो सकती है। तो यह इसमें जो आपने उठाया है यह औचित्य के प्रश्न में नहीं आता है इसलिये इसको निरस्त करता हूँ।

(मद संख्या-3 पुकारने पर एक माननीय सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आगे बढ़ गये हैं। मद संख्या ले लेने दीजिये उसके बाद।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (सातवां संशोधन) नियमावली, 2010†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 1572/30-4-10-167-91टी.सी., दिनांक 05 अगस्त, 2010 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (सातवां संशोधन) नियमावली, 2010 को उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा-29(2) के अधीन दिनांक 08 अगस्त, 2011 को 30 दिनों की कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 09 मार्च, 2012 को पन्द्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सही है, को विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश आवास विकास लिमिटेड लखनऊ के वर्ष 2009-2010 की वार्षिक रिपोर्ट †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 की वार्षिक रिपोर्ट को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदनों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

(मद संख्या 6 पुकारे जाने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं इसी मद संख्या 5 के बारे में बता रहा हूँ आपको। देखिये 1999-2000 मान्यवर, 12-12 साल के बाद में प्रतिवेदन यहाँ पर, माननीय मंत्री जी ने लिखा है विलम्ब के कारण सहित। लेकिन मान्यवर, विलम्ब की कोई सीमा तो होती है। अगर 12 साल के बाद में रखी जा रही है तो चिन्ता नहीं होनी चाहिए इस बात की? यह मान्यवर, मैं इसलिये आपके संज्ञान में और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि वह तो एक औपचारिकता है, विलम्ब के कारणों सहित यहाँ पर रखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि कोई कारण भी तो हो। अगर यह कारपोरेशन चल रहे हैं कम्पनी के अधीन चल रही है तो उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है। सदन को मखौल बनाकर रख दिया जब चाहेंगे ले आयेंगे। इनसे जवाब तलब होना चाहिए कि 1999 के बाद अब क्यों आ रही हैं?

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-8/2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-8/2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापी नहीं गयी।

लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012[††]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूँ।

जनपद बांदा के खपिटिया कलां गांव में लगी आग से प्रभावित लोगों को राहत सम्बन्धी चेक पूर्व सांसद द्वारा बांटे जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 के अन्तर्गत कल मैंने कहा था।

श्री दलजीत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मैं तिन्दवारी विधान सभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर आया हूँ। मेरे यहां 10 जून 2012 को भीषण आग लगी खपिटिहा कलॉ गाँव में, मैं वहां मौजूद था। इसके बाद नियम-51 में भी मैने यहां आकर सूचना दी और जब राहत सामग्री बांटने की बात आई तो एक पूर्व मंत्री राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद के द्वारा बंटवा दी गई। सूचना मिलने पर मैने जिलाधिकारी से मना भी किया कि आप जब चाहें मैं बांट दूँगा यह मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। मना करने के बाद उनसे बंटवाई गई। यह मेरा अपमान हुआ है इस पर कार्यवाही करायें।

श्री अध्यक्ष-

इस पर तो आपने सूचना दी है मैंने पढ़ा है उसके बाद में कार्यवाही होगी।

---

†† दिनांक 21 जून, 2012 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं इनकी बात पर बल देना चाहता हूँ आपका शासनादेश है पीठ के निर्देश है कि अगर दैवी आपदा हो तो उस समय विधायक को जरूर सूचना दी जाए वह चाहे तो उपस्थित रह सकता है। लेकिन यहां तो उल्टा है। यह अनुरोध कर रहे है और इनको नहीं बुलाया जा रहा है यह गम्भीर प्रकरण है इस पर आप और राजस्व मंत्री जी कड़े निर्देश दें।

(कई सदस्यों, के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

श्री अजय मिश्रा 'टेनी'-

मान्यवर, हमारे यहां आग लगी।

एक मा0 सदस्य-

यह हर जगह हो रहा है।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

ग्राम में आग लगी थी मैं चेक बांटने गया वहां नायाब तहसीलदार मौजूद था उसका इसलिए तबादला करा दिया गया कि भा0ज0पा0 के विधायक से राहत राशि क्यों बंटवाई गई। उसके बाद दूसरे दिन चकरा मजरा है.....।

श्री अध्यक्ष-

आपने चेक बांटा या नहीं ?

श्री अजय मिश्रा 'टेनी'-

हमने नियम-51 में दिया था। उसके बाद जो घटनायें हुई उसमें हमें नहीं बुलाया गया। उसके बाद जो वहां के पदाधिकारी थे और जो चुनाव प्रत्याशी थे जो चुनाव हार गए हैं उनको बुलाकर बंटवाया गया। और कई बार राहत सामग्री मिलने में इसलिए देर हो गयी क्योंकि वह प्रत्याशी वहां पहुँच नहीं पाए। तो चेके नहीं बांटी गई। इसको मैंने नियम 51 में दिया था जो स्वीकृत नहीं हो पाया जिसका मुझे क्षोभ है।

श्री अध्यक्ष-

लिखकर दे दों।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मान्यवर जैसा सदन अवगत है महोवा क्षेत्र 45 में ग्राम कोहारी में आगजनी की घटना को लेकर मैंने सूचना दी थी मान्यवर आपने स्वीकार की नियम-56 में सुना गया आपके आदेश के तहत माननीय राजस्व मंत्री की कृपा से अग्नि पीड़ितों उनको राशि उपलब्ध कराई गई जैसा कि हमारे साथियों ने कहा जो चेक की राशि थी वह नायब तहसीलदार जाकर दे आया। उसने हमको अवगत भी नहीं कराया यह शिकायत मेरी है।

श्री अध्यक्ष-

सबकी शिकायतें मुझे मिल गई हैं इसमें क्या हो सकता है इसको हम देखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना दे दें। माननीय नन्दू चौधरी जी, आपका क्या है, बैठिए।

श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आग लगी थी। मैने तहसीलदार को सूचना दिया, वह लोग गए और कहने लगे कि आचार संहिता लगी है, हम आपके द्वारा चेक नहीं बँटवायेंगे और चेक कानूनगो ओर नायाब तहसीलदार से बँटवा दिया।

श्री अध्यक्ष-

यह सही है कि आचार संहिता लगी हुई है।

श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

लेकिन मान्यवर, ग्राम सभा उसमें प्रभावित नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष-

उपेन्द्र जी, आप बैठिए।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

अध्यक्ष जी, विधान सभा फेफना की भी यही समस्या है। जिलाधिकारी के संज्ञान में जिला प्रशासन के अधिकारी नहीं आए।..... इसको संज्ञान में लिया जाए।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष-

हमने सबकी बात सुन ली है पहाड़िया जी, आप तो आज विशिष्ट पहचान में आए है। अब आगे के मद लेने दीजिए, आज सिंचाई का बजट हैं।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों में नायब तहसीलदार से लेकर पटवारी तक, आईएएस तक..... चले गए।

मा0 सिंचाई मंत्री द्वारा दिए गये भोज की सूचना

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, चलिए।

आज एक व्यवस्था है, माननीय सिंचाई मंत्री जी की ओर से, उसकी सूचना दे दें। सभी माननीय सदस्यों को भोजन की व्यवस्था सेन्ट्रल हाल के नीचे कैन्टीन में की गई है और

वह 1.00 बजे से प्रारम्भ हो जायेगी। जो माननीय सदस्य भोजन करना चाहेंगे वह नीचे सेन्ट्रल हाल में, माननीय सिंचाई मंत्री जी का बजट है, उनकी तरफ से आयोजित है, उसमें जा करके भोजन कर लेंगे।

नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 जून, 2012 को नियम 311 में प्राप्त 01 सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 में कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई। कल दिनांक 13 जून, 2012 को अध्यक्ष पीठ में दिये गये निर्देशानुसार चयनित 06 सूचनाओं को उसी क्रम में रखा गया है एवं आज प्राप्त सूचनाओं में से चयनित सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना-

श्री हुकुम सिंह, डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल की प्रदेश में नदियों के पास उपलब्ध होने वाले रेत एवं पत्थर के अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

दूसरी सूचना-

श्री दीपक पटेल, श्री मो0 आसिफ जाफरी, श्री राजेश त्रिपाठी जनपद गोरखपुर के थाना कैन्ट में दिनाक 07-5-2012 को श्री राम भुआल निषाद को फर्जी मुकदमें में फसाये जाने के संबंध में है,

तीसरी सूचना-

(1) श्री प्रमोद तिवारी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अजय कपूर, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्रीमती रूबी प्रसाद, श्रीमती उमाकान्ती सिंह, श्री दलजीत सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री प्रदीप कुमार, श्री संजय जायसवाल, श्री राधे श्याम, कुवंर कौशल सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री पंकज मलिक, श्री दिलनवाज खान, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, तथा श्री गयादीन अनुरागी की प्रदेश में नकली देशी घी की बिक्री से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

चौथी सूचना-

श्री मलिक कमाल यूसूफ की जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर स्थित श्री देवीपाटन मन्दिर में वित्तीय अनियमितताओं से सरकार की राजस्व हानि के संबंध में,

पांचवीं सूचना-

श्री प्रदीप माथुर की आगरा मण्डल में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है,

छठी सूचना-

श्री राजबली जैसल, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया तथा श्री शाह आलम (गुड्डू जमाली) की जनपद के उन्नाव थाना असोहा में थाना इंचार्ज द्वारा श्री पुत्तू लाल पाण्डेय को फर्जी मुकदमें में फंसाये जाने के संबंध में है तथा

सातवीं सूचना-

श्री गंगा सिंह कुशवाहा की कुशीनगर के अन्तर्गत तहसील कसया में जाति प्रमाण-पत्र की मांग कर रहे सैकड़ों लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई अतः अस्वीकृत की जाती है :-

1-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल

2-श्री रामचन्द्र यादव

3-श्री मुकुट बिहारी वर्मा

4-श्री अगयश रामसरन वर्मा

5-साध्वी सावित्रीबाई फूले

6-श्री सुरेश कुमार खन्ना

7-श्री जय प्रकाश निषाद

8-डा0 धर्म सिंह सैनी

9-चौ0 गजेन्द्र सिंह

10-श्री उमाशंकर सिंह

11-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप

12-श्री सलिल विश्नोई

13-श्री बजरंग बहादुर सिंह

14-श्री गुटियारी लाल दुबेश

15-श्री वीरपाल

16-श्री प्रदीप माथुर

17-श्री जय प्रकाश निषाद

18-डा0 धर्म सिंह सैनी

19-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप

श्री अध्यक्ष-

चूंकि इसमें कल की भी सूचनाएँ हैं। इसमें पहली, दूसरी, तीसरी सूचना पर सुना जायेगा, गंगा सिंह कुशवाहा को भी सुना जायेगा, शेष पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा। अब माननीय हुकुम सिंह जी।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है यह समस्त प्रदेश से सम्बन्धित है। मान्यवर, नदियों के किनारे जो रेत है, रेत हमारी अमूल्य सम्पत्ति है, कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, प्राकृतिक रूप से वह आता है। अगर उसके बारे में चिन्तन करें, जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है और जिस गति से खनन हो रहा है। एक पैसा राजकोष में नहीं आता और उन नदियों के किनारे के जो आस-पास के किसान है उनकी जमीन और उनकी फसल बर्बाद हो रही है। यह माफियाराज पैदा हो गया है। मान्यवर, सहारनपुर से लेकर प्रबुद्धनगर और बागपत तक चले जाये तो वहाँ कम से कम 8 से 10 हजार ट्राली रोजाना अवैध खनन हो रहा है। मैंने सिर्फ तीन जिलों की बात कही है। बाकी प्रदेश में तो हो ही रहा है। आखिर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा। मैंने कम से कम एक दर्जन बार अधिकारियों से शिकायत की है। लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक इतनी मोटी आमदनी उन अधिकारियों की है कि कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एक दो लाख नहीं बल्कि करोड़ों रूपये का अवैध धन्धा यह रोजाना हो रहा है। एक तो माफियाराज से खनन हो रहा है लेकिन अगर कोई अपने मकान का निर्माण कराना चाहे तो रेत नम्बर दो का मिलेगा। अपने लिए उठा लाएगा तो पुलिस चालान करेगी अगर अवैध खनन होगा तो चालान नहीं होगा। क्योंकि पैसे की वसूली हो रही है। कोई चेकपोस्ट ऐसी नहीं है जहाँ सुबह से लेकर शाम तक अवैध खनन का धन्धा न चलता हो। अभी सामने प्रश्न आये थे कि सड़क क्यों नहीं बन रही है। लेकिन जब रोड़ी उपलब्ध ही नहीं है तो सड़क कहां से बन जाएगी। वह सारा का सारा माफियाओं ने कब्जा लिया। अगर आज भी कोई मकान के लिए रोड़ी डालना चाहे तो कम से कम उसको दो सौ गुना दाम में मिलेगी। यह बिन्दु आपको छोटे-छोटे लग सकते हैं लेकिन इससे पूरे प्रदेश की जनता प्रभावित है। सरकार बाकी चीजों पर ज्यादा दलील देती है। इन बातों पर कम विचार करती है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप दो-चार दिनों का सर्वे करा लें कि किस प्रकार से माफिया लोग अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। मेरे सामने तो एक उदाहरण था मैं नाम नहीं लेना चाहता भले ही वह किसी सदन के सदस्य हों। पांच साल एक व्यक्ति का साम्राज्य चला। रोड़ी पर भी कब्जा और रेत पर भी कब्जा। अरबों रुपये का इधर से उधर लेन-देन हुआ।

---

* नोट :-[ ] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खाद्य एवं रसद, कारागार मंत्री (कुँवर रघुराज प्रताप सिंह, राजा भईया)-

किसकी सरकार थी।

श्री हुकुम सिंह-

आपको भी पता है कि किसकी सरकार थी। पता नहीं है क्या ?

(हँसी)

मान्यवर, मैं इनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ यह थे नहीं यहाँ पर। मान्यवर, अगर उस सरकार को कोई याद रखेगा तो माननीय मंत्री जी तो नहीं भूलेंगे और कोई भूल जाये तो भूल जाये। जितनी पीड़ा आपने परसों बतायी वह वाकई रोंगटे खड़े करने वाली थी। मान्यवर, मैं इस बात को छोड़ता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अवैध रेत, अवैध रोड़ियों के खनन से निजात कैसे दिलायी जाये। ढ़ाई-तीन महीने हो गये हमें उम्मीद थी कि सरकार आयेगी तो इस पर नियंत्रण करेंगी। आज तक आपने इस तरफ एक भी कार्यवाही की है। अधिकारी वही हैं। जब उनको लगा कि सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो उन्होंने वसूली के और पैसे बढ़ा दिये। मान्यवर, इस समस्या का बहुत बड़ा आकार है। आज प्रदेश में इतनी नदियां हैं इतना रेत है इतनी रोड़ी है अगर उससे हमारे राजकोष में पैसा आये तो अरबों रूपये आएगा और हमारे प्रदेश के विकास के काम में लगेगा। सब माफियाओं की जेब में जा रहा है। आपको न टैक्स देते हैं न आपको उसका कोई हिस्सा बाँटकर देते हैं। आम उपभोक्ता प्रताड़ित हो रहा है। अगर कोई आज अपना मकान बनाना चाहे तो उसको रोड़ी नहीं मिलेगी। कई सौ गुने दाम पर मिलेगी। कल लोक निर्माण विभाग का बजट था। सड़क निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। बड़ी भारी धनराशि का प्रावधान आपने किया है लेकिन बिना रोड़ी के कैसे सड़क बन जायेगी। उन्होंने जो कब्जा कर लिया है उस पर सरकार तभी नियंत्रण कर पायेगी जब सरकार बहुत ज्यादा इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करेगी। मेरा बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह आपके माध्यम से सरकार से कि इस बीमारी से निजात दिलायें आज जकड़ गया आम नागरिक एक गरीब आदमी, साधारण सामान्य व्यक्ति अपने मकान का अपने छोटे आवास का निर्माण करने में भी अक्षम हो गया है। सरकार के काम सब अवरूद्ध हो गये। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि आज सरकार ऐलान करे मजबूती के साथ में कि इस माफिया राज की समाप्ति होगी, अवैध खनन नहीं होने दिया जायेगा, नियंत्रित किया जायेगा और जो सरकारी कर्मचारी पुलिस कर्मी इस अवैध धन्धे में लगे हुए हैं रोजाना करोड़ों की कमाई कमा रहे हैं, उनके विरूद्ध भी कार्रवाई होगी, यह आश्वासन मान्यवर, मैं चाहता हूँ।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 हुकुम सिंह जी ने जो बातें यहाँ रखी हैं, उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता हुआ, इसका जो असर हम लोगों के क्षेत्र में पड़ रहा है उसका मैं वर्णन सिर्फ दो मिनट में करना चाहता हूँ। यह खनन माफिया जहां अवैध खनन कर रहे हैं वह तो कर रहे हैं कार्रवाई का हिस्सा है, उनका जो दूसरा सबसे बड़ा खेल है झांसी एक बहुत बड़ा केन्द्र बना है। उनका दूसरा सबसे बड़ा खेल है जहां वैधानिक रूप से खनन होता है वहां यह प्रभाव बना करके इस खनन की पूरी की पूरी प्रक्रिया को अवरूद्ध कर रहे हैं जिससे कि इनका एक स्थान में जो अवैध खनन का माल है, वह सही तरीके से उपयोग हो सके उदाहरण के लिए मैं गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहा हूँ, गोरखपुर में और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले गिट्टियां हम लोगों को नौतनवा से मिल जाती थीं, निर्माण कार्य कराने के लिए, लागत पड़ती थी, 40 रुपये घनफिट आज स्थिति है जो पूरी तरह से बन्द प्राय है, सोनभद्र में काम रूका हुआ है सरकारी आदेश से, अब गिट्टियां आती हैं झांसी से और बंगाल और बिहार के बार्डर से और यह गिट्टियां 40 रुपये की जगह पर 85 रुपये घनफिट पड़ रही हैं ओर जो भी पैसा हम लोग स्वीकृत कराते हैं विधायक निधि या अन्य चीजों से हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है मा0 अध्यक्ष जी कि गुणवत्तायुक्त निर्माण करा सकें, जब तक इन अवैध माफियाओं के ऊपर रोक नहीं लगाई जायेगी और जो दबाव बनाकर के यह गिट्टी की उपलब्धता को प्रभावित करें, उन पर कार्रवाई नहीं की जायेगी जैसा मा0 हुकुम सिंह जी कह रहे थे, विकास कार्यों को कराना बहुत मुश्किल होगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री-(श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर सवाल है और इस सवाल से पूरे उत्तर प्रदेश का भविष्य जुड़ सकता है। पिछली सरकार में जिस तरह से खनन माफियाओं का वर्चस्व रहा और सिर्फ पैसा ही नहीं उनको जो मान सम्मान मिला, ऐसे लोगों को जिन्हें हम माफिया भी कहें, समाज जिन्हें बुरी निगाह से देखता हो, उन्हें इस जमाने में बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए लोग उनकी गाड़ी से सड़क से रिसीव करके लेकर आयें, यह पूरी व्यवस्था के लिए बहुत शर्म की बात थी। कितने पैसे की लूट हुई है, कितना खनन के नाम पर प्रदेश बरबाद हुआ है और हम अभी एक बात कर रहे थे, मान्यवर और मुख्य मंत्री जी ने जाते-जाते मुझसे कुछ कहा भी है जो मैं आपसे अभी अर्ज करूँगा, बहुत कष्ट है, उन दिनों का, बहुत नुकसान हुए हैं जैसे आपने कहा कि कल जिस तरह से जेल मंत्री जी ने बात को रखा था, अमानवता की, जुल्म करने की और विरोधियों को बरबाद कर देने की, मिटा देने की जो नीति रही थी बहुजन समाज पार्टी की और जितना गिर कर मानवता से, गिर कर इन्सानी कदरों से, गिर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

कर, जिस तरह से सरकार चलाई थी, पूरी दुनिया में उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। मान्यवर, किसी की बपौती नहीं है सरकार चलाना, समाजवादी पार्टी हमेशा सत्ता में रहेगी यह तय नहीं है, कब कौन सत्ता में आ जायेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि राजनीति में जुल्म करने वालों के अन्जाम ऐसे हुए हैं जिसे इतिहास ने याद रखा है। 1975 में इमरजेन्सी लगी, जरूर लगी, लेकिन 1977 में जब पूरे देश में राजनैतिक बदलाव आया तो मिसेज इन्दिरा गाँधी जैसी बड़ी नेता को लोक सभा ने उनकी सदस्यता को समाप्त किया शाह कमीशन बैठाया गया क्योंकि एक राजनैतिक गलती हुई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जो पाँच साल किया है वह राजैनतिक गलती नहीं थी, वह इन्सानियत के खिलाफ जालिमों का जुल्म था। और बहुत घटिया जुल्म था। हर लिहाज से लूटा था समाज को और सिर्फ लूटा ही नहीं था, लोकतंत्र को जितना कमजोर किया था, लोकतंत्र की आस्थाओं को जितना कमजोर किया था उससे पूरे सदन के हर व्यक्ति को हर राजनैतिक दल को सबक मिलना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रह पायेगा। अगर राजनीति में इतने गिर के काम करेंगे कि जेल में भी लोगों की हत्याएं करा देंगे, विरोधियों को बिल्कुल नेस्तानाबूद कर देंगे। उनका नामो निशान मिटा देंगे। उनको जीने नहीं देंगे, जैसा आज सरकार चलाने वाले हैं कल उनकी पीड़ा सुनने के बाद रोगटें खड़े हो गए होंगे, लोंगों के। ऐसे चला है शासन 5 वर्ष का, ऐसी चली है सरकार कि विरोधियों को खत्म कर दो और इस काबिल ही नहीं छोड़ने कि वह आवाज कभी उठ सके। इतना तो मान्यवर, हिटलर ने भी नहीं किया था, उसने भी कुछ विरोधी छोड़ दिए थे, जो बदलाव ला सके। कम से कम हिटलर को हिटलर कहने वाले लोग तो जिंदा रहे।

बहुजन समाज पार्टी यह चाहती थी कि हिटलर को हिटलर कहने वाले लोग भी बाकी न रहें। इसलिए मान्यवर, जो पिछले पाँच वर्ष हुआ, खनन के नाम पर वह निंदनीय है और मुख्य मंत्री जी का यह आश्वासन है कि हम पूरी व्यवस्था को बदलेंगे। कुछ ऐसे पट्टे हैं जिन्हें हम समाप्त नही कर सकते, वह समय के साथ समाप्त होंगे अन्यथा आप जानते है कि अदालती संरक्षण मिल जाएगा। उसमें मजबूरी है हमारी, लेकिन पूरे सिस्टम को बदलने का आश्वासन देकर गए है मा0 मुख्य मंत्री जी। पूरे सिस्टम को बदलने का और कुछ ऐसी चीजें है जो अभी सदन में कहने की नहीं है और जिससे कम से कम किया जा सके चोरी को, खनन माफियाओं के वर्चस्व को कम से कम किया जा सके। मान्यवर, जहाँ मैंने कोशिश की है शैक्षिक संस्था बनाने की, इस सदन में आ गए है चुनकर के ऐसे लोग, जिन्हें पुलिस ले कर गयी थी, खड़े होकर रेत के ट्रक भरवाने में। कहो तो बुरा लगता है, जब ऐसे लोग कल की सरकार में शामिल रहे हों और आज भी रहे हों हमारे सिस्टम का हिस्सा, तो रोकने में दुश्वारी आएगी, परेशानी होगी, ऐसे लोग आड़े आएंगे लेकिन उसे सख्ती से रोकने की जरूरत होगी। जरूर कुछ ऐसा बदलाव होगा कि जिससे मा0 हुकुम सिंह जी को लगेगा कि हम खत्म

तो नहीं कर सके। जैसा कि मैंने कहा था कि बुराई इतनी ड्रीप रूटेड हो गई है, इतनी ज्यादा अंदर तक चली गयी है कि उसे पूरा खत्म करना इतनी जल्दी संभव नहीं होगा लेकिन उस पर रोक लगाने के जितने संभव तरीके हो सकते है और इसी के साथ राजस्व बढ़ाने के तरीके भी अख्तियार होगें और कम से कम 5,6,7 से लेकर के 8-10 गुना तक राजस्व को बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है। उससे हमारे पूरे प्रदेश का भला होगा। 20 करोड़ जनता का भला होगा। इसी आश्वासन के साथ मैं आग्रह करता हूं कि इसे पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैने मा0 हुकुम सिंह जी को सुना, मैंने मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुना।

(मा0 नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

नेता विरोधी दल-(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत ही संजीदगी के साथ सदन को गुमराह करने का काम किया है। मान्यवर, यदि पूर्ववर्ती सरकार में कहीं कोई गलती हो गई है, और आप उसे गलती मानते हो तो वह आपको गलती करने का प्रमाण-पत्र नहीं है। एक बात तो यह हो गई दूसरी बात यह है कि पूर्व में जो भी आवंटन हुआ उसका राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ तो बिना आवंटन किए पूरे समाजवादी पार्टी के लोग अपने संरक्षण में पूरे उत्तर प्रदेश में खनन का कार्य करा रहे है। अपने पास को छुपाने के लिए इस तरह का आरोप-प्रत्यारोप हम समझते हैं कि केवल सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कार्यवाही है। मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है। मा0 नेता भाजपा ने जो प्रश्न प्रस्तुत किया कि प्रदेश का राजस्व का घाटा हो रहा है, जो राजस्व मिलना चाहिए था वह नहीं प्राप्त हो रहा है। उसको प्राप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं बताया। बल्कि बी0एस0पी0 ने ये किया, बी0एस0पी0 ने ये किया और समाजवादी पार्टी के पापों को नहीं गिनाना चाहते हैं ये लोग, कितना पाप किया है आपने पूर्ववर्ती सरकार में, सारे उत्तर प्रदेश की जनता उसको सुनकर थर्रा जाएगी।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहस को आगे बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह आरोप, पहले तो मैं इसका खंडन कर दूँ कि समाजवादी पार्टी ने दो महीने में खनन के नाम पर प्रदेश को लूट लिया है उसके विधायक या कार्यकर्ता ऐसा कर रहे है, मैं इसका कड़ा खंडन करता हूँ, आपका यह आरोप गलत है। दूसरे मान्यवर, जिस तरह आपने बात को रखा अगर चीखते-चीखते आप विधान सभा की छत पर भी चले जायेंगे तो आपके वह 5 बरस, वह लूट के 5 बरस चाहे खनन के नाम पर हो या 40 हजार करोड़ के पत्थर खरीदने के नाम पर हो, इंसानों के शरीरों से खून खींचकर हाथी बनाने के नाम पर हो, लोगों को भूखा मार देने के

नाम पर हों, उन्हें आप जायज करार नहीं दे सकेगे। आपने जिस तरह मासूस बच्चियों के साथ बलात्कार करके थानों के बाहर उनकी लाशें टांग दी,

(सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस तरह हल्केपन से ओछी बात कह करके सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम समझते हैं मान्यवर, कि यह सदन का अपमान हो रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, हम माननीय नेता विरोधी दल का सम्मान करते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं। नेता सदन का इस वक्त कुछ मूड खराब है।

श्री अध्यक्ष-

नेता सदन नहीं, नेता विरोधी दल।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

होना भी चाहिये। अगर नेता प्रतिपक्ष को नेता सदन कह दिया तो कितना बुरा मान रहे है। नहीं भाई, ये तो नेता सदन के काबिल ही नहीं है। मैंने गलत कहा मैं माफी चाहता हूं और आपका समर्थन करता हूँ। कहाँ राजा भोज--, आप क्यों इतना बुरा माने अपने नेता प्रतिपक्ष के लिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सबसे वरिष्ठ होने के नाते यह मुख्य मंत्री तो बन नहीं पाये और मुख्य मंत्री न बनने की पीड़ा इनकी आज जाहिर हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

बहुत हास परिहास हो गया, अब विषय पर आइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, वहीं मैं कह रहा हूं कि चूंकि यह सबसे वरिष्ठतम नेता थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बाद। माननीय मुख्य मंत्री न बनने का इनका दर्द आज उभरकर सामने आया है। इन्होंने कहा कि हम नेता सदन लायक नहीं हैं। अरे हम तो अभी जब मौका आयेगा, तो देखा जाएगा और जिस लायक है, हम वहां बैठे है। लेकिन आप जिस लायक थे, वहाँ नहीं बैठ पाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मैं तो माननीय अध्यक्ष जी यही चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष का सम्मान रहे। अब अगर मेरे मुंह से नेता सदन निकल गया तो साथियों को उसका स्वागत करना चाहिये था लेकिन साथियों ने ही अपने नेता का स्वागत नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप गलत कर रहे हैं। आप उनकी नौकरी लेना चाहते है। आजम खाँ को मुझसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं समझता, क्योंकि 1980 में यह भी आये और 1980 माडल मैं भी हूँ। यह जानबूझकर उस बेचारे को चढ़ा रहे हैं और उनके मुँह से गलती से निकल भी गया । वक्त आने दो देखा जायेगा। मै सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वक्त आने दो देखा जायेगा, यह बात अगर दिल्ली पहुंच गयी तो इतना समझ लें मान्यवर, कि जो आप चाहते हो वह हो जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रमोद तिवारी जी, अब हमें तो नहीं कहना चाहिये वह पहले हमें कहने के बजाय अपने दामन में झांक लेते। आज प्रदीप माथुर जी को क्यों लाया गया, आखिर इन्हें अपनी ओर देखना चाहिए था क्योंकि वहाँ कांग्रेस के लोगों ने शिकायत कर दी कि यह सदन में कांग्रेस का पक्ष नहीं रखते, बल्कि सत्ता पक्ष का पक्ष ज्यादा रखते है, इसीलिए मान्यवर, इनको हटना पड़ा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, अब हो गया, अब आगे बढ़ें। आज सिंचाई का बजट है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सिंचाई ही तो हो रही है और क्या हो रहा है, सिंचाई और खिंचाई में बहुत फर्क है। मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं बहुत आभारी हूं नेता विरोधी दल का, वह मेरे दोस्त हैं, उनको मेरे दल के बारे में अपने दल से ज्यादा जानकारी है और इतना मैं स्पष्ट कर दूँ बहुत विनम्रतापूर्वक कि मैंने तो मित्रता का भाव निभाया, मैंने आपको बचाने की कोशिश की है वरना इनका इरादा बड़ा खतरनाक था और अगर इनका इरादा कामयाब हो जाता तो आप भी वहीं होते जहाँ मैं बैठा हूँ इसलिए मैंने आपको बचाने की कोशिश की है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, माननीय, हुकुम सिंह जी ने जो प्रश्न रखा है उसके लिए मैंने पहले ही कहा कि बहुत गम्भीर है लेकिन हुकुम सिंह जी ने भी जिक्र किया तो चुहिया का किया, नेता

प्रतिपक्ष ने जिक्र किया तो बिल्ली का किया तो कोई चूहे और बिल्ली की भी तो बात करे। मैं आपसे अर्ज करूं कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचने नहीं चली है, एक ऐतिहासिक सच है, एक वाकया है, जो सामने रखा है। आपको बुरा लगा उसके लिए मुझे कष्ट है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और मा0 मुख्य मंत्री जी का आश्वासन है कि बहुत ही अच्छी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैंने मा0 हुकुम सिंह जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

दूसरी सूचना श्री दीपक पटेल, मो0 आसिफ जाफरी और श्री राजेश त्रिपाठी जी की जनपद गोरखपुर के थाना कैन्ट में दिनांक 07.05.2012 को श्री राम भुआल निषाद को फर्जी मुकदमें में फँसाये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने नियम 56 के अन्तर्गत गोरखपुर की एक घटना और इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे और कभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे व्यक्ति के बारे में उठाने का अवसर दिया। मान्यवर, एक घटना घटती है 07 मई, 2012 को गोरखपुर में छात्र संघ चौराहे पर दिन के डेढ़ बजे के आस-पास चार हमलावर जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने गोलीबारी किया, एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी, एक व्यक्ति को बाँह में गोली लगी और उस घटना की एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। एफ0आई0आर0 में इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे और मंत्रि-मण्डल के भी सदस्य रहे श्री राम भुआल निषाद जी को उस घटना मे दर्शाया गया, वादी ने कहा कि हमने अपनी आँखों से देखा कि कनौजिया गाड़ी को चला रहा था और श्री राम भुआल निषाद पीछे बैठे गोली चला रहे थे। एफ0आई0आर0 दर्ज हुआ, यकीनन वादी के कथन पर पुलिस ने तहकीकात की होगी, संयोग से जहाँ पर यह घटना हुई वही पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे हुए थे, उस कैमरे को निकाला गया उसकी सी0डी0 निकाली गई, उसमें ज्ञात हुआ कि उन हमलावरों में श्री राम भुआल निषाद जी तो हैं ही नहीं, उसमें कहीं उनका चेहरा तक नहीं है। जो चेहरे थे वह कोई और थे और वादी ने एफ0आई0आर0 में लिखाया कि हमने उनको स्वयं देखा कि वह मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर गोली चला रहे थे। बाद में चार हमलावर जो सी0सी0 टी0वी0 कैमरे में आ गये थे, वह गिरफ्तार भी हुए, बाद में पता यह लगा कि 07 तारीख की घटना के बाद 14 तारीख को पुलिस ने एक दूसरा तथ्य लिया और उसमें बाकी द्वारा कहा गया कि मुझसे गलती हो गई राम भुआल निषाद साजिश में शामिल थे, पीछे बैठे व्यक्ति वह नहीं थे, मैंने बदहवासी में उनका नाम ले लिया जबकि

एफ0आई0आर0 में वादी द्वारा यह कहा गया है कि हमने चार को पहचाना दो अज्ञात थे इसलिए दो को नहीं पहचान पाये। उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से दो को नहीं पहचानने की बात की और चार को पहचानने की बात की और मान्यवर, पुलिस की तहकीकात में यह स्पष्ट हो गया कि श्री राम भुआल निषाद जी उस घटना में शामिल नहीं हैं तो फिर कहा गया कि अब उनको 120 बी में लाओ। किसी तरीके से इनको फँसाओ।

मान्यवर, राम भुआल निषाद जी इस सदन के सदस्य रहे हैं, गोरखपुर ग्रामीण विधान सभा से प्रत्याशी रहे है। विधान सभा चुनाव के दौरान एक घटना हुई थी, आपसी तनाव में एक पार्टी के प्रत्याशी से उनके समर्थकों के बीच विवाद हुआ था, उस विवाद में इस वादी का नाम भी आया था। इस वादी के बारे में ऐसी कथन है कि प्रदेश के टॉप आपराधिक गिरोह से इसका सम्बन्ध है। हो सकता है कि उस व्यक्ति की किसी और से दुश्मनी रही हो, किसी और द्वारा गोली चली हो। मेरा इसको नियम 56 में लाने का आशय सिर्फ इतना है कि स्थानीय पुलिस द्वारा एक सप्ताह के अन्दर दो अलग-अलग बातें कहीं गयीं, उनके परिवार को सन्देह है, उन्होंने प्रमुख सचिव, गृह व शासन को पत्र लिखा कि हमें सन्देह है कि हमारे साथ न्याय नहीं होगा। वह इस सदन के सदस्य रहे हैं इस नाते हम आपसे अनुरोध करना चाह रहे हैं कि इस मामले को मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, सरकार संज्ञान में लेगी। इसे एस0आई0एस0 में जाँच दे दी जाए, किसी अन्य एजेन्सी से जाँच करा ली जाए, अगर वह दोषी है तो बिल्कुल हमें कुछ नहीं कहना है। जो भी दोषी हो उसे दंडित किया जाए। लेकिन केवल राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता में किसी को फँसा दिया जाय यह ठीक नहीं है। सी0सी0टी0वी0 कैमरे में चेहरा न आने पर अब बात नहीं बन रही है तो साजिश के तहत 120 बी में ला दिया जाए, यह सम्भवतः उचित नहीं होगा। अतः मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि इस मामले की एस0आई0एस0 या किसी अन्य एजेन्सी से जाँच करा दी जाए जिससे की पीड़ित को भी न्याय मिले, वादी को भी न्याय मिले और जिस पर आरोप लगा है उसे भी न्याय मिले और सदन की गरिमा भी रह सके। हम इसमें नियम 56 के तहत बहस कराने की माँग करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, माननीय सदस्य, सदन के बहुत ही संजीदा और अच्छे सदस्यों में से एक हैं। मैं उनकी बात को बहुत गम्भीरता से ले रहा हूँ। राजनीतिक दल अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत चरित्र अपनी जगह है। मैं नहीं समझता कि मा0 विधायक ने सदन में गलतबयानी से काम लिया होगा। उनकी पीड़ा सही है। इस मामले को संसदीय कार्य मंत्री के स्तर पर, सरकार के स्तर पर तो देखा ही जायेगा। मेरा आपसे निवेदन यह है कि अगर दूसरे पक्ष की तरफ से कोई दरख्वास्त आपकी चिट्ठी के साथ मुझे मिल जाए तो मैं इसे अलग से भी इसको दिखवा लूँगा। मैं आपके इस मामले को गम्भीरता से लेता हूँ।

श्री राजेश त्रिपाठी-

संसदीय कार्य मंत्री जी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री राजेश त्रिपाठी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आता है, इसलिए इसे अग्राह्य करता हूँ। तीसरी सूचना प्रमोद तिवारी जी की, प्रदेश में नकली देशी घी की बिक्री से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक संवेदनशील विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह संवेदनशील इसलिए है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। लोगों की भावनायें भी इससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वैसे तो कई जगहों पर मिश्रित और मिलावटी मसाले हों, मिलावटी खाद्य पदार्थ हों, मिलावटी मावा हो ये चीजें तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात उभरकर आयी है जो दो छापे पड़े हैं और जिनसे उभरकर बात सामने आयी है। मैं आपका ध्यान चाहता हूँ कि देशी घी जो बाजार में दिया जा रहा है, या दूसरा घी दिया जा रहा है उसमें मान्यवर, 3 कुन्टल हड्डी से लगभग 30 कि0ग्रा0 देशी घी बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1857 की याद दिलाता है जब कारतूस में चर्बी लगी थी और उस पर लोगों की भावनायें भड़की थी। कुछ ऐसा ही सवाल इस समय है। देशी घी में चर्बी के रूप में इस्तेमाल की जा रही है और जो पकड़ी गयी, जहाँ, मैने निश्चित जगह बतायी है, हापुड़, आगरा और मेरठ। जो कन्फेशन आया है वह बहुत खतरनाक है। वह कन्फेशन यह है कि 3 कुन्टल हड्डी से 30 कि0ग्रा0 देशी घी बन रहा है। मान्यवर, सस्ता पड़ता है, बाकायदा फैक्ट्रियाँ चलती है और इनको कहा जाता है कि बाहर से आने वाला व्यापारी जब फिल्टर माल कहा जाता है तो तैयार माल समझा जाता है, जब पीला माल कहा जाता है कुछ खास जानवरों के इस्तेमाल होने का इशारा होता है।....

मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हमारे हिन्दू भाइयों के लिए और सबके लिए यह विशेष रूप से जो शुद्ध रूप से शाकाहारी है या हमारे से हिन्दू भाई है जो खासतौर से एक की हड्डी का जिक्र भी आ जाय तो गलत समझते हैं हमारे मुसलमान भाई हैं उनकी भी भावनाएं इससे जुड़ी है मैं बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ पब्लिसाइज्ड नहीं करना चाहता मैं सिर्फ आपके माध्यम से इस शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि शासन इस पर अपने स्तर से इतनी जबरदस्त कार्यवाही करे कि हड्डी से और चर्बी से जो घी बनाई जा रही है उसको रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाय मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो प्रकरण रखा है, गम्भीर है और इन्तेहा यह है कि इस तरह के कारोबार करने वाले इतने ढीठ होते हैं इतने बेशर्म और इतने बेहया होते है कि खुद रामपुर में मंत्री रहते मैंने रामलीला जहाँ लगती है हमारी उसके बराबर मार्केट है उसमें स्वयं जाकर नकली बनता हुआ घी पकड़ा। गिरफ्तार कराया, कई हजार डिब्बे नकली बरामद किए, जेल भिजवाया और मान्यवर, एक हफ्ते बाद जब मैंने दुबारा छापा मारा तो जमानत पर आ गया था और फिर वही घी बना रहा था। अब इससे ज्यादा इन लोगों के ढीठ चरित्र के बारे में नहीं कहा जा सकता है। सख्ती हुई भी है, मैने जैसा आपसे कहा था कि दूध पर हम सख्ती करेंगे, दूध की जांच करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो भैंसे बहुत कम रह गई हैं। दूध का खर्च बहुत है आखिर यह दूध कहाँ से आ रहा है, किस चीज से बन रहा है? एडल्ट्रेशन भी नहीं है वह तो कहते हैं कि मिलावट है ही नही, एक बूँद भी दूध नहीं हैं। इसलिए एडल्ट्रेशन का मुकदमा ही गलत है, बात यहाँ तक चली गई है। मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है साम्प्रदायिक के अलावा हिन्दू मुसलमानों के जज्बात के अलावा मान्यवर, यह इन्डायरेक्ट जहर है तो इस पर सख्ती हुई है, सख्ती होगी और ज्यादा सख्ती करेंगे। यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोशिश करेंगे कि इस बुराई को भी कम से कम किया जा सके खुद माननीय सदस्य ने भी यही कहा है कि सिर्फ इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, तवज्जो है तवज्जो में इजाफा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैने इस सूचना पर माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना इस पर पूरी चर्चा हो गई इसे मैं अग्राह्य करता हूँ।

चौथी सूचना श्री मलिक कमाल युसुफ की जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर स्थित श्री देवीपाटन मंदिर में वित्तीय अनियमितताओं से सरकार की राजस्व हानि के सम्बन्ध में है मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

पाँचवी सूचना श्री प्रदीप माथुर की आगरा मण्डल में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

छठी सूचना श्री राजबली जैसल, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया, श्री शाह आलम गुड्डू जमाली की जनपद उन्नाव के थाना असोहा में थाना इंचार्ज द्वारा श्री पुत्तू लाल पाण्डेय को फर्जी मुकदमें में फंसाये जाने के सम्बन्ध में इस पर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

सातवीं सूचना श्री गंगा सिंह कुशवाहा की कुशीनगर के अन्तर्गत तहसील कसया में जाति प्रमाण पत्र की मांग कर रहे सैकड़ों लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में। इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

(श्री रामचन्द्र यादव, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार खन्ना के एक साथ अपनी बात रखने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठिए सिचाई मंत्री जी का बजट आने दीजिए। आपकी सूचना पर ध्यान आकृष्ट करवा दूँगा। बैठ जाइए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना कई बार दे चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मैं उसको बहुत पढ़ता हूँ। लेकिन उससे गम्भीर मामले आ जाते हैं मैं क्या करूँ। कल आप अपनी सूचना लेकर मेरे कक्ष में आइएगा मै सारी सूचनाएं आपको पढ़ाऊंगा। अगर उससे महत्वपूर्ण नहीं होगी तो आपकी ले लेंगे। 315 पर तो अभी बैठक हुई नहीं है। विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है, मंत्रियों का विविध वक्तव्य नहीं है। कार्य स्थगन का प्रस्ताव खत्म हो गया।

बजट अनुदानों को एक साथ रखे जाने के संबंध में सुझाव

श्री अध्यक्ष-

बजट के सम्बन्ध में यह कहना है माननीय नेता सदन और विभिन्न नेतागण आज बहुत मदें है तो सिंचाई से सम्बन्धित जितनी मदें हैं वह एक साथ रख दी जाय। आज आबकारी भी है उद्योग भी है, मुद्रण लेखन सामग्री भी है जिसमें लिखा नहीं है कि विवाद नहीं होगा। खाने खनिज भी है हथकरघा उद्योग भी है।

.....तो इसमें लघु उद्योग प्रोत्साहन है तो इसको अलग किया जाये, कैसे किया जाये मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 अध्यक्ष जी, सभी एक साथ रख दें और जिन मा0 सदस्य की जिसमें रुचि हो, उस पर बोले।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन कट मोशन तो एक ही आदमी पेश करेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सिंचाई विभाग का इकट्ठा रखा दिया जाये, आबकारी का एक बार रख दिया जाये और सारे उद्योग का एक बार रख दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मेरी राय यह है कि एक आदमी को सब पर कटौती दे दीजिये। सब पर थोड़ा-थोड़ा बोल के कटौती कर दें और मा0 सभी सदस्यगण जिसको जिस विषय पर बोलना हो, बोल लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जैसे सिंचाई पर कटौती हमारे भाजपा के मा0 सदस्य करेंगे, आबकारी पर बी0एस0पी0 के करेंगे और उद्योग के सभी अनुदानों पर कांग्रेस के लोग कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, हम मा0 नेता प्रतिपक्ष की राय से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, सहमत है।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 की आय-व्यय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) एवं अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,27,29,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,76,31,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मा0 अध्यक्ष जी, नहरों के नाम से ही देश और विदेशों में आदिकाल से विभिन्न सभ्यतायें विकसित हुयी है जैसे कि सिन्धु घाटी, नील घाटी आदि। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में गंगा और जमुना की तहज़ीब से जाना जाता है। पानी की मांग, कृषि उद्योग, ऊर्जा, पेयजल के लिये बढ़ती हुयी जनसंख्या के साथ-साथ प्रतिदिन बढ़ रही है। आगे आने वाले समय में विशेषज्ञों को चिन्ता है कि पानी के प्रयोग की बढ़ती हुयी मांग को देखते हुये खेती, उद्योग, ऊर्जा, पेयजल आदि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये योजना बनायी जाये कि अधिक से अधिक पानी संचित करके उपयोग किया जा सके। विशेषकर बाढ़ का त्रासदी से बचने के

लिये बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। हमें जनाब बशीर बद्र साहब के एक मशहूर शेर से मुख़ातिब होना चाहिये जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी के लिये जल के महत्व को समझें और मिलजुल कर चिन्तन करें।

"अगर फुरसत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना,
हर इक दरिया हज़ारों सालों का अफ़साना लिखता है।"

(मेजों की थपथपाहट)

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश की 70 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है और मुझे अफ़सोस है कि हमारे प्रदेश की आमदनी 28 प्रतिशत है मान्यवर, मात्र उसका हिस्सा 28 प्रतिशत हैं। मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा बुन्देलखण्ड सूखा से ग्रसित है और पूर्वान्चल बाढ़ से ग्रसित है और यहीं तक नहीं मान्यवर, 5 साल में हमने विशेष योजना बनाकर प्रयास किया है कि समस्त असिंचित क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जाये और किसानों की टेल पर ही नहीं, टेल में और खेत में पानी पहुँचना चाहिए।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, हमने प्रयास किया है इस दिशा में। मान्यवर, 25 साल का जो इतिहास है नहरों की सिल्ट सफाई नाम मात्र के लिए होती रही है और साल भर में केवल अक्टूबर के महीने में बरसात के बात आपने देखा होगा कि केवल घांस छील दी जाती थी मान्यवर, आपको याद होगा कि अंग्रेंजों के जमाने में जब नहरें बनी थी तो उनमें एक पत्थर लगता था उसका मतलब यह था कि वहाँ तक सफाई होनी चाहिए। मान्यवर, पिछले 5 साल के समय में पूर्ववर्ती सरकार के समय में नहरें बिल्कुल बन्द हो गयी थी सफाई नहीं हुई थी। मान्यवर, हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकार अब वर्ष में नहरों की सफाई खरीफ फसल से पहले एक बार होगी।

(मेजों की थपथपाहट)

और मैंने शुरू भी करवा दिया है और हमने अपने बजट से लगभग 85 करोड़ रुपये रिलीज भी करा दिया है।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, बरसात के बाद दूसरी बार नहरों की सिल्ट सफाई अक्टूबर महीने में होगी जिससे किसानों के टेल तक ही नहीं आखिरी खेत जो है हर खेत को पानी पहुँचेगा। मान्यवर, पहले होता क्या था कि टेल तक पानी एक दो घण्टे पहुँच गया और अधिकारी वहाँ से चले आये और कह दिया कि पानी पहुँच गया है। अब ऐसा नहीं होगा यह हमने निर्णय लिया है।

(मेजों की थपथपाहट)

सफाई अभियान शुरू है मान्यवर, बरसात से पहले जितनी ड्रेनेज हैं, नाले-नालियां हैं उनकी भी सफाई करा देंगे। क्योंकि जब वर्षा आती है तब फसल को भी नुकसान होता है। उससे ठीक से बुआई नहीं हो पाती है जहाँ पानी भरा रहता है। मान्यवर, हमने निर्णय लिया है फूड सिक्योरिटी का। मान्यवर, आज प्रदेश में बहुत जरूरत है खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने की, दुनिया में इसकी बहुत जरूरत है। इसलिए हमने इस ओर विशेष ध्यान दिया है और यहीं तक नहीं हम केन्द्र सरकार के केन्द्रीय मंत्री पवन बंसल जी से भी दिल्ली जाकर मिले थे उन्होने भी आश्वासन दिया, मुझे सिंचित क्षमता भी बढ़ानी है क्योंकि अभी तक जो योजनायें चल रही थी, सरयू नहर परियोजना, बाण सागर नहर परियोजना, चौधरी चरण सिंह लहचूरा बांध, कचनौदा बांध, अर्जुन सहायक परियोजना, हरदोई शाखा प्रणाली की सिंचन क्षमता में सुधार, मध्य गंगा स्टेट परियोजना, शारदा सहायक प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना, 25 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षमता होनी थी और अभी तक केवल डेढ़ लाख ही पानी दे पाई। कहाँ 25 लाख और कहाँ डेढ़ लाख। आपको जानकारी है कि पूर्वान्चल का पूरा भविष्य सरयू परियोजना पर टिका हुआ है, शारदा सहायक पर टिका हुआ है और अभी हमने दौरा किया था अपने अधिकारियों के साथ बाण सागर परियोजना का। माननीय अध्यक्ष जी पिछली सरकार ने वह योजना केवल 300 करोड़ और वह योजना बढ़कर अब पहुँच गयी है 3100 करोड़ रुपये पर। इसके बावजूद भी मिर्जापुर और इलाहाबाद क्षेत्र में एक बूँद पानी नहीं, और अभी तक 1700 करोड़ रुपया खर्च हो गया और पुरानी सरकार ने 5 साल में उसने लगभग खर्च कर दिया है 1210 करोड़ और उससे अब तक एक बूँद पानी नहीं, उससे पानी मिर्जापुर और इलाहाबाद को मिलना था लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर के लिए, और एक बूँद पानी नहीं सीधा-सीधा मैंने उसका निर्णय लिया है कि इस योजना के द्वारा 2 साल के अन्दर अब वह योजना मुझे पूरी करनी है और 6 माह के अन्दर कुछ क्षेत्रों में हमें पानी पहुँचाना है और 2 साल के अन्दर वह पूरी योजना पूरी करनी है। इसी तरीके से सरयू नहर परियोजना, शारदा सहायक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना, बाणसागर नहर परियोजना, लहचूरा बांध का आधुनिकीकरण, कचनौदा बांध परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना के साथ अन्य निर्माणाधीन परियोजना जैसे भोपाली पम्प नहर की क्षमता वृद्धि, निचली रोहणी बांध, उटारी बांध, भौरट बांध, जमरार बांध, पहाड़ी बांध, पहुंज बांध, कनहर सिंचाई परियोजना, बदायुं सिंचाई परियोजना, राजघाट नहर परियोजना को पूर्ण किया जाना है यह सब पूरी करना है और इसके 10 नई परियोजना बहाबनी बांध, बढ़नी बांध, बैराज सागर बांध, पंचनद बांध, केन बेतवा लिंक परियोजना, सुकनई बेराज, बघेल बांध, गुरूवारा बांध, रतौली वीयर बांध, क्योलारी बांध को पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। इस बजट में यह 10 परियोजनाएं पूरी करनी है और इसके लिये मैंने प्रयास किया था। विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वाटर रिस्ट्रक्चर परियोजना का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश की लगभग 100 वर्ष से अधिक

पुरानी लोवर गंगा कैनाल के सुदृढ़ीकरण आदि का काम कराया जायेगा। राष्ट्रीय प्रोजेक्ट ए0आई0बी0पी0 प्रोजेक्ट एवं विश्व बैंक प्रोजेक्ट के माध्यम से लागू करने के बाद सरकार का यह प्रयास है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में विकास से कोई भी जिला अछूता नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे खाद्य सुरक्षा का एक कीर्तिमान स्थापित करना है। इसलिये हमको यह योजनाएं पूरी करानी है। इस समय प्रदेश में 29016 राजकीय नलकूप हैं। 245 लघु डाल नहरें, 2600 जलाशय के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी है। 3 वर्षों में 3 हजार नये नलकूपों का निर्माण करने के लिये डा0 राम मनोहर लोहिया नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 682.19 करोड़ रुपये का प्राविधान इसी बजट में किया गया है। पिछले 5 वर्षों में जो कि टयूब वेल लगाये गये थे उसमें घटिया सामग्री लगाई और वह साल दो साल में खराब पानी भी नहीं दे रहे। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में 5 हजार नलकूप खराब हैं। किसी में वोल्टेज नहीं, किसी में जो लगाने वाले थे ठीक से नहीं लगाया। घटिया किस्म के पाइप और उपकरण लगाये गये। जिसके कारण आज 5 हजार नलकूप खराब पड़े हैं और सिंचाई की कितनी परेशानी है। हमें खाद्य सिक्योरिटी का इंतजाम कराना है, कैसे करायेंगे। जो ब्लैक लिस्टेड कम्पनी थी उसी से उपकरण खरीदे गये। अच्छी कम्पनियां हैं, उनसे नहीं खरीदे गये और रेट क्या था ? जो रेट अच्छी कम्पनी देती थी वह घटिया कम्पनी से देकर वह सामान खरीदा गया इसी कारण से यह 5 हजार नलकूप खराब हुये। किसी-किसी नलकूप से तो पानी हीं नहीं निकला और ट्यूबवेल लग गया। इसकी तो जांच करायेंगे और जांच होना जरूरी है। मैंने तो इसीलिये कल कहा था कि ठेकेदारी। अगर मंत्री लोगों के परिवार के लोग ठेकेदारी करने लगे तो फिर तो सिंचाई का इंतजाम नहीं हो सकता है। हुआ है, मौर्या जी, पिछली सरकार में हुआ है, इसलिये मैं बता रहा हूं। पिछली सरकार में, इसलिये बता रहे हैं यहां तक कि इंजीनियर खुद ठेकेदारी में शामिल हो गये। इसलिये ट्यूबवेल सब खराब हो गये। पांच हजार ट्यूबवेल ठीक कराने हैं, तीन हजार नये ट्यूबवेल लगाना है जिसके लिये मैंने बताया 682.19 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है और तीन साल में यह नये ट्यूबवेल प्रतिवर्ष एक-एक हजार नलकूप लगेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाने के लिये, हम मिले थे केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री पवन बंसल जी से, उन्होंने आश्वासन दिया है, इसके लिये मैं केन्द्र सरकार के मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे 5 हजार करोड़ रुपया बहुत जल्दी बाढ़ से बचने के लिये देने को कहा है। पूर्वांचल बाढ़ से परेशान है और बुन्देलखण्ड सूखे से परेशान है। इसलिये बजट में मैंने रखा है और सिंचाई विभाग के कई अधूरे कार्यों और जो बच जाएगा अनुपूरक बजट फिर उसमें रखेंगे कई अधूरे काम बच जाते हैं और इसी के साथ हम वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगाकर के ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। जिससे हमारे ट्यूबवेल बिजली विभाग पर निर्भर न रहें।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसलिये नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगाकर ऊर्जा का उत्पादन करने की हमने पहल की है। इससे ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोत्तरी, पानी के बेहतर प्रबन्धन में सहयोग मिलेगा और प्रदेश में जल संरक्षण एवं रिचार्ज करने के लिये वृहद योजना बनानी आवश्यक है क्योंकि अधिकांश पुराने टैंक, तालाब से संबंधित केन्द्र सरकार की आर0आर0आर0 योजना के अन्तर्गत सुदृढ़ करके विभाग द्वारा प्रथम चरण में लगभग रु0 500 करोड़ की योजना केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दी है। मान्यवर, नोएडा में यमुना के दिल्ली क्षेत्र में जहां पर नोएडा विकास प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र भी नहीं है गम्भीर मामला है यह। पिछली सरकार की बदनीयती के चलते वरिष्ठ अधिकारियों ने एक तो नोएडा ऑथारिटी के अध्यक्ष दूसरे आप अध्यक्ष हैं, आप तो पूरे प्रदेश का भला चाहते हैं। आपको बहुत चिन्ता है और नोएडा के अध्यक्ष जी थे उन्होंने सिंचाई विभाग की लगभग 15 हजार से 20 हजार करोड़ की भूमि कौड़ियों के भाव नोएडा विकास प्राधिकरण को ट्रांसफर कर दी और भूमि उपयोग परिवर्तन कराकर बिल्डर को बेंच दी, बेंच दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

यह उनका प्रस्ताव था।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हम इसे मंत्रि-परिषद में ले जायेंगे। आडिट पैरा के अनुसार एक ही जमीन पर तत्कालीन अधिकारियों के इस कृत्य से 2642 करोड़ की आर्थिक क्षति इससे पहुंची है और अध्यक्ष जी, मैं इसको आपके पास भिजवा रहा हूं। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट जो है, उसकी एक प्रति मैं आपके लिये और एक प्रति आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष के लिये भिजवा रहा हूं। इसीलिये मैंने कहा कि एक आप अध्यक्ष और एक नोएडा एथारिटी के अध्यक्ष, जिन्होंने 2642 करोड़ की आर्थिक क्षति पहुंचाई है, सिंचाई विभाग को और इसे हम मंत्रि-परिषद में ले जायेंगे और सिंचाई विभाग की जमीन वापस ली जायेगी और जिन अधिकारियों ने यह किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मंत्रि-मण्डल जो भी निर्णय ले, इसमें आपराधिक मुकदमा होना चाहिये। ऐसा बहुत जगह है, माननीय अध्यक्ष जी, यही लखनऊ में सिंचाई विभाग की जो परिकल्प कालोनी थी, परिकल्प भवन जो था और उसका क्षेत्रफल था 21923.93 वर्ग मीटर और उसका ध्वस्तीकरण जिस प्रकार से हुआ, वहां पर जो सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी थे, इंजीनियर्स की कालोनी थी, बहुत से लोगों के यहां शादी थी, वह अपना सामान भी नहीं निकाल पाये। तुरन्त एक कमेटी बनती है और सुप्रीम कोर्ट में एफीडेविट भी लग जाता है कि नहीं तोड़ेंगे और 24 तारीख को कमेटी की रिपोर्ट से ले करके, सुप्रीम कोर्ट में एफीडेविट लगा है कि नहीं तोड़ेंगे, लोग अपना सामान

भी नहीं निकाल पाये और सिंचाई विभाग का रिसर्च सेन्टर, जिसकी लागत लगभग 80 करोड़ थी। हमारी पिछली सरकार ने भी उस पर 5-10 करोड़ रुपये लगाये थे। जल से लेकर, नहरों से लेकर कितनी उसमें रिसर्च होनी थी, रातोंरात उसे तोड़ दिया।

(शेम-शेम की आवाज आई)

मान्यवर, फिर उसके बाद वहीं पर 72 करोड़ की कालोनी बन रही है, रिसर्च सेन्टर बन रहा है। वैसे तो उसे तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, जब वहीं पर बनवाना था और इतना ही शौक था बनवाने का तो कहीं खाली जगह पर बना लेते, खाली जगह बहुत पड़ी थी लेकिन सिंचाई विभाग की उस पूरी कालोनी को तोड़कर, रिसर्च सेन्टर को तोड़कर पार्क बना दिया। रिसर्च सेंटर की तोड़फोड़। पार्क बना है जिसमें चार मुंह वाली मूर्ति लगी है।

राजस्व, आवास, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

10-मुंह वाला रावण और चार मुंह वाली रानी।

(हंसी)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

राष्ट्रीयकरण (तकनीकी मूल्यांकन) द्वारा आवासीय एवं अनावासीय भवनों की नेट वैल्यू 13.93 करोड़ केवल आंकी गयी है। मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार परिकल्प नगर आवासीय भवनों के ध्वस्तीकरण से हुयी शासकीय क्षति 118.47 करोड़। जिसमें भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं है और अब जो भवन बन रहे हैं वही कालोनी जो तोड़ दी हैं वह बन रहे हैं 72 करोड़ से और जमीन की कोई वैल्यू नहीं है। तब यह है। इसी तरीके से जो वहां पर बौद्ध विहार बना है उसकी कीमत का शुरू में जो आगणन था उसका हर महीने रिवाइज इस्टीमेट बनता चला जाता था। शारदा नहर, लखनऊ शाखा के किमी0 172 किमी0 175 दाहिने विकास कार्य सम्बन्धी परियोजना थी जिसकी कीमत केवल 80 करोड़ 67 लाख थी और जब यह इस्टीमेट बढ़ा तो 153 करोड़ पहुंचा। फिर तीसरी बार में फिर रिवाइज इस्टीमेट बढ़ा बौद्ध पार्क का, योजना शुरू हुयी है 80 करोड़ से फिर बढ़कर हो गयी है 193 करोड़, फिर तीसरी बार में हो गयी है 247 करोड़। फिर चौथे में हो गयी है 259, फिर पांचवें में 271 करोड़ हो गयी। फिर छठवें में 360 करोड़ 56 लाख और फिर बढ़कर हो गयी 385 करोड़ 52 लाख। फिर सातवीं बार में हो गयी 448 करोड़ 83 लाख। 80 करोड़ से बढ़कर इतने में रूकी। इतने तो लग चुके हैं और बताइये पूर्वांचल, सरयु परियोजना कब से बन रही है। कितने साल हो गये। अधूरी पड़ी है। इसी तरीके से शारदा सहायक अधूरी है। बाण सागर में 17 सौ करोड़ रुपया खर्च हो गये और पांच साल में सरकार ने 12 सौ 10 करोड़ रुपया खर्चा किया और एक बूंद पानी मिर्जापुर और इलाहाबाद को नहीं मिला।

हमने तो वहां कार्रवाई कर दी, आठ-दस लोग सस्पेण्ड भी किये जा चुके हैं और अब मैंने निर्णय लिया है दो साल के अन्दर और छः महीने के अन्दर हम पानी देंगे। तो मान्यवर, इस तरीके से लूट हुई। वैसे तो बहुत मसाला है मेरे पास, लेकिन समय कम है। माननीय अध्यक्ष जी, हम तो अभी एक दिन ओखले भी गये थे, यमुना में बहुत सिल्ट है, बिल्कुल सिल्ट सफाई नहीं हुई और 25 साल से सिल्ट नहीं निकाली गई और यमुना में जो वहां पर पानी की क्षमता है वह बहुत कम है, जहां सात दिन कम से कम लगातार पानी रहना चाहिये, आज उसकी स्थिति थी केवल दो घण्टे पानी वहां रह सकता था। बताइये पानी हमको दिल्ली को भी देना था यमुना से, हमें मथुरा को भी देना था मुझे आगरा को भी पानी देना था और केवल दो घण्टे का पानी, जो कि सात दिन का होना चाहिये था, लेकिन हर साल बजट जाता रहा, पिछले पांच सालों तक लगातार जाता रहा और कोई सिल्ट सफाई नहीं हुई, कहां जाता रहा यह धन, आखिर यह पैसा कहां गया। तभी तो मैं कहता हूं कि काला धन निकालना पड़ेगा अध्यक्ष जी, कालाधन को वापस लाना ही पड़ेगा। मान्यवर, आज पानी की बहुत जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत तो पीने के पानी की है। सबसे पहले इन्तजाम होना चाहिये था पीने के पानी का। बताओ क्या मथुरा में पीने के पानी का इन्तजाम हो गया है, और मैं पूछना चाहता हूं आगरा के लोगों से क्योंकि वहां का भी पानी खारा है, क्या आगरा में पीने के पानी का इन्तजाम हो गया है, वहां भी पीने के पानी की बहुत जरूरत थी, लेकिन मान्यवर, कहीं पर भी इसका इन्तजाम नहीं हुआ। मान्यवर, यह हमारी जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी थी कि कम से कम जो हमारे महानगर हैं वहां पर चाहे नहरों से चाहे पाइप लाइन से उन शहरों के मुहाने तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी थी, सिंचाई विभाग की थी, जो सिंचाई मंत्री रहे, उनकी थी। उसके बाद जब शहरों के मुहाने तक पानी पहुंच जाता फिर मा0 आजम साहब की जिम्मेदारी हो जाती, पानी शहर में पहुंचायें, नगर में पहुंचायें। रोज चिल्लाते रहे पानी की कमी है और खन्ना साहब तो सामली लगाते रह गये, खन्ना साहब अब पानी का इन्तजाम किया जायेगा, आपके रहने का भी इन्तजाम ठीक से करा दिया जायेगा और शेष इन्तजाम तो मा0 हुकुम सिंह जी से कहेंगे, वह भी इन्तजाम करा देंगे। तो मान्यवर, अगर देखा जाय तो आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारी नदियों में बी0ओ0डी0 है अगर देखा जाय तो उसमें मछली भी नहीं रह सकती, इन्सान अगर पानी पी ले तो उसका क्या होगा, क्या बी0ओ0डी0 है, गाजियाबाद में आज की तारीख में बी0ओ0डी0 24 है। और होनी कितनी चाहिये 3 से नीचे। बुलन्दशहर में बी0ओ0डी0 है 10 और होना चाहिये था 2.76, कानपुर में होना चाहिये था 4.33 और है 77 से भी ज्यादा है। इस तरीके से हालत खराब है एक बात याद ही होगी आप लोगों की बदायूं में एक नदी है, उसमें एक बार आदमी गिर गये तो उसमें से निकल नहीं पाये, वे आदमी मर गये पानी उनके मुंह में चला गया जिससे वे मर गये। तो इस तरीके से आज हम लोग एक तरह से जहर पी रहे हैं।

यह तो हालत है कितने नाले हैं, बड़े-बड़े शहरों में, जो नदियों में गिराये जा रहे हैं। हम एक स्कीम और लाना चाहते हैं जो गंगा की निर्मल धारा के लिये बी0ओ0डी0 के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि 3 मिलीग्राम रहना चाहिये था आज वह बी0ओ0डी0 है 25 से 30 मिलीग्राम। हमें गंगा की निर्मल धारा के लिये भी काम करना है। गंगा को हरिद्वार से लेकर के कन्नौज से लेकर के, कानपुर से लेकर के, इलाहाबाद से लेकर के पूरे बनारस तक तथा बलिया तक निर्मल करना है और जितनी भी औद्योगिक इकाईयां है और जितने भी गंदे नाले हैं और घरों को जो गंदा पानी और औद्योगिक इकाइयों का जो गंदा पानी है, उससे नदियों में जो प्रदूषण फैल रहा है, उसे समाप्त करना है। इसके साथ ही रामगंगा और काली नदी तथा गंगा की अन्य सहायक नदियों में प्रदूषण को भी रोकना है। दिल्ली में ओखला बैराज के पास यमुना नदी में बी0ओ0डी0 25 से 30 है, इसे भी सुधारना है। तो यह सब काम करना है सिंचाई विभाग को इस लिये हमने विभाग के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिये, जिनसे मिलकर मुझे यह काम करने हैं, हम आज यह बजट लेकर आयें हैं, एक शेर जो मैंने अभी पहले भी सुनाया था वह सुनाना चाहता हूं कि-

''अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना,
हर एक दरिया, हजारों साल का अफसाना लिखता है।''

इसी के साथ मैंने जो बजट प्रस्तुत किया है, आप सब लोग मिलकर उसे पास करें।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने लगभग 35 मिनट के उद्बोधन में 10 मिनट इस पर, कि आगामी क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसका जिक्र किया और लगभग 25 मिनट जो इस विभाग के पाप थे, उनको गिनवाया। मान्यवर, मेरा तो सुझाव यह है कि माननीय मंत्री जी जिस प्रकार से आपने सारी बातों का वर्णन किया है, कितने घोटालों का तो वर्णन आपने खुद किया और इसके बावजूद भी आपकी हिम्मत है कि आप अनुदान की राशि पास कराने आ गये। वरना आपका प्रस्ताव तो आज यह होना चाहिये था कि इस विभाग पर बजाय अनुदान पास करने के लगभग एक हजार करोड़ का जुर्माना किया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाये और जुर्माने की राशि मंत्री से तथा उन अधिकारियों से वसूल की जाये, जिन्होंने यह पाप किया है। चूंकि इस प्रदेश की जनता के साथ में जिन लोगों ने धोखा किया है खाली उनकी बुराई करने तथा आलोचना करने तक सीमित न रहें, उनको पता भी होना चाहिये कि उनसे ऊपर भी कुछ है। मान्यवर, अल्लाह मियां तो है ही ऊपर, यहां भी लोग बैठे हैं इस सदन की भी कुछ शक्ति है, इसका अंदाजा उन्हें होना चाहिये। वैसे तो आज सिंचाई मंत्री पूरे मूड में थे और साहित्यिक अंदाज में उन्होंने शेर पेश किया, यह इनका नया स्वरूप मुझे देखने को आज मिला। मान्यवर, इन्होंने कहा कि...

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पिछले साल भी मैंने पढ़ा था, आपको याद है।

श्री हुकुम सिंह-

आपने कहा कि जल की तहरीर को पढ़ लेना। मान्यवर, जल की तहरीर हम कहां से पढ़ेंगे। नदियों से, आप अंदाजा लगाइये कि कितनी नदियां आपकी सूख चुकी। तहरीर कहां रह गयी, दुख होता है, जब कभी किसी ने लिखा होगा तो उसके सामने स्वच्छ गंगा बहती होगी, जमुना बहती होगी, गोमती की शुद्ध धारा बहती होगी, सरयू बहती होगी और उसके मन में अंदाज आया होगा कि जल का कुछ महत्व है। लेकिन आज क्या स्थिति है जितनी उत्तर प्रदेश की सीमा है, जमुना का वहां वजूद नहीं, यह आपने खुद कहा। पूरा वजूद ही समाप्त हो गया। गंगा की हालत यह है कि जिस गंगा के बारे में चर्चा यह थी कि पानी इसका रख दें और कभी खराब नहीं होता। इसकी पवित्रता का अंदाजा इससे लगता था पवित्र गंगा मां का पानी, एक तुलना उसकी की जाती थी। आज गंगा मैया की स्थिति यह है कि उसको आप पी नहीं सकते, नहाना भी दुश्वार हो गया। गोमती नदी जो लखनऊ के पास बहती है, आज वह कूड़ादान होकर रह गयी है और हम यह तहरीर पढ़ेंगे। वह तहरीर आज इतनी खराब हो चुकी है, इतनी प्रदूषित हो चुकी कि उस तहरीर का क्या करें। लिखने वाले अगर आज जीवित रहे होते तो आज कहते कि मेरी तहरीर वापस दे दो, मेरा वह शेर वापस दे दो। मैं नदियों को देखकर क्या करूं, आज नदियों की हालत यह हो गयी है, इसको हमें समझना चाहिये। मान्यवर, मैं शुरूआत वहीं से करूंगा, जहां से माननीय सिंचाई मंत्री जी ने की थी और उन्होंने बहुत सी बातें गिनाई। अब मान्यवर, अगर अनुमति हो तो थोड़ा सा आपके कार्यकाल पर आ जाऊं। यह पुस्तक आज आपने दी है, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इसको आप पढ़ जरूर लें, छोटी पुस्तक है, इसके माध्यम से सब कार्यक्रम आपके सामने आ जायेंगे। सिंचाई विभाग, कार्य प्रगति का संक्षिप्त विवरण 2011-12। मान्यवर, इसके पेज नं0-5 पर आप देखें, टिहरी जल उपयोग की परियोजना, देवबन्द शाखा के समानान्तर पोषक नहर का निर्माण। इसमें आगे है समानान्तर देवबंद शाखा फीडर चैनल परियोजना वर्ष 2003 में टिहरी

जलाशय से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त जल जो अतिरिक्त जल था लगभग 1100 क्यूसिक, को पूर्वी यमुना नहर प्रणाली के चैंनल 89.50 किलोमीटर के नीचे की प्रणाली को पोषित करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई थी। यह परियोजना पहली बार दिनाँक 26.12.2003 को व्यय वित्त समिति द्वारा 85.027 करोड़ की स्वीकृत हुई, इसमें नाबार्ड से ऋण प्राप्त हुआ। परियोजना व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.10.2005 द्वारा 241 करोड़ रुपये की अनुमोदित हुई। शुरुआत कहाँ से हुई 85 करोड़ से और दूसरी मीटिंग में 241 करोड़ की हो गई। जानकारी आपको होगी कि यह 241 करोड़ की कैसे हो गई, किलोमीटर उतने के उतने हैं, काम उतने का उतना है और जब अधिकारियों ने पूछा कि साहब 85 का 241 करोड़ कैसे कर दें तो कहा जाता है कि यह आपका काम है टेक्निकल आदमी आप हो। पक्के काम का 85 करोड़ हो रहा है तो कहा कि मिट्टी का काम दिखा दो, क्या यह प्रदेश के साथ पाप नहीं हुआ। किसी की हिम्मत हुई कुछ रोकने की, कम से कम एक साहस तो किसी ने दिखाया होता कि 85 करोड़ के बजाय आप इस योजना को कहाँ लिये जा रहे हो। कोई काम नहीं हुआ, न कोई राजबहे का काम जुड़ा, न किसी माइनर का काम जुड़ा कोई पक्का काम नहीं और बाकी काम मिट्टी का दिखा दिया गया और यह योजना 85 करोड़ से बढ़कर 241 करोड़ रुपये की हो गई और हम शान्त बैठे रहे। मान्यवर, एक इंजीनियर था राधेश्याम नाम का, इस योजना ने उसकी जान तक ले ली, हत्या हो गई उसकी और इस कारण हत्या हुई कि जब करोड़ों-करोड़ों रुपये के हेरफेर होंगे तो माफिया राज पैदा होगा और उसने इसकी कीमत अपनी जान दे करके चुकाई। केवल एक योजना ऐसी नहीं है बल्कि अनेक ऐसी योजनाएं हैं मंत्री जी। कार्रवाई कराइये तब तो कुछ पता चलेगा, लेकिन कहाँ से होगी कार्रवाई, 2003 और 2004 में कौन था और आपको मा0 अध्यक्ष जी याद होगा कि लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ने इसी योजना की समीक्षा की थी और समीक्षा करने के उपरान्त एक रिपोर्ट दी, किन परिस्थितियों में वह रिपोर्ट नहीं आ सकी, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। यह जो राजनैतिक दबाव है, इस राजनैतिक दबाव ने शायद ही कोई काम अच्छा करके दिखाया हो बल्कि इस राजनैतिक दबाव ने ही इस भ्रष्टाचार को पनपाया है। मेरा, तेरा, मेरा होगा तो सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारा हो तो सब गलत होगा। इसी दृष्टिकोण को आज पूरा प्रदेश भुगत रहा है। आपने नहरों की सफाई की बात कही, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि मैं कार्य मजबूती से कराऊंगा लेकिन कराओगे कैसे, जो व्यवस्था नीचे जिलों में है उस व्यवस्था में आप तब्दीली कर पायेंगे क्या ? व्यवस्था यह है कि माफिया लोग ठेकेदार बन गये और उस इंजीनियर की मजबूरी है उनको ठेका देना, अगर वह उन्हें ठेका नहीं देता है तो अपनी जान से जाएगा या तबादला हो जाएगा। अब उन्होंने समझौता कर लिया कि मुझे तो जान प्यारी है, समझौता हो गया, बिल बनाकर दो और पैसे ले जाओ, सफाई हो गई। यह प्रक्रिया आज से नहीं वर्षों से चल रही है, हम नियन्त्रित कर पाये क्या, हममें नियन्त्रित करने

की इच्छाशक्ति है क्या। माननीय सदस्य इधर के भी और उधर के भी बैठे हैं, सभी के क्षेत्र का यही हाल होगा, अगली बार हम लोग मिलेंगे तो अपनी रिपोर्ट दे देंगे आपको कि कुछ तब्दीली आई है या नहीं आई है। आपने अपने भाषण में बड़े मार्मिक रूप में परिकल्प भवन की बात कही, उसे तोड़ा गया, इमारतें तोड़ी गईं, ऐसे-ऐसे अभिलेख वहाँ पर थे जो शायद अब उपलब्ध भी नहीं हो पायेंगे। मुझे भी तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के साथ में वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं भी प्रभावित हुआ था कि हाँ इस प्रदेश में बहुत बड़े-बड़े काम हो रहे हैं। जो हम सोचते थे रिसर्च की ओर कोई काम नहीं चल रहा है, मान्यवर, बहुत अच्छे-अच्छे काम वहाँ पर हो रहे थे। चलिये, जिसने किया सो किया, आपका काम तो इतना ही रहेगा कि आप जाँच करायेंगे, बस। किस बात की जाँच करायेंगे ? भवन था या नहीं, सिद्ध है, तोड़ा गया या नहीं सिद्ध है। आप वहाँ जाँच कराइये, उसके दो हिस्से हैं, एक राजनैतिक हिस्सा है, एक ब्यूरोक्रेटिक हिस्सा है। हम गलत आदेश दे सकते हैं, हम ट्रेंड नहीं हैं। कभी-कभी हम अपने अहंकार के शिकार हो जाते हैं लेकिन उस अधिकारी का भी कुछ दायित्व बनता है कि मैं गलत काम नहीं करूँगा, उसमें भी तो इतना साहस होना चाहिए कि मैं यह गलत कार्य नहीं करूँगा। जिन अधिकारियों ने यह काम करके दिखाया है, इतना घिनौना पाप इस प्रदेश के साथ जिन्होंने किया है, अभी तक तो उनमें से दस-पाँच को जेल में होना चाहिए था, जाँच की बात कहाँ रह गयी ? आप ढाई महीने से बैठे हैं। क्यों नहीं कार्यवाही करते उनके खिलाफ, कुछ तो सन्देश जाता इस प्रदेश में। काम करने की इच्छा आप में है। खाली इस विधान सभा में खड़े होकर के यह एक पक्ष कह लें और मैं दूसरा पक्ष कह लूँ, यह तो पर्याप्त नहीं है। हाँ, कुछ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए। मान्यवर, कई योजनाओं का आपने जिक्र किया, एक स्थिति है, अगर आप प्रतिवर्ष देखें, यह विभाग हो या कोई और विभाग हो। हमको लिटरेचर मिलता है, मा0 मंत्रिगण का भाषण होता है, बजट भाषण होता है। सिंचाई विभाग प्रमुख विभाग है, इसका भी जिक्र होता है। क्या इस सदन का यह दायित्व नहीं है कि जब यह अवसर मिलता है हम पिछले वर्षों के कार्य-कलापों की समीक्षा कर सकें। अगर यह दायित्व है तो फिर चिन्ता हमें होनी चाहिए कि आपने इतनी घोषणा की, उसका क्या हुआ ? हर बात की एक एक्शन टेकेन रिपोर्ट होती है। इसको जब भी आप ले करके आयें, प्रगति रिपोर्ट तो आपने दी है लेकिन कम से कम जो घोषणायें की हैं, बजट भाषण में घोषणायें की, पैसों का प्राविधान किया। 2008-09 का मैं देख रहा था, 2008-09 में 3789 करोड़ रुपये स्वीकृत किये विभिन्न परियोजनाओं के लिए, जिसमें राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण था उसमें 180 करोड़ रुपये दिये, बाढ़ नियंत्रण का काम था, 370 करोड़ रुपये उसमें भी दिये और उस समय यह वायदा किया गया था, जो वायदा आज आपने किया है। मंत्री जी कि नहरों का पानी अंतिम छोर तक जायेगा, अंतिम छोर का मतलब टेल तक। जब से हम सदन में बैठ रहे हैं, कोई भी सिंचाई मंत्री ऐसा नहीं रहा जिसने यह न कहा हो कि

टेल तक पानी पहुँचाकर रहेंगे। आज आपको इतने वर्षों के बाद भी फिर यह कहना पड़ा की टेल तक पानी पहुँचाकर रहेंगे। इसका मतलब टेल तक पानी नहीं पहुँचा। तभी तो आपको फिर यहाँ कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। हजारों, हजार करोड़ रुपये का बजट दिया जा रहा है और कह कर जा रहे हैं कि टेल तक पहुँचायेंगे, आखिर वह टेल कहाँ है ? कब तक पहुँचेगें उस टेल तक। हर वर्ष कहते रहेंगे लेकिन कभी यह समीक्षा नहीं करेंगे कि आखिर टेल तक पानी क्यों नहीं पहुँचा। ये सारी की सारी प्रणाली आंशिक रूप से मुगलकाल की प्रणाली है। उन लोगों ने बहुत अच्छी-अच्छी नहरें बनायी और उसी प्रणाली को जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने आगे बढ़ाया। मान्यवर, अगर आप उस प्रणाली को देख लें। कल्पना कीजिए गंग नहर की, जो हरिद्वार से निकलकर कहाँ तक जाती है। उस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्टूमेन्ट नहीं था जिससे हम लेबलिंग देख लें कण्टूस देख लें। एक व्यक्ति घोड़े पर चढ़कर हरिद्वार से चलता और चला जाता आखिर तक, केवल आँखों से देखता है वह और गंग नहर का निर्माण हो जाता है और आज तक उस गंग नहर में कोई फर्क नहीं आता है। क्या हम लोगों में कमी आयी कि हमने समानान्तर गंग नहर का निर्माण शुरू किया, वह आ करके रुड़की में रुक गयी और एक इंच भी नहीं चली। जो पैसा हमको विश्व बैंक से मिला उस पैसे से दफ्तर बना लिये, भवन तो बना लिये कि इन भवनों में इंजीनियर आ करके रहेंगे, लेकिन नहर की चिंता किसी ने नहीं की। क्या हमारे अन्दर वह आत्मशक्ति पैदा नहीं हो पायी कि विदेश का आदमी आ करके यहाँ पर इतने समर्पण भाव से काम कर सकता है और हम यहाँ के निवासी होने के बावजूद हमारा समर्पण यह है कि 100-100 करोड़ रुपये हमने भवनों के बनाने में बर्बाद करके रख दिये, दफ्तर के बनाने में, लेकिन सवाल उठता है कि नहर कहाँ गयी ? समानान्तर गंगा आपने कहा था कहाँ गई वह। क्यों नहीं बन पाई इस बारे में हमारी चिन्ता रही ही नहीं। न अधिकारियों में रही हम लोगों में भी फर्क आया है। 2010 और 2011 में यह वायदा किया गया था और 1296 करोड़ का प्राविधान किया गया था। लघु सिंचाई के लिए आजमगढ़ शाखा शाहगंज शाखा इसमें कहा गया है कि 4 करोड़ 60 लाख फिर अर्जुन सहायक परियोजना आई, शारदा सहायक प्रणाली आई लेकिन उपलब्धि क्या रही। 729 नए राजकीय नलकूप बनाने का लक्ष्य रखा गया आज मैं आपसे यह अपेक्षा करता था कि आप इन सब कार्यक्रमों की समीक्षा करके आएंगे आपने केवल सतही बात तो कही लेकिन आपने यह नहीं बताया कि इन काम को पूरा न होने के क्या कारण थे पैसे का प्राविधान हो गया और पैसे का ही प्राविधान नहीं हुआ हर महीने खर्चा बढ़ता ही गया और अकेले सिंचाई विभाग को यह श्रेय है जो मैंने थोड़ा अध्ययन करने का प्रयास किया है यह विभाग एक करोड़ से शुरू होता है और हजार करोड़ तक पहुँच जाता है। योजना वही रहती है। इस विभाग के बारे में मैं मंत्री जी से चाहता हूँ कि आप हम लोगों को बुला लें और बैठ लें कि आखिर इस विभाग में क्या खास बात है क्यों ऐसा होता है इसके पीछे कारण हैं। सरकार की आर्थिक

स्थिति को देखकर पहले जो प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आकर्षक हो वित्त मंत्रालय इसके ऊपर प्रतिबन्ध न लगा दे नियोजन उस पर प्रतिबन्ध न लगा दे तो बहुत सूक्ष्म धनराशि से यह शुरू करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता धनराशि आसमान को छूती जाएगी और हम लोग उसके शिकार होते जाएंगे परियोजना धरी रह जाएगी, इसलिए काम उतना लीजिए जितनी आपकी क्षमता हो पहला प्रयास यह होना चाहिए। मेरी क्षमता आज 50 करोड़ देने की है तो मैं काम 70 करोड़ का ले सकता हूँ लेकिन एक हजार करोड़ का काम अगर मैं ले लूँ तो परिणाम यह होगा कि काम समय से पूरा होगा नहीं जिससे बढ़ोत्तरी हो जाएगी फिर बजट में प्राविधान करना मुश्किल हो जाएगा और जो पैसा लगेगा वह पैसा बरबाद हो जाएगा। यह पैसा वसूल होना चाहिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है। मान्यवर, इस समय उत्तर प्रदेश इस बारे में सौभाग्यशाली है कि हमारा 90 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र में आता है और 90 में आपकी जो विशेष नदी हैं गंगा है गंडक, घाघरा, सोन, गोमती है यह नदियाँ ऐसी हैं जो कम से कम 75 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करती हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि इन नदियों में स्थिति क्या है। कितना पानी हम इनसे ले सकते हैं। क्योंकि पीने के पानी की भी समस्या है। मैं मध्य गंगा कैनाल की बात आपको बताता हूँ मध्य गंगा कैनाल एक हजार 60 करोड़ की लागत से प्रस्तावित थी बिजनौर में इसका हेड वर्क है और 2012-13 में इसके सम्पूर्ण होने की बात थी। इसकी आज क्या स्थिति है आप बताएंगे। आपने खुद कहा अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में आपने जिक्र किया 741 करोड़ की लागत और 2012-13 में इसके पूर्ण होने की बात थी। ऐसे ही वृहद और मध्यम परियोजनाएं आपकी हैं रोहिणी डैम है विराट सागर डैम है राजघाट कैनाल परियोजना है 7,738 करोड़ के आपके अनुमानित बजट की बात है। महासागर परियोजना में 2200 करोड़ अब तक लग चुके हैं। बावजूद इसके पानी नहीं मिला है। सिंचाई मंत्री जी गए समीक्षा की निश्चित रूप से इन्होंने कार्यवाही भी की 9 अभियन्ताओं को निलम्बित किया जिसमें मुख्य अभियन्ता तक शामिल हैं। क्या स्थिति हो रही थी बांदा में चित्रकूट में मिर्जापुर में, इलाहाबाद में जमकर लूट हो रही थी कि नहीं। अलीगढ़ में तैनाती है मुख्य अभियन्ता की और काम कहाँ का देख रहा है मिर्जापुर का। एक अधीक्षण अभियन्ता थे मैं नाम नहीं लेता मुख्य अभियन्ता का भी नाम नहीं लिया था। अधीक्षण अभियन्ता लेकिन न जाने कितने अभियन्ताओं का काम वही देख रहे थे। यहाँ तक चीफ इंजीनियर से लेकर बाकी सब अभियन्ता घर बैठे थे अकेले उनके पास जिम्मेदारी थी उसकी पुनरावृत्ति न हो यह बुराई न आए इसको सोचना चाहिए आपने निलम्बित किया ठीक है।

आपने कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर दिया। मान्यवर, अगर इन अधिकारियों ने इस सरकारी कोष के सैकड़ों-सैकड़ों करोड़ रुपये लूट करके अपने घर में रख लिये, आज आप उन्हें केवल कुछ दिनों के लिये वेतन से वंचित कर देंगे, 2 महीने के लिए, 6 महीने के

लिए इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जब इतनी बड़ी गड़बड़ आप के सामने आयी है तो जेल क्यों नहीं भेजा। भेजो जेल, वहीं काम है इनका, अगर भेजेंगे तो 2 महीने, ढाई महीने में हो गया न, अब आगे नहीं भेज पाओगे फिर तो शायद समझौता हो जायेगा। यह समझौता मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, मानसिकता बन जाती है, सोच बन जाती है, थोड़े दिन सत्ता में रह करके। जब आते हैं तो जोश के साथ आते हैं फिर आहिस्ता-आहिस्ता जोश कुछ ठण्डा होने लगता है तो में चाहता हूं कि जो कुछ करना हो करके दिखा दो। मान्यवर, जिनकी गड़बड़ी मिलती है, आखिर यह लूट है या नहीं है। मान्यवर, इस गरीब प्रदेश के खजाने के साथ इससे बड़ी लूट क्या होगी। कुछ संज्ञान आपने इस बात का लिया, आपने खुद कहा कि आपको केन्द्र सरकार से 5 हजार करोड़ मिलेंगे और केन्द्र सरकार के साथ में आपकी बैठक हुयी है। मान्यवर, सरजू परियोजना है, आप खुद भी कह रहे थे कि 77 करोड़ से शुरू हुयी थी आज वो 7 हजार करोड़ रुपये पहुंच गयी है। कैसे होगा काम, हम क्या उम्मीद करेंगे विभाग से। 5 अप्रैल, 2012 आपको जाना था या शायद मुख्यमंत्री जी को जाना था और यह शारदा कैनाल में देखना चाह रहे थे कि सिल्ट का काम हुआ कि नहीं हुआ। देखो कितने होशियार अधिकारी आपके हैं, इन्हें कुछ न कुछ मेडल मिलना चाहिये। जैसे ही पता लग गया कि प्रोग्राम है, उसमें पहले ही पानी भर दिया। वो देख ही नहीं पाये, 5 को जाना था, 4 को ही पानी भर दिया। जो यहां आपके सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने गुस्ताखी अगर कर सकते हों, उन अधिकारियों से आप काम ले पायेंगे क्या? इसलिये मैं कह रहा हूं। मान्यवर, हमें मा0 मंत्री जी का ध्यान दो चार बिन्दुओं की तरफ दिलाना है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, सिंचाई मंत्री जी जब इस तमाम चर्चा का उत्तर देंगे का तो उल्लेख करेंगे लेकिन जो कार्यवाही हुयी है, उसका उल्लेख भी मा0 नेता भाजपा करते तो अच्छा लगता कि इंजीनियर इन चीफ को भी बख्शा नहीं गया है और बहानेबाजी के लिये किसी जे0ई0 को या छोटे इंजीनियर को नहीं, उस जिम्मेदारी के लिये मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 सिंचाई मंत्री जी के दौरे में मै मौजूद था और वहां से लौट करके इंजीनियर इन चीफ़ को भी सस्पेण्ड करने का काम किया और जेल भी जरूर भेजेंगे।

श्री विवेक कुमार सिंह–

जो सरगना हैं उनका तो नाम ही आप लोग नहीं लेते हैं अधीक्षण अभियन्ता, इंजीनियर इन चीफ़ तक अटक जाते हैं जिसने कराया है उसको भी लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

मा0 हुकुम सिंह जी, चर्चा जारी रखिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

क्या आप पटरा–पैजामा की बात कर रहे हैं, उन तक भी जायेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ये पटरा–पैजामा कौन है ?

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज बहुत बजट है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अब ये लोग बोलने देंगे तब तो बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष–

अब ये लोग तो आप ही के लोग हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा। जैसे आपने जो टिहरी बांध का अतिरिक्त पानी था, उसका उपयोग करने के लिये आपने नहर बनायी। जिन लोगों की जमीन गयी, जहां से वह नहर बह करके जा रही है, वो तो पूर्णतया वंचित है उसके लाभ से, पता नहीं पानी कहां भेज रहे हैं उसका। आपने इसमें लिखा है कि मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर कई जिले आपने लिखें हैं, एक क्यूसेक पानी का भी इस्तेमाल इन जिलों में नहीं हो रहा है। मैं सुझाव देता हूं, अगर आप मेरी जन कल्याण की बात मानें तो। जैसे मैंने नदियों के सूखने की बात कह ही दी है। मान्यवर, आज दो नदी पड़ती हैं बीच में, एक काठा पड़ती है और एक कृष्णा पड़ती है। ये बिल्कुल सूखी हुयी हैं। कृष्णा में केवल पेपर मिलों और चीनी मिल का गन्दा पानी है। आज वहां के आस–पास के गांव वालों की जिन्दगी बिल्कुल खत्म हो गयी है कि मैं कह नहीं सकता। वहां पर कैंसर का रोग हो गया, पशु बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। हमने जो सुझाव दिया था लेकिन सुझाव तभी समझ में आयेगा, जब आप सुनेंगे पहले।

मान्यवर, पहले वालों की समझ में तो नहीं आया इसलिए आपसे कह रहा हूँ। अगर हफ्ते में एक दिन भी पानी इस नहर का कृष्णा नदी में छोड़ दिया जाये तो गन्दगी बह जायेगी। उससे लाखों किसानों का फायदा होगा, पशुओं का भला हो जायेगा और शुद्ध पानी मिल जायेगा। मान्यवर, इसी तरह से काठा नदी है वह

सूखी है लोगों ने उसमें बरमीन और धान लगा दिया है। अगर आप उस नदी को जिन्दा कर देंगे। उसमें पानी छोड़ देंगे तो वाटर लेबल ऊपर आने में सुविधा होगी और लोगों को फायदा होगा। मान्यवर, जो व्यवहारिक व्यक्ति होता है। उसी से यह बात कही जा सकती है। आप खेती से जुड़े हुए हैं। मा0 मंत्री जी इसलिए आपसे कह रहा हूँ। अधिकारियों से भी मैंने कहा लेकिन वह तो मैं जानता हूँ कि नियम कानून बताने लगते हैं और मैं चाहता हूँ कि इसमें प्रैक्टिकल दृष्टिकोण अपनाया जाये।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की जो बातें कही गयी हैं उसको केवल सामान्य रूप से न लें जिस स्तर का कोई अधिकारी है। दोषी है अगर आप छोड़ देंगे तो फिर यहीं बात आयेगी कि समझौता वादी दृष्टिकोण अपना लिया है। मान्यवर, पानी की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसमें गुणवत्ता की बात भी है। अब इन सब के बावजूद जो उपलब्ध है उसका हम कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं। यह आपके देखने की बात है। इसको आप विचार करके आगे बढ़ायें।

मान्यवर, जहाँ तक लघु सिंचाई का प्रश्न है, केवल नाली बनाने तक सीमित रह गया है यह विभाग। आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप उसमें कोशिश करें तो उपयुक्त होगा कि इन दोनों विभागों में आपस में सामन्जस्य स्थापित हो जाये। उसके बाद ही इसका कुछ अच्छा उपयोग हो पायेगा। मेरा अनुरोध है कि जो मैंने कुछ सुझाव दिये हैं। उन पर आप सकारात्मक निर्णय लेंगे और विचार करेंगे, धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मा0 सिंचाई मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि की सफलता सिंचाई पर निर्भर करती है। सिंचाई एक ऐसा महत्वपूर्ण बिन्दु है जिससे हमारे जीवन के सारे आयाम जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि जल का सदुपयोग हो और उसका सही उपयोग किया जाये। यह हमारे राष्ट्रीय महत्व का भी विषय है। मान्यवर, आज यह भी घोषणा हो चुकी है और यह भी धारणा बन चुकी है कि आगे आने वाला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। मान्यवर, एक तरफ पूरा प्रदेश बाढ़ से ग्रसित होता है। लखीमपुर से लेकर बलिया तक पूरा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त होता है और दूसरी तरफ पानी के अभाव में तरसता है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि पानी के सदुपयोग पर कहीं न कहीं ज्यादा ध्यान दिया जाये।

मान्यवर, सिंचाई विभाग के साथ–साथ, भारत की ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व से जुड़ी हुई है। गंगा नदी, वह हमारी भारतीय संस्कृति की सम्वाहक है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। आपने उसको निर्मल बनाने का प्राविधान किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मान्यवर, जैसा कि हम देखते हैं कि जल हमारे लिए वरदान है, जीवन है, लेकिन कहीं न कहीं वहीं जल पूर्वान्चल के लिए अभिशाप बनकर आ जाता है। उस अभिशाप को दूर करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी बजट प्रस्तुत किया उसमें सरयू नहर परियोजना की बात आई है। सरयू नहर परियोजना 1977–78 में शुरू की गयी थी और उसे 1988–89 में पूर्ण होना था और तब उस परियोजना की लागत 222 करोड़ रुपये थी। योजना थी कि हम 9205 कि0मी0 लम्बी नहरों का निर्माण करके पूर्वान्चल के 8 जिलों को जो लखीमपुर से शुरू होते हैं और गोरखपुर तक जाते हैं। सिंचन क्षमता की वृद्धि करेंगे। यह दुर्भाग्य है कि अब 2008 में उस परियोजना का चौथी बार मूल्यांकन किया गया वह 222 करोड़ की योजना 7270 करोड़ 36 लाख में परिवर्तित हो गयी तो कहाँ 222 करोड़ रुपया और कहाँ 7272 करोड़ रुपया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इससे लगता है कि इस बीच में जो भी रहा है। उसने इस परियोजना को गम्भीरता से नहीं लिया। पिछले समाजवादी के शासनकाल में माननीय नेता जी के निर्देश पर डुमरियागंज तक पानी पहुँचाने का कार्य किया गया था। इमामगंज शाखा को चलाया गया था और उसके बाद फिर वह काम वहीं रोक दिया गया। पिछली सरकार में नहरों का निर्माण तो मान्यवर नहीं हुआ लेकिन जहाँ नहरें बननी थी। वहाँ पुलिया बनाकर खड़ा कर दिया गया, जो आवागमन के साधन थे। किसानों के उनको रोक दिया गया तो नहरों के बीच में पुलिया खड़ी है और नहरों के बीच में कहीं कनेक्टीविटी नहीं है। यह सब इसलिए किया गया इसकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने की, माननीय नेता हुकुम सिंह जी ने की पिछले सरकार के भ्रष्टाचार की, सीधे–सीधे तत्कालीन माननीय मंत्री जी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे और पूरी तरह से उन्होंने लूटने का काम किया। 2005 में मैं भी सिंचाई विभाग में राज्य मंत्री था। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो घाघरा, सरयू और टेढ़ी तीन नदियों के बीच में बसा हुआ है। उसको बचाने के लिए एलगिन ब्रिज से लेकर चरसड़ी तक 42 कि0मी0 लम्बा बांध सकरौर से लेकर भिखारीपुर तक 18 कि0मी0 लम्बा बांध 2005 से मैंने निर्माण शुरू कराया 2006 में बनकर हमारे बांध तैयार हो गये। दोनों नये बांध थे। वे न 2007 में टूटा, न 2008 में टूटा न 2009 में टूटा और उसके बाद

जब 14 करोड़ का बांध 56 करोड़ रुपये अनुरक्षण पर लगा तब एलगिन ब्रिज चरसड़ी बांध 2010 से लगातार टूट रहा है। जब नसीमुद्दीन साहब जाते हैं तो चारों तरफ पहरा लगा दिया जाता है कि अब आम जनता नहीं जायेगी। वहीं से हेलीकाप्टर से ब्रीफकेस उनके यहाँ आते थे। 2010 में टूटा, 2011 में टूटा।

हमारे जो वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री जी हैं 2010 में सकरौर भिखारीपुर बांध टूटा था। आप स्वयं गये थे, 2011 में माननीय शिवपाल यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे, एलगिन ब्रिज चरसड़ी बांध टूटा, आप स्वयं मौके पर गये थे। भ्रष्टाचार इन दोनों बांधों में हुआ है। मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है जो तत्कालीन काम कराये गये थे। उन कामों की जांच करा करके जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ ही साथ जो माननीय मंत्री जी थे। उनके ऊपर भी एफ0आई0आर0 दर्ज करके कार्यवाही कराई जाय। पूरे क्षेत्र को मान्यवर, लूटा गया। बांध टूट जाते हैं हमारे क्षेत्र में एक गांव है। चंदापुर किठौली। सकरौर भिखारीपुर बांध टूटने के बाद उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया पूरा का पूरा गांव ही विलीन हो गया उस समय हमने सरकार से मांग की थी। अधिकारियों से मांग की थी कि यहाँ के लोगों को पुनर्वासित किया जाय। फाइले यहाँ राजस्व विभाग में आ गयी तो यहाँ प्रति बीघा मांगा जाने लगा। यह बात हमने गांव में तो बहुत सुनी थी कि 2 हजार रुपया बीघा, 4 हजार रुपया बीघा, उन बाढ़ से पीड़ित लोगों से बीघे के हिसाब से भुगतान मांगा जाने लगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सिंचाई मंत्री जी को कि अभी आप मई माह में बांध पर गये थे तो मैंने स्वयं आपके सामने रखा था। आपने तत्काल आदेश किया था। अभी 4 दिन पहले माननीय मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शासन ने वहाँ पैसा अवमुक्त कर दिया पुनर्वास के लिए वह पैसा दिया जा चुका है। एक हमारी सोच है कि महीने भर के अन्दर लोगों को पुनर्वासित करते हैं और एक वह लोग है जो 2008 और 2009 में टूटे हुए बांध के लिए आप माननीय मंत्री जी स्वयं देख करके आये हैं कि कम से कम 800 परिवार उस बांध पर जीवन जी रहे हैं। एक छप्पर के नीचे उसमें बेटा रहता है, उसी में बहू रहती है, उसी में बाप रहता है। उसी में मां रहती है, सारी पारिवारिक परम्पराएं, सारी भारतीय संस्कृति है। इससे जुड़ी हुई जो हमारी परम्पराएं हैं वह कहीं न कहीं ध्वस्त होती दिखाई पड़ेंगी। उसी एक झोपड़ी में बच्चे पैदा हो रहे हैं। रहने का साधन नहीं है, पानी का साधन नहीं है, हैंड पम्प नहीं लगे हैं। रहने लायक नहीं हैं लेकिन वे आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया है। इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि एक मिनट हमारी बात सुन लें। हर वर्ष हम सुनते हैं कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। बनबसा बैराज से पानी छोड़ दिया गया और मान्यवर, वह पानी लखीमपुर से लेकर बलिया तक को ध्वस्त करता है। मेरा आपसे एक

अनुरोध है बनबसा बैराज में 10 हजार क्यूसिक से ज्यादा पानी हम नहीं रोक सकते, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जितना पानी जरूरी है, बनबसा बैराज से जुड़ी नहरों का पानी देने के लिये तो कहीं न कहीं हम उस लेविल पर फिक्स कर दें और जो पानी नेपाल से आ रहा है। उसको रोका न जाय बल्कि उसकी निरन्तरता बनायी रखी जाय तो जो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा जाता है। यह हमको बरबाद नहीं करेगा। एक बार 3 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया तो यह पानी आता है और सारा क्षेत्र पानी में डूब जाता है। हम तीन दिन चार दिन जैसे तैसे प्रतीक्षा करते हैं तो समाचारों में आ जाता है कि आज 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप भी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपने स्वयं पानी में घुसकर देखने का काम किया है। मैं भी उस क्षेत्र में पैदा हुए किसान का बेटा हूँ मेरा आपसे अनुरोध है कि जो बनबसा बैराज में पानी रोक दिया जाता है जब वह छोड़ा जाता है तो उससे बहराइच डूबता है, गोण्डा डूबता है, लखीमपुर डूबता है और उसके आगे फैजाबाद से होकर बलिया, बस्ती तक पूरा का पूरा बाढ़ से भर जाता है। आपसे अनुरोध करेंगे इसको गम्भीरता से देखिये। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर लाल बत्ती न जलाइये शाहजहाँपुर में पानी नहीं जाता है। हम लोग डूबकर मरते हैं। दर्द है, पीड़ा है कह लेने दीजिये। आप लोग तो हमेशा कह लेते हैं, हम लोग तो कह भी नहीं पाते हैं। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यह व्यक्तिगत हम लोगों से जुड़ा प्रश्न नहीं है, पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। मैं भी इस विभाग में 4 वर्ष काम कर चुका हूँ। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो बनबसा बैराज का पानी है, उसको रोका न जाय। एक लेविल तक रोक कर उसकी निरन्तरता बनाये रखेंगे तो जो करोड़ों, अरबों रुपये की जो हमारी सम्पत्ति जाती है और बाद को उसके लिये सरकार को पैसा लगाना पड़ता है और जो दाग आता है सरकार पर कि फलां सरकार के समय में बाँध टूट गया कहीं न कहीं वह कलंक का टीका भी हमसे दूर होगा। मैं आपसे चाहूँगा कि इसको गम्भीरता से लेकर इस पर उचित कार्यवाही करने का काम करें। एल्गिन मिल से लेकर चरसड़ी का बाँध जिसके लिये आपने घोषित किया है। 14 किलोमीटर तक बढ़ाने का काम किया है।

मैं आपसे अनुरोध करूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी, मुख्य मंत्री जी और स्वयं सिंचाई मंत्री जी आपने जनता से कहा भी था और आप अपने कमिटमेंट पर रहते हैं। हम चाहेंगें कि इस बाँध का पक्काकरण किया जाय और सड़क मार्ग बनाकर एक वैकल्पिक सड़क हमारी घाघरा घाट से अयोध्या तक जोड़ने का काम करेगी। अगर यह सड़क बन जाती है तो पूरे बाँध का लाभ हमें मिलेगा और आने जाने के हमारे साधन भी बने रहेंगे। इसी तरह से सकरौर और भिखारीपुर बाँध पर, पंचवटी घाट पर एक रेगुलेटर का निर्माण कराया जाय। जब तेजी से बाढ़ आती है पूरे क्षेत्र को घेरे रहती है। पानी बढ़ता है और बीसियों गाँव डूबने लगते हैं

तो हमेशा पंचवटी घाट पर काटा जाता है। चाहे प्रशासन के लोग काटे, चाहे शासन के लोग काटे, चाहे किसान काटे हमेशा वहाँ कटिंग बनाई जाती है। उस कटिंग के लिये मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव बनकर वहाँ से आ चुका है उस पर रेगुलेटर का निर्माण कराया जाय। मान्यवर, एक योजना माननीय नेता जी के आदेश पर शुरू हुई थी। अपनी पिछली सरकार में चौधरी चरण सिंह नहर पटरी निर्माण योजना। उस समय विचार आया था माननीय नेता जी ने कहा था कि चौधरी साहब की एक सोच है कि नहरों पर भी हमको कहीं न कहीं चलने का अधिकार दिया जाय। उस योजना के तहत 7 जिलों को पायलेट जिले मानकर सड़कें बनाने का काम हमने किया था। प्रथम वर्ष 90 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था। हमारी सरकार गई और वह योजना भी चली गई। आज जो सड़कें मैनपुरी में बनी थीं, कन्नौज में बनी थीं, इटावा में बनी थीं, बागपत में बनी थीं, गोण्डा में बनी थीं, मथुरा में बनी थीं। वह सड़कें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। हम उन पर चल नहीं सकते हैं यह किसी दूसरी योजना से नहीं बनी थीं। सिंचाई विभाग ने बनवाया था। सिंचाई विभाग ने उस योजना को बन्द कर दिया मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि उस पर पुनर्विचार करके चाहे इस बजट में शामिल कर लें, चाहे अनुपूरक बजट में शामिल कर लें तो बहुत बड़ी आपकी कृपा होगी और वह सड़कें चलने लायक हो जाएंगी। रिपेयर ही करवा दें। मान्यवर, पसका घाट पर रेगुलेटर का निर्माण कराया जाए। मान्यवर हमारे गोण्डा जनपद में मनवर, बिसवही और चन्दही तीन नदियां हैं। इन नदियों का स्वरूप बिगड़ चुका है। इनमें पानी रह नहीं गया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा जैसा कि आपने कहा है कि नदियों का इन्टर कनेक्शन किया जाए। नदियों को दुबारा अपने स्वरूप में लौटाकर लाया जाएगा। आपकी कृपा की आवश्यकता है।

अभी आपने कहा कि चौधरी चरण सिंह नलकूप परियोजना में तीन हजार नलकूप लगाएंगे। नहरों पर सोलर पैनल लगा करके अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है क्यों कि मैं भी इस विभाग में रह चुका हूँ। दिल्ली के नजदीक जो सिंचाई विभाग की जमीनें हैं। मेरे समय में भी एक पी0आई0एल0 हुई थी और पी0आई0एल0 पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया था। मात्र एक रुपये के दाम पर एक बहुत बड़े संस्थान को, मैं किसी दल विशेष पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक रुपये के दाम पर विशेष वर्ग को निर्माण करने की अनुमति दी गई। उसके बाद जब बसपा की सरकार आई चाहे अक्षरधाम से मिली जमीन ले लीजिए, चाहे कहीं जमीन ले लीजिए। सारी की सारी सिंचाई विभाग की जमीन है। हमारी अरबों की जमीन है अभी आपने स्वयं अपने भाषण में कहा 2622 करोड़ रुपये की राजकीय क्षति की गई है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा आपका दृढ़ संकल्प है, आपकी विचारधारा है। आप जो कहते हैं वह

करते है, आप इसकी जाँच करा करके जमीन को मुक्त करायें और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। परिकल्प भवन की बात आपने कही कि परिकल्प भवन गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, ध्वस्त करने में 118 करोड़ की राजकीय क्षति हुई। 72 करोड़ का फिर निर्माण हो रहा है। मान्यवर, यह धन न आपका है न हमारा है यह धन जनता का है। इसके साथ जो दुरुपयोग हुआ है, इसमें हम आपसे अनुरोध करते हैं। आपकी कृपा भी चाहते हैं। इसमें आपराधिक कार्यवाही की जाए। शासकीय कार्यवाही से काम नहीं चलेगा, जब तक कुछ लोग जेल नहीं जाएंगे। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद दूँगा कि इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसी के साथ मैं चंदापुर कितौली गाँव के लोगों के पुनर्वास के लिए आपने आदेश दिया था उस आदेश का अनुपालन हो गया है। वह सात सौ परिवार जो बांध पर पड़े हुए थे, जिनको पीड़ा आपने देखी थी। एक अच्छा सन्देश देने का काम आपने किया है। सिंचाई विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। यह आप जैसे सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में गया है। आपकी क्षमता है, आप काम करना जानते हैं। आपसे अनुरोध करूँगा जैसा कि आपने भी घोषणा की थी और मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी घोषणा की थी। विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दें कि बांध कोई नहीं कटेगा। पूरे प्रदेश में बाढ़ को नियंत्रित करने का काम करें। आपके पास अच्छे अधिकारियों की टीम है। उनको लगाकर मेहनत से काम किया जाए और काम करके इस प्रदेश की जनता को बाढ़ से मुक्ति दिलाई जाए। सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। मेरा आपसे अनुरोध है। अन्त में बजट के समर्थन पर बल देते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ जयहिन्द।

*श्री सुल्तान बेग–

माननीय अध्यक्ष जी, वरिष्ठ सदस्य श्री हुकुम सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, ज्यादा लम्बी–चौड़ी बात मुझे नहीं करनी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सिंचाई विभाग की बजट पत्रिका हमारे सामने भी है, इसमें बरेली में भी एक सिस्टम है, रूहेलखण्ड नहर खण्ड सिस्टम बरेली, इस पूरी पत्रिका में इसका कहीं जिक्र नहीं है और यह रूहेलखण्ड नहर खण्ड सिस्टम बरेली जिससे विधान सभा बहेड़ी, विधान सभा भोजीपुरा और विधान सभा 119–मीरगंज है। इन तीनों विधान सभा क्षेत्र की पूरी सिंचाई इसी सिस्टम के द्वारा होती है। मान्यवर, यह सिस्टम ब्रिटिश दौर में बनाया गया और तब से लेकर लगातार पिछले 15 साल तक इस नहर के द्वारा लाखों–लाख किसानों को पानी मिलता रहा। लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब इस नहर की स्थिति यह है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इसकी जितने क्यूसेक पानी लेने की कैपेसिटी थी, लगभग 19 हजार क्यूसेक पानी इस नहर कैनाल के माध्यम से जो हमारे रजबहा है या हमारी माइनर्स हैं, वहाँ से लेकर उनको पानी देने का काम किया जाता था। आज यह नहर पूरी तरह से पट गयी है। इसकी जो क्षमता है वह 19 हजार क्यूसेक से घटकर उसकी 1/4 भी नहीं रह गयी है और इसका नतीजा यह होता है कि जब मेन कैनाल में पानी छूटता है, वह नहर के आखिर छोर तक नहीं पहुँच पाता। इसमें एक दर्जन से ज्यादा रजबहा हैं, इसमें माइनर्स हैं, जिनमें पानी जाना होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जैसी सरकार की इच्छा है, सरकार चाहती है कि हम टेल तक पानी पहुँचायें, जब मेन नहर में पानी लेने की क्षमता ही नहीं रहेगी तो टेल तक पानी कैसे पहुँचेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि रूहेलखण्ड नहर खण्ड सिस्टम बरेली जो है, इसकी पुनः स्थापना करा ली जाए और पुनः स्थापना होने के बाद जिस सूरत में यह नहर थी, उसी सूरत में अगर इसकी स्थापना हो जायेगी तो मैं समझता हूँ कि टेल तक पानी पहुँच सकता है। इसके लिए मैंने शासन से भी माँग की थी, इसमें जो अधिकारी थे, उनको भी मैंने लिखा था, लेकिन अब तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे अफसोस के साथ इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो पत्रिका दी गई है। इसमें इस नहर सिस्टम का कहीं जिक्र नहीं है, जबकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंचाई प्रणाली है, इसके जरिए से लाखों–लाख किसानों को सिंचाई का पानी मिल सकता है। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि इसको गम्भीरता से लें और रूहेलखण्ड नहर सिस्टम की पुनः स्थापना करने हेतु इसमें जरूर कुछ न कुछ बजट का इन्तजाम करे, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ। साथ ही मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की जो मुख्य परेशानी है, समस्या है, वह आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूँगा। हमारा विधान सभा क्षेत्र लगभग 7–8 नदियों से घिरा है। वहाँ पर कई बड़े गांव हैं, जिनकी आबादी 5 हजार से ऊपर की है। एक डिमुना गाँव पड़ता है, मोहम्मदगंज, पहुँचा बुजुर्ग गाँव पड़ता है और उसके अलावा हरदोई और श्यामपुर ये पूरे के पूरे गाँव पूरी तरह से नदियों के कटान की चपेट में आ चुके हैं और इससे हजारों एकड़ जमीन पिछली वाली कटान से खत्म हो चुकी है, जमीन नदियों में समा चुकी है लेकिन अभी तक उस कटान को रोकने का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा कि डिमुना गाँव का जिसका पीलाखार नदी द्वारा कटान किया जा रहा है, पहुँचा बुजुर्ग जिसका पीलाखार नदी द्वारा कटान किया जा रहा है और मोहम्मदगंज, श्यामपुर और हरदोई जो रामगंगा द्वारा

इसका जबरदस्त कटान हो रहा है और एक गाँव जौनर है, उसका भी पीलाखार नदी द्वारा कटान किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा कि उस कटान को रोकने के लिए पिचिंग या पत्थरों की टोकर वगैरह कुछ लगा दी जायें ताकि वहाँ कृषि योग्य जमीन जो बेतहाशा कटान के जरिए से बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है और लाखों–लाख रुपये की हानि वहाँ के किसानों को हो रही है, उस आर्थिक हानि से उनको बचाया जा सके, उनके जानमाल की हिफाजत हो सके। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर मुझे आपने अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने लखीमपुर जनपद की निघासन तहसील जो बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, उसका संज्ञान लेते हुए, अपना पहला सरकारी दौरा हमारी विधान सभा का ही किया था लेकिन अभी तक बाढ़ को रोकने के सम्बन्ध में उससे उत्पन्न स्थितियाँ जो आ सकती हैं, उसके विषय में अभी कोई कारगर कदम नहीं उठाये गए हैं। मेरी विधान सभा बाढ़ प्रभावित है और पिछले चार वर्षों से हजारों एकड़ फसल और मकान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं पर शारदा नदी, करनाली नदी, मुहाना और सरयु के द्वारा हजारों एकड़ कृषि भूमि का कटान भी हुआ है। नदियों में सिल्ट जमा है। तटबंध नहीं है। जगह–जगह पर नदी की धारा तोड़कर बस्तियों में चली जाती है। जिससे 5 से अधिक गाँवों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। 827 परिवार इस समय सड़क पर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। मैंने अनुरोध किया था। अभी हमारी जिलास्तर पर एक बैठक हुई थी उसमें भी हमने एक बात रखी थी कि हमारे यहाँ जो इंदिरा आवास योजना है। वह अभी पूरी तरीके से सेचुरेटेड नहीं हुई है और जो सड़क पर लोग गुजर–बसर कर रहे हैं। वह वास्तव में बी0पी0एल0 श्रेणी में ही आते हैं। इसलिए इंदिरा आवास के द्वारा ही उन 827 परिवारों को कम से कम आवास उपलब्ध कराने का काम माननीय मंत्री जी के द्वारा कर दिया जाये तो मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा। नदियों में सिल्ट की सफाई करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सिल्ट की सफाई न होने के कारण ग्राम सूरत नगर व गंगा नगर में कटान बहुत तेजी से हो रहा है और सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि के साथ-साथ जंगल के भी बहुत सारे पेड़ उसमें बह चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि

वहीं ग्राम मजरापूरब, खैरीगढ़, खमरिया के रास्ते में भी बालू जमा हो गयी है। उसमें थोड़ा सा ही काम करना है।

मैंने जिलाधिकारी को और माननीय मंत्री जी को प्रश्न भी पूछा था। उसमें मैंने अनुरोध किया था कि अगर क्षेत्र विकास निधि के द्वारा यह काम हो सके तो हम लोग उस बालू को हटवाने का काम करा दें। उसमें थोड़ा सा ही काम है, अगर वह हो जाये या बजट में उसको शामिल कर लिया जाये तो बड़ा नुकसान हमारे विधान सभा क्षेत्र का बच सकता है। उसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारा विधान सभा क्षेत्र पूरी तरीके से बाढ़ से ग्रस्त है। इन्हीं समस्याओं में बल्लीपुर से खमरिया, बैलहा, सिरसी, महादेवा तक का पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है। वहाँ के लोग आन्दोलित हैं। मैने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया था कोई हल न निकलने पर मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जीसे भी प्रश्न किया था। उनका जो उत्तर आया है उसमें ग्राम खमरिया के सामने स्टड निर्माण हेतु दो करोड़ 33 लाख रुपये की परियोजना सहित मुहाना आदि नदियों हेतु बनायी परियोजना पर भी काम करने की बात कही गयी है।

मैं माननीय मंत्री जी को यह संज्ञान में लाना चाहता हूँ अभी ग्राम खमरिया में स्टड बनाने और मुहाना नदी में जो कटान हो रहा है उस परियोजना पर भी अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि इसका संज्ञान लेकर अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें। जिससे यह काम अतिशीघ्र शुरू हो सके क्योंकि जुलाई के बाद बाढ़ आ जाती है। अभी जैसा माननीय सदस्य ने बनबसा बाँध का जिक्र किया था। बनबसा बांध में जो पानी छोड़ा जाता है उसका पहला हमला लखीमपुर जिले में ही होता है और जब अनियंतित्र 3-4 लाख क्यूसेक पानी आता है तो एकदम से पूरे क्षेत्र में फैल जाता है और 4-5 दिन तक जीवन-यापन दूभर हो जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सुहेली, शारदा, करनाली और सरयू नदी की जो बाढ़ आती है उस बाढ़ से कैसे हम लोग बच सकें इसके लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि इस बजट में इस योजना को शामिल करके और जो परियोजना उन्होने बनायी है उसके लिए धन अवमुक्त करने की कृपा करें जिससे अतिशीघ्र काम शुरू हो सके। मान्यवर मैने सुहेली नदी के बारें भी प्रश्न पूछा था। उन्होंने उसके उत्तर में शारदा और सुहेली नदी की बाढ़ से पलिया क्षेत्र को बचाने हेतु जीएफसीसी की विचाराधीन योजना का जिक्र किया था। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यह जो सुहेली और सरयू नदी का मामला था यह मैने पलिया क्षेत्र के लिए नही बल्कि निघासन विधान सभा क्षेत्र में जिसका भारी प्रकोप होता है उसके लिए किया था । मै उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह जीएफसीसी योजना जिससें रिंग बांध बनाने की योजना है उसमें निघासन विधान सभा क्षेत्र को भी शामिल करने की कृपा करें। इस बजट में एक ऐसे बाढ़

प्रभावित क्षेत्र जिसको वास्तव में बहुत धन की आवश्यकता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। जहाँ पर सिल्ट की सफाई, तटबंध बनाना, स्टड बनाना, रिंग बांध का निर्माण करना ऐसे सारे काम होने हैं। लेकिन मैंने वह देखा है कि मेरी बगल की एक पलिया विधान सभा है वहां पर भी काम हुआ है, धहरौरा में भी हुआ है, निघासन क्षेत्र में एक भी काम शुरू नहीं हुआ है। मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह बड़ा संवेदनशील विषय है, इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ मैं अपना यह भी अनुरोध करते हुए इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

माननीय अधिष्ठाता जी, मा0 सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, आपने उसके समर्थ में बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मै आपके प्रति शुक्रगुजार हूँ। मान्यवर, मै बहुत ध्यान से मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को सुन रहा था और तीन दिन से लोक निर्माण, ऊर्जा और सिंचाई विभाग का बजट बड़े ध्यान से मैने सुना तो मेरी अब समझ में आया कि जो गाना चुनाव मे बज रहा था, ''तू तेरी सरकार लुटेरी'' चरितार्थ हो गयी, क्योंकि 86-86 करोड़ के बंगले और अभी मंत्री जी ने बताया परिकल्प भवन जो शारदा नहर पर रिसर्च सेण्टर था नहर विभाग का और परिकल्प नगर जिसे बसपा के महा सचिव सतीश मिश्रा ने सुबह हाईकोर्ट में दस बजे एफीडेविड दिया और शाम को वह परिकल्प भवन और परिकल्प नगर दोनों जमीदांज हो गये। इसी तरह लखनऊ जेल जो आदर्श जेल थी और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1930 में इस जेल पं0 जवाहर लाल नेहरू, पं0 गोविन्द बल्लभ पंत बंद रहें, आजादी की दूसरी लड़ाई में हम तमाम लोग, जयप्रकाश जी, मोरार जी भाई देसाई, श्री राजनारायण जी, चौधरी चरण सिंह और हमारे मा0 नेता मुलायम सिंह जी कैद रहे आजादी की दूसरी लडाई में हम लोग बन्द रहे लखनऊ जेल में इस जेल को दस बजे न तोडे जाने का हलफनामा और और शाम को जेल जमीदोज हो गई। मान्यवर, यह जो नहर है इस नहर पर इतने अच्छे-अच्छे डाक बंगले है जिसमें नरोना डाक बंगला, एक रोड निकलता है मोहान से जो कन्नौज की तरफ जाता है, उस पर पुल कम चौड़ा है मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी से अनुरोघ करूगाँ कि उस पुल का चौड़ीकरण करा दें क्योंकि वह सिंचाई विभाग के अन्तर्गत आता है और डाक बंगले का भी सुदृढ़ीकरण करायें उसकी पैमाइस करा दें, काफी जमीन है डाक बंगले में । हमारे यहाँ सरोजनी नगर में अमौसी रजबहा के किनारे एक डाक बंगला है जिसमें भी काफी जमीन है अगर उसको मा0 मंत्री जी ठीक करा दें तो उसके लिए भी मै उनको धन्यवाद ज्ञापित करूँगा।

मान्यवर, दस पन्द्रह साल से अमौसी रजबहा, प्यारेपुर माइनर, ऐन माइनर और उसकी जो माइनरें है, उनकी सफाई नहीं हुई है। बहुत बड़े-बड़े पेड़ शीशम आदि के उस पर खड़े हुए हैं, पानी जा नहीं रहा है, मा0 मंत्री जी की जो आकांक्षा है टेल तक पानी पहुँचाने की, अमौसी रजबहा सई नदी में गिरती है, करीब 35 किमी0 की दूरी तक यह पानी ले जाती है, परन्तु पानी कही नही जाता। मान्यवर, मैं तो यह कहूँगा कि इसकी सफाई नहीं हुई और उसका पेमेण्ट हो गया ठेकेदारों को, इसकी जाँच मा0 मंत्री जी करा लें, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ हमारे यहां सई नदी निकलती है जो हरदोई से निकल कर उन्नाव होकर और लखनऊ होकर प्रतापगढ़ चली जाती है उसके किनारे एक गांव है तेरूवा जहां पर नदी का कहर बरपा होता हैअगर उस पर मा0 मंत्री जी बांध बना दें कम से कम एक किमी0 का बांध बनेगा तो वहां जो हर बार बाढ़ में ग्रसित होता है वह बच सकेगा। मान्यवर इसी सड़क पर शारदा नहर पर पकरी का पुल था जिसे अगेंजों ने आज से 86 वर्ष पूर्व बनाया था, परिकल्प नगर, परिकल्प भवन को तो तोड़ा ही पकरी गांव दो भागों में विभक्त है एक तरफ पकरी खेड़ा और दूसरी तरफ पकरी गांव। अंगेजों ने उस गांव की सुविधा के लिए उस पकरी के पुल को बनाने का काम किया था, परन्तु पिछली पूर्व सरकार ने जहाँ चारों तरफ मूर्तियां लगा रखी हैं ''जिधर जाइएगा हमे देखियेगा'' वाला नारा चरित्रार्थ करने का काम किया है।.....

जिधर जाइएगा उधर मुझे पाइएगा। वहाँ पर मायावती जी की चारों तरफ से मूर्तियाँ हैं, बुद्ध जी की चारों तरफ से मूर्तियाँ हैं। कांशीराम जी की चारों तरफ से मूर्तियाँ हैं। मान्यवर, उसी जगह पर पकरी का पुल है। आशियाना और गीतापल्ली आलमबाग इनका रास्ता काट दिया गया, पकरी का पुल तोड़ दिया गया। आज दोनों क्षेत्र कैंट विधान सभा क्षेत्र और सरोजनी नगर विधान सभा की जनता आज आंदोलित है और वह चाहती है कि यह पुल पुनः जोड़ दिया जाए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैंने यह मांग की है कि जो यह पार्क है उसमें गर्ल्स यूनिवर्सिटी बना दी जाए और जहाँ पर मायावती जी का मकबरा बना हुआ है उसमें बच्चों के खेल का मैदान बना दिया जाए और जहाँ पर बुद्ध विहार बना हुआ है, चारों तरफ देखती हुई मूर्तियाँ बनी है, वहाँ पर गर्ल्स हास्टल बना दिया जाए। पकरी का पुल अपने आप खुल जाएगा जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र व कैंट क्षेत्र भी है क्योंकि कैंट से भी मुझे विगत में दो बार समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। इसी कारण मान्यवर, दोनों क्षेत्रों की जनता मुझसे सवाल करती है कि जब आज आप उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पहुँच चुके है तो यह पुल क्यों नहीं खुल रहा है। मान्यवर, अगर मैं विपक्ष में होता तो शायद आज मैं इस दिवार को तुड़वा दिया होता है। चाहे जो कुछ होता , जिस तरह लोकबन्धु राज नारायण चिकित्सालय मायावती जी ने बंद कर रखा था, जो तीन साल बंद रहा। जब लोकबन्धु राज नारायण जी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने 25 नवम्बर,

2010 को धरना दिया तो वह अस्पताल अपने आप खुल गया। 30 दिसम्बर को वह अस्पताल अपने आप खुल गया और जिसे 300 बेड के स्थान पर 100 बेड का रखा गया। मान्यवर, आज यह स्थिति है कि हमारे क्षेत्र में किला मोहम्मदी ड्रेन जो बहती है, किला मोहम्मदी नगर ड्रेन जो आजादनगर का पानी लेकर के सई नदी मे गिराती है, उस ड्रेन को उन्होंने बंद कर दिया। दूसरी तरफ डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय बनाने पर जो गाजीउद्दीन हैदर ने मुगल शासन में गोमती को गंगा से मिलाने के लिए एक गाजीउद्दीन हैदर कैनाल बनायी थी इस विश्वविद्यालय को बनाने पर पूर्व सरकार ने हैदर कैनाल के एक पुल को, जो शारदा नहर के नीचे से निकलता था, उसे बंद करा दिया, जिससे वहाँ पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। मा0 अधिष्ठाता जी मैं चाहता हूँ कि पकरी का पुल और हैदर कैनाल पर बना हुआ पुल, इन दोनों पुलों का खुलवाने की व्यवस्था मा0 सिंचाई मत्री जी कर दें, ऐसी मेरी इच्छा है और अभिलाषा है क्योंकि जनता इससे आंदोलित है क्योंकि कहीं ऐसी स्थिति न बन जाए कि अपने आप कोई हादसा बन जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप सरकार का आदेशित करें। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि नहर की पटरियो को पक्का करा दिया जाए। जहाँ पर पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दकी ने नरौना पुल तक सड़क बनाई है। चार लेन की इस सड़क को अगर हरदोई तक जोड़ दिया जाए तो वहाँ के लोगों को सड़क का सुलभ साधन मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री तेजपाल सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय कटौती प्रस्ताव से अपने आप से सम्बद्ध करते हुए कुछ सुझाव सरकार को देना चाह रहा हूँ। आपके माध्यम से, मा0 मंत्री जी चले गए है मैं चाह रहा था कि कुछ अच्छी-अच्छी बातें थी वह सुनते तो बहुत अच्छा रहता लेकिन फिर भी।

श्री अधिष्ठाता-

चलिए कार्यवाही में आ जायेगा। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के स्थान पर शाह साहब बैठे हैं।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है और इस महत्वपूर्ण विभाग में क्योंकि यह जो सिंचाई का पानी है यह किसान की जान है और मान्यवर, किसान एक-एक पेड़ को जिस तरह से सींचता है यदि उसके लिए अगर सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो किसान मजबूर होकर के अपनी सूखी हुई फसल को देखता है और किनारे खड़े होकर रोता है। मान्यवर, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा मा0 मंत्री जी का बजट हमने पढ़ा है, देखा है,अच्छा है, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि हम टेल तक पानी पहुँचाने की नहीं हम अन्तिम खेत तक पानी पहुँचाने की बात करेंगे लेकिन मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है

और मैं सुझाव भी देना चाहूँगा मा0 मंत्री जी को कि टेल तक पानी पहुँचाने के बाद आप लास्ट खेत तक पानी तो पहुँचाएंगे लेकिन सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि कभी-कभी मान्यवर, जब अधिकारियों ने यह कोशिश की है कि टेल तक पानी पहुँच जाए तो टेल के आगे टेल गुल की कोई व्यवस्था सरकार की नहीं है और टेल गुल न होने से समस्या यह आती है कि खड़ी फसल में पानी बहता है। खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह चाहूँगा कि जहाँ उनकी ऐसी मंशा है, ऐसी मंशा है, ऐसी इच्छा है कि हम खेतों तक पानी ले जायेंगं और टेल से भी आगे ले जायेंगे तो टेल-गूलों की व्यवस्था उससे पहले करा दें, यह बहुत आवश्यक है। इसके अलावा एक बात और माननीय मंत्री जी ने कही है खुदाई के संबंध में नहरों की सफाई के संबंध में, यह बात उन्होंने कही कि हम खरीफ में खुदाई भी करायेगें और रबी में भी खुदाई करायेगें। बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिये। खरीफ में नहीं करायेंगे तो जहाँ धान की फसल होती है, वहाँ धान की फसल नहीं बोई जायेगी और यदि रबी में अक्टूबर-नवम्बर में अगर समय से नहीं करायेगें तो रबी की फसल नहीं बोई जायेगी। मान्यवर, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि उन्होंने जो एक बात कही ओखला बांध की।

मान्यवर, आगरा कैनाल इसी से निकलती है, इसी से आगरा और मथुरा जिले की सिंचाई होती है। आगरा कैनाल के संबंध में पूरे बजट में किसी तरह का कोई जिक्र आया नहीं है कि आगरा कैनाल भी कोई है और उसका भी कहीं कोई काम होता है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ओखला बांध की खुदाई चल रही है, उस पर टीले बन गये थे,यह बात सही है और डैम में पानी भरने की व्यवस्था भी कम हो गयी और उसमें इन्होंने खुदाई कराई और 15 जून तक का आखिरी समय बताया गया कि इसके बाद उसमें पानी आ जायेगा। तो मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मैं यह भी चाहूँगा कि 15 जून का जो दिया हुआ समय है उसके बाद यदि आगरा कैनाल में पानी नहीं दिया गया तो मथुरा और आगरा जनपदों में धान की जो पौध लगाई जा रही है, वह पौध नहीं लग पायेगी और धान की रोपाई नहीं हो पायेगी। मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री जी चले गये लेकिन संबंधित अधिकारी कुछ यहाँ जरूर बैठे होंगे। अच्छा आप राज्य मंत्री जी बैठे है, आप सुन रहे है। माननीय मंत्री जी मैं यह कहना चाहूँगा कि आपकी आगरा कैनाल हरियाणा से निकलती है उसके बाद मथुरा और मथुरा से आगरा। जो आगरा कैनाल है, उसके हेड पर हमसे पहले जो हरियाणा वाले बैठे हैं, वह पूरे पानी की चोरी करते है और जहाँ तक मुझे जानकारी है, उन पर संभवतः आपका राजस्व का 13 करोड़ से ऊपर का बकाया है और आपने वह पैसा वसूल करने की कोई कार्यवाही नहीं की। उसमें मैं आपको यह और बताना चाहूँगा कि यह जो हरियाणा का हिस्सा हमसे पहले पड़ जाता है, क्योंकि नहरों के कुलाबे अब नहीं रहे, तो हरियाणा में जमीन के नीचे अंडर पाइप डालकर

कर के हरियाणा वाले पानी की पूरी तरह से चोरी कर रहे है। हरियाणा के लोग जब पानी की चोरी कर रहे है। तो वह पानी हमारे आगरा और मथुरा तक पहुँच ही नहीं पा रहा। तो इसमें सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि जो लोग जमीन के अंदर पाइप डाल करके पानी की चोरी कर रहे हैं, चाहे वह हरियाणा में हो रही है या हमारे प्रदेश मे हैड पर हो रही है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करे और उन पाइपों को तुरन्त उखड़वाया जाये जिससे सभी लोगों को आगे पानी मिल सके। साथ ही हरियाणा पर जो टैक्स बकाया है, वह वसूली भी करायी जाये । तो इसमें सबसे ज्यादा महत्तवपूर्ण बात हम यह कहना चाहेगें कि इन्होंने कह दिया कि हम खुदाई सफाई करायेंगे, लेकिन मेरा अनुभव है इस बात का, और सभी विधायक इस बात को जानते होंगे कि जहां सड़क किसी नहर के या बम्बे के पुल को क्रास कर रहीं है तो उसके आजू-बाजू बहुत अच्छी सफाई हो जाती ताकि यहाँ आते-जाते आदमी को दिखाई दे कि यह सफाई बहुत अच्छी है लेकिन उसके अगर दो-चार किमी0 आप अन्दर जायेंगे तो आपको सफाई नाम की भी नहीं मिलेगी।

यह मेरे अनुभव की बात है क्योंकि मै भी इस विभाग का राज्य मंत्री रहा हूँ उस समय मैने खुद दौरा किया और अधिकारियों ने गुमराह करने की कोशिश की और उन्होंने दिखाया कि पूरी सफाई हो गयी है जब मैं गाडी छोड़कर आगे तीन किमी0 तक पैदल गया तो आगे देखा कुछ नहीं था। केवल डेढ़ किमी0 तक उन्होंने खुदाई की और उसके बाद आगे कुछ नहीं किया और अधिकारी बार-बार यह कोशिश कर रहे थे कि मैं वहाँ तक नहीं जाऊँ।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, मैं एक मिनट और लूँगा। मेरा अनुरोध आपसे यह है कि यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसमें जैसे एक पिछली बार योजना बनी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। चौधरी चरण सिंह सिंचाई विकास योजना हमारे समय में बनी। अभी जैसे माननीय शुक्ला जी ने एक बात कही, नहर की पटरियों को पक्का कराने का, हम तो अपने समय में एक योजना लेकर आये थे चौधरी चरण सिंह सिंचाई विकास योजना, उस योजना के माध्यम से हमने नहर की पटरियों और बन्धों पक्का कराने का काम किया था। उस योजना का कहीं बजट में जिक्र नहीं किया गया है, इस योजना का जिक्र न करने से ऐसा लगाता है कि कहीं सरकार उस योजना को भूल तो नहीं गई है, सरकार उसको करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि जो जनहित के काम हैं उनको हम पूरा करें। मैं सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि सिंचाई विकास योजना जो बन्द कर दी गई है उसे पुनः लागू किया जाए यह बहुत जरूरी है। आगरा कैनाल के बारे में जो मैने बताया आज

उसकी व्यवस्था बिगड़ गई है, उसको पूरा किया जाए, हरियाणा से जितना बकाया है उसको वसूल किया जाए। माननीय मंत्री जी ने एक बात और कहना चाहूँगा नालों के सम्बन्ध में, ठीक है कि आपने पैसा दे दिया है लेकिन मान्यवर, बरसात आने वाली है अगर बरसात के पहले नालों की सफाई नहीं हो पाई तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी सिंचाई की व्यवस्था या नालों की खुदाई की व्यवस्था उन्हें करनी है उसे बरसात से पहले करने का काम करें। एक बात और कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि नलकूप के नाम पर, मथुरा जनपद में मुझे बहुत अफसोस हुआ, इंजीनियर जो बात कह देते हैं उसको ये सही मान लेते हैं। मान्यवर, दो नलकूप लगे थे सैफऊ ब्लाक में और सैफऊ ब्लॉक चला गया हाथरस जिले में। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा कि जितने नलकूप है उनको चालू रखने की सुचारू रूप से व्यवस्था बनाई जाए जिससे किसानों को पानी मिल सके और वह सिंचाई कर सके।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, एक अनुरोध मैं और आपसे करना चाहूँगा आज कल यमुना में पानी नहीं है यमुना में पानी न होने की वजह से पानी नहीं मिलता। हमने गंगा से पाँच हजार क्यूसेक पानी हिण्डन नदी में डलवाने की व्यवस्था की थी, लेकिन उसे बन्द कर दिया गया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उसे फिर से डलवाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते अपनी बात समाप्त करता हूँ धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी ने बोलने के लिए समय की सीमा निर्धारित की है, इसके बाद उद्योग विभाग और आबाकारी विभाग का भी बजट है इसलिए सभी माननीय सदस्यों से मैं चाहूँगा कि समय-सीमा में ही अपनी बात रखें।

श्री विवेक कुमार सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी तक आप बाढ़ के बारे में सुन रहे थे। मान्यवर, अंग्रेजों के वक्त में रंगवाँ, गंगऊ और वरियारपुर डैम बने थे, अरबों रुपया दिया गया इन डैमों को ठीक करने के लिए, नये बनाने की तो बात छोड़ दीजिए आज इन डैमों की हालत यह है कि किसी भी वक्त यह टूट सकते हैं? 80-80 लाख रुपए इनकी रिपेयरिंग के लिए दिया गया और आज हालत यह है कि पूरी की पूरी नहर चाहे गिरवाँ क्षेत्र हो, चाहे, नरैली क्षेत्र हो, चाहे बिसंडा क्षेत्र हो और चाहे

खुरहट व महुल क्षेत्र हो, वहाँ पर जो पक्का निर्माण हो रहा है, उसको देखने के लिए आप एक टीम भेज दीजिए और जन प्रतिनिधियों को साथ भेज दीजिए, वहाँ हालत यह है कि अगर एक ठोकर मार दीजिए तो पूरी की पूरी सीमेंट नीचे आकर गिर जा रही है। नहरों में न तो कहीं कुलाबे हैं, न सींचने की सुविधा है, न पानी रोकने का साधन है और आपको ताज्जुब होगा मान्यवर कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एक समझौता हुआ कि 34 क्यूसिक पानी मध्य प्रदेश रंगवा डैम से बाँदा जनपद को देगा लेकिन हालत यह है कि 17 क्यूसिक से ऊपर पानी उठाने की क्षमता ही नहरों में नहीं है। और इसमें करोड़ों रूपये की धनराशि खायी गयी है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहूँगा कि हालत यह हो गयी नहर विभाग की, नहर विभाग बाँदा में कमाई की गयी, उसके बाद उस इंजीनियर को उन्नाव भेज दिया गया, उन्नाव में कमाई की गयी, तत्कालीन मंत्री के रिश्तेदार में साथ उसके बाद उसे कांशीराम जी के नाम पर बने पार्क के निर्माण में, एल0डी0ए0 में भेज दिया गया। इतने काम्पीटेंट इन्जीनियर वहाँ मौजूद है कि बाँदा में बनाते हैं। आप ताज्जुब करेंगे, मैं उन इन्जीनियर साहब का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उनकी पत्नी उपमा गुप्ता की जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं सब उपमा गुप्ता के नाम होती है, उसके बाद मंत्री जी के परिवारीजनों के नाम होती हैं। यह विषम स्थिति है कि हमारा पैसा, एक तो बुन्देलखण्ड वैसे ही सूखे की हालत से जूझ रहा है, बुन्देलखण्ड के अन्दर भूख से मौतें हो रही हैं, खड़ी फसल सूखी जा रहा है। पानी बरस नहीं रहा है, धान बोये जायेंगे या नही बोये जायेंगे, इसकी कोई परवाह नहीं है और बाँध में एक बूँद पानी नहीं है। ऐसे इलाके पर आखिर कौन सी कार्रवाई आप करने जा रहे है ? अधिशासी अभियंता, जूनियर अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता को सस्पैंड कर देने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। अगर वास्तव में आप कृषि के क्षेत्र में कुछ प्रगति चाहते हैं तो बिना पानी के प्रगति नहीं हो सकती। आप उसके सरगना को गिरफ्तार करने की ताकत क्यों नहीं दिखाते हैं? आपने सस्पैंड कर दिया, आधी तनख्वाह वह पा रहा है, मौज कर रहा है। जिस दिन आपकी इच्छा होगी उसकी तैनाती हो जायेगी और जब तैनाती हो जायेगी तो उसको बकाया भुगतान मिल जायेगा। सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। एक-दो बातें और कह कर अपनी वाणी को विराम दूँगा। चूँकि औद्यागिक क्षेत्र का भी आज बजट है। जरा देख लीजिए नोयड़ा के अंदर सेक्टर 25 ए और 32 ए, ये दोनों बड़े बड़े सेक्टर किस कीमत पर पोंटी चड्ढ़ा को तत्कालीन सरकार ने दिये है। 500 करोड़ की बालू ही केवल वह बेच चुका है। 6-7 साल में उसको भुगतान करना है। तीन गुनी कीमत वह पहले वसूल चुका है। मान्यवर, यह जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जनता की जमीन ली गयी है किस कार्य हेतु लिया गया है यह आपको देखना है। सरकार अगर नहीं देखेगी तो आने वाले दिनों में बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि इसके गम्भीर परिणाम भी

आपको भोगने होंगे । मान्यवर, बार-बार आप लाइट जला रहें है तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्यायें रखने का अवसर दिया है।

श्री अभय नरायन सिंह पटेल-

मा0 अधिष्ठता महोदय, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर सन् 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय इस विभाग की सिंचाई क्षमता केवल 27.40 लाख हेक्टेयर थी। हमारी सरकार ने वर्ष 2012-13 में 225.85 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा है। लघु सिंचाई सेक्टर में अनुसंधान एवं सर्वेक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में मेरी सरकार द्वारा रुपये 50 लाख का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के लिए मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में रूपये एक हजार लाख का प्राविधान किया गया है। कल्याणकारी सरकार होने के कारण प्रदेश के चतुर्मुखी विकास हेतु प्रत्येक अंचल में उपलब्ध सभी श्रोतों का अधिकाधिक उपयोग कर पर्याप्त सिंचन क्षमता सृजित करना मेरी सरकार का लक्ष्य है। सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को देश में चतुर्थ स्थान प्राप्त है।

मान्यवर, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर आया हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में योजना काल से पूर्व सिंचन क्षमता 100.80 हजार हेक्टेयर थी जो बढ़कर अब 5335.39 हजार हेक्टेयर हो गयी है। इस प्रकार योजनाकाल में पूर्वी उत्तर प्रदेश की सिंचन क्षमता में लगभग 53 गुना वृद्धि हुई है। श्रीमान् उत्तर प्रदेश राज्य के अर्न्तगत आजमगढ़ मण्डल में सृजित सिंचन क्षमता 342918.50 हेक्टेयर है। इस मण्डल में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई 550 नहरों की 2920.65 कि0मी0 लम्बाई द्वारा विभिन्न नहर प्रणालियों के माध्यम से की जाती है। मान्यवर, आजमगढ़ राजस्व मण्डल की नहरे सुदूर एवं अन्तिम छोर पर स्थित होने के कारण विगत वर्षों में किसानों को सिंचाई हेतु पानी सही समय व सही मात्रा में उपलब्ध नहीं था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने नहरों, राजवाहो एवं अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई की व्यवस्था दोनों फसलों में किए जाने से सिंचाई हेतु पानी सही समय व सही मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा। वर्तमान खरीब फसल में अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग करते हुए नहरों एवं नालों की सफाई का कार्य प्रगति पर है। नहरों नालों की सिल्ट सफाई की कार्य योजना में प्राथमिकता का निर्धारण कार्य योजना का अनुमोदन क्रियान्वयन अनुश्रवण तथा सत्यापन एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शी अनुश्रवण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय समिति भी वर्तमान सरकार द्वारा गठित की गई है। मान्यवर, हमारी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तो मिला क्या केवल खोखला बजट मेरी सरकार द्वारा 2005-06 में छोड़ी गई नहरें जिनमें सुधार आधुनिकीकरण प्रस्तावित था किन्तु पूर्ववर्ती बसपा सरकार द्वारा कुछ नहीं

कराया गया जो योजनाएं मिली है वह भी अधूरी जिनमें प्राथमिकता तथा नियोजन की कमी रही। जो पुरानी नहरें है उनका जीर्णोद्धार हमारी सरकार करने वाली है। आज पैसों की कमी है लेकिन हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि कम पैसे में अधिक परिणाम प्राप्त हो। हमारी सरकार सिंचाई विभाग में सुधार के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहती है। जिसे इच्छाशक्ति कह लीजिए या संकल्प। इस शासन ने निर्णय लिया है कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह अब लूट नहीं होने दी जाएगी। बूँद बूँद पानी का उपयोग खेतों में किया जायेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अन्त में यहीं पर अपने निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी जनपद आजमगढ़ की एक खास समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी मेरा निर्वाचन क्षेत्र घाघरा नदी के किनारे स्थित है और बरसात में बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित रहता है। घाघरा नदी की कटान से मेरे क्षेत्र के तीन गाँव चक्की हाजीपुर, हाजीपुर खास तथा गागेपुर मठिया बुरी तरह प्रभावित है। मान्यवर उक्त तीनों गाँवों के निवासियों की बरसात में बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मा0 सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उक्त तीनों गाँवों को काटन से बचाने के लिए सरकार द्वारा अधिक से अधिक प्रयास किए जांए और जिनके मकान नदी के कटान में आ चुके है उन्हें पुर्नवासित किया जाय तथा उचित मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था की जाय। हैदराबाद से महुआ तक तीन माह बाढ की विभीषिका से लोग महुआ गढवल बांध पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते है। यह ताडव घाघरा नदी का है। यहाँ गरीब लोग निवास करते है सरकार द्वारा समय-समय पर कुछ भी नहीं किया गया है जिससे लोगों में आत्मग्लानि है। मैं मांग करता हूँ कि महुआगढ़ बॉध को समुचित रूप से ठीक कराया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया-

अधिष्ठाता महोद्य, आपने मुझे सिंचाई विभाग की कटौती पेश करते हुए श्री हुकुम सिंह जी द्वारा जो सुझाव पेश किए गए हैं उन्हीं पर बल देने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर हमार विधान सभा खेत्र धौरहरा बाढ की दृष्टि से बहुत ही क्योंकि वहाँ शारदा नहर निकलती है घाघरा और गंगा के बीच का यह क्षेत्र है हमारे यहाँ लखीमपुर से शारदा नहर निकलकर सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बनारस यहाँ तक वह सीचने का काम करती है। जब बाढ शुरू होती है नेपाल का पानी आ जाती है नेपाल का पानी आने की बजह से पानी नहर में छोड़ा जाता है नहरे अपनी कुल क्षमता में चल रही होती है नदी में भी पानी कसकर भरा होता है। तटबन्ध बने न होने की बजह से यह पानी क्षेत्र में जाकर गाँव में जाकर भर जाता है जिससे बाढ़ की भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जहॉ 240.93 लाख हेक्टेयर है।

प्रदेश में 73.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है जिसके सापेक्ष 58.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना सम्भव है। संसाधनों की कमी के कारण मार्च 2012 तक मात्र 20.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ही सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि शारदा नदी के किनारे तटबन्ध बने हुये हैं, वो टूट रहे हैं, और उनसे पानी गांवों में फैल रहा है जिससे गांव के गांव डूब रहे हैं, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ के द्वारा करीब 16 गांवों का अस्तित्व समाप्त हो गया है जो कि गैर आबाद गांव वो घोषित हो चुके हैं और लोग वहां से पलायित हो करके सड़कों पर आ करके रह रहे हैं, उनका अपना जीवन जीना दूभर हो रहा है, अपने खाने की व्यवस्था करना उनके लिये दुर्लभ होता है, जानवरों के चारे की व्यवस्था करना उनके लिये दुर्लभ होता है और मान्यवर, दुर्लभतम तब हो जाता है। जब बाढ़ से पीड़ित लोग सड़क पर बसे हुये होते हैं और बारिश का पानी भी उनको परेशान करता है। ऐसी स्थिति में उनकी क्या स्थिति होती है कि नीचे बेघर हो करके वो सड़क पर खड़े हुये हैं, उनके पास अपना सिर छुपाने की जगह नहीं है और ऊपर से बारिश हो रही है जिससे उनके जानवर, उनके बच्चे, उनकी महिलायें, बुड्ढे अनेक प्रकार की बीमारियों में जब वो पानी में भीगेंगे तो बीमारियों से वे ग्रसित हो जाते है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके पुनर्वास के लिये वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाये। अभी मानसून आने में जैसा कि बता रहे है कि जून भर में आ जायेगा, अभी 20, 25 दिन है तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था के तिरपाल की व्यवस्था कर ली जाये और तहसील के माध्यम से ऐसे लोग जो अपने घरों में पानी भर जाने की वजह से सड़कों पर आ करके बस रहे हैं, तिरपाल के द्वारा उनको छत, उनके सिरों को ढकने के लिये, उनको सोने के लिये उनकी व्यवस्था कर दी जाये। मान्यवर, वहां पर लोग आते हैं, एनजीओ आती है, स्वयंसेवी लोग आते हैं। वे अपने लंच पैकेट बना के, ब्रेड वगैरह दे करके उनका खाना कुछ टाइम तक चला देते हैं लेकिन मान्यवर, उनको कोई सिर छिपाने के लिये तिरपाल की व्यवस्था नहीं करता। जानवरों के चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती क्योंकि पूरी की पूरी की पूरी तहसील, पूरा का पूरा जिला पानी से भरा होता है। नौबत यह आ जाती है कि पिछले कुछ सालों में राष्ट्रीय राजमार्ग कटने की नौबत हो जाती है किन्तु वहां पर बहुत ही मजबूती से काम चल रहा है और जिस हिसाब से काम चल रहा है, उससे लग रहा है वो रोड कटने से बचाया जा सकेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस राष्ट्रीय राजमार्ग को बचाया जाये। अभी मुख्य मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी यहां से शपथ लेने के बाद पहली बार लखीमपुर खीरी गये थे, वहां पर उन्होंने उस बैराज पर शारदा नहर के सुन्दरीकरण के लिये कुछ जगहें चिन्हित की है, उसमें कुछ गरीब बसे हुये हैं, मछुआरे समुदाय के लोग बसे हुये हैं। उनके घर उजाड़ने की सरकार वहां पर योजना बना

रही है। नौबस्ता ग्राम सभा वहीं से सटी हुयी है, उसके मजरे हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन गरीबों के घर न उजाड़े जायें। कुछ लोग तो अपनी निजी जमीनों में भी बसे हुये हैं लेकिन ये अधिकारी वर्ग उनको उजाड़ना चाहता है तो मान्यवर, उनको उजाड़ने से रोका जाये। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि शारदा नगर का जो तटबन्ध हुआ है। झण्डीराज तक जाता है, उस पर जो रोड बनी हुई थी। निघासन जाने के लिये उसी पर से सारा ट्रैफिक जाता है, वो रोड बिल्कुल जर्जर हो गयी है तो उस रोड को शारदा नगर से झण्डीराज तक उस तटबन्ध को बनाया जाये। मान्यवर, आपसे एक रिक्वेस्ट हमारी यह है कि....

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरु भइया-

बाढ़ का मामला लखीमपुर का बहुत ही संवेदनशील मामला है। मुख्य मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी सब लोग इसीलिये वहां पर सबसे पहले गये थे कि बाढ़ पीड़ितों की व्यथा को सुन सकें, वहां के दुखदर्द को जान सकें। तो मान्यवर, यह बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो तटबंध अधूरे रह गये हैं। चाहे उन्होंने स्टे ले लिया हो या उनकी जमीन का अधिग्रहण न हो पाया हो तो उसकी जमीनों का अधिग्रहण कराके उस तटबंध को पूरा करा दें, क्योंकि अगर वो तटबंध पूरा नहीं होगा तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

साध्वी निरंजन ज्योति-

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर मा0 हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं उस पर बल देने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, मैं जब से इस विधान सभा में आयी हूँ मुझे ऐसा लगा कि यहाँ आरोप प्रत्यारोप हर विभाग में हो रहा है। मान्यवर, जो घोटाला करते हैं। बेइमानी करते हैं उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, जो सिंचाई विभाग पर कटौती का प्रस्ताव मा0 हुकुम सिंह जी ने प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने काफी अच्छी बातें कही हैं। मा0 सिंचाई मंत्री जी ने कहा है कि इस बार जून के महीने में नहरों की सफाई हो जायेगी पहली बार और दूसरी बार अक्टूबर माह में हो जायेगी। मैं इसके लिए सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगी। मान्यवर, यदि यह हो जायेगा तो बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, होता क्या

है कि जब गेहूँ बोने का वक्त आता है तो उसमें सफाई नहरों की नवम्बर, दिसम्बर महीने में होती है और जब गेहूँ का कटान होता है तब नहरें पूरी तरीके से चलती नहीं हैं। मान्यवर, अभी यह नयी सरकार आयी है, नया बजट पेश किया है तो मुझे उम्मीद है कि यह सरकार अपना कार्य करेगी और नहीं करेगी तो जिस प्रकार से बसपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर हम लोग उतरते रहे हैं, उसी प्रकार से पानी बिजली की समस्या को लेकर हम लोग इस सरकार के खिलाफ भी फिर सड़कों पर उतरेंगे। मान्यवर, मैं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आती हूँ। अभी मा0 विवेक सिंह जी बुन्देलखण्ड की चर्चा कर रहे थे। मान्यवर, बुन्देलखण्ड की धरती ऐसी है कि कहीं पर भी चावल, बांदा को छोड़कर, उत्पन्न नहीं होता है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में गेहूँ बोया जाता है तो ट्यूबवेल है तो लाइट नहीं है और अगर लाइट है तो ट्यूबवेल चलाने वाला इन्जीनियर या मैकेनिक नहीं है। यहीं हालत नहरों की होती है। हम नहरों की सफाई को लेकर उसमें पानी की व्यवस्था को लेकर लड़ते रहते हैं और जनता त्राहि–त्राहि करती रहती है।

मान्यवर, हमीरपुर जनपद विधान सभा क्षेत्र झांसी में पारीक्षा बांध से जो जालौन होकर हमीरपुर आती है हमारे कुरारा ब्लाक है वहां पानी की दिक्कत है। जब अधिकारियों से बात करते हैं तो वह कहते हैं यहाँ पानी कम है इसलिए हम हमीरपुर को पानी नहीं दे पायेंगे। मान्यवर, इस तरीके से नहर तो है लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी तरीके से मान्यवर, हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं अनुरोध करूँगी जो सिंचाई का लगान लगता है, उसको वापस किया जाये। मान्यवर, हमारे यहाँ बुन्देलखण्ड में सूखा हमेशा पड़ा रहता है लेकिन इस वर्ष ओले गिर गये हैं और उन ओले के कारण वहाँ का किसान त्राहि–त्राहि कर रहा है। मान्यवर, मैं चाहती हूँ कि जिन किसानों के खेतों में ओले गिरे हैं और उससे जो नुकसान हुआ है। उसमें सिंचाई का बिल माफ किया जाये। मान्यवर, पहले भी सूखे के नाम पर बिजली का बिल माफ किया गया लेकिन बाद में उसे दुगुना लगा कर भेज दिया गया। इस तरह से एक प्रकार से उसको स्थगित किया गया था। मान्यवर, बुन्देलखण्ड के किसानों के साथ विचित्र स्थिति है। पहली बात तो पानी उपलब्ध नहीं है और अगर पानी उपलब्ध होता है तो लाइट नहीं उपलब्ध होती है। मान्यवर, हमारे यहाँ हमीरपुर में सुमेरपुर ब्लाक में पत्योरा कैनाल है। 9 कि0मी0 लम्बी नहर है, इसमें 12 मशीनें होनी चाहिए लेकिन 6 मशीनें ही हैं और जिसमें से 4 चलती नहीं हैं तो मेरा कहना यह है कि उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं

हो पा रहा है। उस नहर में 4 किमी0 रोड़ बनी हुई है। मेरी मांग है कि उसकी सफाई करा दें। क्योंकि वहाँ पानी नहीं पहुँचता है। यदि वहाँ किसानों का पानी पहुँचना है तो वहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दें। वहाँ पटिया बिछी हुई थी। वह भी देख रेख के अभाव में टूट गयी है। उससे टेल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि वहाँ की व्यवस्था को दिखाया जाये और ठीक कराया जाये।

समय बोलने से इंकार करता है यहाँ सारे लोग जनता की भलाई के लिए आये हैं, जनता के विकास के लिए आये हैं मैं ऐसा मानती हूँ। मैंने सुना था कि विधान सभा में जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग पहुँचते हैं, अभी हमारे मंत्री जी ने कहा कि जिन्होंने गड़बड़ी की है, उन्हें हम सजा देंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगी कि सजा नहीं उनको आजीवन कारावास होना चाहिए जिन्होंने घोटाला किया है और एक बात और कहना चाहती हूँ कि सरकारी पैसे से जो बिल्डिगें बनी हैं, उन बिल्डिगों में गरीबों के बच्चों के लिए विद्यालय खोले जायें, गरीबों के लिए अस्पताल खोले जायें, यह मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, यह मैं आपसे मांग करती हूँ। जिन लोगों ने जनता की गाढ़ी कमाई को अपने सुख के लिए अपने उपभोग के लिए उस पैसे को अर्जित किया है, गरीबों का पेट काटा है, गरीबों की रोटी काटी है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो जिसने गरीबों की रोटी छीनी है उसके बने हुए मकानों में सरकारी विद्यालय खोलकर गरीबों के बच्चों को पढ़ाया जाय। आपने बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई विभाग के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, यह जो बजट आज पेश हुआ निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों के बजट से बिल्कुल अलग है, बहुत सुन्दर बजट था और इसलिए भी सिंचाई का विभाग महत्वपूर्ण होता है क्योंकि किसी भी देश या प्रदेश का जो सिंचित क्षेत्र होता है वह वास्तव में उस देश या प्रदेश के विकास का सूचकांक होता है। जितना ज्यादा सिंचित क्षेत्र होगा उतना ही वह देश या प्रदेश विकास के पथ पर आगे होगा, यह अवधारणा थी और इसका हम इस तरह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नदियों के किनारे की, चूंकि वहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थीं। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास हुआ। चाहे वह नील की सभ्यता रही हो, चाहे वह मेसोपोटामिया की रही हो जो दरिया और फराद के बीच में हुई या वह भारत की सिन्धु घाटी की सभ्यता रही हो, सभ्यताओं का विकास हमेशा इनके किनारे हुआ और आज भी गंगा, यमुना के दोआब की विशिष्ट संस्कृति है। वह गंगा जो हमारी जीवनदायिनी है, वह गंगा जो शीरदायिनी है, वह गंगा जो अरबों लोगों को मोक्ष देने वाली है, वह शीरदायिनी, कलकल निनदिनी, सततवाहिनी, अमृतवाहिनी, मोक्षदायिनी मां गंगा का जो आज इतना दूषित रूप में सामने आया है कि अफसोस होता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन यह जरूर कहूँगी कि विपरीत परिस्थितियों में आज उत्तर प्रदेश का लगभग 81 प्रतिशत क्षेत्रफल सिंचित है और इस हिसाब से यह देश के चौथे स्थान पर है। हालांकि यह गर्व का विषय नही है। यह 2008 और 2009 के आंकड़ों के हिसाब से है। यह मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि 81 प्रतिशत भी सिंचित भूमि उपलब्ध नहीं हो सकती थी अगर पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं होती। यह हमारी सरकार की इच्छाशक्ति थी कि 81 प्रतिशत भूमि आज सिंचित भूमि के रूप मौजूद है। विश्वास मानिये, अभी मैंने देखा चाहे उधर के हमारे साथी रहे हो चाहे इधर के लोग हों उनका दर्द उनकी बातों से नजर आ रहा था किस तरह से बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित हुए निश्चित रूप वह पिछले 5 वर्षों का मार्मिक वर्णन कर रहे थे। हमारे इधर के साथी सम्भवतः वह धौरहरा से थे, बाढ़ की विभीषिका का वर्णन कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आपकी सरकार थी। 695 करोड़ रुपये का बजट बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, जल निकासी के नाम पर खर्च हुआ और उसके बाद का काला सच उत्तर प्रदेश ने इस शक्ल में देखा कि बाढ़ के पानी में डूबते हुए लोग, पलंग के ऊपर बैठे हुए लोग, मचानों के ऊपर चढ़कर बैठे हुए बूढ़े और बच्चे, अपनी जान को बचाने की गुहार करते हुए लोग आखिर वह पैसा गया कहाँ।

आखिर वह पैसा गया कहाँ ? इस एक-एक पैसे का हिसाब लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश की जनता को है, क्योंकि वह वहां के करदाता की गाढ़ी पसीने की कमाई थी। साथियों अभी लोक निर्माण विभाग का बजट आया, ऊर्जा विभाग का बजट आया कुछ बातें इधर से कही गईं। कुछ बातें उधर से कही गईं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आइना बदल देने से चेहरे नहीं बदलते। लोग नाराज हो गये, शायद किसी साथी ने आइना दिखाने का कुसूर कर दिया था, जिस तरह से दुर्घटना में चेहरा विकृत हो जाय और उसके बाद आइना देखकर आदमी दहल जाय। उसी तरह से 5 वर्षों की दुर्घटना में आप अपना चेहरा देखकर के दुखित हो गये, दहल गये चेहरे को देख करके इसीलिये शायद आपकी जबान पर यह सवाल आ गया। मुझे तुमने जो आइना दिखा दिया क्यों अपने आप से डरा दिया। उस आइने में किसी और की

नहीं आपकी अपनी सूरत थी। कितने आइने तोड़ोगे? माननीय अधिष्ठाता जी, मैं तो कहती हूँ कि पूरे प्रदेश के आइनों को तुड़वा दीजिये। न तो कोई आइना रहेगा न किसी को अपना घिनौना अक्श नजर आयेगा। लेकिन आइना हो न हो जन तो फिर भी रहेंगें। अविरल निर्मल गंगा तो फिर भी रहेगी। इसके पानी में अगर अपना तरीर चेहरा देखोगे, उसके पानी में अगर अपना अक्श देखोगे तो क्या करोगे उस निर्मल गंगा को भी सुखाकर रख दोगे क्या? आज यह सवाल है, कहा जा रहा था कि विकास का कार्य नहीं हुआ। मैं ज्यादा बात न कह कर सिर्फ इतना कहूँगी कि बुन्देलखण्ड के लोगों ने बात कही है। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बात बताई चाहे वह राज घाट बाँध की बात रही हो या वह बाण सागर बाँध की बात रही हो या वह मध्य गंगा नहर की बात रही हो। ज्यादा विस्तार में न जा करके मैं केवल इतना आपसे कहूँगी कि सरयू नहर परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी और उसमें 3600 नये नलकूप व 2 हजार किलोमीटर लम्बे नाले का निर्माण प्रस्तावित है। साढ़े चार करोड़ वृक्ष उसमें लगाये जायेंगें जिससे जनता को इससे लाभ मिल सके। इसी तरह से निचली गंगा नहर प्रणाली की क्षमता को पुर्नस्थापन किया जाना है। अधिकांश इसका पक्का भाग 150 सालों से ज्यादा पुराना है। इस कारण इसकी परिकल्पित क्षमता के अनुरूप नहीं चल पा रही है। इसलिये इसको इसकी परिकल्पित क्षमता के अनुरूप चलाने के लिये निचली गंगा नहर प्रणाली को 988 लाख रुपये का प्राविधान वर्ष 2012-2013 के बजट में किया गया है जो पिछले वर्ष 2011-2012 की तुलना में लगभग 100 लाख ज्यादा है, क्योंकि पिछले वर्ष में यह 889 लाख रुपये दिया गया था। यह इस बात का परिचायक है कि वर्तमान सरकार लोगों के दुःख और दर्द से पूरी-पूरी हमदर्दी रखती है। मैं एक बात अपने क्षेत्र के लिये भी कहूँगी कि देवकली पम्प कैनाल की भी अत्यन्त जर्जर दशा है। उसकी कंक्रीटिंग करने के लिये मैं आपसे अनुरोध करूँगी और साथ ही कम से कम 500 किमी0 नाले का निर्माण उस पर कर दिया जाय तो उसको सुविधा हो जायेगी। मान्यवर, कहने को तो बहुत हैं लेकिन मैं इतना कह कर अपनी बात खत्म कर दूँगी कि आज आपको दुःख हो रहा है, अभी आपने कहा था कि लखीमपुर खीरी में दौरा करने के लिये गये थे। वहां पर कुछ लोगों को हटाया जा रहा है। जिन लोगों को हटाया जा रहा है, उनके पुर्नवास की निश्चित रूप से उत्तम व्यवस्था की गयी होगी इसका मुझे पूरा विश्वास है और इसका बजट में भी उल्लेख है लेकिन साथियों मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि कभी आपने सोचा कि परिकल्प विभाग की पूरी कालोनी थी, उसको तहस नहस कर दिया जाता है और उसके बाद वहां पर मूर्ति खड़ी की जाती है। अभी किसी ने बताया कि यह चौमुखी मूर्ति थी। यह चार मुख जो हैं लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष को दर्शाते थे। उस पूर्व मुख्यमंत्री के जिसने प्रदेश को लूटने का काम किया था। मान्यवर, आज दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अपना जमाना याद कर रहे हैं। जब नहरों में टेल तक तो क्या नहरों में सिर तक पानी मौजूद नहीं था। मैंने स्वयं अपने विधान सभा क्षेत्र के लिये बार-बार कहा कि हमारी

नहरों में पानी नहीं है, नहरों में पानी दिया जाय, मगर पानी नहीं दिया गया। यह व्यथा अकेले बुन्देलखंड की या पूर्वी उत्तर प्रदेश की नहीं है। यह व्यथा उत्तर प्रदेश कि करोड़ों करोड़ किसानों की है। वह किसान जो पानी के अभाव में अपने खेत में पानी नहीं लगा सका, वह किसान जो गेहूँ नहीं उगा सका, वह किसान जो सूखी हुई फसलों को देखता रहा, वह किसान जो आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ, उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या करता रहा और उसकी जबान ने कहा कि दिल में एक शोला भड़क उठा है, आखिर क्या करूँ। जब वह किसान आत्महत्या करता है तो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर जाता है। इसलिये कि उसकी उम्मीदें थीं कि जब उसकी फसल तैयार हो जायेगी उसको बेचकर के अपनी बेटी की डोली को उठायेगा, अपनी बहिन के हाथ को पीले करेगा।

अपनी बहन के हाथ को पीला करेगा लेकिन जब उसके सामने फसल सूखती है, तो उसके सीने में पीड़ा होती है, कि-

दिल में एक शोला भड़क उठता है आखिर क्या करूँ
जख्में-सीने का महक उठा है आखिर क्या करूँ,
बढ़कर इस इन्द्र सभा का साजो-सामाँ फूँक दूँ,
इसका गुलशन फूँक दूँ उसका शबिस्तां फूँक दूँ,
तख्ते-सुल्तां क्या मैं सारा फ़न्ने-सुल्तां फूँक दूँ।

मान्यवर, यह उसकी आह का नतीजा था जो आज आप लोग इतना बेइज्जत होकर उत्तर प्रदेश की सरकार से बेदखल हुए और यहां की जनता ने जो आपको बहुमत दिया था बेइज्जत करके हम कह सकते हैं- बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर आप 2012 में जनता के कूचे से निकले हैं। आपकी माँग पर हम लोग माँग करते हैं कि केवल इंजीनियरों को निलम्बित न किया जाए बल्कि जिनकी शह पर कार्य हुआ था जिन लोगों ने अपने पेट को भरने का काम किया था उन लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए। तभी उस समाज का सपना साकार होगा। जहहिन्द जय भारत।

*श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, आपने हुकुम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ जैसा अभी माननीय सदस्या ने कहा उससे हम लोग सहमत हैं। हम इससे पिछली सरकार और उससे पिछली सरकार द्वारा भी किये गये घोटालों के बारे में आपको बता देंगे, हमारा अनुरोध है कि आप जाँच जरूर करा लीजिएगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहे इससे पिछली सरकार में घोटाले हुए हों, चाहे उससे पिछली सरकार में हुए हों। नुकसान किसका हुआ, न तो यहां बैठे लोगों का नुकसान हुआ, न वहां बैठे लोगों का नुकसान हुआ, नुकसान उसका हुआ जो धरती का सीना चीरकर लगान देने का काम करता है। किसान को न पानी मिल पाया, न बिजली मिल पाई। माननीय अधिष्ठाता जी, आप सहमत होंगे कि कृषि के लिए जितना बीज और खाद्य जरूरी है, उतनी आवश्यकता उसके लिए सिंचाई की भी है। किसान हमारा अन्नदाता है और किसान की अन्नदाता सिंचाई है। मान्यवर, इससे पूर्व और पिछले पाँच सालों में उससे पहले, जो सूखे पड़े, बार-बार सफाई के नाम पर मोटा घोटाला किया जाता है। कृष्णा नदी अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने बताया था। कूड़े से अटी पड़ी है। उन्होंने भी अनुरोध किया था और मैं भी अनुरोध कर रहा हूँ कि कम से कम एक बार उसमें पानी छोड़ दिया जाए तो सफाई होगी और किसान को पानी मिलेगा, पशुओं का लाभ होगा क्षेत्र का लाभ होगा। अगर अच्छी फसल होगी तो क्षेत्र की उन्नति होगी, प्रदेश की उन्नति होगी देश की उन्नति होगी आप जानते हैं पूरी अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है और इस प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो कृषि है और किसान है। किसान हम लोगों को अन्न देने का काम करता है। मान्यवर, पूर्व में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए समानान्तर देवबन्द ब्रांच का निर्माण कराया गया था जिसका उद्देश्य गंगा नहर का पानी यमुना नहर एवं कल्लरपुर रजबाहें होकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना था जिससे यमुना नहर के रजबहे लोई, भौरा व कल्लरपुर में सिंचाई का प्राविधान किया गया था परन्तु शाख लोई में एक बूंद पानी नहीं है। पिछले कई वर्षों से पानी नहीं आया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है वहां पानी छुड़वाने की व्यवस्था होनी चाहिए वहां नहरों, रजबहों को अगर पक्का कर दिया जाए तो जो पानी वेस्टेज होती है वह कम होगी और किसानों को इसका लाभ होगा। ताजेवाला बांध का सुदृढ़ीकरण किया जाए एवं वैज्ञानिक तरीके से इसका निर्माण कराकर हम किसानों को किसान के हिस्से का पानी दे सकें तो अच्छा होगा परन्तु दुर्भाग्य यह है कि किसी सरकार ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया है। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

*श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने सिंचाई विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री से यह कहना चाहूँगा कि मान्यवर, चाहे वह पुरानी सरकार रही हो, चाहे यह सरकार चल रही हो, चाहे यह सरकार 1991 की रही हो, चारों बार मान्यवर, मैंने इस सदन में अपने जनपद मथुरा का बड़े जोरशोर से सिंचाई के बजट पर मामला उठाया, आपके लोक निर्माण के बजट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर भी मामला उठाया लेकिन इसका कोई भी समाधान आज तक नहीं हुआ। मैं कहना चाहूँगा जिस बहुमत से आपकी सरकार आई है और जिस जोश से सरकार अपना बजट पेश कर रही है, परन्तु रिजल्ट ढाक के तीन पत्ते ही हैं। मान्यवर, जनपद मथुरा में हमारा बलदेव क्षेत्र है। देश की आजादी के बाद भी वहाँ ऐसी स्थिति है, वहाँ के लोगों ने वोटिंग नहीं किया, वोट नहीं डाले, अभी तीन माह पहले, उससे बड़ा विरोध का इजहार क्या हो सकता है? नगला विजयी है, आप दिखवा लें, नगला विजयी राया ब्लाक के अन्तर्गत वहाँ के लोगों ने वोट नहीं डाले, कारण केवल पानी और नहर के पुल की समस्या है। अंग्रेजों के जमाने का मान्यवर, पुल बना हुआ है, एक मीटर चौड़ाई का है, उस गाँव को आने-जाने का आज भी कोई रास्ता नहीं है, न ट्रैक्टर निकल सकता है, न ही बैलगाड़ी निकल सकती है। कई बार मैंने लिखा, झूठा आश्वासन दिया गया, कहा गया कि पैसा मंजूर हो गया, पता नहीं कहाँ पैसा मंजूर हुआ लेकिन आज भी नगला विजयी में इस पुल के चौड़ीकरण के अभाव में समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन लोगों ने वोटिंग नहीं की, आगे वह क्या करें, भगवान जाने। लेकिन यह बात जरूर है बहुत अपेक्षा है कि इन समस्याओं का समाधान हो। इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश के किसानों को, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भी पूर्व में कहा कि 70 प्रतिशत प्रदेश के लोग केवल खेती पर निर्भर हैं, अपनी फसल पर ही निर्भर रहते हैं, अगर उन्हें पानी न मिले तो वह किस पर निर्भर रहेगा, उसका जीवनयापन कैसे होगा, यह आप स्वयं सोच सकते हैं। मान्यवर, जनपद मथुरा के अन्तर्गत ही बलदेव रजबहा है, आज पाँच वर्ष हो गए हैं, आप तो टेल की बात कर रहे है, मंत्री जी, उसकी तो स्टार्टिंग में ही पानी नहीं हैं। मान्यवर, मैंने लिखकर भी भिजवाया, चिट्ठी भी भिजवाया, माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे जनपद मथुरा के बलदेव क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बलदेव रजबहा, कुरसण्डा रजबहा, कारव रजबहा, महावन रजबहा, विसावर रजबहा, पचावर रजबहा, दधैटा रजबहा एवं जुगसना रजबहा की सफाई, खुदाई, सिल्ट निकासी एवं कठेला माइनर, पिरसूआ माइनर, अचरू माइनर तथा कटेला माइनर की सफाई खुदाई, सिल्ट निकासी एवं इन रजबहों के किनारों की पटरियों की मरम्मत व सड़कों की मरम्मत का प्रावधान इस बजट में सम्मिलित कराया जाय और वहाँ जो अन्य माइनरें निकलती हैं उनकी भी हालत सुधारी जाए। कहीं पर और किसी भी स्तर पर यहाँ से पैसा जाता है, सरकारें देती हैं, सफाई के लिए देती है, खुदाई के लिए देती हैं, सिल्ट निकासी के लिए भी देते हैं लेकिन काम केवल कागजों पर हो जाता है। आज हालत यह है कि किसान आत्महत्या करने पर तुला हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के कुछ गाँव नगला अकोस, सेहत, नेरा, खेरा, नरहोली घाट एवं मादौर में 2010 में बाढ़ आई, पुल बह गए, सड़क बह गयी, नगला अकोस का 7 दिन तक सम्पर्क पूरे देश से कटा रहा। हम लोग वहाँ एसडीएम, एडीएम आदि को लेकर स्टीमर एवं नाव से गाँव में गए तब जाकर उनका इलाज

सम्भव हुआ तथा लोगों को आने-जाने के लिए नावों की व्यवस्था कराई। पुल और सड़क बहने से और रास्ता बन्द होने पर आपके विभाग द्वारा पुल की मरम्मत और सड़क मरम्मत कराई गई जो कि मानक के अभाव में पुनः 2011 में पुल और सड़क बह गई। अभी भी यहाँ की सड़क व पुल बहने के कारण आवागमन अवरुद्ध है। माननीय मंत्री जी के पास सिंचाई विभाग भी है और लोक निर्माण विभाग भी है, मैं उनसे अपेक्षा करूँगा कि इसको दिखवा लें और इसके लिए बजट में तुरन्त व्यवस्था करायें।

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ फरह, बरारी, महुअन, कारव, कुरसण्डा, महावन, बल्देव, विसावर, पचावर, धधैटा, जुगसना रजबहा है और कुरकन्दा, परखम, ओल, कठेंघा, पिसुआ, कटैला, अचरू व किरारई माइनर है। उसकी सफाई, खुदाई सिल्ट की सफाई करवाने का बजट में प्रावधान करने की कृपा करें। वहां पर पानी की सुनिश्चित व्यवस्था की जाये। हमारे इस बजट में प्रावधान किये जाये और जो हमारे यहाँ नगला अकोस का पुल व सड़क टूटा है उसको बनवाने का प्रावधान इस बजट में करने की कृपा करें। जो बलदेव क्षेत्र के रजबहों, माइनरों पर आने-जाने का रास्ता है। वह जर्जर हो गया है। आपके पास तो सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग दोनों हैं। आप सक्षम भी हैं। कृपया हमारे बलदेव क्षेत्र अन्तर्गत नहरों की सफाई, खुदाई व सड़क मरम्मत का कार्य सुनिश्चित किये जाने हेतु बजट में प्राविधान करने की कृपा करें। मैं सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश की जनता ने आपको बहुमत से जिताकर भेजा है। उनकी भावना को देखते हुए उसमें किसानों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर सुनिश्चित करें जो किसान की, इस प्रदेश की जनता की मूलभूत जरूरत है। वह आप मुहैया करा सके। इसके साथ ही मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आज देख रहा हूँ, परसों से माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी बजट रख रहे हैं और जो भी माननीय सदस्य बोलता है, वह मांगता है। सड़क दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, खम्भे दे दीजिए। वहाँ तक तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन अभी आबकारी विभाग का बजट आना है। फिर माननीय सदस्य कहेंगे कि नहीं साहब छोटे से काम नहीं चलेगा बड़ा दे दीजिए तो सदन में मुश्किल होगी। इसलिए मान्यवर, अपनी बात रखी जाये लेकिन हर चीज मांगी न जाये। अभी आबकारी का बजट आने वाला है और लोगों ने मांगना शुरू कर दिया कि हमें ड्रम दे दीजिए, हमें जरकिन दे दीजिए। तो बड़ा संकट हो जाएगा।

(हँसी)

श्री विश्वम्भर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये सिंचाई विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी

हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हम बुन्देलखण्ड के जनपद बांदा की बबेरू विधान सभा क्षेत्र से आते हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की तकलीफ और दिक्कत यह है वहाँ के लोग बूंद-बूंद पीने के पानी के लिए तरसते हैं। खेत के लिए किसान सिंचाई के पानी के लिए तरसता है। जो हैण्डपम्प लगे हैं गर्मी में जलस्तर घटने के कारण आज हैण्डपम्प केवल ठूंठ साबित हो रहे हैं। उनसे पीने को पानी नहीं मिल रहा है। पिछली सरकार में जितने भी हैण्डपम्प बोर हुए वह मानक के अनुरूप नहीं बोर हुए। सही से बोरिंग नहीं की गयी जिससे पूरे के पूरे हैण्डपम्प आज पानी देना बंद कर दिये हैं। हर गाँव में रोज पानी के लिए लाठी चलती है। रोज झगड़े होते हैं। पिछले पाँच सालों में बुन्देलखण्ड में कम से कम 500 हत्यायें पानी के लिए हो चुकी हैं। जो हैण्डपम्प से पीने के पानी के सवाल पर हुयी हैं। अध्यक्ष जी, चाहे पीने का पानी हो चाहे खेत का पानी हो। गर्मी के महीनों में हमारे बुन्देलखण्ड में हजारों पक्षी और पशु पीने के पानी के अभाव में मर जाते हैं। अगर वहाँ जलस्तर सुधारने की कोशिश नहीं हुई जो कि पिछले पाँच सालों में नहीं हुई तो निश्चित रूप से हमारा मानना है और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बुन्देलखण्ड की धरती रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगी और लोग वहाँ से पलायन कर जायेंगे। चूंकि बुन्देलखण्ड को पानी मिलने के कोई रास्ते नहीं हैं। बरियारपुर जो बांध बना। बरियारपुर बांध से खेतों को जो पानी बुन्देलखण्ड को दिया जाता हैं उस बरियारपुर बांध के फाटक पूरी तरह से टूटे पड़े हैं। वह जर्जर अवस्था में है। बरियारपुर बांध से मिलने वाला पानी पर्याप्त नहीं है। खेतों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर खेतों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो जल स्तर नहीं सुधरेगा और जब जलस्तर ऊँचा नहीं आएगा तो पीने के पानी की दिक्कत बुन्देलखण्ड में हमेशा बनी रहेगी।

(इस समय 3 बजकर 32 मिनट पर भी अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष जी, विगत पाँच वर्षों में जो नहरों में पानी आया, जो नहरों में पानी दिया गया , उस पानी को किस तरह से नालों में डाल कर के बरबाद किया गया किसान को सींचने के लिए पानी नहीं दिया गया और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अध्यक्ष जी, कि खेत को तो पानी मिला नहीं लेकिन नहर आस-पास उसकी सिंचाई लिख ली गई, सींचपालों द्वारा और उनसे जबरदस्ती किसानों से पानी के लिए पैसे की वसूली की गई। मा0 अध्यक्ष जी हमें आपको और पूरे सदन को इस पर विचार करना होगा, सोचना पड़ेगा कि बुन्देलखण्ड को कैसे पानी मिले और बुन्देलखण्ड की धरती को पानी मिलने का केवल एक ही रास्ता है मा0 अध्यक्ष जी कि जब तक यमुना नदी में यमुना बैराज नहीं बनाया जायेगा तब तक बुन्देलखण्ड की धरती को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल सकता और कोई रास्ता नहीं है कि बुन्देलखण्ड की धरती को पानी मिले। मा0 अध्यक्ष जी, इससे भी बड़ी एक और दिक्कत है, हमारे यहाँ बुन्देलखण्ड में एक कहावत है कि ''गगरी न फुटै चाहे खसम मर जावे '', पति की मौत की चिन्ता नहीं है वहां की नारियों को लेकिन पानी की इतनी चिन्ता है कि गगरी न

फूटै, सुबह भोर में जग कर के दूर-दूर से पानी लेने जाना पड़ता है, तीन-तीन चार-चार घण्टे तमाम महिलाओं के पीने के पानी को लाने में ही व्यतीत हो जाते हैं तो जब तक खेत को पानी नहीं मिलेगा, खेत को पानी नहीं पहुँचेगा, खेत में पानी नहीं पहुँचेगा, तालाब नहीं भरेंगे, पोखरें नहीं भरेंगे, तब तक जल स्तर बुन्देलखण्ड का ऊपर नहीं आ सकता है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे कमासिन में कठार पम्प कैनाल की योजना बनी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, लेकिन वह तकनीकी कमियों की वजह से कठार पम्प कैनाल नहीं बन सकी, सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए चूँकि वहां जमीन रेतीली हो गयी है, कमासिन क्षेत्र को पानी न मिलने के कारण तमाम जमीन और वह जमीन जो असिंचित रहती है, भगवान भरोसे किसान उसमें बीज डालता है लेकिन अगर चार पसेरी बीज डालता है एक बीघे में, उसे दो पसेरी और तीन पसेरी भी वापस नहीं मिलता है अगर पानी नहीं बरसता है। तो मा0 अध्यक्ष जी, जो कठार पम्प कैनाल योजना बनी थी, उसकी तकनीकी कमियों की वजह से अगर वहां से नहीं बन सकती तो मान्यवर मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक पम्प कैनाल यमुना से जो बनी थी उसकी जगह अगल बगल से कहीं बन सकती है तो बनाया जाना चाहिए जिससे उस क्षेत्र को पानी मिल सके और दूसरी हमारे यहां ममसी गांव से बागे नदी निकलती है, ममसी गांव में भी बागे नदी पर एक 20 क्यूसेक क्षमता का पम्प कैनाल बनाया जाना क्षेत्र की जनता के हित के लिए बहुत ही जरूरी है। अन्त में कठार पम्प कैनाल और बागे नदी पर ममसी पर बनने वाली कैनाल के साथ-साथ यमुना बैराज की बात पर बल देते हुए अध्यक्ष जी अपनी बात को समाप्त करूँगा अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*श्री काली चरन सुमन-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए आज आपने जो बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, मान्यवर, मैं आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूँ। मान्यवर, सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि नहरों का पानी टेल तक पहुँचाया जायेगा, परन्तु मान्यवर, टेल तक पहुँचना तो दूर आगरा में नहरों में फसल के समय पशुओं को पानी पीने के लिये दुर्लभ है। मान्यवर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे बसे गांव बाढ़ के समय जलमग्न हो जाते हैं लोग बेघर हो जाते हैं तथा कृषि योग्य भूमि कटान के कारण समाप्त हो जाती है। अतः माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मा0 मंत्री जी कृपया यमुना नदी के किनारे बसे गांव महलबादशाही, गढ़ीमहावन, समोगर, तनौरा नूरपुर, मेहरा नारगंज, बरौली गूजर आदि गांवों की भूमि कटान को रोकने के लिए पक्के तटबन्ध, ठोकर आदि बनाकर के भूमि कटान को रोका जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि खारी नदी जो अकोला की है उसका रेगुलेशन किया जाए। मान्यवर, नहरों की पुलिया टूट चुकी है। जैसे बाई खेड़ा सिरौली मार्ग नहर की पुलिया का निर्माण कराया जाए। मान्यवर, नगला परमाल और नगला काटे के बीच ग्राम शंकरपुर की नहर की पुलिया टूट चुकी है, उसका निर्माण कराया जाए। पचगाई नहर की पुलिया का निर्माण कराया जाए। सेमरीताल नहर की पुलिया का निर्माण कराया जाए। गढ़ी वृन्दावन में श्यामों नहर के बीच की पुलिया का निर्माण कराया जाए क्योंकि पुलिया टूटने से लोगों का रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। मान्यवर, खारी नदी पर रामनगर पिनानी पुल का निर्माण कराया जाए क्योंकि यहाँ भी आम रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। मान्यवर, मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि नहरों की दो बार सफाई होगी। उसके बारे में कहना चाहूँगा कि यह तथ्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की जानकारी में भी लाना होगा। मा0 मंत्री जी ने आगरा शहर की नदियों और पुलों का जिक्र नहीं किया है। अतः आगरा की परियोजनाओं को भी समायोजित किया जाए। मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि बड़ी नहरों में तो पानी आ जाता है परन्तु जो छोटी-छोटी माइनरें होती हैं उनमें पानी नहीं पहुँचता है। मान्यवर, मेंरे विधानसभा क्षेत्र की नहरों की पटरियों की स्थिति बहुत खराब है। वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उनका भी लेपन, मरम्मत आदि कराया जाए, उनमें से कुछ निम्न है, जैसे मलपुरा माइनर, सेमरी माइनर, रोहता माइनर, नगलाकारे माइनर, नगला परमार, डिगनेर माइनर, श्यामों माइनर ये सभी पटरियाँ टूट चुकी हैं। इनकी मरम्मत कराई जाय। मान्यवर, खारी नदी में खारे पानी की विकट समस्या है। इस क्षेत्र में मीठा पानी देने के लिए रामनगर अकोला क्षेत्र में एक चैक डैम बनाना चाहिए जिससे लोगों को मीठा पानी मिल सके। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और कटौती प्रस्ताव को बल देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने जो इस बजट प्रस्ताव पर बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जब मैं मेजा विधान सभा का विधायक बनकर आया। मैं तो सबसे बड़ा आभारी हूँ अपने सिंचाई मंत्री जी का जब विधान सभा का तो मेजा डेम की व्यवस्था मेरे हाथ में थी। बाण सागर का पानी मेजा डेम में आता है और मेजा डेम का पानी मेजा विधान सभा, करांव विधान सभा और करछना विधान सभा को भी पानी उपलब्ध कराता है। मैं जब विधायक बना तो मैंने सोचा कि किस तरह से मैं बाण सागर को चालू कराऊँ। मैं भागते-भागते पहली चिट्ठी लिख करके अपने सिंचाई मंत्री जी के यहाँ पहुँचा, उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि यह बाण सागर है क्या? मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि मैं बाण सागर के लिए व्यवस्था करूँगा और आपने ऐसी व्यवस्था की कि

12-12 इंजीनियरों को सस्पेंण्ड किया इसलिए मैं आपको बार-बार बधाई देना चाहता हूँ कि आपने भ्रष्टाचारियों और अत्याचारियों के ऊपर पहला कदम उठाया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बाण सागर का पानी अढ़वा में आकर मिलता है, अढ़वा का पानी मेंजा डेम में मिलता है और मेजा डेम का पानी आकर के बेलन नदी में मिलता है और बेलन नदी के माध्यम से हमारी नहरें संचालित होती हैं। आज हालत यह है कि जिस तरह से स्वाति नक्षत्र में पपीहा ऊपर देखता रहता है, उसी तरह से हमारी विधान सभा क्षेत्र 40 साल से बाण सागर-बाण सागर चिल्ला रही है। आज तक उसे बाण सागर का पानी नहीं मिला और बाण सागर का करोड़ों-करोड़ रूपया बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और अधिकारियों ने बांट लिया। मैं यह खुला आरोप लगाना चाहता हूँ कि जो बाण सागर है उससे अढ़वा और मेजा डेम की दूरी सिर्फ 30-35 किलोमीटर है। आज वह बंद है, उसका जो पत्थर निकला मिर्जापुर के डी0एम0 और इलाहाबाद के तत्कालीन डी0एम0 ने उस पत्थर को कौड़ियों के भाव बेच दिया। जितने पैसे में अढ़वा बांध बन सकता था, उससे ज्यादा इस पत्थर में घपला हुआ है। मैं अपने सिंचाई मंत्री जी से चाहता हूँ कि वह पत्थर क्या हुआ, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। जो नहरों से पत्थर निकला वह कौड़ियों के भाव में अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर बांट लिया।

देश का और हमारे अढ़वा बाँध का करोड़ों-करोड़ों रूपये का नुकसान हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मेजा डैम से मेजा ब्रान्च निकलती है, मेजा ब्रान्च से हरदिहा रजबहा निकलता है, रामनगर रजबहा निकलता है, माण्डा रजबहा निकलता है, कोरॉव रजबहा निकलता है, इन रजबहों पर उच्चीकरण का काम नहीं किया गया। अगर भगवान ने हम लोगों की सुन लिया और हमारे नेताओं की कृपा हो गई और पानी आ भी गया तो वह जाएगा कहां। नहरों में क्षमतावृद्धि हो नहीं रही है, हमारा पानी जाएगा कहाँ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो नहरें अधूरी हैं जो रजबहे पूरे नहीं किये जा सके हैं उनको भी बनवाने की व्यवस्था की जाए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब भगवान पानी बरसाते हैं तो हमारे डैम में पानी आता है और तब हमारे खेतों की सिंचाई होती है, आज हम संकट में हैं। हमारे यहाँ चाहे उमापुर पम्प कैनाल हो, चाहे खिरसा पम्प कैनाल हो और चाहे हमारे यहाँ यमुना पम्प कैनाल हो किसी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। अगर बाणसागर बाँध ठीक हो जाता तो हमारे यहाँ पम्प कैनाल चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और बाण सागर योजना से हमारे खेतों की सिंचाई हो जाती। मैं आपसे निवदेन करना चाहता हूँ कि बेलन नदी हमारे यहाँ है, उस पर एक बाँध बना दिया जाए और उससे लिफ्ट लगा करके हमारे उस इलाके को सिंचित किया जा सकता है जो सैकेड़ों साल से अंसिचित हैं। मैं सिंचाई मंत्री जी से अन्तिम निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तो वहाँ पर गाड़ियों से पहुँच नहीं सकते, आपका कोई अधिकारी लगातार पाँच-सात

साल से उस डैम पर गया ही नहीं हैं, मैं चाहता हूँ कि एक दिन के लिए आप समय निकाल लीजिए, जो अधिकारी आपके कहते हैं कि 2012 में चला दूँगा, वह झूठ बोलते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वह 2012 में चला सकें, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप एक दिन दौरा कर लेंगे तो पूरी की पूरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, इसलिए मेरा निवेदन है कि एक दिन का समय निकालकर आप उस बाँध तक जाने का कष्ट करें।

श्री अगयस रामसरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग के आय-व्ययक पर कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए जो मुझे अवसर दिया गया है इसलिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ तथा हृदय से आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के नेता मा0 हुकुम सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ कतिपय बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहता हूँ। मान्यवर, जो सिंचाई विभाग की पुस्तिका हमें मिली है उसमें दो प्रणालियों का कोई जिक्र नहीं है नम्बर-1 शारदा नहर प्रणाली और नम्बर-2 शारदा सागर प्रणाली। जबकि यह दोनों प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली हैं। शारदा नहर प्रणाली के अन्तर्गत निगोली शाखा नहर, शाहजहाँनपुर शाखा नहर दो ब्रान्च नहरें हैं। निगोली ब्रान्च नहर में तीन रजबहा और नौ अल्पिकाएं हैं इसी प्रकार से शाहजहाँनपुर शाखा नहर में चार रजबहा और तेइस अल्पिकाएं हैं शारदा सागर प्रणाली के अन्तर्गत बीसलपुर ब्रान्च नहर है जिसमें एक रजबहा तथा सात अल्पिकाएं हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में इन सारी नहरों का छोर अधिकाशतः पड़ता है और मान्यवर, ऐसी कोई नहर नहीं है जिसमें छोर तक पानी पहुँच रहा हो। हमारे यहाँ बीसलपुर ब्रान्च नहर का गोवल रजबहा है जिसमें तीन अल्पिकाएं हैं एक खरगापुर अल्पिका, एक शिवपुरी अल्पिका और बोनी अल्पिका, यह नहरें वर्षों से बन्द पड़ी हैं। इसी प्रकार से बेनीपुर अल्पिका, मुझे लग रहा है कि यह 1995 से लगातार पटी पड़ी है और उस नहर पर जानवर बाँधने और कंडे रखने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार से एक सावेपुर रजबहा है इसमें जसोली अल्पिका है, यह सावेपुर रजबहा भी बन्द पड़ा है और इसकी अल्पिका जसोली में भी पानी वर्षों से नहीं जा रहा है। इन नहरों की सफाई वर्षों से नहीं हुई है इसलिए बीसलपुर शाखा नहर के बहुत कम हिस्से में पानी जा रहा है। मान्यवर, हमारा जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनपद है, जिसमें बाढ़ का प्रभाव प्रदेश के सम्पूर्ण जनपदों से अधिक है।

शारदा से लगभग पचास गाँव प्रभावित रहते हैं और पचासों गाँव कट करके, कोई नहर की पटरी पर बसा हुआ है तो कोई सड़क के किनारे बसा हुआ है जिनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसी तरह एक नदी दियोहा हमारे यहाँ है उस देहुआ नदी से भी लगभग चालीस गाँव प्रभावित हैं और वहाँ भी कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ के लोग सड़कों के

किनारे बसे हुए हैं। एक सिमरिया गाँव है वहाँ के लोग सड़क के किनारे बसे हुए हैं। इसी प्रकार एक गाँव उचसिया है, पूरा का पूरा गाँव कट गया है, शेरगंज धरमगदपुर पूरा का पूरा गाँव कट गया है, लोग दूसरे गाँवों में जा करके रह रहे हैं और उनके सामने आवास की समस्या बहुत कठिन है। हमारे यहाँ कुछ गाँव ऐसे भी हैं जैसे कि एक गाँव पुरनापुर पुरैना गाँव है उसके भी किनारे-किनारे नदी बह रही है और निकट भविष्य में उन गाँवों के कट जाने की सम्भावना है और उन पर जो तटबन्ध भी बनाये जा रहे हैं वह तटबन्ध निर्धारित रूप से न बना करके उनका सारा पैसा हजम किया जा चुका है। मैं माँग करूँगा आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से कि उन पर तटबन्ध तुरन्त बनाये जाएं मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में, बल्कि बीसलपुर नगरपालिका परिक्षेत्र के अन्तर्गत ही तीन-चार एकड़ सिंचाई विभाग की जमीन है और उस पर एक माफिया का कब्जा वर्षों से चला आ रहा है, उस जमीन पर खेती कर रहा है और उसने उस पर भवन भी बना लिये हैं। मैं चाहूँगा कि सिंचाई मंत्री जी उस माफिया के खिलाफ कार्यवाही करें। बीसलपुर ब्रान्च नहर पर से पूर्व में एक मंत्री जी बसपा के थे, जिन्होंने मिट्टी का खनन करके अपना पेट्रोल पम्प पर डाल ली है मैं चाहूँगा कि उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। मान्यवर, हमारे यहाँ एक नहर की कोठी है जिसे गोवल नहर कोठी बोलते हैं। इस नहर कोठी पर भी माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और वहाँ की लकड़ी, पेड़ और जितना मलबा था वह सारा का सारा गायब कर दिया है। अतारांकित प्रश्न के माध्यम से मुझे जानकारी भी मिली है लेकिन अब तक उसके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से मांग करूँगा कि उस माफिया के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मान्यवर, हमारे यहाँ खनन का काम काफी होता है। एक बार मैंने खनन के सम्बन्ध में शिकायत की तो कुछ माफिया किस्म के लोग हमारे पास आये, उन्होंने कहा कि भाई आपने हमारी शिकायत क्यों कर दी है। उन्होंने एक हमें कविता पढ़ करके सुनाई वह मैं बताना चाहूँगाः-

हाथी पर हैं तीन सवार,
दारू, बालू और पुष्टाहार,
जिनके पोन्टी चड्ढा हिस्सेदार,
सबके आनन्द भैया हैं पहरेदार।

तो इस तरीके से हमारे जनपद में भंयकर खनन हो रहा है।.....

(सत्तापक्ष के अनेक मा0 सदस्यों ने आग्रह किया कि वर्मा जी कविता एक बार फिर सुना दीजिए।)

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

हाथी पर हैं तीन सवार,
दारू, बालू और पुष्टाहार,
इनके पोन्टी चड्ढा हिस्सेदार,
सबके आनन्द भैया हैं पहरेदार।

तो इस तरीके से हमारे जनपद पीलीभीत में जो माफिया किस्म के बालू खनन मिट्टी खन्न का काम करते हैं.....

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ यह जो मिट्टी, बालू, बजरी का खन्न होता है, उसका ईंट के भट्ठों पर बहुत सारा ढेर लगा हुआ है। उस सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जाए। मा0 अध्यक्ष जी, मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सिंचाई मंत्री जी के सिंचाई के बजट प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सिंचाई मंत्री जी इस उत्तर प्रदेश के लौह-पुरूष हैं, हरदिल अजीज हैं, विकास पुरूष हैं। पिछली सरकार में माननीय सिंचाई मंत्री के लोक निर्माण मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के नदियों और नहरों पर जो पुलों और सड़कों का निर्माण किया था, वह 63 साल की आजादी में अपने में एक मुकाम रखता है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी के सामने एक शेर पढ़कर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ-

किसी के दिल में उतरना कमाल होता है,
नफस-नफस में बिखरना कमाल होता है।
बुलन्दियों पर पहुँचना कोई कमाल नहीं,
बुलन्दियों पर ठहरना कमाल होता है।

ये हैं मा0 शिवपाल यादव जी, जिन्होंने आज सिंचाई विभाग का अद्वितीय बजट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। मान्यवर, कुछ दिनों पहले हम लोग इसी विधान सभा में सामने की तरफ बैठते थे और इधर बैठे वे लोग जो सत्ता के मद और घमण्ड में चूर थे, इतरा रहे थे। हम लोगों ने लोकमहत्व के, गरीबों, मुफलिसों की आवाज इसी उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उठाना शुरू किया

जो एक ऐसा माहौल बनाया गया कि उत्तर प्रदेश का बजट 7-8 मिनट में पास करा करके सरकार भाग गयी, मैदान छोड़ दिया और बहस करने का मौका नहीं दिया। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस सरकार को, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मुख्य मंत्री जी और उनके मंत्रि परिषद् को और माननीय अध्यक्ष जी, आपको भी। क्योंकि बहुत विद्वता के साथ जनता की उन तकलीफों को ले करके जो सम्मानित सदस्य आये हैं, हर सदस्य को क्रमवार सुनते हैं और उनको अपनी आवाज उठाने का मौका दे रहे हैं इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। सिंचाई विभाग के इस बजट में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मा0 मंत्री जी ने खजाना खोलने का काम किया है। सरकार बनते ही, अभी तो बहुत अल्पायु में यह सरकार है। उत्तर प्रदेश का दौरा करके उन भ्रष्ट और नकारा अधिकारियों को उनके ठिकाने तक पहुँचाने का काम किया है। हमारे पत्रकार साथी हमसे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर अगर सरकार की धमक किसी ने बनाई है तो वह विकास पुरुष, लौह पुरुष मा0 शिवपाल सिंह यादव जी हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, जिस तरीके से राजस्व मंत्री और मा0 सिंचाई मंत्री जी अभी हमारे जिले बलरामपुर के दौरे पर अधिकारियों को ले करके गये थे। कोड़री घाट का पुल है, जो 1991 में बना था लेकिन राप्ती नदी के काटने की वजह से पुल शो-पीस बन करके रह गया। नदी कहीं चली गयी, किसानों का खेत कहीं चला गया। मैं मुबारकवाद देता हूँ राजस्वमंत्री जी को, मा0 सिंचाई व लोक निर्माण मंत्री जी को कि उन्होंने हम लोगों की आवाज को सुना और सुबह 8.00 बजे ही, यहाँ से असेम्बली छूटी थी 5.00 बजे और अगले दिन सुबह 8 बजे हेलीकाप्टर लैंड हो गया। यह है गरीबों का दर्द, यह है सरकार चलाने का तरीका, यह है उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जाने का तरीका उसी दिन उत्तर प्रदेश के तीन चार जिलों में जाकर विकास की तरफ अग्रसर करने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, हमारे मंत्री जी ने उसके लिए मैं उनको बार-बार मुबारकवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र उतरौला से चुनकर आता हूँ वह अध्यक्ष जी आपकी विधान सभा क्षेत्र से जुड़ता है। उसके बीच एक पुल है सिंगार जोत का। उसके एक तरफ इटवा विधान सभा क्षेत्र आपका है इस तरह हमारा क्षेत्र है। मान्यवर, वह एप्रोच टूट गया है। मैं मांग करता हूँ कि उसको जल्दी ठीक करा दिया जाय। जिससे जनता की परेशानियाँ दूर हों।

श्री अध्यक्ष-

वह तो पी0डब्लू0डी0 में आता है।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

मंत्री तो एक ही है। अध्यक्ष जी मेरा विधान सभा क्षेत्र उतरौला जिसे राप्ती नदी पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। राप्ती नदी की वजह से हमारी विधान सभा क्षेत्र की कई

हजार एकड़ फसलें बरबाद हो रही हैं मैं माँग करता हूँ कि हमारी विधान सभा क्षेत्र में राप्ती नदी के किनारे किसानों की गरीबों की जमीन बचाने के लिए बन्धे का निर्माण कराया जाय। यह बहुत ही आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

हमारे विधान सभा क्षेत्र में सरजू परियोजना की नहर के निर्माण का कार्य काफी दिनों से संचालित है पिछली सरकार की अदूरदर्शिता के कारण वह कार्य ठप हो गया है। जो सरयू नहर परियोजना का कार्य ठप कर दिया गया था पुलों का और खुदाई का उसे प्रारम्भ किया जाय। चूंकि बहुत साथी बोलने वाले हैं इसलिए माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी इस पर चर्चा लगभग तीन घण्टे हो गई है बहुत से विभाग बाकी है इसलिए मैं सोचता था कि इस पर मतदान कराकर चर्चा बन्द करा दी जाय। दो सदस्य इस पर और बोल लें उसके बाद आपको बुला लेते है।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मुझे इस पर दो मिनट का अवसर दे दें

श्री अध्यक्ष-

आप रोज तो बोलते हैं। अब क्या रोज बोलेंगे।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी बात रखूँगा।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल जी बैठिए। आपके बाप भी इतनी जिद नहीं करते थे।

श्री राजबली जैसल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भी श्री हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और हमारे इलाहाबाद जनपद में हमारी कोरांव विधान सभा जो पूरी तरह पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। वहाँ पर ज्यादातर लोग वर्षा पर निर्भर रहा करते है। सिंचाई का मात्र साधन एक बेलन नहर प्रखण्ड है उसके अलावा और कोई सिंचाई का साधन नहीं है। मैं

कहना चाहूँगा कि चट्टानी और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते हमारे विधान सभा में एक भी ट्यूबवेल लगने का काम नहीं हुआ जब भी ट्यूबवेल लगने का काम जाता है तो उसको डार्क घोषित कर दिया जाता है और वहाँ एक भी ट्यूबवेल नहीं लग पाया है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इलाके में सिंचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो तमाम पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते जो पहाड़ी नदियाँ हैं उन नदियों में अगर बड़े चेक डैम बना दिए जाएं तो निश्चित रूप से कुछ सिंचाई के साधन हो सकते है जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र में गुरमा नदी है अगर गुरमा नदी में पैतिहा या हरदौन के सामने बड़ा चेक डैम बनाया जाय और चन्दापुर, मानपुर के समाने अगर बड़ा चेकडैम बनाया जाये तो निश्चित रूप से किसानों को सिंचाई की सुविधा हो सकती है। इसी तरह से बेलन नदी ओर टोंस नदी हमारे क्षेत्र में पड़ती है। टोंस नदी में अगर पम्प कैनाल लगा दिया जाये तो निश्चित रूप से किसानों को कुछ सिंचाई की सुविधा मिल सकती है, उसके लिये पहले भी प्रस्तावित गांव शाहपुर और इसौटा के सामने टोंस नदी में एक लिफ्ट की परियोजना लगा दी जायें और बेलन नदी में कड़ेवर और सिरावल ग्राम के बीच में अगर लिफ्ट लगा दिया जाये तो सिंचाई की सुविधा मिल सकती है। सिंचाई हेतु जैसा कि अभी मा0 सदस्य जी ने बताया कि बाड़ सागर परियोजना जो विगत कई वर्षों से लम्बित है जिसकी 2012 में चलाने की पहले से घोषणा थी कि 2012 में उसको चालू कर दिया जायेगा और वह घोषणा काफी पहले की गयी थी लेकिन हमें लगता है कि 2012 में उसको न चालू करके 2014 तक उस योजना को ले जाने का काम हुआ है। अगर बाढ़ सागर की यह परियोजना सही तरीके से लागू हो जाती है तो उस इलाके में पानी के लिये तो तमाम बेलन नहर की माइनरें निकली हुयी हैं उनमें पानी पहुंच सकता है और सिंचाई का साधन हो सकता है। इसी तरह से, हमारी बेलन नहर प्रखण्ड है जिससे उपरौध रजबहा और सुखड़ा माइनर निकलती है वहां पर पानी टेल तक पहुंचने का काम नहीं होता, वहां पहले 1995 में उस उपरौध रजबहा में एक बार टेल तक पानी पहुंचा था उसके बाद आज तक उसमें टेल तक पानी नहीं पहुंचा।

मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूं कि निश्चित रूप से जब नहरों का निर्माण हुआ होगा तो जो भी इंजीनियर निर्माण किया रहा होगा वहां तक पानी पहुंचाने के लिए ही किया रहा होगा। परन्तु आज वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मैं यह भी मानता हूं कि आज पानी की कमी है, चाहे नदियों में, टोंस नदी हो, चाहे बेलन नदी हो पानी की कमी के कारण भी टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है ओर नहरों की तमाम अव्यवस्थाओं के कारण भी पानी टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो हमारी सुखड़ा माइनर है उसका पूर्ण रूप से पुनर्गठन करके उसमें सफाई का कार्य किया जाये और चूंकि विधानसभा पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते सिंचाई की असुविधा होती है।

तमाम हमारे बुन्देलखण्ड के साथी कहा करते हैं कि बुन्दलेखण्ड में पानी की सुविधा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद के यमुना पार के जो शंकरगढ़, माण्डा, कोरांव और मेजा चार विकास खण्ड है। वो किसी भी तरह से बुन्देलखण्ड से कम नहीं है। इसके लिये मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इसकी विधिवत जांच करा लीजिये अगर आपको लगता हो कि बुन्देलखण्ड की तर्ज पर ही यह विकास खण्ड है निश्चित रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में सिंचाई ही नहीं बल्कि विकास के और कार्यों के लिये भी आपको स्पेशल पैकेज देना चाहिए अन्त में कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुंवर कौशल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी, किसान दो चक्कियों के बीच पिसा जा रहा है। जब मन में कुण्ठा होती है हमारी सोच ऐसी होगी कि हमारा मतदाता किसान है ही नहीं तो हाथी को पानी पिलाने की आवश्यकता एक हजार एकड़ के खेतों में पड़ जा रही है पार्क के द्वारा। लेकिन हमारे खेतों में लहसुन और प्याज की सिंचाई करने के लिये पानी देने में विगत सरकारें अक्षम रही है। मेरा यह कहना है आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से कि हम लोग सदन के अंदर आते है तो शपथ पत्र दे करके आते है कि हमारा धन कितना है और हम किस रूप में चुनाव लड़े हैं। लेकिन अगर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को देखा जाये एक पीढ़ी पहले ये क्या थे और कितनी पीढ़ी की व्यवस्था ये कर लिये हैं इसकी जानकारी हमको नहीं मिल पाती और हमारी यह दुर्दशा है कि देश की आजादी के बाद जो भी नहरें बनायी गयीं या जो भी हमारे टयूबवेल विकसित किये गयें आज उसमें से आधे से अधिक खराब पड़े हुये हैं और नहरों की स्थिति यह है कि वे जर्जर हो करके टूट गयी हैं। उसका जीता जागता उदाहरण जनपद महाराजगंज में सबसे बड़ी नारायणी नहर है जिसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था, वो नहर सिल्ट से पट चुकी है और उसी के साथ हमारे यहा रोहिन नहर प्रणाली है और डाण्डा नहर प्रणाली है। आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने सन् 2005 में वहां जाकर पैसा देने का काम किया और उस नहर पर पाया बनाया गया। उस हेड पर कैनाल को ठीक करने के लिये पाया बनाया गया। विगत सरकार में पाया बना और बनने के दो महीने बाद ही ढह गया और मानक के विपरीत बनाया गया वो पाया। आज तक उसकी जांच नहीं हो पायी। आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 70 गांव के किसान उस नहर से वंचित हैं और मै चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो दोनो नहरें है उनको आपके माध्यम से उसमें पैसा भी पड़ा हुआ है। जिन दोषी अधिकारियों ने वहां पर लूट-खसोट का काम किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को सिंचित बनाया जाये। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मैं इस सिंचाई विभाग के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है। इसलिए यहां पर कृषि एवं सिंचाई की उन्नति किया जाना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, मा0 सिंवाई मंत्री जी ने अपने बजट में जो प्राविधान किये हैं उन्होंने उसके द्वारा उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को यह संदेश देने का काम किया है कि हमारा दल जो वायदें करता है हमारी पार्टी ने जो लोगो से गरीबों से वायदे किये हैं उन्हें पूरा करने के प्रति हमारी सरकार गंभीर है और प्रयत्नशील है। मान्यवर, इस सरकार को बने हुए अभी लगभग 10 हफ्तों का समय हुआ है। मा0 मंत्री जी ने उन सभी गरीब किसानों के लिए सभी सुविधायें उपलब्ध कराने की बात कही है जो शायद उन किसानों को पिछले 5 सालों में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में नहीं मिल पायी थी। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र 156 हरदोई की कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेरा जनपद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और कई हैक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित होती हैं मान्यवर मेरा अनुरोध है कि वहां पर हरदोई में बाढ़ खण्ड का एक उपखण्ड बनाया जाये। मान्यवर, लखीमपुर हमारे बगल का जनपद है वहां पर बाढ़ का खण्ड है तो उसका एक सब डिवीजन हरदोई में अगर बन जायेगा तो वहां पर एक अधिकारी उपलब्ध हो जायेगा। मान्यवर हमारे यहां एक मेन्टेनेन्स का खण्ड है जो रजबाहों और नहरों की सफाई का कार्य देखता है अगर वहां पर एक बाढ़ से संबंधित अधिकारी पोस्ट हो जायेगा तो उससे वहां की बाढ़ की सही स्थिति का आंकलन हो जायेगा और उससे जनता को भी राहत कार्य मिलने में सुविधा होगी। मान्यवर, एक शासनादेश हुआ है कि माइनरों की सफाई मनरेगा स्कीम के तहत मैन्युअल आधार पर करायी जाये इसमें कुछ व्यवहारिक समस्यायें आ रही हैं। जैसे हमारे यहां बल्हरा और बज्हेरा माइनरें है। यह बड़ी है। और लगभग 10-10 कि0मी0की है। यह रजबाहों से बड़ी है। तो इनमें मशीनों के अलावा काम होने में कठिनाई होगी इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस शासनादेश के संबंध में आप कृपया अपने अधिकारियों से बात कर लें और जो माइनरें जिनकी लम्बाई 5 किमी0 से अधिक है उनकी मशीनों से कार्य कराने की अनुमति दी जायें।

श्री अध्यक्ष-

अब नितिन अग्रवाल जी आप कृपया बैठ जाये। आप लिखकर दे दीजियेगा। जो मा0 सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले पाये हैं वह लिखकर दे दें कार्यवाही में सम्मिलित कर लिया जायेगा।†

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, ठीक है मैं लिखकर दे दूंगा आप उसको कार्यवाही में शामिल करा लीजियेगा। इसी के साथ प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† (देखिये मा0 सदस्यों के लिखित भाषण नत्थी 'क' आगे पृष्ट 187-189 पर)

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, डिपार्टमेन्ट बहुत महत्वपूर्ण है, किसान से जुड़ा हुआ है। प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है और आज जो माननीय सदस्यों ने चिन्ता दिखाई दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ-साथ विभाग से उन्होंने दुनिया भर की अपेक्षाएं की बोलना चाहते हैं। बहुत लोग, क्योंकि सीधा-सीधा उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ विभाग है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन सभी सदस्यों का चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों जिन्होंने किसी न किसी रूप में मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। किस रूप में किया है, ढेरों समस्याएं हैं हर क्षेत्र में, हर माननीय सदस्य आतुर है कि मैं बोलूँ, मैं अपनी बात को रख पाऊँ। आखिर इतने दिन के बाद में उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाया। मैंने पहले भी प्रश्न किया था अब फिर मैं कह रहा हूँ। माननीय मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करता हूं बहुत दिन तक हम दूसरों की बुराई करके जीवित नहीं रह पायेंगे क्योंकि समय होता है, देश को आजादी मिली बहुत दिन तक हम यही कहते रहे कि अंग्रेजों ने यह किया, अंग्रेजों ने वह किया लेकिन जनता ने पूछना शुरू किया कि आप क्या कर रहे हैं। अब जो कुछ हो गया 5 साल का कार्यकाल चला गया वह। अब हम उम्मीद यह करेंगे कि कार्यकाल तो नया शुरू हुआ है। उसमें हम क्या कर रहे हैं। अगले साल मिलेंगे आप ही सिंचाई मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री न हो पाये तो, तब हम आपसे पूछेंगे एक साल की कालावधि में आपने उन समस्याओं के बारे में जिनका उल्लेख आपने स्वयं यहाँ किया है का कितना समाधान कर पाये कितना नहीं कर पाये। नदियों में पानी बहुत कम होता जा रहा है, नदियों के अलावा नहरों को चलाने का यह तो बड़ा विरोधाभास होगा, बहुत से लोगों ने सुझाव यही दिया और आपके विभाग के जो बहुत ही वरिष्ठ और काबिल इंजीनियर है। वह भी सुझाव देते हैं कि नहर के दोनों तरफ ट्यूबवेल लगा दीजिए और पानी लेकर उसको सप्लीमेन्ट कीजिए यह आगरा नहर में किया आप देखिये जाकर और इतना बड़ा धोखा हुआ कि जब आगरा कैनाल बनाई गयी और देखा कि पानी कम है तो सुझाव यह आया कि इस नहर के पास में नलकूप लगा दिये जायें और नलकूप को चलाकर पानी नहर में डाला जाय। अगर जमीन से पानी लेकर नहर चलानी है।

श्री अध्यक्ष-

यह सुझाव सरयू कैनाल के पास भी आया था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ऐसे-ऐसे सुझाव आयेंगे जिससे कि विभाग कार्य की पद्धति का, कार्यशैली का अनुमान आप लगा सकते हैं। मान्यवर, मैं लोक लेखा समिति का चेयरमैन था तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि कुछ सीख तो लूँ जा करके और जब मैंने उनके नलकूपों को देखा जा करके

उनके कमरे बने हुए थे। अन्दर न मोटर था, न स्टार्टर था और बिजली के बिल निकलवाये तो बिजली के बिल विभाग द्वारा भुगतान हो रहे थे कहीं पर पाइप था एक पाइप नीचे लगाकर उसके ऊपर सील किया था वह खुला हुआ भी नहीं था फिर भी बिजली के बिलों के भुगतान हो रहे थे। यह विभाग का ऐसा दुर्भाग्य रहा कि लोगों ने इसको धोखा ज्यादा दिया अपना योगदान कम दिया। माननीय मंत्री जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि पहले जो पुरानी नहरें हैं जिनके बारे में आपने जिक्र किया और अल्पिकाएं है। माइनर के रूप में हों या रजबहे के रूप में हों, यह सुनिश्चित कर लीजिए जैसा आपने कहा कि टेल तक पानी जायेगा यह सुनिश्चित कर लीजिए कि उनकी मेन्टीनेंस क्या है। आज न जाने कितनी अल्पिकाएं और नहरे आपको मिलेंगी कि पटरी कट-कट कर खेत का हिस्सा बन गयी, उसका वजूद ही नहीं रहा वहॉ पर जाकर जब ऐसा होगा तो पानी कहाँ से जायेगा। मैं दोबारा न कहकर इन्हीं माननीय सदस्यगण के जो सुझाव आये हैं सब कार्यवाही का हिस्सा है क्या यह सम्भव है कि उन सुझावों की समीक्षा कर ली जाय जो जो उन्होंने मांग रखी है। उसको सूचीबद्ध कर लिया जाय और सूचीबद्ध करने के बाद देखें कि किन सुझावों को मान सकते हैं और किन सुझावों को नहीं मान सकते हैं।

क्या यह संभव है, उन सुझावों की समीक्षा कर ली जाय जो जो उन्होंने मॉग रखी है। उसको सूचीबद्ध कर लिया जाय। सूचीबद्ध करने के बाद में देखें कि किनको मान सकते हैं। किनकों नहीं मान सकते हैं। क्योंकि अपेक्षा तो हर एक ने की है, अपने-अपने क्षेत्र की समस्या उनकी है। अगर उनके क्षेत्र की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करा देंगें तो सन्तोष होगा हर एक को कि हॉ हमने सदन में बात रखी थी। कुछ सदस्य तो जानकारी करते हैं कि हम भाषण तो दे रहे हैं, अपनी बात बोल तो रहे हैं उस पर अमल होगा भी कि नहीं। अमल तो एकदम होगा नहीं जा करके। अमल तो तब होगा जब विभाग के मंत्री इसमें रूचि लेंगें और इसकी समीक्षा करेंगें दो महीने बाद, तीन महीने बाद एक बार विभाग के अधिकारियों से पूछ जरूर लीजिये। इतने माननीय सदस्य थे 50 बोले, 60 बोले, इतने बोले उनकी समस्या आई उसका क्या समाधान हुआ और अगर एक पत्र आपने लिखकर डाल दिया। माननीय सदस्य को कि आपने यह समस्या उठाई थी, इसका इतना समाधान हुआ है। मान्यवर, कितना वह कृतार्थ समझेगा अपने आप को कि माननीय मंत्री जी का उत्तर मेरे पास आया है। वह क्षेत्र में जाकर लोगों को दिखायेगा कि मैंने आपकी समस्या उठाई थी। उसका यह समाधान हुआ है। यह संभव है, आप कर सकते है, विभाग आपके पास में बहुत हैं फिर भी समय निकल सकता है। दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कह रहा हूँ नलकूप विभाग आहिस्ता आहिस्ता बहुत से क्षेत्रों में एकदम प्रभावी हो गया है, निजी ट्यूबवेल लग गये हैं। जमीन तो रही नहीं सिंचन के लिये। जहाँ-जहाँ ऐसा है एक अनावश्यक भार है विभाग के ऊपर। डिवीजन बने हुए हैं और डिवीजन के लिये 10 नलकूप नहीं हैं देखने के लिये।

आपरेटर की नियुक्ति हो रही है। जरा इसको जाकर देख लीजिये। बस मैं इतना कह रहा हूँ। कि कटौती के प्रस्ताव पर लगभग अपवाद को छोड़कर सभी सदस्यों ने समर्थन किया, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूँ।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी बहुत से सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं। माननीय हुकुम सिंह जी ने अपने पुराने अनुभव के रूप में भी सुझाव दिये हैं लेकिन हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब व्यवस्था बदल गई है। आपने कुछ कारण पूछे थे तो मेरी नीयत साफ है और हमारी सरकार की नीयत साफ है। थी कुछ लोगों की बदनीयत, उसकी वजह से नहरों में जो काम होना चाहिए था, बाढ़ में जो काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ। शारदा सहायक की बात आपने कही थी। इन्जीनियर लोगों ने पानी खोल दिया तो उसी समय वहीं पर निर्णय ले लिया था। इन्जीनियर इन चीफ सबसे बड़ा अधिकारी सिंचाई विभाग का, वहीं पर निलम्बित हुआ और उसके साथ-साथ सिंचाई विभाग के 17 बड़े अधिकारी और निलम्बित हो चुके हैं। जो लापरवाही करेंगें उनको छोड़ा नहीं जायेगा। 5 साल के अंदर बजट पर चोरी नहीं हुई है। डकैती पड़ी है, सीधे-सीधे डकैती। अगर मेहनत करते क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर थे, डिग्रियॉ थीं, तो चोरी बर्दाश्त की जा सकती थी। लेकिन डकैती चाहे कोई बड़े अधिकारी हों जिसके इशारे पर हुआ है जिसके आदेश पर हुआ है क्योंकि बहुत कमियां थोड़े दिनों में मेरे सामने आ चुकी हैं और यहां तक कि मंत्री के पी0ए0 की स्लिप पर ठेके बांटे गये अब यह सब बन्द हो चुका है, आपको पता भी लग गया होगा। जो पी0ए0 की पर्चियों पर ठेके बांटे जाते थे। काम हो न हो पेमेन्ट हो जाते थे अब अगर मंत्री के पी0ए0 की स्थिति की भी जाँच करा ली जाए, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग का पैसा था नहरों का पैसा था, यह बहुत से हमारे सदस्यों ने कहा बंधों को पक्का हो जाना चाहिए था, पक्का होने का पैसा था, सिल्ट सफाई का पैसा था। जो रजवहा, माइनर, अल्पिकाओं की बात चल रही है। मैंने आदेश दे दिये हैं और मैं सभी सदस्यों से कहना चाहता हूँ जिसके यहां रजवहा, माइनर, अल्पिकाएं जो भी हों दे देना डी0एम0 को, दस दिन के अन्दर दे देना उनकी सिल्ट सफाई से लेकर के पूरी की पूरी नहरें रजवहा सब सफाई हो जाएगी।

(मेजें थपथपाई गई)

और इसके साथ-साथ मान्यवर, मैं हुकुम सिंह जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि टेहरी का पानी देवबंद के माध्यम से, अपर यमुना नहर के माध्यम से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जनपद को दिया जाता है। इससे दिल्ली आगरा को भी पेयजल हेतु पानी दिया जाता है और जहां तक पानी की कमी है। मेरा प्रयास है मैंने योजना भी बना ली है और वैसे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे आप अनुभवी हैं बुजुर्ग हैं हम चाहते हैं आपकी लम्बी आयु हो।

श्री अध्यक्ष-

अभी बाल काले हैं बुजुर्ग नहीं हैं। बाल पके नहीं हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आपके भी काले हो सकते हैं पूछ लो।

(हँसी)

क्योंकि नहरें, यह सही है कि मुगल राज्य में अंग्रेजों के समय से नहरें हम मेन्टेन भी नहीं कर पाए। इसमें हमें अफसोस करना चाहिए। हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं आज के इस बजट पर कि पानी भी बढ़ाया जाएगा और नहरों की मरम्मत से लेकर के, पटरियों से लेकर के और जो नहरों के किनारे किसी समय बहुत अच्छे पेड़ लगे रहते थे। लेकिन अब पेड़ भी नहीं हैं और पानी की वजह से कहीं-कहीं पानी इतना बरसात के दिनों में हो जाता है। फसल लोग बो नहीं पाते हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था जरूरी है क्योंकि हम तो जानते हैं किसानो से मेरा संबंध रहा है। ड्रेनेज की व्यवस्था भी जरूरी है।

इसलिए मुझे पता है कि कब पानी लगता है, मुझे टेल के बारे में भी पता है क्योंकि हमारे यहाँ जो सिंचाई होती थी, हमारा गाँव टेल पर ही था इसलिए हम इसकी हम पीड़ा भी जानते हैं। अभी एक सदस्य ने कहा था कि हेड पर ही पानी नहीं है तो टेल पर पानी कैसे पहुँचेगा। यह सही है कि जब हेड पर नहीं है तो टेल पर कैसे पहुँचेगा, बीच में भी नहीं पहुँचेगा। लेकिन जो हमने कहा है टेल तक नहीं, टेल पर जो अन्तिम खेत होता है, उस तक पानी पहुँचना चाहिए और कल ही हमने मीटिंग बुलाई है, बाढ़ के सम्बन्ध में और जो भी सदस्य 10 दिन के अन्दर सिंचाई के सम्बन्ध में कोई भी परियोजना वह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उस पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे और जितनी भी इस तरह की समस्याएँ हैं, चाहे बुन्देलखण्ड की समस्या हो, चाहे पूर्वांचल के बाढ़ की समस्या हो, चाहे पश्चिम की समस्या हो, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, उस पर हम गम्भीर है और जहाँ तक गंगा नदी की बात है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय गंगा रिवर बेसिन एथारिटी का गठन किया है लेकिन गंगा-यमुना की अविरल एवं निर्मल धारा बनाये रखने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं, वह अधूरे हैं और जो भी किया गया वह न के बराबर है, कुछ किया ही नहीं। इसके लिए हमने पहल की है। गंगा बेसिन मैनेजमेण्ट प्लान तैयार करके अब गंगा की अविरल एवं निर्मल धारा बनाने की कार्यवाही तेजी से शुरू हो गयी है। जब से यह 2 महीने ढ़ाई महीने से यह सरकार आई है तेजी से काम शुरू किया है। इसलिए हम माननीय हुकुम सिंह जी से यही अनुरोध करेंगे कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और आपकी जो भी भावनाएँ हैं, हम उस पर खरे उतरेंगे।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री हुकुम सिंह-

यह तो संयोग की बात है कि मंत्री जी का गाँव भी टेल पर है और मेरा गाँव भी टेल पर है। मान्यवर, कटौती का यह प्रस्ताव संसदीय शिष्टाचार है। मेरे कहने से कोई कटौती नहीं हो गई, यह मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन एक संसदीय परम्परा चली आ रही है, हम इसमें सुझाव भी देते है। मान्यवर, यह संसदीय शिष्टाचार ही है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब तो इस पर मतदान होने जा रहा है।

थोड़ा सा आग्रह है, यह जो सरयू कैनाल है, इसकी शाखा सिद्धार्थ नगर के इटवा और डुमरियागंज तहसील में भी जाती है। होता यह है कि यह पानी देते नहीं है, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ और यहाँ पर बहुत से लोग हैं जान जायेंगे, चूँकि मेरे क्षेत्र का यहाँ बोलने वाला कोई है नहीं, उसमें मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि यह पानी तो देते नहीं और पूरे गाँव की वसूली भेज देते हैं, पूरा गाँव का गाँव रोज तहसील पर प्रदर्शन करता है। इसको आप दिखवा लें कि जिन खेतों में पानी जाये, उन्हीं से वसूले। जब नहर में पानी ही नहीं है, तब भी वसूली जारी रखते है, हमारे लिए बड़ा सरदर्द रहता है। इसको आप दिखवा लें।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जिन गाँवों में अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। जलभराव के कारण जहाँ फसलें नष्ट हो जाती हैं, वह काम मनरेगा से आसानी से हो सकते हैं। केवल नाला खुदवा दें। मान्यवर, मैं दो साल से एक नाले की खुदवाई की बात करता रहा हूँ। मैंने माननीय मंत्री जी को लिखकर भी दिया है। जहाँ पर पैसा भी अतिरिक्त नहीं खर्च होना है। केवल व्यवस्था की बात है। कम से कम 15 गाँव पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। मनरेगा से वह काम करवा दें। एक ट्यूलस से लेकर टिकरा तक हमारे 15 गाँव पूरे जलमग्न हो जाते हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी उसके बारे में कुछ कह दें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी नहीं चाह रहे हैं तो क्या जबरदस्ती कहलावा दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बाढ़ नियंत्रण भी बहुत जरूरी है, बंधा बनना बहुत जरूरी है।

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी आपने इतना वृहद बजट पेश किया। आपने कोई ऐसी पालिसी बनायी है कि प्रदेश में जो नदियाँ

' वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

बहती रहती है और उसका पानी निकल जाता है। उसके लिए कोई वाटर स्टोरेज काम्प्रिहेंसिव प्लान इसका बनावाइये जिससे इसके पानी का स्टोरेज हो सके। एक सुझाव और देना चाहूँगा कि 50 वर्षों से 20 लाख हे0 फ्लड से प्रोजेक्ट जुड़ गया, पूरे प्रदेश की भूमि में। अभी 38 लाख हे0 भूमि और पड़ी है। तो उसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनके लिए फ्लड मैनेजमेन्ट प्लान आप बनाइये। ताकि तीन-चार सालों में पूरे प्रदेश की फ्लड की समस्या का समाधान हो सके। उसी तरह एक बात और कहना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग की 15-20 हजार करोड़ की भूमि नोएडा अथारिटी को ट्रांसफर कर दी और वह करोड़ो रूपये की जमीन थी और वह दिल्ली मे ंथी। क्या नोएडा अथारिटी से वह जमीन सिंचाई विभाग को वापस लेंगे। यदि आप उस जमीन को बेचकर आक्शन करायेंगे तो पूरे के पूरे प्रदेश का पांच साल का मामला उस पैसे से कर पायेंगे। इसी तरह से पिछली सरकार ने नहर को कवर करा दिया। साढ़े चार सौ करोड़ का बजट बनाया है। उसकी भी जांच करा दीजिए। तो मान्यवर, यह मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,27,29,97,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होन वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,76,31,47,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 की आय-व्यय की अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग की मांग पर चर्चा एवं मतदान।

*लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,17,30,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-47 में निरूपित सिद्धान्त के अनुरूप प्रदेश के आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण तद्नुसार मद्यनिषेध की नीति को प्रमुखता देते हुए विभाग सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाय। आबकारी विभाग का लक्ष्य है कि पूर्व पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व अर्जित किया जाय तथा अवैध एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों की बिक्री, उपभोग को हतोत्साहित किया जाय। प्रदेश में मदिरा के व्यवसाय से प्रदेश के राजस्व में आशानुरूप वृद्धि के उद्देश्य से समय-समय पर आबकारी नीति में परिवर्तन, परिवर्जन किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्था में प्रयोगत्मक सुधारों से जहाँ एक ओर राज्य के लिए राजस्व अर्जन होता है वहीं दूसरी ओर जनता को गुणवत्तायुक्त मानक मदिरा की प्राप्ति होती है, जिससे जन स्वास्थ्य, जन-हित सुरक्षित रहता है। वित्तीय वर्ष 2011-2012 में निर्धारित लक्ष्य का 8625 करोड़ था जिसके सापेक्ष 8139.09 करोड़ की प्राप्ति हुई थी, जिसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए रूपया 10070 करोड़ रूपये राजस्व अर्जन का लक्ष्य निर्धारित है, जो कि इसके सापेक्ष में 1715.88 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य से 55.88 करोड़ अर्थात् 3.33 प्रतिशत अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। प्रदेश में मदिरा की ओवर रेटिंग रोकने के लिए प्रभावी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलिता को गम्भीरता से लिया जा रहा है। शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त पुष्टि करा कर जिला आबकारी अधिकारी बरेली तथा जिला आबकारी अधिकारी कन्नौज को निलम्बित भी किया जा चुका है। विभाग के राजस्व वसूली में शिथिलता अथवा प्रभावी पर्यवेक्षण में लापरवाही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बरतने की वजह से पाँच अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संस्तुति की गई है। प्रदेश में मदिरा व्ययवसाय पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने एवं राजस्व प्राप्ति में निरन्तर वृद्धि के लिए सामान्य जन-जीवन के स्वास्थय पर प्रतिकूल प्रभाव बचाने के उद्देश्य से प्रवर्तन कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अन्य पड़ोसी राज्यों से मदिरा की तस्करी की शिकायत मामला प्राप्त होने पर इसके रोक-थाम के उपाय किये जाते हैं। कस्टम में हरियाणा राज्य से तस्करी रोकने हेतु मुख्य सचिव स्तर से पत्राचार भी किया गया है। आबकारी विभाग में वित्तीय वर्ष 2012-2013 में मतदेय पक्ष राजस्व में रूपया 01 अरब 26 करोड़ 78 लाख 31 हजार रुपये मतदेय पक्ष पूँजी में रूपया 02 करोड़ 89 लाख 19 हजार कुल योग रूपये 01 अरब 29 करोड़ 67 लाख 50 हजार रुपये तथा भारित पक्ष में रूपया 20 लाख रुपये का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है। सम्पूर्ण वर्ष के वेतन हेतु। वेतन मद में कुल रुपया 58 करोड़ बयासी लाख 56 हजार रुपये की व्यवस्था है, सम्पूर्ण वर्ष के महँगाई भत्ते हेतु महंगाई मद में कुल 40 करोड़ 58 लाख 97 हजार रुपये की व्यवस्था है, सम्पूर्ण वर्ष के मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता, स्टेशनरी भत्ता एवं वाहन भत्ता हेतु इस मद में कुल रुपया 5 करोड़ 25 लाख 17 हजार की व्यवस्था है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कुल वार्षिक वेतन आदि मदों में कुल रुपया 1 अरब 4 करोड़ 66 लाख 70 हजार की व्यवस्था की गयी है, जो बजट का 80.59 प्रतिशत है। आबकारी विभाग के सुदृढ़ीकारण हेतु अनुमन्य श्रमिकों की मजदूरी हेतु रु0 एक करोड़ 66 लाख रु0 की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 में विभाग की मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु विक्रय किए गए लॉटरी फार्म पर वाणिज्य कर विभाग के द्वारा वैट आहरित किए जाने पर वैट कर की प्राप्ति हेतु 5 करोड़ 92 लाख रु0 की व्यवस्था की गयी है। विभागीय वाहनों एवं संविदा पर वाहनों के डीजल पेट्रोल हेतु 4 करोड़ 35 लाख रूपये की व्यवस्था है। विभाग के समस्त कार्यालय व्यय हेतु 1 करोड़ 40 लाख रुपये तथा टेलीफोन व्यय हेतु 64 लाख रुपये, विद्युत व्यय हेतु रु0 22 लाख रुपये जलकर हेतु 22 लाख रुपये तथा गृह कर हेतु 16 लाख रुपये की व्यवस्था है। विभाग के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों की सम्पूर्ण वर्ष की यात्रा भत्ता हेतु रू0 22 लाख, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता हेतु 21 लाख रुपये, चिकित्सा हेतु 65 लाख रुपए एवं अवकाश सुविधा हेतु रु0 2 लाख 50 हजार रुपये तथा प्रशिक्षण हेतु रु0 13 लाख की व्यवस्था की गई है। विभाग के निष्प्रोज्य वाहनों के प्रति स्थानीय वाहनों के क्रय हेतु 87 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है। विभाग के विविध व्यय हेतु 40 लाख रुपये तथा लेखन सामग्री के क्रय हेतु रु0 36 लाख रूपये, फर्नीचर के क्रय हेतु 24 लाख रुपये, प्रकाशन हेतु 2 लाख रुपये, मशीनों और उपकरणों के क्रय हेतु रु0 5 लाख, औषधि तथा रसायन के क्रय हेतु रु0 3 लाख तथा अन्य व्यय हेतु 3 लाख 10 हजार तथा गुप्त सेवा हेतु रु0 पाँच हजार की व्यवस्था की गयी है। विभाग के कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर क्रय हेतु रूपया 11 लाख की तथा इनके अनुरक्षण

हेतु 50 लाख की व्यवस्था की गयी है। विभाग के सरकारी कार्यालय हेतु उसके अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु 25 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। विभाग के व्यवसायी कार्यालय एवं उसके अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु 10 लाख की व्यवस्था की गयी है। विभाग के सरकारी कार्यालय हेतु उनके वृहद निर्माण हेतु 2 करोड़, 26 लाख, 94 हजार रु0 की तथा इन कार्यालयों में गोदामों में लघु निर्माण हेतु रु0 62 लाख 25 हजार रूपये की व्यवस्था पूँजी लेखा के अन्तर्गत की गयी। विभाग में मोटर क्लेम भुगतान के अन्तर्गत 20 लाख की व्यवस्था की गयी, तो यह सब व्यवस्था है।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अंबिका चौधरी)-

इतनी अच्छी व्यवस्था है। इसके बाद भी अगर मा0 सदस्य कोई और व्यवस्था चाहते हो तो बता दें। अलग जाकर बता दें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कटौती का प्रस्ताव कौन रख रहा है, मा0 नेता प्रतिपक्ष आप रख रहे हैं तो उठिए और बोलिए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मा0 सदस्य श्री जय प्रकाश जी प्रस्ताव रखेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह कटौती रखे यह इनका अधिकार है मान्यवर, आपने अनुमति दे दी है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ लेकिन प्रदीप माथुर जी, जितना नाराज हो रहे हैं इन पर कटौती रखने के कारण, चेतावनी देना मेरा काम है, बाकी रिस्क उठाना आपका काम है।

(श्री जय प्रकाश, माननीय सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव रखने हेतु खड़े होने पर)

मान्यवर, माननीय सदस्य कटौती रखे, यह इनका अधिकार है। आपने अनुमति दे दी, मैं कैसे मना कर सकता हूँ लेकिन प्रदीप माथुर जी कटौती रखने के कारण इन पर कितना नाराज होगें, यह चेतवानी देना मेरा काम है, बाकी रिस्क उठाना इनका काम है।

श्री अध्यक्ष-

प्रदीप जी की बांतों से आप पूरी तरह अवगत हैं, इसलिये आगाह कर रहे हैं।

*श्री जय प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मै आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचला करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी राजस्व मंत्री जी ने माथुर जी के ऊपर कहा है, मैं तो शायद कटौती प्रस्ताव रखता भी नहीं और मै रखना भी नहीं चाहता था लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी जो आबकारी मंत्री है, बहुत पुराने और अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं तो इसका समय भी नहीं समझ पाया कि इसका समय कब होता है, लेकिन इन्होने इसे बहुत पहले रख दिया, इसलिये इस समय कटौती प्रस्ताव रखना आवश्यक हो गया।

श्री अध्यक्ष-

आप इसका समय समझते है न?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हम शाम को इनको निमंत्रण दे रहे हैं।

श्री जय प्रकाश-

मान्यवर, आपने मुझे आबकारी विभाग पर कटौती के संबंध में बोलने का मौका दिया है, मैं आपका आभारी हूँ। मैं बजटीय आंकड़ों में नहीं फंसना चाहता क्योंकि हमारे राजस्व का बहुत बड़ा श्रोत आबकारी विभाग है। राजस्व का सबसे बड़ा विभाग सेल्स टैक्स है और व्यापार कर के बाद आबकारी विभाग का नाम आता है जो दूसरे नम्बर पर सबसे बड़ा माना जाता है। मान्यवर, इस प्रदेश के राजस्व की सबसे ज्यादा प्राप्तियां होती है वह इस विभाग से ही होती है इस विभाग के बाद ही और कोई विभाग है जिससे इतना राजस्व आता है। यह हमारे आय का मुख्य श्रोत है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ इस सदन में, कि जो इस देश के महापुरूष है, महात्मा गांधी जी, जिनका फोटो इस सदन में लगा हुआ है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसका बहुत व्यापक प्रचार नहीं होना चाहिये। उनका बस चलता तो उनकी इसको बंद करने की मंशा थी। उन्होंने सम्पूर्ण बंदी की बात कहीं थी लेकिन हमारी कमी है कि राजस्व के लालच मे हम इसे बढ़ाते चले जा रहे है इस पर हम अंकुश नहीं लगा पा रहे है। ऐसे-ऐसे गांव में दुकानें खुल गयी है, जहाँ इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। जहाँ इसके कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। परिणाम क्या हुआ कि विवाद बढ़ता जा रहा है और उस विवाद में हम सब लोग फंसते जा रहें है। मान्यवर, इसलिये इसकी जहां आवश्यकता हो, वहां दुकान चलाना चाहिये। यह गरीब बस्तियों में, इटीरियर इलाकों में इसको नहीं चलाना चाहिये। सब जगह दुकानें खोलकर के, जो नहीं पीना जानते थे उन्हें भी इन्होंने पीना सिखा दिया, पियाऊ बना दिया। अब अपने भाषण में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह दवा के काम आती है। इन्होंने तमाम योजनायें बढ़कर सुनाई, कहां-कहां किस मद में खर्च करते हैं, वह बताया है। यह दवा के काम आता है इसी बहाने हर आदमी कहीं न कही पीता है, अगर उसे यह बात दी जाये कि इसमें शराब है तो बहुत आदमी दवा खाना भी बंद कर देगें। अपने जीवन को बरबाद करने के लिये कई जगहों

पर दुकानें खुलवा दी हैं। मैं चाहता हूँ कि आबकारी के बजाय आप दूसरे श्रोतों से राजस्व बढ़ाने का काम करें। मान्यवर, आबकारी विभाग में दो विभाग आते है। माननीय मंत्री जी एक विभाग से कहलवाते है कि पीना बंद करो और दूसरे विभाग से कहलवाते है कि दुकान चलाओ। अब ऐसी बड़ी विडम्बना है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आबकारी विभाग में एक विभाग पिलाता है तो दूसरा पीने से मना करता है। किसी भी जिले में आप देख लीजिये जहां आबकारी विभाग है, वहीं पर मद्य निषेध विभाग भी है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी व्यवस्था आप करिये कि जिस तरह आप मुनाद करके शराब बिकवा कर राजस्व अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं उसी तरह से इसको रोकने का भी प्रयास करिये ताकि आम लोगों की जो निरीह मौतें होती है, उस पर रोक लगाई जा सके। मान्यवर, ग्रामीण अचंलों में नदी के कछार में शराब बनाने की परम्परा बढ़ गयी है। इसको रोकने की जरूरत है आपने दुकान किसके लिये खोली है जो 500 रूपये कमाता है, वह 300 रूपये की शराब पी लेता है तो कुछ नहीं जाता। लेकिन मान्यवर, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति अगर 100 रुपया कमाता है तो उसमें अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिये शाम को मूली वाला झूम और शराब की बोतलें खरीदता है और उसको उसका पैसा उस बोतल पर चला जाता है तो इस प्रकार के संस्कार को आप बढ़ावा दे रहे हैं, यह आप चरित्र बना रहे हैं या चरित्र बिगाड़ रहे हैं। अगर चरित्र बना रहे हैं तो राजस्व का कहीं और से इंतजाम करिये इससे काम चलने वाला नहीं है। राजस्व की व्यवस्था बढ़ाइये।..... माननीय मंत्री जी आप राजस्व की व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश करिये इससे काम चलने वाला नहीं है। आने वाली पीढ़ी को विकृत न करिये। यह चरित्र आदमी का ही जाता है, बड़े तो आराम से बैठ करके ए0सी0 में पीते हैं। इसलिए छोटी दुकानों को आप हतोत्साहित करें। इस पर गम्भीरता से ध्यान दें। इसके अलावा गाँवों में जो शराब बनाने की परम्परा है इसको भी रोकने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री जय प्रकाश-

मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा में दो थाने आते हैं, दोनों थानाध्यक्ष, मैं एक अनुमान लगाता हूँ कि लगभग तीन से चार लाख रूपये तक महीने में हफ्ता वसूली करने का काम करते हैं। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और गरीब परिवार का व्यक्ति था, उससे जो हफ्ते की धनराशि तय थी उससे बढ़ाकर माँगने का जब काम किया गया। वह आदमी पढ़ा लिखा कम था उसने मुझसे पूछा कि मा0 विधायक जी पहले हम इतना देते थे आज पुलिस वाले मुझसे इतना माँग रहे हैं, क्या इसका टैक्स बढ़ गया है?

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री जय प्रकाश-

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इसको बढ़ावा मिल रहा है, इसको रोकने का प्रयास करिये। मैं आपका ध्यान शराब माफियाओं की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आता हूँ गोरखपुर से सटा हुआ बिहार का इलाका आता है। मान्यवर, राजस्व की हानि इतनी होती है कि जो दूसरे प्रदेशों से तस्करी करके शराब, चरस, गांजा की तस्करी करके अपने प्रदेश में ला करके बेचने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए सरकार डाल डाल चलती है तो शराब माफिया पात पात चलते हैं। शराब माफिया ठेके लेते तो वह अपने लोगों के घरों में भट्ठियाँ खुलवाते हैं और उनमें अल्कोहल डालते हैं तथा तमाम विषाक्त चीजों को डाल करके शराब तैयार करवाते हैं और उन निरीह गरीब समाज के लोग उसको पीकर के परलोक सिधार जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अब खत्म करिये, आगे और बड़ा बजट है।

श्री जय प्रकाश-

मैं माननीय मंत्री जी से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग उस देश के इंसान हैं जहाँ पर महात्मा गाँधी, बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जैसी महान विभूतियाँ पैदा हुई हैं। यह गंगा-यमुना की संस्कृति है जो दुनिया को शान्ति का संदेश देती है, जिन्हें देखने के लिए विदेशी तरसते हैं, जहाँ मानवता और इंसानियत बसा करती है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि शराब का ठेका, भांग का ठेका, बीयर का ठेका होता है लेकिन शराब की दुकानें व्यवहारिक रूप से देखें बगैर गाँजा के नहीं चलती। गाँजा की बिक्री और तस्करी काफी मात्रा में पूरे प्रदेश में हो रही है और इतना हो रही है कि पुलिस भी किसी न किसी आदमी को पकड़कर लेती है और नाजायज ढ़ग से गाँजा में चालान कर देती है। पुलिस कहाँ से पाती है गांजा और 10 लीटर कच्ची शराब के कारण ले करके चालान करती है और मुकदमा दर्ज हो जाता है।

श्री योगेश प्रताप सिंह-

माननीय सदस्य ने बहुत बढ़िया पढ़ा है, गांजा, भांग, शराब सारी चीजें आ गयी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य- यह जितनी जल्दी खत्म कर देंगे उतनी जल्दी यह लोग जाकर मस्त हो जाएंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी अभी जो सदस्य कटौती प्रस्ताव रख रहे थे सदस्य को अपनी पीठ से बार-बार आवाज दे रहे थे कि माननीय सदस्य हो गया रहने दीजिए लेकिन ऐसा लगा कि

उनके ऊपर बिल्कुल चढ़ गई है। मान्यवर, जब चढ़ती है तो आप हमारे संरक्षक हैं और सबसे ऊँची पीठ पर है लेकिन जब चढ़ जाती है तो यह होश नहीं रहता है कि कौन क्या बोल रहा है। आबकारी विभाग जिनका बंदोबस्त करता है अपने राजस्व के लिए उसका असर तो सबेरे तक उतर जाता है लेकिन मान्यवर कुछ ऐसी चढ़ती है जो पाँच साल तक नहीं उतरती है। और जब उतरती है तो गली की नाली में आदमी मिलता है। बड़ा बुरा असर होता है उसको आबकारी विभाग नहीं देख रहा है। मैं अनुभवी ही नहीं बहुत सारे गिरे हुए लोगों को सबेरे तक उठाकर ले जाने का काम करता हूँ। बड़ा तर्जुबा है। अध्यक्ष जी एक बड़ा भारी भ्रम है आबकारी विभाग पर जब चर्चा आती है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

हमारी पार्टी की सदस्या श्रीमती सीमा द्विवेदी जी दो घटनाएं शराब के संदर्भ में कल हुई है उसके सम्बन्ध में एक मिनट मे अपनी बातें कहना चाहती है।

श्री अध्यक्ष-

वह नियम-301 में दे देंगी उसका जवाब चला जाएगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, विमला जी को भी शराब के सम्बन्ध में कोई तर्जुबा होगा इसलिए उनको जरूर सुन लें।

साध्वी निरंजन ज्योति-

इसलिए महिलाएं खड़ी हो रही है कि जिन बच्चों के हाथ में कापी और पेन होना चाहिए था जिन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए गाँव-गाँव में शराब का ठेका खुलने के कारण बच्चे बरबाद हो रहे हैं विकास का रास्ता रूक रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी एक बहुत गम्भीर बात यह है कि राजस्व अर्जन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है आबकारी विभाग और जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि हम इतना व्यापार कर विभाग से, आबकारी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्ट यह राजस्व अर्जन के चार मुख्य विभाग हैं वैसे तो राजस्व अन्य विभागों से भी थोड़ा थोड़ा आता है। लेकिन मुख्य रूप से यह चार महकमे हैं सदस्य ने कटौती रखते समय कहा कि गाँधी जी चाहते थे कि कम हो जाय। गाँधी जी पूरी तरह से शराबबंदी के पक्ष में थे। और गुजरात में जो बात लागू की गई उसके दुष्परिणाम दूसरे हैं। आप में से कोई भी गुजरात जाएगा और जो ब्रांड ढूंढेगा जो ब्रांड मांगेगा वह ब्रांड आपको उपलब्ध होगी। कहने को कागज पर शराब बंदी है। लेकिन शराब बंदी नहीं है। आन्ध्रप्रदेश में इस फार्मूले को लागू किया दूसरे प्रदेशों में लागू हुआ हिन्दुस्तान के कई प्रदेशों में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई लेकिन बाद में इस फैसले को वापस

लेना पड़ा हरियाणा में बहुत बेइज्जत होकर इस फैसले को वापस लेना पड़ा । आबकारी विभाग को जो काम करना चाहिए वह दूसरी बात है। शराब का नाम आता है तो आबकारी विभाग का नाम आता है तो अचानक लोगों के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। और कुछ लोगों की जीभ होंठ पर चलने लगती है। एक जो मुस्कुराते हैं दूसरे जिनकी प्यास तेज होती है उनकी जीभ सूखे होठों पर घूमने लगती है। मै इन दोनो से अलग हटकर दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ। आबकारी विभाग को सिर्फ शराब से जुड़ा महकमा समझना बहुत बड़े भ्रम की बात है। जहाँ आवश्यकता इस बात की है पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें चीनी उद्योग के रूप में एक बड़े उद्योग का हमारे प्रदेश में होना और उस उद्योग का जो बाइप्रोडक्ट है दूसरी जगहों पर जो उत्पादन हो रहा है। इसके ऊपर इण्स्ट्रियल स्प्रिट और इंडस्ट्रियल एल्कोहल बनाने पर अगर कदम मजबूती से आगे बढ़ाया जाय हमारी सरकार अभी दो ढाई महीने की सरकार है हम इसमें बजट लेकर आये हैं सम्भव है कि अगली साल जब बजट आए तब तक स्थितियाँ बदली हुई हों आबकारी विभाग में एक बड़ा हेड आपको नजर आए जो पेय मदिरा से प्राप्त न होकर दूसरी तरह से एल्कोहल और स्प्रिट से प्राप्त हो सके जिसकी आवश्यकता है। किन्तु इन सारी चीजों के बजाय सिर्फ एक बिन्दु पर ले आ करके अपने को, रोक करके समझ यह दिखाना कि नहीं अब तो बात शराबखाने की होने लगी। ये बात सही नही है आबकारी विभाग को पूरी तरह से सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। जैसा मा0 मंत्री जी ने बजट प्रस्तुतकरते समय शुरू में ही कहा कि हमारी सामान्य नीति यह है कि लोग नशे के आदी न बनें, मद्य निषेध विभाग भी चलाते हैं। नशे के आदी भी न बनें और इसके दुष्प्रभाव भी न हो, सामान्य नीति है, इसको पूरी तरह से कण्ट्रोल नही कर सकते। इसके दुष्प्रभाव तो आ ही रहे हैं लेकिन इसके साथ आवश्यकता यह है कि फिर भी अगर शराब पीनी है लोगों को और हमको राजस्व उससे आना है तो उनको शराब के नाम पर जहर न परोसी जाये। पिछले 5 सालों मे मान्यवर, इस नाजायज शराब के चलते जितनी मौते हुयी हैं, कीर्तिमान है क्योंकि उतनी ज्यादा शराब से मौतें देश मे कभी इन 5 सालों में नही हुयी हैं और माफियाओं को प्रश्रय देने का जो काम हुआ मान्यवर। भूमाफिया जमीन खरीदने के लियें लोगों का दारू पिला करके और इस स्थित में ले जाना चाहते थे, बनारस में इतनी गम्भीर घटना हुयी जिसमें 30, 35 लोगों की मृत्यु हो गयी और कितने लोग स्थायी रूप से अंधे और अपंग हो गये और वो सारा खेल माफियाओं का था। इन माफियाओं की मान्यवर, एक बड़ी विचित्र बात है। शुरू में बड़ा ठण्डा रहा, बीच में गरम हो गया फिर ठण्डा हो गया और असली कथा यह थी मान्यवर कि पहले जिनसे हिस्सा था, मेरी हिम्मत नही है लेकिन मा0 मंत्री जी शायद नाम जांच-वांच करा करके जब थोड़े दिन बाद रिपोर्ट ले आयेंगे तो पेश करेंगे कि कौन-कौन लोग उसमें शामिल थे मान्यवर। सबसे ऊँचे स्तर पर जिनका नाम था, सूबे में जो तीन लोग जाने जाते थे त्रिमूर्ति, उस त्रिमूर्ति में से एक तो सीधे उसमें इन्वॉल्व थे

और उस माफिया के चलते, उस इन्वॉल्वमेण्ट के चलते बनारस में वो घटना हुयी और लोग मरे। पूरे प्रदेश में ये घटनायें हुयी । मा0 मंत्री जी ने जो बात कही है आबकारी विभाग के सम्बंध में वह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कच्ची शराब बनाने के नाम पर जो जहरीली शराब मान्यवर जो चोरी होती है स्प्रिट की मेथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल ये समझे बिना और दूसरे को भी समझ लेना शराब और ले जाकर के लोग पीते हैं और मर जाते हैं। उन नियंत्रण करने का काम जो सस्ती शराब आती है और इण्डस्ट्रियल शराब जो आती है उसको भी मदिरा में मिला करके बेच देना कि ज्यादा कोई दिकक्त नही आयेगी। और उस सब के अलावा तस्करी से ले आ करके जिसका कटौती प्रस्ताव रखने वाले मा0 सदस्य ने स्वयं जिक्र किया, उन सारी चीजों पर नियंत्रण रखने के लिये आबकारी विभाग के माध्यम से सम्पूर्ण राजस्व की वसूली हो और पेय मदिरा के नाम पर लोगों को जहर न परोसा जाय, नशे तक सीमित रहे मान्यवर इसका समुचित प्रबन्ध करने का काम सरकार ने किया है और उन प्रबन्धों को मा0 मंत्री जी ने गिराया है। अब ज्यों इसका जिक्र आता है मान्यवर लोगों की बात बिल्कुल बदल जाती है, वक्त बिल्कुल बदल गया है। पहले बहस होती थी तो सचमुच लगता था कि ये उसके पक्षधर है ये उसके मुखालिफ है। अब वो दौर बदल गया है मान्यवर ।

''अब मैं की मजमस्त में तकरीर नहीं होती,

अब मैं की मजमस्त में तकरीर नहीं होती,

अब तो वाइस भी साकी के शीशे में उतर गये।''

मान्यवर आज बहुत बड़ा संकट है, ऐसा नही है कि जब शराब पर बात चलती है। मान्यवर यह बहुत कमबख्त चीज है, यह बहुत कमबख्त चीज है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

आप उनकी तरफ इंगित करके क्यों कह रहे है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ऐसा नही है, मै तो केवल एक बात कर रहा था कि अफसोस होता है कि जब केवल इस बजट का विरोध करते हैं, तो उसके साथ-साथ लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव भी आने चाहियें। यदि किसी ने कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है या कोई सुझाव दिया है तो हमारे लिये अच्छें ही हैं। हम यह भी चाहते हैं कि कटौती के साथ इस सदन में महत्वपूर्ण सुझाव भी आयें जोकि हमारे लिये बहुत आवश्यक है। हम अवश्य उसकी ओर ध्यान देते हैं। मैं केवल सरकार की ओर पक्ष रख रहा हूँ मैं इस बात का कभी पक्षधर नहीं हो सकता कि शराब की दुकान किसी धार्मिक स्थल, जैसे मंदिर, स्कूल, कॉलेज, लड़कियों के कालेज के पास खुले जिससे उनको परेशानी हो अथवा शराब की दुकाने ऐसी जगह पर हो जहां पर आवासीय

बस्तियां हो और जिससे वहां के रहने वाले लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़े। अगर उसके पास कहीं पर शराब की दुकान खुल रही है और आपके पास शिकायत है कि वह नियम विरुद्ध है। तो सरकार उसमें मुकम्मल कार्यवाही करेगी। मान्यवर, जो नीतियां हैं उनका हम नियमन करायेंगे। कहीं पर अगर शराब माफिया कोई इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं तो हम बता दें कि अब शराब माफियों का धन्धा बन्द, उत्तर प्रदेश में।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, सरकार राजस्व बढ़ाने के लिये उपाय करेगी और उसका नियमन करेगी। मान्यवर हमारा इस बार का लक्ष्य 10 हजार 30 करोड़ का है। यह शत प्रतिशत वसूल हो और इससे ज्यादा भी हो इसका हम उपाय करेंगे। मान्यवर, अभी आप लोग लोक निर्माण विभाग में सड़कों और पुलों की मांग कर रहे थे बिजली विभाग के बजट में खम्भों की मांग कर रहे थें सिंचाई विभाग में यह मांग कर रहे थे कि अल्पिकाओं में पानी दिलवा दिया जाये। तो इसी तरह की मांग न करने लगियेगा धोखे में कि यह आबकारी विभाग का बजट है। हम चाहते हैं कि राजस्व बढ़ाने के लिये आपके सार्थक सुझाव आयें। मान्यवर हमारे यहां शराब पर कई बड़े लेखकों और कवियों ने अपनी बातें कही हैं। जिनमें हरि शंकर राय बच्चन, फिराक जी, नीरज जी आदि।

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका उद्देश्य है सुझाव देना। इसमें आप सुझाव दें कि कैसे इस लच्छित राजस्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसे बढ़ाया जा सकता है।

मान्यवर, शराब के नाम पर मौते भी होती हैं। हमारी सरकार की कोशिश होगी कि वैसी जहरीली शराब न बनने पाये। अभी उद्योग विभाग का बजट आने वाला है। इसलिये अपनी बात को नियंत्रित करते हुये यही कहना चाहता हूं कि आप सब के सुझाव आमंत्रित हैं। मान्यवर, यहां पर तो यह दृश्य भी देखने को मिला है पिछली सरकार में जब 17 मिनट में पूरा सत्र समाप्त हो गया यह एक रिकार्ड है। मान्यवर, अभी दुर्भाग्य है कि कल मशहूर शायर मेंहदी हसन जी दुनिया से उठ कर चले गये। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अगर शराब महंगी लगती है तो थोड़ी-थोड़ी पिया करो। इसलिये मेरा कहना है कि शराब को लेकर ज्यादा बेचैन न हों और परेशान न हों। मान्यवर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके अलावा भी आय सुझाव दे सकते हैं। मान्यवर, इस शराब से ज्यादा प्रभावित महिलायें होती हैं। क्योंकि घर में कोई पी कर आ गया तो गालियां देता है या मारता है। तो वह संगठित होकर बहुत जगह आगे भी आयी हैं और दुकानें बन्दी भी करायी हैं। उनका यह मानना होता है कि यह चीज ही उनके परिवार की तबाही का कारण बन रही है। माननीय सावित्री बाई फुले जी आप तो साध्वी हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर कोई बात जरूरी है तो ले लीजिये अन्यथा मतदान कराइये इसमें कुछ बहुत बचा नहीं है और माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्रीमती सीमा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय न मेरा और न मेरे मतलब का है और मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगी कि दुनिया में अगर मुझे किसी चीज से नफरत है तो वह नफरत है नशे से, शराब से। हम लोग मान्यवर, क्षेत्र में जाते हैं गांव में जाते हैं, गावं की महिलाओं की पीड़ा को देखते हैं उनके भूखे प्यासे बच्चों को देखते हैं तो आंख से आसू निकल आते हैं। सब्जी बेचने वाली पत्नी का पति रात में जब शराब पीकर आता है तो दिन भर की कमाई को छीन लेता है। ठीक है, आपकी नीति है, आपको सरकारी राजस्व में वृद्धि प्राप्त हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है। और मुझे कभी-कभी हंसी भी आती है जब यह कहा जाता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। खुलेआम चौराहों पर इसकी अच्छी-अच्छी दुकाने हैं एक दुकान खुली है उसके बगल में एक और दुकान खुल गयी है यह सरकार की व्यवस्था है इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं हम इसमें दो बातों का जिक्र करना चाहते हैं। मैं जहां से चुनकर आती हूं मुगराबादशाह विधान सभा से उसमें सुजानगंज ब्लाक है वह बहुत ही पढ़ा लिखा एजूकेटेड क्षेत्र है ऐसा सभी लोग जानते होंगे। दिनांक 9.6.12 को सुनहिता जोकि सुजानगंज बाजार में आती है उस दुकान को एक राजेश उर्फ गुड्डू के नाम से दुकान आवंटित हुई है राजेश गुड्डू, विजय शंकर जायसवाल, सुभाष जायसवाल, शम्भू नाथ, विमलेश सरोज, प्रदीप सरोज। इन लोगों ने मान्यवर, मध्य प्रदेश से और दूसरे-दूसरे प्रदेशों से एक नहीं कम से कम 10 ट्रक दारू ले आ करके रात में उतारे हैं और शराब उतारे कहां हैं अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस वालों को सूचना मिली, एस0टी0एफ0 वाले आये पूरा छापा पड़ा मान्यवर, और बहुत अच्छी संख्या में शराब वहां बरामद हुई। उनके खिलाफ तो मुकदमें हो गये जो वहां से शराब लेकर बेचते थे लेकिन जो जिले में शराब बिकवाता है जिला आबकारी अधिकारी जिसके दिशानिर्देशन में यह काम होता है उसके खिलाफ न कोई कार्यवाही हुई न उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया और मान्यवर, यह खत्म भी नहीं हुआ था कि हमारे सुजानगंज में दिनांक 12.6.2012 को एक घटना और हो गयी, समाजवादी पार्टी का एक नेता, नाम नहीं लूंगी वह 2-3 बार से वहां से जिला पंचायत का मेम्बर है, उसकी गाड़ी में 50 पेटी दारू पकड़ी गयी, वह मुल्जिम बनाया गया उनके साथ 3-4 और लोग मुल्जिम बनाये गये। आज जब मैंने पता लगाया उसकी दुकानें सीज हुई कि नहीं, उसके खिलाफ कार्यवाही हुई कि नहीं तो मुझे बताया गया कि उसके खिलाफ मुकदमा तो लिखाया गया है लेकिन अभी तक उसकी दुकान सीज नहीं हुई है। मान्यवर, और विडम्बना है कि जब मैंने पता किया और लोगों से तो वह आदमी जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है वह आदमी जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में बैठकर पैसे की लेनदेन करके अपने को निकलवाने की

बात कर रहा है। मान्यवर, ऐसी बातों को आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं और आग्रह करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ अगर कार्यवाही हुई है जो लोग निर्दोष है जिनको यह नहीं पता है कि शराब लेकर बेचने से क्या होता है उनके ऊपर इतने बड़े-बड़े मुकदमें लादे गये। मान्यवर, कैसे यह बात मानी जाय कि इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएं हो जाये और हमारे जिला आबकारी अधिकारी की जानकारी में न हो, इंसपेक्टर को जानकारी में न हो यह बात गले से नीचे नहीं जाती। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

(श्री सुलतान बेग द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

सुलतानबेग जी आप इसमें कहां से फंस गये।

श्री सुलतान बेग-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव बल देते हुए कहना चाहता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे विधान सभा क्षेत्र की है यह ग्राम गौतारा थाना व ब्लाक फतेहपुर पश्चिमी मस्जिद के सामने शराब की दुकान खुली हुई है और जब जुमे की नमाज पढ़कर लोग निकलते हैं तो नमाजियों से अभद्रता होती है, गाली-गलौज होती है, मारपीट होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि इस दुकान को बन्द करा दें वर्ना कभी भी शांति भंग हो सकती है।

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

जामा मस्जिद के बगल में यह दुकान खुली कब है ?

जामा मस्जिद के बगल में यह दुकान खुली कब है ? इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अरे जांच करा लेना, कब खुली दुकान। अब कुछ नहीं। मद संख्या 12 ले रहा हूं।

श्री सुल्तान बेग-

वहां पर दुकान खुली है, नमाजियों से अभद्रता हो रही है। बदतमीजी हो रही है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत संजीदा बात है। बहुत संजीदा बात है, कोई शक नहीं और सरकार की प्राथमिकता है जैसा कि अम्बिका जी ने कहा विद्यालयों के पास, धार्मिक स्थलों के पास, धार्मिक स्थल का मतलब मंदिर, गुरूद्वारा गिरजा और मस्जिद भी है। आपने जो सवाल उठाया उस पर माननीय अध्यक्ष जी आपकी पीठ से यह सवाल हुआ कि अरे आप और शराब! जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता दें जहां पर खुदा न हो। आपके इस सवाल के जवाब में जो जवाब आया या सवाल आया वह टाल देने का नहीं

हैं मान्यवर, उस सवाल को सिर्फ इसलिये कि आपने बात कह दी और इधर से भी बात कह दी गयी। बुनियादी बात यही है कि हमें जो कुछ मिला है, उमसें क्या सही और क्या गलत मिला है, यह बात सदन को भी मालूम होनी चाहिये, प्रदेश को भी मालूम होना चाहिये कि बहुजन समाज पार्टी से एक मुसलमान नुमाइंदा जिसके चेहरे पर अल्लाह का नूर भी है नबी की दाढ़ी भी है वह खड़े होकर यह कहे कि मस्जिद के बाहर शराब की दुकान है और यह न बताये कि उस दौर में थी जिस दौर में आप बहुजन समाज पार्टी में समाजवादी पार्टी छोड़कर गये थे और अभी भी आपने चुनाव उसी पार्टी से लड़ा जिसने आपकी मस्जिद के सामने से शराब की दुकान नहीं हटाई। तो इतने कमजोर किरदार के बाद क्या यह मुतालबा आपका बगैर कोई मुनासिब वक्त दिये सही है। आज बजट पेश हो रहा है, इस बात का इंतजार होना चाहिये कि सरकार समीक्षा करें और ऐसी दुकानों को हटवा दे और आप अपने जमीर की बुनियाद पर अभी यह ऐलान करें कि सिर्फ इसलिये कि शराब आपके मजहब में हराम है और अल्लाह के घर के बाहर शराब की दुकान है कम से कम अल्लाह के इस फरमान के खातिर आप यह ऐलान करेंगें कि आप बहुजन समाज पार्टी इसी वक्त छोड़ रहे हैं।

(मेजें थपथपाई गई)

श्री सुल्तान बेग-

अध्यक्ष जी, मेरे कायद हैं, मेरे नेता हैं और बहुत अच्छी बात कही। यकीनन मैं मुसलमान हूँ । और इसीलिए बात मैने रखी है कि मजिस्जद के सामने जो शराब की दुकान खुली है वहाँ पर जो जुमे के दिन जो नमाजी आते हैं उनके साथ बदसलूकी होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी तो खुशकिश्मती है कि जब यह दुकान खोली गई थी तब भी मैं यही बैठा था और आज जब यह बात रख रहा हूँ तब भी मै यहीं बैठा हूँ। उस समय मैं समाज वादी पार्टी में था जब यह दुकान खोली गई यह बात सही है और आज मै बहुजन समाज पार्टी में हूँ जब इस बात को मैं कह रहा हूँ कि आप इस दुकान को बंद करा दे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 01 आबकारी विभाग के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 01 आबकारी विभाग के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,17,30,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

बजट अनुदानों को एक साथ लिए जाने के सम्बन्ध में सुझाव

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब मैं चाहता हूँ कि आप यह अनुदान संख्या 07, 08, 04 और 06 तथा 03 एक साथ रख दें।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोकसेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर , आपके आदेशों का तो हर हाल मे पालन होगा। जैसा आप कहेंगें।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 की आय व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हस्तकरघा उद्योग) तथा अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोकसेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मै आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,21,56,07,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 94,21,43,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर मै आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,92,80,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर मै आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,90,49,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर मै आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,89,14,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर कई विभाग हैं इसलिए मैने इसको रख दिया है। इनसे संबंधित मंत्रीगण या दूसरे सदस्यगण इस पर अपने विचार रखेंगे कटौती आ जायेगी तो उसी आधार पर विपक्ष के माननीय सदस्य और दूसरे लोग इस पर अपनी राय रखेंगे। मान्यवर, दो विषयों पर अपनी बात रखना चाहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण विभाग है इसलिए मै इस पर आपकी आज्ञा से बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूँ अवस्थापना और औद्यौगिक विकास का यह बजट है और अवस्थापना और औद्यौगिक विकास कितना महत्वपूर्ण है श्रीमन् आप स्वयं जानते हैं। अवस्थापना के बगैर आधारभूत जो अवस्थापना है और जो उसकी संरचना है उसके सुदृढ़ हुए बगैर किसी तरह के विकास की कल्पना नही की जा सकती है। और इन्फ्रास्ट्रक्चर अंग्रजी में जो कहते हैं अगर यह नही रहेगा तो दाबे चाहे जितने कर लिए जायं वह चीजें पूरी नही हो सकती है। अब वह इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित हो अवस्थापना सुविधाओं का कैसे विकास किया जाय इसके लिए सरकार की दृष्टि बिल्कुल भिन्न है अपने मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव की जो दृष्टि है मैं उसकी सराहना करता हूँ उनको बधाई देता हूँ कि उन्होने सरकार के स्थापना के दिन से शपथ लेने के दिन से 15 मार्च के दिन से लगातार इस बात का उल्लेख किया है कि उत्तर प्रदेश जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया है उसको बाकी प्रदेशों के बराबर लाने और देश को उससे भी आगें ले जाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है उसके लिए अवस्थपनाओं का विकास कैसे किया जाए । उद्योगों को कैसे उत्तर प्रदेश में लाया जाए, और उसके लिये कैसा परिवेश बनाया जाए, क्या माहौल बनाया जाए, और उसको दृष्टिगत रखते हुए जो प्रबन्ध किये जाने चाहिए उसकी एक छोटी झलक इसमें विभागीय बजट में जो विभाग से संबंधित मदों में उसका जिक्र होगा लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी उसको रखा। उसके परिणाम आने लगे जो हमने माहौल बनाने की कोशिश की है उसका स्वागत पूरे देश में होने लगा है। मान्यवर, एक समय ऐस था कि उत्तर प्रदेश में लगे हुए उद्योग पलायन कर रहे थे और दूसरा समय अब ऐसा आया है कि हिन्दुस्तान का बड़े से

बड़ा उद्योगपति यहां उद्योग लगाने के लिए आना चाहता है। मा0 मुख्य मंत्री जी के यहां मा0 लोक निर्माण मंत्री यहां, मा0 संसदीय कार्य मंत्री के यहां हम जैसे तमाम छोटे कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करता है कि वे उद्योग लगाने के लिए जो उत्तर प्रदेश में संभावनायें बनी हैं उसके अन्तर्गत वह कैसे उत्तर प्रदेश में आए कैसे उद्योगों के विकास में अपना व्यवसाय बढ़ायें और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण ऐसा हो सके। कि दूसरे उद्योग भी आये, मान्यवर, इसके लिए कोशिश लगातार हो रही है। श्रीमन्, मैं अपनी बात आगे कहूँ उसके पहले एक-दो बातें बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चल जायेगा कि उद्योगों की क्या स्थिति है। उद्योग बन्धु के पदेन अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री और पाँच वर्ष के सम्पूर्ण कार्यकाल में माननीया मुख्य मंत्री ने एक भी बैठक उद्योग-बन्धु की नहीं की, उद्योगपति और उद्योगों का कैसे संरक्षण हो सकता था, क्या माहौल बन सकता था ? हम समझते हैं कि जितनी जल्दी हो सकेगा माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस फोरम को बहुत मजबूत करते हुए वह करेंगे और मान्यवर, इसका प्रभाव पड़ा और प्रभाव यह पड़ा कि जो सीआईआई है, कन्फर्ड्रेशन आफ इण्डियन इन्डस्ट्री, उसके अध्यक्ष और उससे सम्बन्धित आदि गोदरेज जी आए, सीआईआई उत्तर भारतीय शाखा द्वारा मालविंदर मोहन सिंह ओटिस ग्रुप के और दूसरे प्रतिनिधित्व आए। एसोचेम इण्डिया के प्रतिनिधि चल कर आए। अब एसोचम कैसी संस्था है, सीआईआई कैसी संस्था है, आप सब भिज्ञ लोग हैं, इसलिए कहना चाहता हूँ, देश के उद्योगपतियों का जो संगठन है और उनसे जुड़ी जो सर्वोच्च संस्थाएँ हैं, उसके प्रतिनिधि स्वयं उत्तर प्रदेश में आ करके इन सम्भावनाओं को और मजबूत करने के लिए इस सरकार ने जो अपनी नीतियाँ रखी हैं, उनके प्रति अपना विश्वास जताते हुए इन उद्योगों के वातावरण को बनाने के लिए आ रहे हैं। मान्यवर, फिक्की के0 के0 मजूमदार साहब भी आए। मान्यवर, वी0सी0 त्रिपाठी जी, जो गेल के अध्यक्ष हैं, जो गैस एथारिटी ऑफ इण्डिया लि0 है, भारत की जो नवरत्न कम्पनियाँ हैं, उसमें गेल सबसे ऊँची कम्पनियों में से है जो ऊर्जा से सम्बन्धित है, जो खाद के लिए गैस की सप्लाई करती है, नेचुरल गैस को सप्लाई करने वाली जो गेल है, उसके अध्यक्ष भी आए। मान्यवर, इण्डियन ऑयल के भी आए। रिलायन्स इन्डस्ट्रीज के अनिल धीरू भाई अम्बानी ग्रुप के लोग आए। अनिल धीरू भाई अम्बानी स्वयं शपथ ग्रहण में आए, उसके बाद आए और मान्यवर, लगातार रिलायन्स जो सबसे नामचीन नाम है आज हिन्दुस्तान में उद्योग के क्षेत्र में उसके लोग आए। एचसीएल के शिवनादर आए। एचसीएल के शिवनादर पूरी दुनिया में एक ऐसी शक्सियत है जिन्होंने अपने उद्यम के बूते ऐसा वातावरण विकसित किया है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में आ करके और अपने उद्यम को लगाने का, उन सारी चीजों का प्रजेण्टेशन दिया और मान्यवर, प्रसंग नहीं था लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मिजाज के हिसाब से, इस जमीन की आत्मा के हिसाब से शिवनादर साहब से कहा जिन चीजों को ले करके आप प्रजेण्टेशन के लिए आए हैं, उसमें इनको समाहित करना सुनिश्चित कीजिए और उन्होंने कहा कि यहाँ आकर मेरी दृष्टि

बदली है। मैं दूसरी बात सोच रहा था, यहाँ उद्योग तो लगायेंगे ही लेकिन जो आप की दृष्टि है, समाजवादी सरकार की जो दृष्टि है, उस दृष्टि के अनुसार हम आगे की योजनाओं में इसको शामिल करने का काम करेंगे। श्रीमन्, माइक्रोसाफ्ट के बिलगेट्स भी आए। बिलगेट्स उद्योग लगाने के लिए नहीं आए लेकिन एक बहुत बड़ा मामला यह है कि दुनिया का सबसे धनी एक व्यक्ति जो आ रहा है, सोशल एसेट्स क्रिएट करने के लिए और सोशल सर्विस से जुड़े मामलों में, चिकित्सा के क्षेत्र में अपना सर्वाधिक योगदान देने के लिए, जिसके चलते बिहार की तस्वीर बदल गयी है, इस फ्रन्ट पर और वह स्वयं अपनी ओर से आए और उन्होंने कहा कि हमको यहां का जो परिवेश अखिलेश यादव के नेतृत्व में नजर आ रहा है, बिलगेट्स फाउण्डेशन वह सारी चीजें करेगा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और विशेष रूप से बच्चों के लिए, धात्री महिलाओं के लिए, जिनकी स्थिति सबसे खराब है। मान्यवर, यह रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सवाल पर खास तौर से अपना योगदान करने के लिए अपनी ओर से वह आफर लेकर आए। यह माहौल का फर्क है, ऐसा माहौल बदला और यह परिवेश मात्र अखिलेश यादव के शपथ लेने से नहीं बदला। सरकार की जो दृष्टि है, उस दृष्टि के कारण यह बदला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रदेश की मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने के लिए हमारे पास संसाधन की कमी हो सकती है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लूट और भ्रष्टाचार चला है, तो हम खजाने के बूते ही सारी चीजें नही कर सकते लेकिन सरकार इन्तजाम करने के लिए होती हैं, पीपीपी माडल पर हम लोग करना चाहते हैं। सहकारी क्षेत्र में करना चाहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में करना चाहते हैं, हम पब्लिक सेक्टर में भी करना चाहते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेक्टर मे भी करना चाहते हैं, कोआपरेटिव सेक्टर में भी करना चाहते हैं और इसके लिए इनकी इकाईयों के विनिवेश के लिए रुपये 6.55 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए हम एक बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं। देश और प्रदेश ने देखा कि भट्टा परसौल में शर्मनाक तस्वीर उभरी। यमुना एक्सप्रेस वे के नाम पर जो घोटाला हुआ है। गंगा एक्सप्रेस वे के नाम पर जो एक औद्योगिक घराने को, जिनके बारे में नेता प्रतिपक्ष बता सकते हैं कि किनकी-किनकी प्रत्यक्ष हिस्सेदारी थी। नोट गिनने की मशीन से जो माल निकलकर आता था वह बड़ी-बड़ी पेटियों में भरकर सरकारी जहाज में भरकर किसके यहां उतारा जाता था। यह आप जानतें होंगे। मुझे ठीक से पता नहीं इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। मान्यवर, इन बड़े बड़े प्रोजक्टस के टेण्डर एक ही आदमी के नाम से खुलते थे। यमुना एक्सप्रेस-वे के नाम से एक योजना चलती थी तो उसके बारे में मालूम हो जाता कि कौन बनाता है। गंगा एक्सप्रेस वे यह कौन बना रहा है यह सबको मालूम होता था। मिर्जापुर में कौन जाएगा, चुनार की फैक्ट्रियों मे किसका काम होगा, यह पहले से पता रहता था। वह सब लोग जानते थे क्योंकि एक ही घराना था। और उस घराने से सीधे-सीधे सरकार में बैठे सबसे ऊँचे लोग

उससे संबद्ध थे। मान्यवर, एक ही घराने को सब दिया गया। मान्यवर, सड़क बनाने के नाम पर भी जमीन लूटकर दूसरे को दिया गया। हम भी सड़क बनाना चाहते हैं। और आगरा से लखनऊ की न्यूनतम दूरी के आधार पर आगरा-लखनऊ को आठ लेन का एक्सप्रेस-वे बनाना चाहते हैं। वह हम बनायेंगे, लेकिन अपना लैण्ड पार्सल हम किसी को नहीं देंगे कि फलां-फलां शहर है, यह आप पाँच सौ एकड़ किसानों की जमीन ले लीजिए और यहाँ आप अपना फाइव स्टार होटल बनाइये। वह लैण्ड पार्सल देने का काम हम नहीं करेंगे। मान्यवर, हम सड़क बनायेंगे और अधिकतम सात घण्टे में दिल्ली की दूरी तय होगी। मान्यवर, आई0टी0 हब बनाया जाये इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बात बता दी है। लेकिन और भी हब बनाये जा सकते हैं। प्रिन्टिंग हब बनाया जाये। प्रिन्टिंग का बहुत बड़ा काम है और आज उसका बजट भी है। सरकारी प्रेस का बजट मैंने रख दिया है। उत्तर प्रदेश मे इसकी बड़ी सम्भावनायें है। जब चीन से इम्पोर्ट हो रहा है। यहाँ के लोगों के लिए जो मेटेरियल छपाई का है वह चीन में छपता है और चीन से छपकर तैयार होकर बड़े-बड़े बक्सों में यहाँ आता है और हम यहाँ उसको नहीं बना सकते, यह बात नहीं है। हम प्रयत्नशील है। तमाम ग्रुप्स को बुलाकर रखा है और उनके माध्यम से हम इन चीजों को करना चाहते हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र की चर्चा हो चुकी है हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो मूलभूत अवस्थापना सुवधायें हैं उसमे एनर्जी सेक्टर और रोड का निर्माण इन दो को प्राथमिकता पर रखने का काम हमारी सरकार ने किया है। इन पाँच सालों में लोक निर्माण विभाग से इतनी सारी सड़कों को बनाने, सारे गढ्ढ़ों को भरने के अलावा ऐसी सड़कें बनायी जायेगी ताकि आने वाले दौर में प्रदेश किसी से पीछे नहीं रहे और हमको जहाँ जिस भी बिन्दु पर कम्प्टीशन करना है हम उससे आगे निकलकर जा सकें। इसलिए हम इन अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं। मान्यवर, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना में पात्र इकाईयों को वेट के बदले ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। बुन्देलखण्ड और पूर्वान्चल में मान्यवर, दस करोड़ तथा शेष जनपदों में 25 करोड़ या अधिक की पूँजी निवेश करने वाली इकाइयों को दस वर्ष की अवधि में जो वैट वह देते हैं वह पूरा का पूरा वैट का पैसा उनको वापस कर देते हैं, बिना ब्याज के ब्याज विहीन ऋण के रूप में और वह आठवें वर्ष में उसको देते है, सात वर्ष तक बिना ब्याज को रूपया हम उनको दे देते हैं, जितना वैट उन्होंने दिया, उतना पूरा का पूरा उनको लौटा देते हैं और इस मद में मान्यवर, 138.74 करोड़ का प्राविधान किया है, लेकिन मैं दूसरी बात का भी जिक्र करना चाहता हूँ पूर्वाचल और बुन्देलखण्ड में अब तक जो 10 लाख की सीमा थी, सरकार विचार कर रही है कि यह सीमा कम होनी चाहिए। हम पक्षधर है इस बात के कि जितनी छोटी औद्योगिक इकाइयां लगेंगी उतने ज्यादा हाथों को रोजगार मिलेगा। जब हम रोजगार देना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो जितनी सीमा अब एक करोड़ हो जाय, चार करोड़ हो जाय, पाँच करोड़ हो जाय, इसकी व्यवहारिकता पर

विचार हम कर रहे हैं, लेकिन 10 करोड़ की सीमा घटाई जाय इस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और हम जल्दी से जल्दी इस पर नीति लेकर आयेंगे कि एक करोड़ की भी यूनिट लगती है तो दस करोड़ के मुकाबले, दस एक-एक करोड़ की यूनिट में अगर इस बात की सम्भावना हो जाती है कि पाँच गुना अधिक लोगों को अगर रोजगार दिया जा सके तो उसको करना चाहिए। यह सरकार की राय है। मान्यवर, औद्योगिक नीति 2004 में बनी थी जब हम आये थे तब। 2004 में मा0 आजम साहब इसी कुर्सी पर थे, मा0 मुलायम सिंह यादव जी सामने वाली कुर्सी पर बैठा करते थे मै जहां हूँ, मैं यहां था और मुझे स्मरण है 2004 में औद्योगिक नीति आप लेकर आये थे। यह 2012 है मान्यवर, एक सरकार आई, चली गई, औद्योगिक नीति की चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं हुई, उस पर उसको खारिज करने, बदलने, संशोधित करने, सुधार करने किसी बात की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई मान्यवर और जब आज मैं बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ इस सदन में तो सदन के माध्यम से प्रदेश को अवगत कराना चाहता हूँ कि हम फिर समीक्षा कर रहे हैं और जल्दी ही अपनी औद्योगिक नीति और एक ऐसी प्रभावी औद्योगिक नीति आज के परिस्थिति के अनुरूप लेकर के हम लोग आयेंगे कि इस प्रदेश में उद्योगों का विकास किया जा सके। बिना उद्योगों के विकास के तरक्की की कल्पना सम्भव नहीं है इसलिए अपनी फिर औद्योगिक नीति, 2004 में हमने जारी किया था यह नहीं कहा कि उसको जारी रखेंगे, फिर उस पर विचार करेंगे और उसमें जितनी तब्दीली की जानी है, जितना सुधार किया जाना है, उसके साथ एक नई औद्योगिक नीति फिर हम जल्दी लेकर के मान्यवर आयेंगे और पूरे प्रदेश को सदन के माध्यम से बतायेंगे कि कैसे होगा। यह मान्यवर, एक और बड़ी बात है तमाम बातें उठती रहती है मैं मा0 सदस्यगणों को बताना चाहता हूँ जितनी हमारी कताई मिले थी एक को छोड़ करके सब बन्द हो गई और जो जो चल रही है, वह भी मरणासन्न है और यह सारा मामला बी0एफ0आई0आर0 में गया हुआ है और एक और काम हुआ, पिछले दिनों एक गम्भीर खेल हुआ उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को औने-पौने में बेंच दिया, सारे रोडवेज की बस स्टेशन्स को बेचने का ठेका उसी को जिसके जिम्मे पूरा प्रदेश का एक महकमा, खनन और दूसरा और तीसरा तमाम तीन चार महकमें जो पूरी तरह एक आदमी की जेब में डाल दिये गये थे, तो उत्तर प्रदेश सारे बस स्टेशन्स को बेचने का भी जिम्मा उसी को दिया जा रहा था, किन्ही कारणों से यह घटना घटते-घटते आखीर में रह गई, आखिरी दौर में वह बेंचे नही जा सके और उसमें बेच दिया गया था। हम जब यह कताई मिलों को पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं मान्यवर, तो हम उनको बेंचने का काम नही करेंगे। सरकार अगर बजट से व्यवस्था नही कर पायेगी तो हमारी नीति है इस मामले में कि हम यह चाहते हैं कि सरकार को राजस्व भी मिले, वह कारखाने भी चलें और सरकार की पूँजी, सरकार के कारखाने बने रह सकें, इस तरह की कोई नीति करने का काम करेंगें कि जो उद्यमी उसको चलायेगा वह हमको

उसका किराया भी देगा, लोगों को रोजगार भी देगा और इस आधार पर बीएफआइआर में हम केस रख करके लीज के माध्यम से देकर के इन सारे कारखानों को चलवाना चाहते हैं जिसमें उमाशंकर जी आपके रसड़ा की भी जो कताई मिल है वह भी उसमें शामिल है, आपको इसका स्वागत करना चाहिए और सभी जितने बन्द पड़े हैं, मऊ का जो बन्द पड़ा है, बहादुरगंज का बंद पड़ा है, मेजा का है, मेरठ का है सभी जितने है, उन सबको चलाने का समुचित इन्तजाम और यह इस नाते कि सरकार की दृष्टि है किसान को सुखी करना है, छात्र की चिन्ता करनी है, लेकिन उद्योगों को बढ़ाना है, उद्योगों को बढ़ाये बगैर यह तरक्की नही हो सकती, इसलिए मान्यवर, आज जो हमने ये बजट रखा है मान्यवर यह उद्योग विभाग का यह एक छोटी तस्वीर ऐसी है जब आप इसको पूरी तस्वीर में देखेंगें तब आपको उत्तर प्रदेश का एक बड़ा विकास का सपना पूरा होते हुए दिखेगा। मान्यवर, यह तस्वीर अगर आप देखने की कृपा करेंगें तो आपको इस छोटे से बजट में उत्तर प्रदेश के विकास की एक तस्वीर, जैसे बीज में ही वृक्ष की सकल नजर आती है।

उसको जो दूर तक देख सकता है और अगर नही आती तो इस बजट में आपको वह तस्वीर पूरी की पूरी नजर आयेगी। इसलिए मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूँ कि आज सदन इस प्रदेश में जो औद्योगिक विकास के लिए जो माहौल बना है, उस माहौल को और मजबूत करने के लिए और इस परिवेश को ऐसा बनाने के लिए, यह प्रदेश आपका भी है और हमारा भी है, यहाँ पर उद्योग लग सकें। आज एक ऐसा माहौल बने । आज इस सदन से ऐसा संदेश जाए इसलिए मै चाहूँगा कि सर्वसम्मति से उस बजट को पारित करने का काम करें ताकि इस उत्तर प्रदेश में इसके विकास के लिए जो संकल्प मा0 मुख्य मंत्री जी ने लिया है, उस संकल्प को हम उतनी ही मजबूती के साथ पूरा कर सकें। बहुत-बहुत, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आप सभी मदों पर प्रस्ताव रखेंगे।

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इन सभी मदों पर एक ही साथ कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन) के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे मा0 मंत्री जी ने एक आइना दिखाया इन आने वाले पाँच सालों का, आने वाले उस एक वित्तीय वर्ष का,जिसमें कि वह क्या करने जा रहे हैं। मान्यवर, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं और हर सरकार यह कहती है कि हमें उद्योग लगाने है। हमें उद्योग नीतियाँ बनानी हैं, बड़े उद्यमियों को प्रदेश में लाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है पर होता क्या है मैं 1989 के बाद से देख रहा हूँ कि सरकारें आई सत्ता में, भाजपा, सपा-बसपा, बसपा-भाजपा, सपा, बसपा, बसपा और सपा की सरकारें आईं, घोषणाएँ हुईं, वायदे हुए, सरकारी दॉव-पेंच हुए और उद्यम प्रदेश बनानें की घोषणाओं तक मामला सीमित होकर रह गया। स्थिति यह है कि जब से यह दो रीजनल पार्टियां आती हैं, एक बार सपा आती है तो एक बार बसपा आती है, इनमें इतनी कडुवाहट घुल चुकी है कि कोई भी पक्ष करता है जैसे आपने रिलायन्स पॉवर प्लांट लेकर आए वह स्क्रैब हो गया। कितना बढ़िया प्रोजेक्ट पर बिजली बनानी थी, उसके फेल होने के क्या कारण रहे, अगली सरकार ने आकर उसे डाउन करके खत्म कर दिया। इसी तरह अब जैसा भी इन लोगों ने किया, घोटाले किये, पी गये, खा गए, लील गए, जो कुछ भी किया, अब आप लोग उसकी तरफ उस तरह से देख रहे। प्रदेश का विकास तभी हो सकता है जब हम इस सोच को लेकर चलें कि हमें उत्तर प्रदेश में माहौल बनाना है। हमें उत्तर प्रदेश में

उद्योग लगानें हैं और इन सब बातों का असर उन सब बड़े-बड़े उद्यमियों, उद्योगपतियों और छोटे उद्यमियों पर पड़ता है, जो अपनी जेब से पूँजी लगाकर, लोन लेकर ऋण लेकर, शेयर मार्केट में जा कर और कितनी परेशनियों से वह अपनी यूनिट को लगाता है। चाहे वह बड़ा उद्योग हो, चाहे वह स्माल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे वह कुटीर उद्योग हो, चाहे हथकरघा उद्योग हो और वह उस शहादत में शहीद हो जाता है। मै कहना चाहता हूँ पहले वृहद उद्योगों को लेते हैं आप शुरू करें नोयडा से, मैं नोएडा के माामले को, ग्रेटर नोएडा के मामले को, यमुना एक्सप्रेस मामले को बड़े करीब से जानता हूँ। मान्यवर, यह जो सारे अथारिटीज हैं, वह औद्यौगिक अब नहीं रह गए हैं। वहां किसी उद्योग के बारे में बात करिये तो आज कितने उद्योग चल रहे हैं। ऑटोमोबाइल इन्डस्ट्री भाग गयी, पलायन हो गया । आज मुश्किल से 5,7 या 10 फैक्ट्रियाँ नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथारिटीज में चल रही हैं। वहाँ दौड़ है प्लाटों को लेने की । वहाँ दौड़ है रेजीडेन्सियल हब बनवाने की, मल्टीस्टोरी अट्टालिकाएं, बड़ा खूबसूरत शहर बन गया है नोएडा ग्रेटर नोएडा, बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसके पीछे की कहानियाँ देखी हैं विरासत चला करती है वहाँ पर वहाँ बादशाह बैठा करते हैं, अधिकारी तो रास्ते बताते हैं और किसी के भाई, किसी की बहनें, किसी के छोटे भाई पावर्टी सेन्टर होते हैं और उन भाइयों की वजह से कोई कदम हिला नहीं सकता है और यदि कोई बोले कि हमें इण्डस्ट्रियल प्लॉट चाहिए तो वह बोलेंगे कि भइया जी से बात कर लीजिए। कोई सिस्टम नहीं कोई व्यवस्था नहीं, मैं आपकी बात नही कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ तुम भी सोच रहे हो, मैं माहौल की बात कर रहा हूं । आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात की, यमुना एक्सप्रेस हाईवे बना भट्टा पारसौल की घटना हुई, किसानों पर गोलियाँ चली कितनी मुश्किलों से काम पूरा हुआ। माननीय मंत्री जी एक पर्टीकुलर इण्डस्ट्री की बात कर रहे थे, मैं तो सीधे जे0 पी0 ग्रुप की बात कर रहा हूँ। कितनी आटोनामी, कितनी मोनोपोली, समानान्तर सरकारें चलीं। यमुना एक्सप्रेस वे एक बेहतरीन एक्सप्रेस वे बना, कितना भी भ्रष्टाचार हुआ हो लेकिन सवा घण्टे में दो घण्टे में आप आगरा से मथुरा पहुँच जाएंगे। अच्छा होता माननीय मुख्य मंत्री जी यहाँ बैठे होते आपके उद्योग, भारी उद्योग, लघु उद्योग के डायरेक्टर यहाँ पर बैठे होते। मैं समझता हूँ कि बड़े आफीसर यहाँ पर नही बैठे हुए हैं, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर पता नही यहाँ पर हैं या नही। नहीं बैठे हैं मै जानता हूँ एक जमाना हो गया इन सब अधिकारियों की शक्ले देखे हुए मैंने देखा कि माननीय मुख्य मंत्री जी में सोच है, सरकार सोच रही है कुछ करने के लिए, हर बात को निगेटिविटी में नही लेना चाहिए कि हम कटौती रख रहे हैं तो अगेन्सट बोलें। आपको देखना है कि राज्य में कितना औद्यौगिक निवेश हुआ। आपको कानून व्यवस्था ठीक करनी होगी, जब तक कानून व्यवस्था ठीक नही होगी तब तक उद्योग नही पनप सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि एक माहौल बनता है कि हम जाएंगे तो हमसे चौथ वसूली होगी, हम जाएगें तो हमारी कनपटी पर गोली मार दी जाएगी, हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा में चले जाएंगे तो हमें गाड़ी से उतारकर किडनैप कर लिया जाएगा। यह माहौल है उत्तर प्रदेश

का पूरे देश के अन्दर और पूरी दुनिया के अन्दर। मैंने लन्दन के एक उद्योगपति से कहा कि आप आइये, हम बात करेंगे क्योंकि हमारे नौजवान मुख्य मंत्री हैं, उनका विजन है, उनकी सोच है और वह पार्टीलाइन से बाहर बात करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है आपको औद्योगिक माहौल एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं मिलेगा, मैं तो समझता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी को औद्योगिक नीति बनाते वक्त एक ऑल पार्टी नीति बनानी चाहिए ताकि सभी पार्टियों के नेता अपना विजन दे सकें, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश हम सबका है, हम सब लोग सफर करते हैं, हम सब लोग परेशान होते हैं जब एक उद्योगपति आता है और भाग जाता है और सोचता है कि हमने बड़ी गलती की। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम आदमी की तो इन्ट्री ही बन्द है। आप सीधे जाओ तो उनसे बात नहीं हो सकती, उनके एजेन्ट घूम रहे हैं आप एजेन्ट के थ्रू जाइये, बात कीजिए। यह चीज तमाम माननीय सदस्य बता देंगे चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के आसान नहीं है। उनसे बात करना, पहले दलालों से बात होती है, तब आपकी इन्ट्री होती है। मा0 अध्यक्ष जी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथारिटी के कोई रूल्स-रेगुलेशन आज तक नहीं बने हुए हैं और सल्तनतें प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों की तरह चल रही हैं। कितनी बार कहा गया कि आप रूल्स और रेगुलेशन बनाइये जिससे कि आप गवर्न हों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो जाती है जो चाहे आप पास कर लेते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, अपनी नीतियाँ बना लेते हैं, जिस तरह से चाहते हैं प्लॉटों को तब्दील कर देते हैं, जिस तरह से चाहते हैं लैण्डयूज चेन्ज कर देते हैं। इतनी ऑटोनॉमी और मोनोपोली इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है जो चाहते हैं कर डालते हैं या तो पिछली सरकार में गवर्नेंस पंचल तल के एक दो अधिकारियों के माध्यम से होती थी। मैं समझ सकता हूँ और सोच सकता हूँ कि जिस तरह का माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है और जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। उससे मैं समझता हूँ कि आप बदलाव लायेंगे, आप डिसेन्ट्रलाइज करेंगे और कन्ट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी इसके दोनों तरफ आपने किसानों से जमीनें ले ली हैं, फाइव स्टार होटल के लिए आपने जमीने बेंच दी हैं। इण्डस्ट्री की कोई बात नहीं रेजीडेंसियल कॉलोनीज के लिए आपने प्लॉट आवंटित कर दिये हैं। अब आप इसमें बड़ी-बड़ी जांचें कराइये कि कौन कितना खा गया और पैसा कहां ट्रांसफर हो गया। आप सख्ती कीजिए मेजर डिसिप्लिन कीजिए क्योंकि वहॉ कुर्सियों पर बैठे हुए लोग एक्सपर्ट हो गये हैं। यदि आप उनके आफीसरों की जॉचें करा लें तो आप देखेंगे कि वह किसी उद्योगपति से कम नहीं हैं। जो पहले थे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जी0एम0, एकाउन्टेंट, कैशियर्स आज भी वहीं बैठे दिखाई दे रहे हैं। मान्यवर, कितने बड़े-बड़े घोटाले हुए, आप कहेंगे कि हम यह करेंगे, वह करेंगे, बीती को बिसारिये की बात इसमें नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के सारे इण्डस्ट्रियल एरिया रुग्ण पड़े हुए हैं। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की पूरे इण्डस्ट्रियल एरिया में एक-एक इण्डस्ट्री है, न वहां ड्रेनेज

है, न वहां सड़कें हैं, न वहॉ फैक्ट्री है। हमने अखबारों में पढ़ा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहाँ प्लॉट फ्री-होल्ड कर दिये हैं। अब तो बड़े मजे हो गये, जितनी इण्डस्ट्रीज थीं अभी तक तो वह लीजहोल्ड थीं, उनकी जमीनें पड़ी हुई हैं जो उन्होंने 10-10, 20-20, 50-50 रुपये में खरीदी थीं। 20 साल पहले वह आज 20 हजार, 50 हजार रुपये प्रतिगज हो गई हैं जिनके एक-एक, दो-दो लाख के लोन पचास लाख हो गये थे वह उन्हें बेच करके अपने आउट स्टैंडिंग ड्यूज को चुका पायेंगे और वह इण्डस्ट्रियल एरिया फिर से रेजीडेंसियल हब बन जायेगा। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से चाहूँगा कि आप वनटाइम सेटलमेंट की स्कीम बनायें। आज आपके जो जी0एम0 हैं वह इण्डस्ट्री लगाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि वह धन उगाही का काम करते रहते हैं। लाओ यू0पी0एफ0सी0 से सेटलमेंट करा दें, पिकप से सेटलमेंट करा दें, व्यवस्था में लगे रहते हैं किसी की कोई रुचि इण्डस्ट्री में नहीं है। मैं कड़वा सच बता रहा हूं हम लोगों के पास लोग आते हैं कि हमारी इतनी रिकवरी निकल गई, हमें बचाओ, हम कैसे बचेंगे और मान्यवर, तमाम लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है। गाजियाबाद और इधर से लगे हुए आपके जो यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के इण्डस्ट्रियल एरिया हैं, पूर्वांचल का इण्डस्ट्रियल एरिया, कानपुर का इण्डस्ट्रियल एरिया सब बन्द पड़े हैं। आप दो तरह से काम कीजिए एक तो वर्तमान नीति की तैयारी कीजिए, आपका विजन और सोच स्पष्ट होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और उसका अनुपालन आप कैसे करेंगे। उसमें आप एक काम करिये, दो तरह से चलिये। आज माननीय मुख्य मंत्री जी होते, एक दिन चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि माथुर साहब आपके सुझावों को मैं सुनूंगा। माननीय शिवपाल सिंह जी बैठे हैं, बड़े भाई आजम खाँ साहब बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि वह मा0 मुख्य मंत्री तक पहुँच जायेगा। आप दो तरह से चलिये एक तो आपकी जो पॉलिसी और सोच है उसका इम्पलीमेंटेशन कराईये। दूसरे, पुरानी फाइलों को पुरानी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए काम करिये। चूँकि होगा फिर यही कि आज आप हवा बनाने में लगे हुए हैं लेकिन 05 साल बाद क्या हवा होगी, वह ईश्वर ही जानता है। हम तो चाहेंगें कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि बनाये रखे। पाँच साल बाद क्या होगा, आप उस पाँच साल की स्थिति को संभाल कर चलिये। हम किसी को क्रिटीसाइज करके नहीं चल रहे हैं। हमारी पीड़ा तो यह है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग कैसे पनपे, बाहर से उद्योग कैसे आयें, छोटी इण्डस्ट्रीज कैसे चलें, बड़ी इण्डस्ट्रीज कैसे चलें, मध्यम इण्डस्ट्रीज कैसे चलें, लोगों को कैसे रोजगार मिले ? आपके नये-नये लेटर ऑफ इण्टैंट कैसे आयें, किस तरह से बड़े-बड़े पूँजीपति आकर आपका स्वागत करें, आपको गले लगायें, अपनी फैक्ट्री लगायें, वह माहौल बना रहना चाहिए। अब स्थिति यह है कि आप गीडा, लीडा, सीडा की हालत देखिये। अभी आपने कताई मिलों की बात करी, वह बी0आई0एफ0आर0 में गई हुई हैं। वही यूनिट्स हैं सिसक रही हैं, गवर्नमेन्ट ने कुछ नहीं देखा। मुझे इस बात का अफसोस है, मैं कोई क्रिटीसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं कम्प्रीजन करता हूँ तो सब एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं। ऐसे आरोप-प्रत्यारोपों से

इण्डस्ट्रियल माहौल नहीं बनेगा। इसी तरह पूर्वान्चल और बुन्देलखण्ड की बात आपने कही। इतना हमारे पास खनिज है, अपार खनिज है। बुन्देलखण्ड में कितना मैगनीशियम, ग्रेनाइट है, सीमेण्ट के लिए व्यवस्थायें हैं, डायमेण्ड है, सोना है सोनभद्र में, ललितपुर में बुन्देलखण्ड और झाँसी में। इतना कुछ है कि अगर आप चाहें तो तस्वीर बदल सकती है। आप माइनिंग कराईये, आप गोल्ड की माइनिंग कराईये, बाहर के लोगों को बुलाईये। आप बहुत तेजी से काम करिये। इस मामले में मैं तारीफ करूँगा, लेना-देना कुछ भी हो लेकिन यमुना एक्सप्रेस-वे 3 साल में बन करके तैयार हो गया। उसी रफ्तार से इण्डस्ट्री को लगाने का काम डण्डा लेकर करेंगे तब इण्डस्ट्री लग पायेगी और आपके इण्डस्ट्री डिपार्टमेण्ट के आफिसर्स भी बड़े शार्प होने चाहिए। बड़े तेज रफ्तार के होने चाहिए। मैनेजमेंट के प्रोग्राम रेयूलेशन, रिव्यू तकनीक से काम करना चाहिए। क्रिटिकल पार्ट मैथड से काम नहीं करना चाहिए कि आटा बना, दाल बनी, चावल बना, सब्जी बनी और रात तक खाना बना। आपको तो इण्डस्ट्री ऐसे लगानी पड़ेगी कि सारे काम एक साथ हों और छठे महीने या एक साल में इण्डस्ट्री आ जाए। आपको इस तरह की ईमेज देनी पड़ेगी, आपको वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, देश में करनी पड़ेगी उसके लिए आप क्राइम पर कण्ट्रोल करें। सबसे पहले लोग इससे डरते हैं कि हमारा अपहरण न हो। मान्यवर, मैं और भी बात कहना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब और कितना समय लेंगे ?

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, पाँच-सात मिनट और लूँगा। यह इम्पोर्टेन्ट मामला है। समझने की कोशिश करिये। 12वीं योजना, मुझे खुशी हुई 2004 में आप उद्योग नीति ले करके आये। उसकी गम्भीरता की बात करिये, यही आपकी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। हर सरकारों में नहरों की सफाई की बात करेंगें, सड़कों की बात करेंगे, आपने उत्तर प्रदेश में इण्डस्ट्रियल माहौल बना दिया तो फिर आप हटने वाले नहीं है। मैं आपको सच्ची और कड़ुवी बात कह रहा हूँ। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल पाक-साफ बात कर रहा हूँ, जरा सुनिये। बात यह है कि आपकी बारहवीं पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावित नीति इण्टरनेट से निकाल कर पढ़ी। आपने जो प्राविधान किये हैं, यमुना एक्सप्रेस-वे में जो खर्चा हुआ, राष्ट्रीय मार्गों का विकास, नगरीय पुनरोत्थान योजना, ऊर्जा क्षेत्र का विकास, माइक्रो हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट्स, सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र का विकास, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र का विकास, परिवहन क्षेत्र का विकास, कुशीनगर में टूरिज्म और इण्टरनेशनल एअरपोर्ट का विकास, स्लाटर हाउसेज की बात। ताज इण्टरनेशनल एअरपोर्ट के लिए साढ़े दस करोड़ रुपये का प्रॉविजन किया। 26 जनपदों में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया। जो इन्फ्रास्ट्रेक्चर की बातें हैं, हमारे बड़े भाई आजम

खाँ साहब बैठे हुए है, नगर विकास मंत्री हैं। मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि किसी भी मामले में जो आपकी केन्द्रीय परियोजनायें आती हैं। इसको आप गम्भीरता से देखें। क्योंकि केन्द्रीय परियोजनाओं का धन इस तरह से लूटा गया कि अब केन्द्र सरकार भी हिचकती है। आपने जब कोयले की बात करी तो मैंने तत्काल यू0पी0ए0 की चेयरपरसन से बात की। मैंने कहा कि कोयले की आवश्यकता है। उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी को मैंने एक सजेशन भी दिया कि आप कोयला इम्पोर्ट करिए और बिजली की कीमतें बढ़ाइए। जिसको बिजली लेनी होगी वह लेगा। आप कार्ड इसू कर दीजिए कि आदमी ने कार्ड में पाँच हजार रुपये का टोकन खरीद लिया मीटर में लगाया और बिजली आने लगी। जिसे बिजली लेनी होगी वह बिजली लेगा।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश में औद्योगिक माहौल बने उसमें आपके बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव आ रहे हैं। उसको हम गम्भीरता से ले भी रहे हैं। कल हमने टेलीविजन पर और समाचार-पत्र में देखा जो देश की औद्योगिक नीति का नक्शा आया है। इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति अजीम प्रेम जी नरायण कृष्णमूर्ति जी ने कल कुछ अपनी शंकाएं जाहिर की हैं कि देश की औद्योगिक विकास दर 1 प्रतिशत पर पहुँच गई है। यह 6 से 1 प्रतिशत पर पहुंच गई है तो थोड़ा हम लोग इस दिशा में भी सोचें कि देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं हम आपके विचार जानना चाहते हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष-

आपस में बात न करें।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय सदस्य जी जब आप एम0पी0 बन जाएं और हम एम0पी0 बन जाएं तो वहाँ बहस करेंगे। यह मुद्दा यहाँ का है हमें अपने प्रदेश की चिन्ता है हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश अच्छा औद्योगिक प्रदेश कहलाए। हम भी गर्व से कहें कि हम उन पांच राज्यों में आते हैं। इन 64 सालों में हम प्रथम पाँच राज्यों में नहीं हैं। हमारी गिनती कहीं भी नहीं। उत्तर प्रदेश में पापुलेशन सबसे ज्यादा है वह भी एक एसेट है लेकिन हमारे युवा लोग पलायन कर रहे हैं। वह पंजाब में जा रहे हैं वह गुजरात में जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जा रहे हैं, दक्षिण में जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं। दिल्ली में जा रहे हैं इसकी चिन्ता है। इस बारे में पार्टी लाइन पर बात मत करें। आई0एम0 कंसर्न कि प्रदेश में औद्योगिक माहौल कैसे बने। आप

अगली बार एम0पी0 का चुनाव लड़िएगा हम भी सोच लेंगे तब वहां बहस करेंगे कि केन्द्र की क्या नीति है। मान्यवर, आपने 12वीं योजना में यह सब प्रोजेक्ट डाले हैं। अभी आपकी औद्योगिक नीति भी आने वाली है। मैं उम्मीद करूँगा कि नौजवान मुख्य मंत्री अपनी औद्योगिक नीति बड़ी सटीक लाएंगे और टाइम बाउण्ड लाएंगे मैंने आपसे कहा कि जस्टिस डिनाई इज जस्टिस डिलेट। आप इस मामले में यही फार्मूला अख्तियार करिए।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आप उल्टा बोल गए।

श्री प्रदीप माथुर-

चलिए सही कर देते हैं जस्टिस डिलेट इज जस्टिस डिनाई। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस मामले में आप गम्भीरता लाइए जब तक गम्भीरता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। मान्यवर, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बहुत बात होती है। लोग घबराते हैं, इसे बी0ओ0टी0 बेसिस पर आप लीजिए आप देश के अखबारों में छपवाइए आप इण्टरप्रन्योर को बुलाकर डिसकसन करिए उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इधर भी बड़े अच्छे लोग हैं। आप उस सोच से सबको बुलाइए और एक माहौल पैदा करिए कि हम होंगे कामयाब हम सब लोग एक है उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने के लिए। आपके जो दफ्तर हैं जो नोयडा एथारिटीज ग्रेटर नोयडा एथारिटीज यमुना एक्सप्रेस वे एथारिटीज के आफिस को छोड दें बाकी आफिसेज पूरे प्रदेश में आप जाएंगे तो यह लगेगा कि वह खुद रुग्ण पड़े हुए हैं वहाँ पर बैठे अधिकरियों को लगता है कि वह खुद रुग्ण हो गए हैं। आप सारा माहौल ठीक करिए आप किसी भी जिला उद्योग केन्द्र में चले जाइए आपको ऐसा लगेगा बाबू सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है जी0एम0 साहब पान चबा रहे हैं कोई टांग पर टांग रखे बैठा है इसलिए आपको एक बहुत जबरदस्त सेट अप बनाना पड़ेगा मैं तो देखता हूँ कि कारपोरेट सेक्टर को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है आप स्वयं माहौल बनायेंगे तो आपकी फैक्टरियों के शेयर्स भी बनेंगे, वरना शेर भी नहीं बिक पायेंगे। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं कि इण्डस्ट्री आयें जब आपके यहां माहौल होगा तब शेयर होंगे। मान्यवर, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि जगदीशपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, सुल्तानपुर एरिया, रिलायंस पावर प्रोजेक्ट को फिर लाने की बात करिये आप। आप बात करिये अजीम जी, आप जा करके इन्फोसिस वालों से बात करिये मुख्य मंत्री जी ने आईटी हब्स की बात की है, आईटी हब्स लाइये। बड़े-बड़े शहरों में जो ऑलरेडी सेटैल्ड शहर हैं वहां आईटी हब्स की बात न करिये। आप नयी जगह आईटी हब बनाइये। जो वेल कनेक्टेड हो रेलवेज से, एयरपोर्ट्स से, सड़कों से जिससे कि और जगहें भी विकसित हों। लखनऊ तो ऑलरेडी विकसित है, आगरा ऑलरेडी विकसित है, तमाम बड़े शहर ऑलरेडी विकसित है। आप उन सब आईटी हब लाने वालों से कहिये कि

आप यहां, आयें, लगायें और ऐसी व्यवस्था करिये कि लोग न तो गुड़गाँव जायें, न बम्बई जायें, न बैंगलोर जायें, अपने उत्तर प्रदेश में ही रहे। मुझे आपको पिकअप और यूपीएफसी के बारे में भी कुछ बताना है वहां ओटीएस के मामलों में उद्यमियों को फंसाया जाता हैं मतलब आपकी सारी एजेंसीज, एक आदमी अगर उनकी चकरघिन्नी में आ जाये तो ऐसा रगड़ के डाल देते हैं कि वह तौबा कर जाता है। आपको सब पर कण्ट्रोल करना पड़ेगा। ये सारे बल्कि जो आपके आफिसर्स हैं, वो सिक हो गये हैं, रुग्ण हो गये हैं तो आपको उनके रिवाइवल की भी बात करनी होगी कि इण्डस्ट्रीज के रिवाइवल के साथ-साथ अपने अधिकारियों का रिवाइवल उन ऑफिसर्स का रिवाइवल, पुराने मुद्दों का एजेण्डा एक तरफ और नये करेण्ट मुद्दों का एजेण्डा एक तरह दोनों लाइनों को एक साथ लेकर चलेंगे तब कामयाब होंगे। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, कहते रहें कि यह तो हाउस की व्यवस्था है। पर यदि हम गंभीर है तो जब तक माहौल नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

खत्म करिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, पांचों प्वाइण्ट हैं न मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

प्वाइण्ट तो बहुत रखे हैं आप।

श्री प्रदीप माथुर-

सिर्फ दो मिनट मान्यवर, दो मिनट।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अम्बिका चौधरी-

अरे सुन तो लो, पहले सुन लीजिये। आपकी बात काटूंगा मैं। सुन लीजिये आपके मतलब की बात कह रहा हूं। मान्यवर, यह बड़े सौभाग्य की बात किसी सदस्य के लिये है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि कोई सदस्य कटौती रखे और उस पर सत्तारूढ़ के सभी सदस्य मान्यवर, मेजें थपथपा के उसके सुझावों का स्वागत करें लेकिन ऐसी सर्वोच्च स्थिति के बाद वो फिर अगर फिसलन की नीची जगह पर आ जाये तो ये बेकार होगा। इसलिये जो बात हो गयी मान्यवर, तो अब इतनी ऊंचाइयों पर बने रहिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो मैं आपकी सरकार और मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि ग्रेटर नोयडा में नाइट सफारी के बारे में तवज्जों दी और नाइट सफारी आप देने जा रहे हैं और इसी तरह से आप जो आगरा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट

खोलने की जो बात कर रहे हैं तो मुख्य मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि वो यमुना एक्सप्रेस-वे हाई-वे पर मथुरा और आगरा के बीच में खुले।

श्री अध्यक्ष-

आपने सारे मा0 सदस्यों का समय अपने में समाहित कर लिया है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इसी तरह मैं अपने क्षेत्र की एक बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने नोयडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोयडा अथॉरिटी आपने बनायी है मान्यवर। इसी तरह कोसी, छाता, मथुरा में भी इण्डस्ट्रियल अथॉरिटी आप बनाइये जिससे कि उस इलाके का भी विकास हो सके। आपको पता होना चाहिये कि उत्तर प्रदेश में तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी मथुरा में है। आपको यह पता होना चाहिये कि आज वह मथुरा रिफाइनरी बंद होने की कगार पर है क्योंकि आपकी सरकार उस रिफाइनरी से 1600 करोड़ रुपये एण्ट्री टैक्स के लेती है। रिफाइनरी के ट्रांसपोर्टेशन और ऑयल, डीजल, क्रूड ऑयल उसका भी टैक्स आप लेते हैं। इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुझसे कह रहे थे कि हम तो प्रस्ताव भेज रहे हैं कि हम अपनी इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी रिफाइनरी को बंद कर दें। 1600 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कहां से दें क्योंकि वह लॉसेज में जाने लगी है। तो मा0 मंत्री जी, आपसे इस कटौती के प्रस्ताव पर अब मैं बल देते हुये.....

श्री अध्यक्ष-

मा0 माथुर साहब, अब खत्म करिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, धन्यवाद।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं केवल एक बिन्दु कहना चाहता हूँ कि माननीय नेता काग्रेंस पार्टी ने जो उद्योग विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ लेकिन उनके एक बिन्दु पर अपने पार्टी के स्टैण्ड को लेते हुए उससे पूरी असहमति व्यक्त करता हूँ। जो उन्होंने बिजली की दरों को बढ़ाने की बात कही है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा था इण्ड्रस्टी के लिए मैंने कहा था।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं इस साहित्य के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जिसमें मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित बातें कही गयी हैं। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के अन्तर्गत उद्योगों का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। 70 प्रतिशत उद्योग प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में और उसमें

भी विशेष कर गाजियाबाद और नोयडा में ही लगे हैं और वह उद्योगों का केन्द्र बनता जा रहा है। मान्यवर, मैं उक्त टिप्पणी के लिए सरकार को धन्यवाद दूँगा और आग्रह करूंगा कि जो बातें इस सदन में लगातार होती रही हैं कि क्षेत्रीय विषमतायें हैं उसको सरकार ने स्वीकार किया है इसलिए जब वह उद्योग नीति 2012 लाये तो यह उसमें सुनिश्चित करेंगे और इसकी धार को पलटेंगे ताकि पूरे प्रदेश में समान रूप से औद्योगिक विकास हो सकें।

(मेजों की थपथपाहट)।

श्री धर्मपाल-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे उद्योग विभाग के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि पर आधारित है। मान्यवर, जिस प्रदेश का व्यक्ति कृषि पर आधारित होता है तो कृषि पर आधारित होने के नाते से उस प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी ज्यादा होती है। मान्यवर, महात्मा गांधी कहा करते थे कि यह हिन्दुस्तान गांवों का देश है और देश के अन्दर मानव शक्ति ज्यादा है और पूँजी कम है इस नाते से इसमें मानव शक्ति की, मांग के अनुसार उद्योग लगाने का काम किया जाय। मान्यवर, सरकार ने भारी उद्योग मध्यम उद्योग और लघु उद्योग के बारे में अपनी नीति स्पष्ट की है मान्यवर, आज प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल वातावरण नहीं है कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हैं, सड़कें टूटी हुई हैं बिजली है नहीं, इसलिए कोई भी उद्यमी पूँजी निवेश नहीं करना चाहता है। इसके विपरीत पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात इत्यादि प्रदेशों में पहुँच कर वह उद्योगों को लगाने का कार्य कर रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार को छोटे उद्योगों को कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। आज हो क्या रहा है कि खुरपी, फावड़ा, हसिया जैसी छोटी-छोटी चीजें भी बड़ी-बड़ी कम्पनियां बनाने लगी हैं। छोटे उद्योग छोटी पूँजी रखते हैं और ज्यादा उत्पादन देते हैं और वही बड़े उद्योग बड़ी पूँजी रखते हैं तो कम उत्पादन देते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करें ऐसे उद्योग लगाये जाये जिसमें मशीनों का प्रयोग कम हो और मानव का ज्यादा हो।

मान्यवर, अभी डा0 राधा मोहन अग्रवाल जी ने पश्चिमांचल, पूर्वान्चल की बात कही थी, अच्छी बात है। मान्यवर, भारत सरकार ने पूरे प्रदेश को 13 क्षेत्रों में बांटा है जिसे सेज कहते हैं स्पेशल इकोनामिक जोन, मान्यवर ठीक है ऐसे ही एक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जिसमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बाराबंकी और हरदोई इत्यादि 13 जिले आते हैं यहाँ सेज डेवलप करना चाहिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष आर्थिक जोन बनाना चाहिए। मान्यवर, सरकार की एक अच्छी नीति थी पहले सपा ने उ0प्र0 विकास परिषद बनाई थी। समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाई थी बसपा ने जिसे आकर बन्द कर दिया। उसमें उद्योग विकास परिषद् का गठन किया था जिसमें अध्यक्ष थे माननीय अमर सिंह जी और उसमें सदस्य बड़ी नामी गिरामी हस्तियां थी जो प्रदेश के ही नहीं देश के जाने माने उद्यमी

थे, ऐसे उद्यमी जिसमें थे श्री आदि गोदरेज जी, श्री अनिल अम्बानी, श्री अमिताभ बच्चन, श्री कुमार मंगलम बिड़ला, श्री के0बी0 कामथ, एस0एस0 बग्गा, श्री सुब्रतराय सहारा इन सभी ने उत्तर प्रदेश से संस्तुतियां भेजने का काम तो किया लेकिन उत्तर प्रदेश ने इनके प्रयास से कोई उद्योग नहीं लग पाया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में उद्योग क्यों बन्द हुए मैं आलोचना के साथ-साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ।

अंग्रेजी में फिर हिन्दी में भी बताऊँगा। उद्योग बन्द होने के 3 कारण है। नम्बर एक मिस मैनेजमेन्ट, नम्बर दो फैमिली डिस्प्यूट और नम्बर तीन लैस आफ वर्किंग कैपिटल। यह जो कुप्रबन्धन है पारिवारिक झगड़े है, कार्यशील पूँजी का अभाव है इसके नाते से उद्योग बन्द हुए फिर भी इन बन्द उद्योगों को चालू कराने का काम किया जाय। मान्यवर, मैं आपकी इच्छा को भांप रहा हूँ आप चाहते हों कि मैं जल्दी बन्द करूँ मैं वैसे ही बहुत कम बोलता हूँ। मान्यवर, वृहद उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन नहीं किया गया है। माननीय उद्योग मंत्री जी हमारे बरेली जिले के हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं हमारे मित्र भी हैं। केन्द्र सरकार ने एसाइड योजना चालू की है इस एसाइड योजना में बरेली को भी कुछ रुपया दिया गया है जिसमें माननीय मंत्री जी मैं बताना चाहता हूँ कि इस एसाइड योजना में हर जिले में कोई न कोई योजना चालू की है और मान्यवर, यह भारत सरकार का बजट है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसकी कमेटी बनती है और यह कमेटी प्रदेश से जिलों को धन भेजने का काम करती है लेकिन कोई भी उद्योग नहीं चल रहा है। माननीय मंत्री जी हम चाहेंगे बरेली में वुड सीजनिंग प्लान्ट व कामन फसिलिटी की स्थापना है जिसमें 3413 लाख रुपया दिया गया है। इसको चेक कर लेंगे कि यह कहाँ काम कर रही हैं इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में धन आवंटन किया गया है जब यह काम नहीं हो रहा है तो मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से इतना कहते हुए कि बरेली में एक पराग दुग्ध फैक्ट्री है जो चालू स्थिति में हो सकती है उसको चालू कराने का काम करें। माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा था कि चीनी मिलें बन्द कर दी गयी, 11 चीनी मिलें बन्द कर दी गयी एक बरेली की चीनी मिल है पिछली सरकार ने बहुत सस्ते पैसों में बेच दी। मान्यवर, अरबों-खरबों की जमीन थी वह करोड़ों में बेच दी उसकी जांच करा दें। मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

*श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, उद्योग विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। आपके माध्यम ये यह कहना चाहता हूँ कि जनपद मथुरा के हमारे कांग्रेस के नेता ने काफी कुछ कहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

कांग्रेस के नेता ने आधे घंटे से ज्यादा अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है। आप दूसरे सदस्यों को बोलने दीजिये। आप ही बोलेंगे क्या ?

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात रखूँगा। मान्यवर, हमारे मथुरा जनपद में इतनी बड़ी रिफाइनरी है जिसने मेरे क्षेत्र के 24 गाँव एडाप्ट कर रखे हैं। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि उनका डेवलेपमेंट रिफाइनरी करवाये। कांग्रेस के नेता बैठे है मैं तो उनसे भी अपेक्षा करूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह इतना गम्भीर मामला है कि यह 24 गाँव किसी भी हालत में किसी भी स्थिति में न तो इधर से कुछ पा रहे हैं न उधर से कुछ पा रहे हैं। हालत यह है कि एक साल में 33 मौतें हुई हैं रिफाइनरी से। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से चाहूँगा कि उन 24 गाँवों का विकास भी मुख्य धारा से जोड़ा जाय। अगर मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तो उन 24 गांवों की स्थिति यह होगी कि न तो यह इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। स्टेट कहता है कि सेन्ट्रल की है रिफाइनरी और स्टेट कहता है कि हमारे यहाँ की है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। मान जाइये, बहुत कह दिया आपने। बैठ जाइये।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री उमा शंकर-

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये अवसर दिया। उद्योग विभाग और खनन के लिये कटौती प्रस्ताव पर हमारे कांग्रेस के नेता वरिष्ठ सदस्य आदरणीय प्रदीप साहब ने काफी विस्तार से चर्चा किया हम काफी दिनों से जब से सदन चल रहा है सदन में रहते हैं पर आज मुझे खुशी हुई, जैसे ही हमारे कांग्रेस के नेता खड़े होकर बोलते हैं हम लोगों में चर्चा होने लगती है कि उद्बोधन मथुरा हो जायेगा। लेकिन खुशी हुई कि उन्होंने पूरे प्रदेश की चर्चा की। लेकिन फिर भी हमारे दूसरे मथुरा के साथी है उन्होंने उसको मथुरा बना ही दिया।

श्री अध्यक्ष-

आप उसको बलिया बनाइये।

श्री उमाशंकर-

माननीय मंत्री जी ने जो उद्योग विभाग का बजट पेश किया उसके लिये उनका आभार व्यक्त करता हूँ आपने जो अभी घोषणा की, उद्योग नीति के बारे में इतने विस्तार से बताया और हमको भी आश्वस्त किया हमारा नाम ले करके कि उमाशंकर जो रसड़ा में 20 सालों से कताई मिल बन्द पड़ी है, तो जो हमारी पालिसी बनी है, जिस तरह से बन्द मिलों को चालू करने की योजना बनाई है उसमें आपकी रसड़ा कताई मिल भी शामिल है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवदेन करूँगा चूँकि अब तो मंत्री जी संसदीय कार्य मंत्री जी की जगह पर बैठ गये हैं, हमारे बलिया जनपद के भी हैं वह सारी उपलब्धि उन्हीं को जायेगी। मैं चाहूँगा कि यदि प्रदेश में 20-30 जितनी भी मिलें बन्द हैं जब आप अपना उत्तर देंगे तो उसमें यह कह दीजियेगा कि जब मैं बन्द मिलों को चालू कराऊंगा तो उसमें बलिया की रसड़ा कताई मिल जो 20 साल से बन्द है उसको सबसे पहले शुरू करवाऊंगा, इसके लिये माननीय मंत्री जी मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, समय मिला है एक समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर दूं, यह खनन से जुड़ा है। आज इससे पूरा प्रदेश प्रभावित है और सबसे ज्यादा हमारे राजस्व मंत्री जी विशेष रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान उनके विभाग का हो रहा है राजस्व का। मान्यवर, आपके सोनभद्र की जो खनन है वह 6 मार्च से बन्द है 6 मार्च से बन्द होने के बाद हालांकि पहल हो रही है लेकिन अभी तक खनन चालू नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, आप 6 मार्च के पहले का राजस्व निकलवा के देख लें जो राजस्व सरकार को प्राप्त होता था इस समय वह अब 5-6 प्रतिशत ही रह गया है। लेकिन इसके लिये जैसा संज्ञान में भी आया है कि हाई कोर्ट का ऐसा कोई आदेश हुआ है। मान्यवर, हम कतई इसके पक्षधर नहीं हैं कि बालू का अवैध खनन हो। लेकिन जो बालू के खदान हैं वह सरकार के जो भी मानक हैं, पर्यावरण के जो मानक हैं उसके अनुसार करके उन्हें चालू करना चाहिए। जितनी बड़ी-बड़ी योजनाएं जितना बड़ा-बड़ा बजट चाहे वह पी0डब्ल्यू0डी0 का हो चाहे किसी भी विभाग का है। अगर वहाँ पर खनन चालू नहीं होता तो आपके किसी भी विभाग के बजट को अमली जामा पहनाया जाना एक परसेन्ट भी संभव नही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा इसको वरीयता में लेकर खनन चलाया जाए। जैसा मैंने बताया कि हाईकोर्ट का भी आदेश आ गया है। वहां की लीज चालू कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठ जाएं।

श्री उमाशंकर-

मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सामान्य सी, व्यवहारिक सी दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। अभी उद्योगों की चर्चा हो रही थी, मान्यवर, कोई प्रदेश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक कि उसके उद्योग तरक्की न करें। आदरणीय धर्मपाल जी ने, राधा मोहन जी ने और प्रदीप माथुर जी ने विचार रखें इसी के साथ मै अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि चूँकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मैंने पहले भी यह बात कही थी और आज भी दोहरा रहा हूँ हमारा इन्फ्रास्ट्रचर, हमारी बिजली और सड़कें जो हैं, उसकी हालत आज ऐसी है कि कोई उद्योग लगाने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। एक बात जिसे विशेष रूप से कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ वह यह है कि बार-बार मैं सदन में सुनता हूँ और लम्बे समय से कई बार इस बात की चर्चा भी होती है। भ्रष्टाचार की भी बात होती है और उसका सीधा असर उद्योगों पर भी पड़ा है हमारे प्रदेश के चीनी उद्योग जो कौड़ी के भाव बिक गए हैं हमारे बराबर की एक रोहणा चीनी मिल है एक हजार करोड़ उसकी कीमत है। 65-70 करोड़ में उसको बेच दिया गया। मा0 सदस्या ने किसानों की बात को उनके दर्द को रक्खा वास्तव में मैं उनकी बात से बहुत भावुक हुआ, किसानों का पैसा किस प्रकार लुटाया गया। एक बात से मैं शंकाग्रस्त हूँ माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े मजबूत लोग सदन में सामने बैठे हैं। आप सरकार में आए, सरकार में आप आए अपने एजेन्डे के कारण या विशेष व्यक्तित्व के कारण आए हो, ठीक है पर सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था सरकार में आने का, कि कौन इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है। कौन उन गुण्डों का इलाज कर सकता है। इस कारण आप सरकार में आए और सदन में जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात होती है तो सामने से जवाब आता है हम बहुत गम्भीर है और गम्भीरता के साथ विचार कर रहे हैं कोई न कोई कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, पूरा का पूरा चीनी उद्योग भ्रष्टाचारियों ने बेच खाया क्या किसी के खिलाफ कार्यवाही हुई है। आज वह लोग पूरे उत्तर प्रदेश पर हावी होने जा रहे हैं जिन्होंने कौड़ियों के भाव चीनी मिल खरीदी है, जो खनन के माफिया थे जो शराब के माफिया थे अभी थोड़ी देर पहले आबकारी पर बहस हो रही थी, विद्वान सदस्य आबकारी पर बोल रहे थे। मैं नया सदस्य हूँ इसलिए चुप रहा, अध्यक्ष जी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने तो पश्चिम का दौरा किया है आप जानते है यह वहीं लोग हैं चाहे शराब हो, चाहे खनन हो, चाहे चीनी मिल हो तमाम उद्योगों पर फिर उन्हीं लोगों का कब्जा होता दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मजबूत लोगों की सरकार है किसान पुत्रों की सरकार है आदरणीय मुलायम सिंह जी जैसे सिद्धान्तवादी लोगों की सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ आगे बढ़िए और मजबूती के साथ कार्यवाही करिए। हम भले ही विपक्ष में बैठे हों लेकिन हम सब आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं।

(मेजें थपथपाई गईं।)

ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करिए उनको जेल भिजवाइए। जब आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और गम्भीर कार्यवाही करेंगे ऐसे लोगों को जेल भेंजेगे। खाली बन्दर घुड़की से काम चलने वाला नहीं है आप जब ऐसे लोगों को जेल भेजेंगे, तो प्रदेश का वातावरण बढ़िया होगा, तमाम सुविधायें होंगी और प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बनेगा। यह बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री नदीम जावेद-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात के लिए आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं कट मोशन के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, मैं जौनपुर से पहली बार चुनकर आया हूँ और थोड़ा सा जौनपुर को ब्रीफ भी कर दूँ कि 1399 से 1505 तक, लगभग 106 सालों तक, जौनपुर उत्तर भारत की राजधानी रहा है। एक सरहद उड़ीसा, एक सरहद नेपाल और एक सरहद दिल्ली लगती थी। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की तरक्की पंसद तारीख की बुनियाद भी वहीं पड़ी थी। जो सज्जाद रहीम ने डाली थी, मुंशी प्रेम चन्द्र, कृष्णचन्द्र, महापंडित राव, मुल्क राज आनन्द, फैज अहमद फैज, फिराख गोरखपुरी, मजाज, जैसे शायर अदीव लेखक और कवि इतिहासकार और साहित्यकार प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े थे और एक फ्रीडम स्ट्रगल में बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ था। मैं जो बुनियादी बात करना चाहता हूँ वह यह करना चाहता हूँ कि अर्थ व्यवस्था केवल राज्य की नहीं होती, केवल देश की नहीं होती बल्कि दुनिया से चलती है। 1989 में और 90 के दशक में सोवियत रूस के टूटने के बाद दुनिया की अर्थ व्यवस्था बदली। राजनीति भी बदली और व्यवस्था भी बदली और 1991 में जो तत्कालीन सरकार थी और आज के जो प्रधानमंत्री हैं, वह वित्त मंत्री थे, इस देश में नई आर्थिक नीतियाँ आई। उन आर्थिक नीतियों के चलते मल्टी नेशनल कम्पनीज को और प्राइवेट सेक्टर को विशेष रूप से तवज्जों इस देश के अन्दर दी गई। लेकिन जब 90 का दशक था, इस राज्य के अन्दर वह जो बुनियादी तौर पर वामपंथी दक्षिणपंथी और सामाजिक न्याय के जो आन्दोलन थे, 90 का दशक, 90 से लेकर 2000 तक, पूरा उस आन्दोलन का शिकार था और उसमें जो विकास

का मुद्दा था वह हाशिए पर था और जो राजनीतिक आन्दोलन थे, विचाराधारा के स्तर पर वह आगे थे। आज खुशी की बात है, सामजवादी पार्टी सत्ता में आई है। स्पष्ट जनादेश आया है और मैं उम्मीद करता हूँ, माननीय मंत्री जी ने इशारा भी किया कि यहाँ पर फिक्की आया, यहाँ पर एसोचेम आया, यहाँ पर सीआईआई आया, यहाँ पर अजीम प्रेम जी भी आ सकते हैं। यहाँ पर बिलगेट्स साहब जो दुनिया के बहुत बड़ी कम्पनी है कम्प्यूटर की उसके मालिक है, यहाँ आकर गए है, मुख्य मंत्री से मिलकर, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर पोंटीचड्ढा और जे0पी0 ग्रुप जैसे लोग आने वाले समय में नहीं आयेंगे। उससे बढ़कर जो दूसरी बात है वह यह है, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो यूरोप का माडल है, एकोनॉमिक पालिसी का और एकोनामिक ग्रोथ का उसके बारे में हमारे माथुर साहब ने बहुत विस्तार से बात की है। मैं पूरी दुनिया की बात कह रहा हूँ लेकिन जिलेवार गाजीपुर से गाजियाबाद तक देंखेगे तो हर जिले की कुछ विशेषता है। मऊ में आप चले जाइए, साड़ी, आप मुबारकपुर में चले जाइये तो साड़ी, बनारस बिस्मिल्ला खाँ की शहनाई की वजह से जरूर जाना जाता है, पूरी दुनिया के अन्दर, सेकुलरिजम की वजह से लेकिन बनारस अपनी साड़ियों की वजह से भी जाना जाता है। मुबारकपुर आ जाइये, वहाँ पर बुनाई का काम, आप भदोही चले आयें, वहाँ कारपेट का काम, आप लखनऊ चले आयें तो लखनऊ के चिकन का काम, आप मुरादाबाद चले जायें तो पीतल का काम, आप अलीगढ़ चले जायें, ताले का काम, आप सहारनपुर चले जायें, वहाँ लकड़ी का काम, हर जगह हर जिले की जो आइडेंटिटी है और जो पहचान है, वह कहीं न कहीं उस जिले के कल्चर के साथ भी जुड़ी हुई है और उसकी जो पहचान है वह वहाँ के काम की वजह से भी है। आज यह सवाल बड़ी जिम्मेदारी के साथ उठता है कि भाई हमारे पर लोग बहुत हैं, बेरोजगार बहुत हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, वह जनादेश केवल लैपटाप बाँटने और भत्ते का नहीं है, सरकारें आती है और चली जाती हैं। एक सरकार आती है और दूसरी चली जाती है। दूसरी जाती है तो तीसरी आती है, यह लोकतंत्र है और यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग आते हैं और जाते हैं लेकिन जो विश्वास आपको प्राप्त हुआ है, इस बार का जनादेश, इस बार का जनमत इस बात के लिए प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर को आप बदलेंगे। इसमें मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मल्टीनेशनल सेक्टर को जरूर बुलाइये आप बड़े उद्योग घरानों को जरूर बुलाइये लेकिन जो आपकी बुनियादी आईडेन्टिटी है, जो आपकी पहचान है, उसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। मैं दो बातें और अर्ज करता चलूँ, एक तो यह कि चीनी मिलों के बारे में विस्तार से बात हुई है। हमारे यहाँ एक चीनी मिल शाहगंज में, ललई भैय्या बैठे हैं, इनकी विधान सभा और मेरा घर एक ही है, मैं इनका वोटर हूँ तो वहाँ पर एक चीनी मिल को, नाम लेना मुनासिब नहीं है, बहुत कम पैसे में बेच दी गयी, शायद 9 करोड़ में बेची गयी है और उसकी जो टोटल कास्ट है वह तकरीबन

100 करोड़ रुपये के आसपास आती है। जो सतहरिया विकास केन्द्र है, नोयडा जैसा ही 1989 में बना था, कोलैप्स कर गया है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, कोई उसको सुनने वाला नहीं। ईस्टर्न यू0पी0 में आपको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। अगर ईर्स्टन यू0पी0 में इन्फ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं करेंगे तो यकीन जानिए, अपराध होगा, गुण्डा एलीमेण्ट होगा, हत्याएँ होंगी और यह सारी चीजें कहीं न कहीं रोजगार से जुड़ी होती है। जब लोंगों को आप रोजगार के अवसर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो लोग हाथ में असलहें उठा लेते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सम्बन्ध में भी काम करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, चूँकि आपने समय दे दिया है, 5 मिनट का, एक बात कह कर बात समाप्त करूँगा, वह यह है कि जो डेरी प्रोडक्ट्स हैं, अब तो रिलान्यस भी सब्जी बेंच रहा है, दिल्ली की शापिंग मॉल में जाइये तो रिलायन्स सब्जी बेच रहा है। वालमार्ट इस देश में आने की तैयारी में है, एफडीआई के थ्रू, वह भी किसानों की सब्जी बेचेंगे, आ गया है, वॉलमार्ट आ गया है, एफडीआई आने की तैयारी में है, आलमोस्ट कोई भी सरकार आयेगी, राइट, लेफ्ट सेण्टर सब को लाना है, एफडीआई आज नहीं तो कल आना है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि बिचौलिये पैसा खा रहे हैं किसान का हक और किसान का अधिकार अगर सचमुच देना चाहते हैं तो आपको फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स की तरफ फोकस करना पड़ेगा। ताकि उनका प्रोडक्ट समय से वहाँ पहुंचे और उनको सही पैसा मिले। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। अगर आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो विस्तार से बात होगी। मैं एक नज्म से अपनी बात समाप्त करता हूँ कि यह दागदाग उजाला यह शबगुजीदा सहर, वह इंतजार था जिसका यह वह सहर तो नहीं, यह वह सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं, चले चलो कि वह मंजिल अभी नहीं आयी। शुक्रिया।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत विस्तार से चर्चा हुयी। मैं समझता हूँ कि पूरी विधान सभा के सभी साथी लोग यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हो। क्योंकि पार्टी लाइन और जाति-बिरादरी से ऊपर उठकर प्रदेश का विकास होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें सभी विधायकों की सहमति है। सब चाहते हैं कि वर्तमान सरकार एक विजन के साथ एक दूरगामी सोच के साथ आगे चलें और इस प्रदेश को मजबूत बनाये। इंटनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात हो रही थी उसका जल्दी से प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाइये। खुर्जा की पोटरीज का बहुत बुरा हाल है। माननीय सदस्य पहाड़िया जी कह रहे हैं, इसी तरह से दिलनवाज खाँ साहब एक फल पट्टी के बारे में बात कर रहे हैं उनकी बात सुनिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपको रोकने का मेरी औकात नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ। लेकिन जो बातें आप कह चुके हैं उन्हीं को फिर रिपीट करेंगे तो आपका मान कम होगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, अभी इस सरकार को आये हुए 100 दिन भी पूरे नहीं हुये हैं और जो कुछ भी है। बस एक ग्राफ बढ़ा है वह क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। बाकी सारी चीजें ठीक हो रही हैं, सोच ठीक है। हम तो यह कहेंगे कि आप माहौल बनाइये। उस क्राइम को कंट्रोल करिये। प्रदेश की प्रगति की गाड़ी को आगे दौड़ाइये। यह तो अगले साल पूछेंगे। आपसे कि आपने एक साल में क्या किया। इसी बात को कहते हुए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित जो दूसरे विभाग हैं उन पर इतनी सार्थक चर्चा इस सदन में हुयी है। मान्यवर, आपने बहुत दौर देखे हैं आप इस सदन के सबसे अनुभवी सदस्यों में से एक हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी सार्थक चर्चा बहुत कम विषयों पर हो पाती है। इतना सहयोगात्मक वातावरण हो कि जो कटौती का प्रस्ताव कर रहे हों उनके उद्बोधन पर सत्तापक्ष की ओर से मेजे बजायी जाती हों। यह अनायास नहीं है यह बहुत गंभीर बात है। यह कोई आसान बात नहीं है और कटौती का समर्थन करने वाले लोग बहुत मजबूती से इस बात को महसूस कर रहे हों कि यह माहौल बदलना चाहिए और इस माहौल को बदलने के लिए जितना उनका सहयोग बन सकता है उतना सहयोग वह देना चाहते हैं इसमें किसी तरह की कोई कोताही कहीं से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लोक दल, दलों का कोई भेद नहीं रह गया और इसी बात की आवश्यकता है मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश जहां खड़ा है, हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में आज इस बात को महसूस कर रहे हैं यह बहुत सकारात्मक परिवर्तन है, कोई छोटी बात नहीं है कि हम अपने को घरौंदों में बांधने के बजाय आज उत्तर प्रदेश की मजबूती के लिए इतिहास ने जो जिम्मेदारी आज हम पर आरोपित की है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए उसी मजबूती के साथ खड़े होंगे। मन संकायें आती हैं, धर्म पाल जी कहा, राणा साहब ने कहा कैसे उद्योग आयेंगे बिजली है नहीं, सड़क है नहीं, ठीक बात सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली नहीं है, माहौल खराब है, साख हमारी बिगड़ी हुई है तो क्या सपने देखने बन्द किये जायं, क्या उद्योगों को लाने का जो प्रयास और प्रयत्न हो सकता है, उनकी योजनाएं बनानी बंद कर दी जायं, शायद नहीं, कभी नहीं और हम डा0 राम मनोहर लोहिया की सन्तान यकीन करते हैं इस बात में कि चोट चाहे जितनी भी लगे, लेकिन हम उससे मायूस

होने वाले लोग नहीं है। राजनीति में भी देश के जब अवसर आया तो एक इतनी बड़ी शख्सियत जिसके आगे कोई बात सोचने की गुंजाइश नहीं थी और उसके मुकाबिल भी जब सामने आने की बात हुई, तो डा0 राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि आज एक थोड़ी दरार मैं बना पाया हूँ अपने इस सीने की चोट से, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वह दिन आयेगा जब यह दरार चौड़ी होगी और दरार चौड़ी हो गई। वक्त ने देखा उसको, जो बात उन्होंने तब कहीं वह बात आज साबित हुई और उनकी राह पर चलने वाले हम लोग, जानते हैं उत्तर प्रदेश में माहौल खराब है, अविश्वसनीयता की स्थिति है, उद्योगों के अनुकूल माहौल उत्तर प्रदेश का नहीं है और फिर इसी उत्तर प्रदेश में उस माहौल को लाने के संकल्प के साथ हम अपनी योजना और अपना बजट लेकर के आये हैं मान्यवर और मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो सहयोग की बात हमारे मा0 सदस्यगण ने रखी है, उसके आधार पर हमको आगे बढ़ना चाहिए, हम पक्षधर हैं कुटीर उद्योगों के, हम पक्षधर हैं इनके कि हथकरघा चले, हम पक्षधर हैं कि मुरादाबाद का पीतल उद्योग तरक्की करे, भदोही का कालीन उद्योग संकट में नहीं पड़े, हम पक्षधर हैं इस बात के कि बनारस में फिर वैसी साड़ियां बने जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी अपनी पहचान है, मुबारकपुर का उद्योग मजबूत हो, मऊ हमारा गुजरात से पिट कर के जो बाहर गया पूरी तरह से सारी फैक्ट्रियां बन्द हो गई, सूत का काम बन्द हो गया, वह मऊ फिर से अपनी जगह पर अपनी स्थिति को हासिल कर सके, मान्यवर, हम इस बात के पक्षधर है और उसके लिए खाली सोचने की बात नहीं है। अभी आपने कहा आपको मथुरा, मथुरा के अलावा नहीं जाते, इस बात को विपक्ष के लोगों ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं तो कहता हीं नहीं, आप तो मथुरा के बाहर नहीं आते, लेकिन आज आये और फिर मथुरा में चले गये तो आपको मथुरा का हवाई अड्डा याद रहा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अकेले मथुरा नहीं, मथुरा-आगरा के बीच में हवाई अड्डा बने और कुशीनगर में हवाई अड्डा बने, इसके लिए हमारी सरकार आगे बढ़ चुकी है और जितनी जल्दी हो सकेगा, बनाने का काम करेंगे, केन्द्रीय सरकार से बात कर रहे हैं। मा0 मुख्य मंत्री ने, मा0 उड्डयन मंत्री से बात की है, उनका बयान अभी हमारे लोक दल के साथी मा0 पूरन जी बैठे हैं उन्होंने भी इस बारे में भी आज आपने अखबार देखा हो, इसलिए खुश होइये इस बात के लिए कि हम सारा परिवेश बना रहे हैं उसके लिए। मान्यवर, इसके अलावा दो-तीन बातें हैं, मा0 जावेद साहब को मैं बधाई देता हूँ, एक नौजवान जिन जज्बों के साथ, जो एहसास उसके भीतर जिन्दा हैं, उन एहसास को जो अन्दाज दे सकता है, उन अन्दाजों के साथ एक नौजवान जौनपुर की बात कर रहा है, हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं उनको और उनको विश्वास दिलाते हैं कि जो बात आपके मन में हैं, जो बात इस उत्तर प्रदेश के बदलाव की तस्वीर के साथ बदलाव करने वाले तमाम नौजवान जिनकी प्रदेश के बदलाव की तस्वीर के साथ बदलाव करने वाले तमाम नौजवान जिनकी आवाज बन कर के आप सब लोग हम लोग यहां आये हुए हैं, उनके मन में

है, उसी तरह का उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश में मा0 मुख्य मंत्री जी और यह सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से लगी हुई है और हम उन लोगों के माध्यम से इसको करना चाहते हैं। मान्यवर, एक बात शंका के तौर पर उठी और सही है खनिज के खनन के मामले में स्थिति आई, स्वाभाविक है, अभी यहां मा0 हुकुम सिंह जी आज कह रहे थे कि भई खनन ही नहीं होगा, गिट्टी नहीं आयेगीं, रोड़ी आयेगी नहीं, बालू मिलेगा नहीं, सड़कें कैसे बनेगी, नई सड़कें बनाने की जो योजना है कैसे बनेगी, पुल बनाने की योजना है कैसे बनेगी, विकास कैसे होगा, इसलिए स्वाभाविक है, वह चिन्ता, मैं उस चिन्ता को कोई नाजायज चिन्ता नहीं मानता, लेकिन परिस्थितियां दूसरी हैं मान्यवर, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो गया, उसमें पर्यावरण स्वच्छता के प्रमाण-पत्र के बिना हम जो पट्टे हैं उनको खनन की इजाजत नहीं दे सकते और लगभग 80 परसेण्ट ऐसे पट्टों की जगह पर जहां खनन हो रहा था वह काम बन्द है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना का माहौल तो नहीं बना सकते। हम तो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसको मानने वाले लोग हैं। लोग रहे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मानते थे। सुप्रीमकोर्ट फैसला दिया करें, हम अपना पत्थर का काम जारी रखेंगे। अपना पत्थर का खेल जारी रखेंगे, सुप्रीमकोर्ट कहता रहे। लेकिन, हम तो सुप्रीमकोर्ट की बात मानने वाले लोग है, इसलिए उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, सोनभद्र में दुर्घटना हो गई। वहाँ पर अवैध खनन हो रहा था और अवैध खनन के चलते 10 मजदूरों की मृत्यु हो गई और.....

(मा0 सदस्य श्रीमती रूबी प्रसाद ने मजदूरों की संख्या 15 बताई।)

श्री अम्बिका चौधरी-

हाँ, रूबी जी आप सही कह रही हैं आप ज्यादा बेहतर जानकारी जानती हैं। यह सही है। तो मान्यवर, उन मजदूरों की मृत्यु हो गई। अब उसमें भारत सरकार की डी0जी0एम0एस0 ने भी निर्देश दिए और डायरेक्टर जनरल माईनस की बात हमें माननी पड़ती है और वह खदानें बंद हो गयी थीं, लेकिन अब हमने उसे रिजॉल्व कर लिया है। वह सारी चीजें अब हल हो गई हैं और सोनभद्र के जिलाधिकारी को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि वह देखें कि जितनी वैध खदानें है, वह चालू होनी चाहिए और उनको चालू किए जाने के संबध में निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसलिए शंका में पड़ने की बात नहीं है। स्वयं सरकार इस बात के लिए चितिंत भी है और प्रयत्नशील भी है कि जितनी जल्दी हो सके विकास के कार्यों के लिए जो आवश्यकताएँ हैं, उनको पूरा किया जाए और आधारभूत अवस्थापना जिसकी बात हमने सबसे पहले की, जो हमारा इन्फ्रास्ट्रेक्चर है, बेसिक डेवलपमेंट के लिए, वह सबसे बड़ी प्राथमिकता है मान्यवर, और उस प्राथमिकता के लिए वह चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे हमारा कोई दूसरा सेक्टर हो, उन सबके लिए आधारभूत संरचना इस प्रदेश को मजबूती

से दी जा सके। इसके लिए रास्ते के जितने काँटे हैं, जितने अवरोध हैं, उनको उखाड़ फेंका जा सके। हम सब लोग मिल-जुल करके काम करें। यह मैं आपसे आह्वाहन करना चाहता हूँ और सरकार संकल्पबद्ध हैं। रात-दिन मेहनत करके हम इस काम को करना चाहते है। अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अभी कोई टिप्पणी आ रही थी, मा0 हुकुम सिंह जी ने भी कहा कि एक पालिटिकल बिल का सवाल है। दूसरी नीयत ऐसी है जो अपने स्टेट्स को इस यथास्थितिवाद से उबरने की बात नहीं करती है उसको भी नियंत्रित करने का काम सरकार के जिम्मे है, वह जिम्मेदारी हम लेते हैं। और उस जिम्मेदारी के नाते भी कहना चाहते हैं कि उनको यथास्थितिवाद से हटा करके उनको भी गतिशील और इस गति को और गति देने में उनकी प्रतिभा को जो इस्तेमाल हो सकता है। सरकार उसको भी कर लेगी और अपनी जो योजनाएँ हम लेकर के आएं हैं। आज बजट के माध्यम से जो बात आपके सामने रखना चाहते हैं, जो आज एक खांका हमने रखा है। उसके माध्यम से करेंगे और उसमें एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ असंतुलित विकास प्रकारांतर से विनाश का संकेत होता है। असंतुलित विकास हुआ है और असंतुलित विकास के कारण यह सारी स्थितियाँ हुई, तो विकास जौनपुर में भी हो, विकास मिर्जापुर में भी हो, विकास बनारस में भी, विकास बहराइच में भी हो, विकास गोरखपुर, महाराजगंज में भी हो और बलिया कैसे अछूता रह सकता है, उमाशंकर जी। आपने ठीक उल्लेख किया है, इसमें कुछ सवाल ही नहीं है, इस हिन्दुस्तान की आजादी में अपना एक स्थान रखने वाला बलिया, महर्षि भृगु की तपस्थली बलिया, जय प्रकाश नारायण की जन्मस्थली बलिया, चन्द्रशेखर की बलिया, जनेश्वर मिश्र की बलिया है, उसके पीछे रहने का कोई सवाल नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे सूबे का विकास करेगी और बलिया भी उसमें पीछे नहीं रहेगा, यह सदन को मैं पूरी मजबूती से बताना चाहता हूँ। और, पूर्वांचल को पीछे नहीं छूटने दिया जाएगा मान्यवर। और पश्चिम के साथी, जो हर सवाल पर उनके पेट में दर्द होता है, पूर्वांचल की बात की, बुंदेलखण्ड की बात की, हमारे क्षेत्र की बात नहीं की, एक बात सुनिये, जरा रूकिए, हर समय क्यों परेशान रहते हैं ? इतनी बेचैनी मुनासिब नहीं है। हर समय परेशान रहते हैं कि इसमें हमारी बात ही नहीं की, इसमें हमारी बात ही नहीं की गयी। बड़ी अजीब स्थिति है। हम एक बात कहते हैं लकवा वाले को कि इसके लिए दवा दिए हैं तो दूसरे कहते हैं कि हमको भी एक पुड़िया दे दीजिए हम भी खाना चाहते हैं। हमने कहा कि यह विकलांग है तो इसको कुर्सी दे दो कहा कि एक हमको भी दे दो हम भी व्हीलचेयर पर चलना चाहते हैं। अब जो हम बात करना चाहें पूर्वांचल विकास निधि की तो क्या उसी को गाजियाबाद में भी दे दें लोग बेचैनी से परेशान हो जाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की बात कीजिए यह सदन उत्तर प्रदेश का है। सबके अपने-अपने क्षेत्र हैं, अगर सूबे का विकास अगर बैलेन्स नहीं रहेगा, संतुलित नहीं रहेगा, तो आपके यहाँ और ज्यादा हो जाएगा। हम अंततः दिल्ली के आस-पास आएंगे, चिन्ता मत कीजिए। इसलिए मान्यवर, मैं

कहना चाहता हूँ कि सभी सदस्य ने अपने जिस उद्दात भावना का परिचय दिया है, उसी उद्दात भावना के साथ आप आज इस उद्योग विभाग से जुड़े हुए जितने मद हैं, उन सबको सर्वसम्मति से पारित करने का काम करें, इस विनती के साथ मैं पुनः आप सभी सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और सरकार के जो प्रयास हैं, उनके प्रति आपको विश्वास दिलाता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी हमारे बहुत ही विद्वान मा0 राजस्व मंत्री जी ने अभी सपनों की चर्चा की। सपनों की बात कही तो मुझे एक लाइन याद आ गई।

श्री सुरेश राणा-

मैं एक सेकेंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ

''मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है,

पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है''

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हम उन लोगों में से है कि-

''यह हवा जमाने की हमको क्या डरायेगी,

हम है वो दिया, जिसको आँधियों ने पाला है''

हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आँधियों में पाले हुये दिये हम हैं और विश्वास करते हैं कि उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से विकास के रास्ते पर ले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने

के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,21,56,07,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 94,21,43,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,92,80,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,90,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,89,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 जून, 2012 को नियम-51 की कुल 60 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री विशम्भर सिंह की वक्तव्य हेतु स्वीकृत बुन्देलखण्ड में 2007-08 में किसानों द्वारा निजी नलकूपों हेतु विद्युत कनेक्शन छूट देकर उपलब्ध कराने हेतु कराये गये पंजीकरण के आधार पर छूट के साथ विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय 'गामा' की वक्तव्य हेतु स्वीकृत, जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री सुरेश राणा की वक्तव्य हेतु स्वीकृत विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में जंगली सुअरों द्वारा फैलाये जा रहे आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौथी सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया की वक्तव्य हेतु स्वीकृत महोबा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जिला अस्पताल का दर्जा दिये जाने के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्रीमती नंदिता शुक्ला की वक्तव्य हेतु स्वीकृत जनपद गोण्डा के ब्लाक मुजेहना अन्तर्गत ग्राम बनकसिया दतौली मोतीगंज मार्ग पर अवैध रूप से आरा मशीन का संचालन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छठी सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की वक्तव्य हेतु स्वीकृत जनपद प्रबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र शामली में फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री शेरबहादुर सिंह की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में

मालीपुर से जलालपुर होते हुये रामगढ़ तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री जाकिर अली की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी में मानक के अनुरूप कानून व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु नया थाना बनाये जाने के संबंध में है। नवीं सूचना श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत जनपद लखनऊ के कुर्मांचल नगर एवं समीपवर्ती इलाकों में विद्युत के अत्यन्त लो-वोल्टेज से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दसवीं सूचना डा0 धर्म सिंह सैनी की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत सहारनपुर में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के शेष वेतन का भुगतान कराये जाने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्रीमती हेमलता चौधरी की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत बागपत में वाटर लेविल नीचे होने तथा नहरों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। बारहवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशिमी की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत बलरामपुर स्थित विकास खण्ड रेहराबाजार के कई ग्रामों में विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री कृष्ण पाल राजपूत की ध्यानाकर्षण हेतु झांसी के बबीना के अन्तर्गत पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बाढ़ के कारण डूब जाने वाले गांवों को बाद में पुनः घर बनाते समय खनन् विभाग द्वारा प्रताड़ित किये जाने के संबंध में है। शेष सूचनायें अस्वीकृत की जाती है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना के कतिपय गांवों में कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा प्रजापति, यादव व आदिवासी समाज के लोगों को उनके मूल निवास स्थान से अन्यत्र विस्थापित करने का दबाव बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री-(श्री अम्बिका चौधरी)-

नियम-51 के अन्तर्गत मा0 सदस्य विधान सभा श्री दीपक पटेल द्वारा सूचना दी गई है।

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (श्री वसीम अहमद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[कि ग्राम सभा तेदुआवन, विकास खण्ड चाका, परगना अरैल, तहसील करछना, थाना औद्योगिक क्षेत्र के दबंग व्यक्तियों द्वारा राजनैतिक प्रतिद्वन्दतावश प्रजापति, यादव व आदिवासी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समाज के लोगों को गांव छोड़कर अन्यत्र विस्थापित हो जाने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उपरोक्त बस्ती सैकड़ों वर्ष पुरानी है। उपरोक्त दबंगों द्वारा प्रजापति, यादव व आदिवासी समाज के लोगों का रास्ता भी अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे सम्पूर्ण बस्ती के लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं तथा भयक्रान्त हैं। स्थानीय प्रशासन राजनैतिक दबाववश किमकर्तव्यविमूढ़ हैं जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है तथा जातिगत संघर्ष की सम्भावना है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम सभा तेंदुआवन, थाना औद्योगिक क्षेत्र, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत रामसजीवन प्रजापति पुत्र सालिकराम प्रजापति को प्रमोद पाण्डेय पुत्र काशीनाथ पाण्डेय के पूर्वजों ने बसाया था जिसपर प्रजापति व अन्य जाति के लोग रह रहे हैं। इनके द्वारा प्रमोद पाण्डेय की खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर एस0डी0एम0 करछना/बी0डी0ओ0 व स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को दिनांक 5.3.12 को धारा 107/16 में पाबन्द कराया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में एस0डी0एम0 करछना से जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं किया गया है। यथास्थिति बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों को निर्देशित किया गया है। जातिगत संघर्ष व जनता में आक्रोश जैसी कोई स्थिति नहीं है।]

श्री दीपक पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जवाब एकदम नाकाफी है। हम यह बताना चाहेगें कि वहाँ 200 साल से लोग रह रहे हैं और 5-6 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। वह जमीन जिस पर वह लोग निवास कर रहे हैं, उसको एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारे नाम से है। अब यह रेवन्यू विभाग का मामला है, जब 200 साल से लोग वहां रह रहे हैं तो उनके नाम अभी तक दर्ज क्यों नहीं किया। वह व्यक्ति उनको रोज धमकी दे रहा है कि हट जाइये यहां से। यह ला एंड आर्डर की प्राब्लम भी है, वहां रास्ता रोक दिया गया है। वहां पर ज्यादा संख्या प्रजापति समाज के लोगों की है, सैकड़ों उनके घर हैं और उनका काम मिट्टी से सामान बनाने का है, वह भी सब बंद पड़ा हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि इसको आप दिखवा लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने नियम-51 के अन्तर्गत जो सूचना दी है, यह सही बात है कि प्रजापति समाज के जो लोग हैं, वह कई पीढ़ियों से उस जमीन पर रह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वह भूमि उनकी नहीं थी और वह भूमि मान्यवर, प्रमोद पाण्डेय पुत्र काशी नाथ पाण्डेय के पूर्वजों ने उस पर बसाया था आज जो लोग हैं, उनके पूर्वजों को, यह बात सही है। यह लोग उनकी खाली पड़ी जमीन को कब्जा कर रहे थे जिसका विवाद हो रहा था लेकिन उस विवाद को भी शांत कर दिया गया, दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाये जाने

के लिये समुचित प्रबन्ध कर दिये गये हैं और इसके अतिरिक्त इनके मन में कोई बात होगी तो माननीय सदस्य आप मुझको अलग से दे दीजियेगा तो उसमें जरूरी कार्यवाही हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का यह कहना है कि 100 बरस से रह रहे हैं तो 100 बरस से जिस जमीन पर रहते है तो उसमें उनका स्वामित्व बनता है कि नहीं?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, दो बातें हैं जो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आप सुविज्ञ हैं कि जब जमींदारी एवयूल्यूशन लागू हुआ तो उस समय आप उसके पूर्व के मुकदमें को भी लड़ रहे थे और जमींदारी एवयूल्यूशन के बाद के मुकदमों को भी आपने छात्र जीवन से लड़ने का काम किया, इस कानून को आप बहुत बेहतर समझते हैं। तो इसलिये आपसे निवेदन करता हूँ और माननीय सदस्य भी इसको सुनेगें कि जमींदारी का जब खात्मा हुआ तो उस खात्मे के समय कई श्रेणी के टेनेन्ट्स बनाये गये और इसलिए सारी जमीनें भूमिधरों के लिए नहीं आयी। उसमें कुछ जमींदारी की जमीन रह गयी, जो आबादी थी उसका कोई इंद्राज नहीं हुआ इसलिए उस भूमि को निश्चित रूप से अलग से देखना पड़ेगा और मात्र बस जाने से, वह किस श्रेणी की जमीन थी, शीर की जमीन किसी की रही हो और उसमें किसी को बसा दिया गया हो तो शीर की जमीन बसने के कारण तो उनको नहीं मिल पायेगी। लेकिन अगर आबादी की जमीन रही हो और आबादी की जमीन में कोई बस गया तो निश्चित रूप से उसका अधिकार है, उसके वारिसों का अधिकार है, उसको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने माननीय सदस्य से कहा कि आप रेवेन्यू रिकार्ड की कोई बात होगी तो मुझे बता दीजिएगा। मैं देख लूँगा, न्यायोचित तरीके से मदद होगी, किसी को दबंगई करने की इजाजत नहीं होगी।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में घाघरा नदी के किनारे तेजी से हो रहे कटान को तत्काल रोके जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम-51 के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री जियाउद्दीन रिजवी जी हैं?

(माननीय सदस्य के अनुपस्थित होने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया)

जनपद महराजगंज के क्षेत्र पंचायत नौतनवां अन्तर्गत महाव नाला में बाढ़ आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कुंवर कौशल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

महराजगंज जनपद के क्षेत्र पंचायत नौतनवां अन्तर्गत स्थित महाव नाला एक प्राकृतिक नाला है।

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[जिसका उद्गम नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में है। यह नाला नेपाल के पहाड़ियों के तीव्र ढलान वाले क्षेत्र से आकर महराजगंज के मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होता है। इस नाले का कैचमेन्ट एरिया 650 वर्ग कि0मी0 है तथा भारतीय सीमा में इसकी लम्बाई 23.00 कि0मी0 है। इस नाले का आउटफाल बधेल नाले के माध्यम से रोहिन नदी में होता है। इस नाले के बघेल नाले में आउटफाल स्थल कि0मी0 0.00 से कि0मी0 8.00 तक का भाग सुरक्षित वन क्षेत्र में स्थित है। इस नाले के कि0मी0 8.00 से कि0मी0 23.00 तक चैनेलाईजेशन का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1998 में कराया गया था, जिसके दौरान खुदाई से निकली हुई मिट्टी का डिस्पोजल नाले के दोनों किनारे पर किया गया था। यह सिंचाई विभाग के मानकों के अनुसार निर्मित तटबंध न होकर डिस्पोजल की मिट्टी से निर्मित स्वायल बैंक है। चूंकि यह बैंक बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु मानकों के अनुसार निर्मित तटबंध नहीं है, अतः नाले में तीव्र वेग से प्रवाह होने पर तथा इन स्वायल बैंक के ऊपर से पानी गुजरने की स्थिति में यह बैंक जगह-जगह पर प्रायः टूट जाते हैं जिससे पानी का फैलाव होता है परन्तु क्षेत्र एवं नाले का ढलान तीव्र होने के कारण पानी का जमात, फैलाव वाले क्षेत्र में अधिक देर तक नहीं रहता है। स्वायल बैंक के टूटने पर उन्हें पुनर्स्थापित करने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा की जाती है। यह पुनर्स्थापना का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा क्षेत्रीय जनता की मांग पर कराया गया है तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा भी मनरेगा के अन्तर्गत जिलाधिकारी से धनराशि प्राप्त करके कराया गया है। वन विभाग द्वारा सुरक्षित क्षेत्र में पड़ने वाले नाले की रीच कि0मी0 0.00 से कि0मी0 8.00 में खुदाई कार्य मनरेगा के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से कराया गया है।

क्षेत्र पंचायत नौतनवा द्वारा वर्ष 2011-12 में कराये गये कार्य के सम्बन्ध में धन के बन्दर-बाँट किये जाने से सम्बन्धित बिन्दु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

4-मा0 सदस्य द्वारा क्षतिग्रस्त तटबंध की तत्काल मरम्मत सम्बन्धी मांग के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नाले के दोनों किनारे और निर्मित स्वायल बैंक मानकों के अनुसार बाढ़ सुरक्षा हेतु निर्मित तटबंध नहीं है अतः इनकी मरम्मत करना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा।]

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री कुँवर कौशल सिंह-

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्षेत्र पंचायत नौतनवा द्वारा महाव नाले पर वर्ष 2011-12 में 39.89 लाख रुपये मनरेगा द्वारा खर्च किया गया और आपने सिंचाई विभाग से जवाब हमको दिया है कि इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। हमने बात किया क्षेत्र पंचायत की और जवाब आया सिंचाई विभाग से।

श्री अध्यक्ष-

जवाब वही तो है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मा0 सदस्य ने ठीक आपत्ति उठायी है और बात सही है। आप इसमें यह देखें कि इन्होंने यह कहा कि क्षेत्र पंचायत नौतनवा द्वारा इस पर इतना धन खर्च किया गया। सिंचाई विभाग का उत्तर यह आ गया कि यह बाढ़ विभाग के मानकों के अनुरूप नहीं है इसलिए सिंचाई विभाग इसमें कुछ नहीं कर सकता। सिंचाई विभाग ने उत्तर अपनी जगह ठीक दिया। लेकिन यह प्रश्न सिंचाई विभाग को नहीं जाना चाहिए और किन कारणों से पंचायत को न जाकर सिंचाई विभाग को चला गया, इसको दिखवा लेंगे। उनकी आपत्ति सही है।

श्री अध्यक्ष

माननीय राजस्व मंत्री जी, इसको क्षेत्र पंचायत भेजकर जवाब मंगवा लें।

श्री अम्बिका चौधरी

इस सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायत जिसने धन खर्च किया है उसी का उत्तर आना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यू0पी0टी0ई0टी0 में संस्कृत भाषा को विकल्प के रूप में रखे जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) है ? (माननीय सदस्य अनुपस्थित है।) जो नहीं आता है उसका निरस्त हो जाता है।

बाल विकास एवं पुष्टाहार बेसिक शिक्षा मंत्री-(श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, इस वक्त तक हम लोग जवाब देने के लिए बैठे रहते है और माननीय सदस्य नहीं रहते है तो हमारा समय बेकार हो जाता है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस मामले में सब तैयारी कर रहा हूँ और जो इस प्रकार से प्रश्न देकर के नहीं रहेंगे, अब नियम-51 में उनके प्रश्न लिये ही नहीं जायेंगे।

जनपद पीलीभीत मे स्टेट फार्मेसी के पद पर तैनात अधीक्षक द्वारा अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र एवं फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री प्रकाश चन्द्र, अधीक्षक, स्टेट फार्मेसी, पीलीभीत में तैनात है, इनका चयन लोक सेवा आयोग से अनुसूचित जाति आरक्षण के तहत स्टेट फार्मेसी अधीक्षक के पद पर लखनऊ में हुआ था.....

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (शिवपाल सिंह यादव)-

अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी

[इन्होंने जो अनुभव प्रमाण पत्र मुजफफरनगर फार्मेसी का लगाया था, वह फर्जी है। चूँकि मुजफ्फरनगर मे कोई फार्मेसी है ही नहीं। अतांराकित प्रश्न सं0-66 विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 हेतु मा0 विधायक द्वारा पूछा गया था, जिसके उत्तर में तत्कालीन मंत्री, चिकित्सा शिक्षा द्वारा उत्तर दिया गया कि लखनऊ में तैनात रहते हुए कई लाख रूपये का पुरानी ईंट भवन निर्माण में जो निकली थी, उसका भी उपयोग ठेकेदारों से मिल कर करा लिया गया। तिल का तेल को लैब द्वारा खेल किया गया, उसका भी भुगतान कर दिया गया । प्रकरण की जांच हुई, जांच अधिकारी द्वारा टेलीफोनिक वार्ता कर अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन करते हुए जांच रिपोर्ट प्रकाश चन्द्र के पक्ष में देने का कार्य किया। काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद अभी तक कार्यवाही नहीं की गयी और न ही उन्हें दण्डित किया।

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत उक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि श्री प्रकाश चन्द्र तत्कालीन अधीक्षक, स्टेट फार्मेसी लखनऊ के विरूद्ध उपरोक्त बिन्दुओं पर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोप पत्र निर्गत किया जा चुका है। अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी निदेशक, आयुर्वेद को नामित किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रजनी तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, आवास, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद हरदोई विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत निम्नलिखित चार सेतु.....

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[(1) विकास खण्ड साण्डी के अन्तर्गत चौसारश्रीमऊ मार्ग पर गंभीरी नदी पर, (2) विकास खण्ड हरपालपुर में शेखापुर नगरिया महमदपुर मार्ग पर गंभीरी नदी पर, (3) विकास खण्ड-साण्डी में भदार श्रीमऊ मार्ग पर गंभीरी नदी पर, (4) विकास खण्ड-साण्डी में नोनखारा मंसूरपुर मार्ग पर नीलम नदी पर निर्माण हेतु वर्ष 2010-11 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हुई थी जिसका शासनादेश सं0-1948/23-9-2010-15(नाबार्ड)/10, दिनांक 03 दिसम्बर, 2010 है। उक्त सभी सेतुओं का निर्माण कार्य वर्ष 2011 में प्रारम्भ हुआ था जो अब पूर्ण होने की अवस्था में है लेकिन वर्तमान सरकार के गठन होने के उपरान्त ही उक्त सभी सेतुओं पर दिनांक 27 अगस्त 2006, श्री विश्राम यादव, विधायक(बिलग्राम) की अध्यक्षता में मा0 शिवपाल जी के शिलापट लगा दिये गये है, जबकि वर्ष 2006 में उपरोक्त सेतुओं का अस्तित्व ही नहीं था जबकि उक्त सभी सेतुओं का निर्माण कार्य वर्ष 2011 में ही प्रारम्भ हुआ। उक्त सेतुओं पर गलत तथ्यों के शिलापट लगाये जाने से क्षेत्र जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

2-उक्त के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जनपद हरदोई में आर0आई0डी0एफ0 नाबार्ड-16 योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं0-1948/23-9-2010-15(नाबार्ड)/10, दिनांक 03 दिसम्बर,2010 के द्वारा निम्नलिखित सेतुओं के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी :-

(1) विकास खण्ड-साण्डी के अन्तर्गत चौसार श्रीमऊ मार्ग पर गंभीरी नदी पर सेतु।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) विकास खण्ड-हरपालपुर में शेखापुर नगरिया महमदपुर मार्ग पर गंभीरी नदी पर सेतु।

(3) विकास खण्ड-साण्डी में भदार श्रीमऊ मार्ग पर गंभीरी नदी पर सेतु।

(4) विकास खण्ड-साण्डी में नोनखारा मंसूरपुर से कुचिता मार्ग पर गम्भीरी नदी पर सेतु।

उपरोक्त सेतुओं में से क्रमांक-1,2, व 3 पर अंकित सेतुओं का निर्माण कार्य सेतु निगम द्वारा निम्नवत् किया गया है:-

क्र0 सं0	सेतु का नाम	सेतु की लम्बाई	सेतु की लागत/सेतु अंश	प्रारम्भ करने की तिथि	पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	विकास खण्ड-साण्डी के अन्तर्गत चौसार श्रीमऊ मार्ग पर गंभीरी नदी पर सेतु।	70.40 मीटर	287.83 / 216.26 लाख	22-01-11	30-11-11
2	विकास खण्ड-हरपालपुर के अन्तर्गत शेखापुर नगरिया महमदपुर मार्ग पर गंभीरी नदी पर सेतु।	89.15 मीटर	376.83 / 298.96 लाख	31-01-11	31-12-11
3	विकास खण्ड-साण्डी के अन्तर्गत भादर श्रीमऊ मार्ग पर गंभीरी नदी पर सेतु।	70.40 मीटर	323.49 / 200.63 लाख	29-01-11	29-02-12

क्रमांक-4 पर अंकित सेतु विकास खण्ड-साण्डी में नोनखारा मंसूरपुर से कुचिता मार्ग पर गम्भीरी नदी सेतु के लिए स्वीकृत था, जबकि कार्य स्थल पर नीलम नदी बहती है, अतः इस सेतु का निर्माण नहीं किया गया है। अतः स्वीकृति के अनुरूप निर्माण न किये जाने के कारण सेतु के निरस्तीकरण का प्रस्ताव मुख्य परियोजना प्रबन्धक (नियोजन), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ द्वारा मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को दिनांक 30-09-11 को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु नाबार्ड को भेजने का अनुरोध किया गया है।

जहां तक उक्त सेतुओं पर शिलापट लगाये जाने का प्रश्न है, लोक निर्माण विभाग तथा सेतु निगम द्वारा इन सेतुओं पर कोई शिलापट नहीं लगाया गया है।]

श्रीमती रजनी तिवारी-

मान्यवर, मैंने नियम- 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी थी कि हमारी विधान सभा में उक्त सेतुओं पर गलत तथ्यों के शिलापट लगाये जाने से क्षेत्र की जनता में रोष एवं आक्रोश

व्याप्त है। इसमें सरकार का जवाब आया है कि उक्त के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जनपद हरदोई में आर0आई0डी0 एफ0नाबार्ड-16 योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं01948/23-9-2010-15 नाबार्ड/10 दिनांक 3 दिसम्बर,2010 के द्वारा निम्नलिखित सेतुओं के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे प्रश्न पूछिए।

श्रीमती रजनी तिवारी-

अध्यक्ष जी उक्त सेतु में कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 22-1-11, 30-1-11 व 29-1-11 है और पूर्ण होने की तिथि 30-11-11, 31-12-11 व 29-2-12 है जबकि वह सेतु पूरे बन गए है तो उक्त सेतुओं पर शिलापट लगाए जाने के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी का जवाब है जहाँ तक उक्त सेतुओं पर शिलापट लगाये जाने के प्रश्न है लोक निर्माण विभाग तथा सेतु निगम द्वारा इन सेतुओं पर कोई शिलापट नहीं लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पर जो भी शिलापट पर लिखा हुआ है उसको नोट करके मैंने यहाँ पर दिखाया था उस पर लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड हरपालपुर चौसार श्रीमऊ मार्ग गंभीरी नदी पर गंभीरी नदी सेतु का शिलान्यास श्री शिवपाल सिंह यादव माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग ऊर्जा एवं भूतत्व एवं खनिज निगम खनिकर्म तथा कृषि निवेश कृषि व्यापार विपणन निर्यात विभाग, उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा श्री विश्राम सिंह यादव माननीय विधायक विलग्राम की अध्यक्षता में दिनांक 27 अगस्त, 2006 को सम्पन्न हुआ। माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहती हूँ कि जब इनका निर्माण हुआ है तो 22-1-11, 30-1-11, 29-1-11 उस समय मैं ही वहाँ पर विधायक थी। तो उस समय यहाँ जो पत्थर लगाया गया वह नहीं समझ में आया कि कैसे लगाया गया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी यह पुल मैंने ही स्वीकृत किए थे पुरानी सरकार में उस समय वहाँ विधायक थे स्व0 विश्राम सिंह जी तो जब मीटिंग हुई शिलान्यास वगैरह सब हुए तो मैंने स्वयं वहाँ शिलान्यास किए थे और स्व0 विश्राम सिंह यादव वहाँ से विधायक थे उनकी अध्यक्षता में यह शिलान्यास हुआ था । चलिए अब उसका उद्घाटन बहुत जल्दी कर देंगे। पहले शिलान्यास किया था अब उद्घाटन कर देंगे।

श्रीमती रजनी तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जहाँ पर आपने विश्राम सिंह यादव जी का नाम लिखा है और 2011 में यह

बनने शुरू हुए और 2011 मे ंयह बनकर तैयार हुए उस समय क्या विश्राम सिंह यादव का नाम लिखा जाएगा ?

श्री अध्यक्ष-

जब शिलान्यास हुआ उस समय नाम लिख गया। बनना कब से शुरू हुआ इससे क्या मतलब मैं प्रकरण समझ गया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, इस तरह के बहुत सारे मामले है मैंने बहुत से शिलान्यास किए थे लेकिन पुरानी सरकार ने अपने घरों पर पत्थर रखे रहे अभी मैंने औरैया में पत्थर पकड़े हैं जो शिलान्यास हमने किया था वह थे। कुछ अधिकारियों ने स्टोर में भी पत्थर नहीं रखे थे पुरानी सरकार के अधिकारी ने अपने घर में आंगन में पलटकर पत्थर लगा लिए। उन अधिकारियों के खिलाफ भी हम कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अगर ऐसा करते हैं तो बहुत लोग जाएंगे। हमने 500 बेड का अस्पताल है कैली उसका शिलान्यास किया था वह शिलापट ले जाकर आड़ में कर दिया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी अब सदस्य माननीया रजनी तिवारी जी है चलिए हम उद्घाटन कर देंगे तब आपका भी नाम आ जाएगा।

श्रीमती रजनी तिवारी-

इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, इसी तरह का ढ़ाई-ढ़ाई करोड़ का पुल माननीय मंत्री जी ने शिलान्यास किया था। ढाई-ढाई करोड़ रूपये उस जमाने में दिया था और आज तक वह शिलापट जो लगना चाहिए था हमारे यहाँ बडहरडीह कटया जमालपुर पर दो पुल बने थे उस पर भी पिछली सरकार ने मुख्य मंत्री जी का उद्घाटन का तो लग गया लेकिन आपने पैसा दिया था ढाई-ढाई करोड़ का वह पत्थर नहीं लगा।

श्री अध्यक्ष-

कहाँ तक देखिएगा पत्थर तोड़कर उसमें अपना पत्थर लगाया गया।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत जिगना, लालगंज व हलिया के पावर हाउसों की जर्जर स्थिति के कारण बिजली सप्लाई की समस्या के संबंध में श्री भाई लाल कोल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, जनपद मिर्जापुर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत पावर हाउस ....

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[के 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र जिगना, लालगंज एवं हलिया यद्यपि पुराने हैं परन्तु विद्युत उपकेन्द्र के समस्त प्रणाली उपकरण मरम्मत के उपरान्त सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। इन उपकेन्द्रों से विद्युत आपूर्ति निर्धारित शिड्यूल के अनुसार 10 घण्टे है। माह मई, 2012 की औसत विद्युत आपूर्ति निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	उपकेन्द्र का नाम	औसत विद्युत आपूर्ति माह मई, 2012
1	जिगना	9.10
2	लालगंज	8.40
3	हलिया	8.30

300 से अधिक आबादी के समस्त अविद्युतीकृत मजरों को राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-II में सम्मिलित कर लिया गया है। अन्य ग्राम और मजरों मे टूट फूट होने पर समय समय पर बिजनेस प्लान में क्रमशः प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से चल रही है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के बलसर रिगौली बाँध से धानी बाजार को बाढ़ से सुरक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बजरंग बहादुर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

धर्म सिंह सैनी है। नहीं हैं, छोड़िये। अब इन लोगों का नाम नोट किया जाना चाहिए।

राजस्व अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धक मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, बाद में लिखवाइयेगा। पहले पढ़वाइये।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, इतना जल्दी मत मचाइये। आप राजस्व मंत्री हैं खेती वाले हैं।

(माननीय सदस्य के अनुपस्थित होने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया)

जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में किसानों के हित में उपमण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

संजय कपूर जी हैं, नहीं हैं, रवाना।

राजस्व अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धक मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यहां सिर्फ आप हैं।

(माननीय सदस्य के अनुपस्थित होने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया)

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय मिश्र 'टेनी' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

बजरंग बहादुर सिंह नहीं है। अब नियम-51, मा0 सदस्य जो उपस्थित हैं इन लोगों को आगाह कर दीजियेगा कि आगे से नियम-51 में टाइम नहीं वेस्ट किया जायेगा।

(माननीय सदस्य के अनुपस्थित होने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया)

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत पड़ने वाले कस्बे नकुड़, सरसवां एवं सुल्तानपुर चिलकाना में विद्युत सप्लाई के सम्बन्ध में डा0 धर्म सिंह सैनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

अजय मिश्रा, नहीं हैं।

(माननीय सदस्य के अनुपस्थित होने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया)

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के ब्लाक सैंया में ग्वालियर नेशनल हाई-वे रोड पर बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु बने सरकारी कालेज में प्रशिक्षण बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

भगवान सिंह कुशवाहा हैं।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री-(श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य की नोटिस में मुख्यतः यह उल्लेख किया गया है कि....

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री-(श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[कृपया यह अवगत कराना है कि जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के ब्लाक-सैंया में ग्वालियर नेशनल हाइवे रोड पर बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु एक सरकारी कालेज बना है, जिसमें विगत कई वर्षों से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण कराना बन्द कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त कालेज का भवन खाली है। कालेज की बहुमूल्य जमीन एवं भवन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है तथा भवन में से चौखट, जंगले आदि चोरी कर लिये गये हैं। उक्त भवन एवं जमीन पर भूमाफियों द्वारा कब्जा करने से रोका जाए तथा जिन्होंने कब्जा किया है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही किया जाए तथा मैं चाहूँगा कि यदि उक्त भवन में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोल दिया जाए जिससे जमीन पर कब्जा एवं भवन की क्षति दोनों ही रुकने का काम होगा। साथ ही क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा क्षेत्र में कोई भी राजकीय कन्या महाविद्यालय भी नहीं है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की माँग करता हूँ।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ''जनपद आगरा के विकास खण्ड सैंया में राजकीय दीक्षा विद्यालय संचालित था, जिसमें बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। डायट की स्थापना के उपरान्त बी0टी0सी0 प्रशिक्षण डायट में संचालित होने लगा। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा के सचिव, उच्च शिक्षा को सम्बोधित पत्र दिनांक 23-12-2009 में उक्त परिसर में राजकीय विद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में बिन्दुवार स्थिति इस प्रकार है :-

1-राजकीय दीक्षा विद्यालय की भूमि पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सैंया एवं प्राथमिक विद्यालय, सैंया, तृतीय संचालित हैं।

2-उक्त विद्यालय का कुल क्षेत्रफल 24 बीघा है, जिसमें मात्र 10 बीघा जमीन उपयोग में लायी जा रही है जिसके अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सैंया द्वितीय एवं प्राथमिक विद्यालय सैंया तृतीय संचालित है। लगभग 11 बीघा क्षेत्रफल में राजकीय दीक्षा विद्यालय, सैंया का भवन बना है, जिसमें मुख्य भवन में 10 कमरे, पुराने छात्रावास में 12 कमरे तथा नवीन छात्रावास में 22 कमरे हैं एवं 16 अध्यापक निवास हैं। इसके अतिरिक्त 2 बीघा क्षेत्रफल विद्यालय के कृषि फार्म का है जो रिक्त है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का दायित्व बढ़ेगा साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के सन्दर्भ में अध्यापकों के प्रशिक्षण के सन्दर्भ में भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के उत्तरदायित्व और भौतिक संसाधनों में विस्तार होना है। अतः संस्थान के हित में उक्त भूमि संस्थान के पास रहना कदाचित उचित होगा।'']

(श्री भगवान सिंह कुशवाहा द्वारा खड़े रहकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

भगवान सिंह जी, यह केवल वक्तव्य है, आप देख लो, कोई जरूरी हो तो लिख के बता देना। यह केवल वक्तव्य है इसमें कुछ पूछा नहीं जाता।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

मान्यवर, इसमें डायट की जमीन खाली है और उस पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लिख करके देना, यह केवल वक्तव्य है। मा0 मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, इसमें केवल वक्तव्य है, रुक जाइये न। ये कुछ पूछ रहे हैं क्या कह रहे हैं, बताइये न।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

मान्यवर, उस पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, जो सरकारी बिल्डिंग बनी हुयी है।

बाल विकास पुष्टाहार एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह आपने मंजूर किया है केवल वक्तव्य में। लेकिन यहां पर डायट की स्थापना हो रही है। इसलिये जमीन कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा है, वहां पर सरकारी डायट की स्थापना होगी, उस जमीन की पूरी सुरक्षा की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 23 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
दिनांकः 14 जून, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ 121 पर)

श्री नितिन अग्रवाल-

मा अध्यक्ष जी

(I) बाढ़ खण्ड का एक उपखण्ड हरदोई जनपद में बाढ़ के कार्य के सम्पादन हेतु अलग से खोला जाना नितान्त आवश्यक है।

(II) सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता की पद स्थापना हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई में तत्काल की जाय।

(III) 15 जून के बाद जब तक मानसून सक्रिय न हो नदी और नालों तली की सफाई हेतु अनुमति दी जाय अन्यथा सफाई नहीं हो सकती।

(IV) सुखेता नाला जनपद हरदोई के विकास खण्ड शाहाबाद, टोडरपुर वावन होते हुए साण्डी के समीप गर्रा नदी में समाहित हो जाता है। थाना लोनार के समीप सुखेता नाला दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग लोनार, दौली आदि गाँवों को जोड़ते हुए मलवा अखवेलपुर के पास गर्रा नदी में समाहित होता है। दूसरा भाग लोनार के पास नागामऊ के समीप गर्रा में गिर जाता है। गर्मियों में नाले का पानी दौली लोनार आदि को नहीं मिल पाता है। वीयर बनने से पानी सुखेता नाला होते हुए मलवा अखवेलपुर तक जाएगा जिससे गर्मियों में जानवरों को पीने का पानी मिलता रहेगा एवं भूगर्भ जलस्तर भी बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त सिंचाई की भी सुविधा मिल जाएगी।

(v) हरदोई शाखा पुनर्स्थापना परियोजना प्रणाली में बजट का प्राविधान किया जाए क्योंकि ठेकेदारों के अवशेष भुगतान नहीं हुए हैं तथा ठेकेदार माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट केश कर रहे हैं।

(v1) कुछ माइनरें बड़ी हैं जो रजवाहों से ज्यादा क्षमता रखती है। अतः ऐसी माइनरें जिनकी लम्बाई 5.00 कि0मी0 से अधिक है। मशीनों से कार्य कराने की अनुमति दी जाय।

हरदोई खण्ड शारदा नहर, हरदोई।

वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित पक्के कार्य

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाख रु0 में।
1	हरदोई ब्राँच के किमी0 150.249 पर अधूरे निर्मित पुल को पूरा करने का कार्य।	25.00
2	सुखेता नाले पर नागामऊ गाँव के पास वीयर बनाने का कार्य।	90.00
3	छुइया ड्रेन के कि0मी0 19.2 पर (कसरावॉ गाँव के सामने) पुल का निर्माण।	50.00

4	छोइया ड्रेन के किमी0 15.00 (घोसार एवं खद्दीपुर गाँव के मध्य) पर पुल का निर्माण।	50.00
5	सिकन्दरपुर माइनर के किमी0 6.50 (भिखमंगूपुरवा मजरा कसरावॉ के सामने) पुल का निर्माण।	5.00
6	भदैचा रजबहा पर कि0मी0 6.05 (भदैचा/भिखारीपुरवा गाँव के सामने) पुल का निर्माण।	15.00
7	छुइया ड्रेन के किमी0 24.400 (तत्योरा गाँव के सामने) पुल का निर्माण।	50.00
8	कमरौली माइनर के किमी0 6.28 पर दीवार बनाने का कार्य।	7.00
	योग :	322.00

हरदोई खण्ड शारदा नहर, हरदोई

वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित कार्य योजना

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाख रु0 में।
1	हरदोई रजबहा की सिल्ट सफाई	25.00
2	भदैचा रजबहा की सिल्ट सफाई	10.00
3	बिलग्राम रजबहा की सिल्ट सफाई	10.00
4	कौढा रजबहा की सिल्ट सफाई	5.00
	योग	50.00 लाख

अलगू प्रसाद चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, मुखालिसपुर पम्प कैनाल स्व0 शारदा प्रसाद रावत सिंचाई मंत्री थे। उन्होंने कैनाल बनवाया था, पुराना एवम जर-जर होने के कारण वर्ष में चार से छः बार तक टूट जाता रहता है। जिससे किसानों का धान एवं गेहूं सूख जाता है। मान्यवर के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कैनाल की मरम्मत कराने का कष्ट करेंगे।

मान्यवर आपको मालूम है और बताना चाहते हैं। घनघटा विधान से दो नदियों के बीच में सरयू और कुआनों नदी के बीच में पड़ता है। वर्षा के समय हमेशा बाढ़ आने की सम्भावना बना रहता है। बन्धे के बसे किसान हमेशा दहशत में रहते हैं। कब टूट जायेगा। यह निश्चित नहीं है। मान्यवर आपके द्वारा मन्त्री जी से कहना चाहते हैं सभी बन्धों को पिच करवाने का कष्ट करें।

मान्यवर मुखालिसपुर कैनाल और सरयू परियोजना के दुग्गपट के बीच में साईफन न बनने के कारण आगे का सिंचाई नहीं हो पाता है और नहर टूट जाता रहता है। मान्यवर आपके द्वारा कहना चाहते हैं, मन्त्री जी से साईफन बनवाने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष जी सिंचाई विभाग के बजट पर हमे बोलने का समय दिया गया। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देता हूँ। और बजट का पूरा समर्थन करता हूँ।

श्री हेमराज वर्मा-

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में अमेड़ी नदी, माला नदी, कठना नदी पूर्वी छोर से तथा देवहा नदी पश्चिमी छोर मेनड्रीम करके जहाँ-जहाँ लूप लेती है, कई गांवों का कटान करती है, जो सड़क के तरफ का इलाका है। ग्राम-सिमरिया ताराचन्द के करीब लिपुलिक भिंड मार्ग की ओर बढ़ रही है। जहाँ पर प्रोटेक्शन वर्क कटान निरोधक कार्य कराना जरूरी है। अमेडी, माला व कठवा नदी का नहरीकरण करने, नहरों में सिल्ट सफाई का कार्य करने की जरूरत है। हमारे जनपद में शारदा नदी बड़ा विकराल रूप लेकर कटान करती है तथा जनपद के बड़े हिस्से को बाढ़ से प्रभावित करती है। हजारों एकड़ जमीन बाढ़ की विभीषिका से खत्म हो चुकी है। किसान तबाह व बर्बाद हो रहा है। तथा उक्त नदी शारदा सागर डाम जोकि लगभग 72 वर्ग कि0मी0 में फैली हुआ के समीप पहुँच गयी जिससे शारदा सागर डाम को खतरा उत्पन्न हो गया है। शारदा नदी द्वारा किये जा रहे नुकसान को देखते हुए स्वयं मा0 मुख्यमंत्री जी ने लखीमपुर जनपद का दौरा किया तथा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को पीलीभीत भेजकर सर्वे कराया जिसमें हम लोग मौके पर मौजूद थे। नदी के कटान व बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कुछ बड़े कदम सरकार को लेने होंगे। पूर्ववर्ती सरकारों ने करोड़ों रुपया गलत तरीके से व गलत समय पर इस समस्या के समाधान हेतु खर्च करने के नाम पर उसमें भारी घोटाला किया। हम अपनी इस चिन्ता को आपके माधयम से सरकार का ध्यान इस ओर लाना चाहते हैं किसानों की हजारों एकड़ जमीन हर साल शारदा में समा जा रही है। इसका समाधान एक कार्य योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से कराये जाने की जरूरत है।

हमारा जिला नेपाल बार्डर का जिला है जोकि अति संवेदनशील भी है तथा शारदा नदी पर कई घाट व एक पैन्टेन पुल है। कंजरिया घाट, कल्लू घाट, रमनगरा घाट, मोतिया घाट, राहुलनगर घाट व पैन्टेन पुल व अन्य घाटों का ठेका एक लम्बे समय से आपराधिक पृष्ठभूमि के माफिया लोग पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से लेते आ रहे है तथा इन्हीं घाटों व पुलों के माध्यम से पीलीभीत के किसानों की खाद व बीज नेपाल चला जाता है जिस पर मा0 मुख्यमंत्री जी ने पीलीभीत दौरे के समय चिन्ता भी जतायी थी। उक्त पुलों के ठेकेदारों की सांठगाठ से तस्करी व पशु तस्करी व अन्य अपराधिक गतिविधियां भी असामाजिक तत्व करते हैं। चूँकि माफिया लोग एक बड़ी धनराशि देकर इन पुलों का ठेका ले लेते हैं। सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना है। इस सम्बन्ध में गंभीर कदम उठाना वक्त की जरूरत है। खुफिया विभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में अपनी गोपनीय रिपोर्ट भी शासन को निरन्तर भेजी गयी है। हमारे क्षेत्र व जनपद में नदियों के नहरीकरण, कटान निरोधक कार्य किया जाना तथा किसानों को टेल तक पानी देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इस सम्बन्ध में पीलीभीत जनपद के लिए अलग से कार्ययोजना बनाकर कार्य करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ।

श्री त्रिभुवन राम-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र अजगरा वाराणसी में स्थापित चन्दावली पम्प कैनाल की ओर मा0 सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

मान्यवर, चन्दावली पम्प नहर गंगा नदी पर लगायी गयी है। नदी की धारा पम्प से लगभग 200 मी0 दूरी पर चली गयी है जिससे नहर पिछले चार-पांच माह से बन्द पड़ी है। अब तो वहां से नहर का स्टाफ भी हट गया हैं

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों की विकट समस्याओं को देखते हुए उक्त पम्प कैनाल को पुनः प्रारम्भ कराया जाय।

श्री इन्द्रपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सिंचाई बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा का अवसर दिया जिसके लिये आपका आभारी हूँ।

मान्यवर, सिंचाई मंत्री की घोषणा टेल तक पानी पहुंचाने की है मात्र भ्रम का पिटारा है। केवल टेल तक एक बार पानी दिखा देने से किसान की समस्या हल नहीं होती जब तक पूरी फसल हेतु समय-समय पर पानी नहीं मिलेगा तब तक फसल पैदा होने वाली नहीं बल्कि यदि गेहूँ की फसल को तीन चार बार पानी नहीं मिला तो किसान का बीज व खाद भी बेकार चली जाती है जिससे कृषक बेमौत मर जाता है।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र में स्थिति अमराहट पैम्प कैनाल की ओर ले जाना चाहता हूं। यह नहर मात्र 13-14 कि0मी0 लम्बी है परन्तु पानी व मुसकिल 8-9 कि0मी0 तक ही पहुंचता है। आगे के काश्तकारों की फसल पानी के अभाव में पूर्ण रूपेण सूख जाती है अतः अनुरोध है कि अमराहट पम्प कैनाल का पानी पूरी फसल टेल तक पहुंचवाने की कृपा करें। मान्यवर हमारा क्षेत्र का बड़ा भाग बेहड़ी है जहां कोई नहर नहीं बन सकती ऐसी सूरत में स्टेट ट्यूबवेल लगवाने की कृपा करें। कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री प्रभुदयाल बाल्मीकी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मुझे सिंचाई के बजट पर यह कहना है कि हस्तिनापुर विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ में प्रत्येक वर्ष बाढ़ का प्रकोप रहता है। हजारो किसानों की फसल चौपट हो जाती है। सैकड़ो पशु मर जाते है। सैकड़ों पशु बाढ़ के पानी में बह जाते है तथा भारी मात्रा में हजारों एकड़ जमीन बाढ़ के पानी से नष्ट हो जाती है।

मान्यवर, हस्तिनापुर में प्रत्येक वर्ष भीषण बाढ़ आती है। जो हस्तिनापुर गंगा, बैराज गंगा पानी किसानों को गांव और घर छोड़ने को मजबूर कर देती है। मेरा आपसे अनुरोध है

मा0 सिंचाई मंत्री जी का हस्तिनापुर क्षेत्र की ओर भी अपना ध्यान कर कृपा करें ताकि हस्तिनापुर गंगा में पत्थरों से ठोकरे बनाई जा सके। पहले भी आपने हस्तिनापुर क्षेत्र से गंगा में पत्थरों की ठोकरे बनवाई थी।

अतः मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक नगर है परन्तु प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आने पर हस्तिनापुर क्षेत्र विकास से भी पिछड़ता जा रहा है मैं सिंचाई विभाग के इस बजट को बल देते हुए अनुरोध करता हूं कि मेरे इस पत्र को बजट भाषण में जोड़ने की कृपा करें।

श्री राधेश्याम-

अवगत कराना है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित खेती के सिंचाई की समस्या का निदान करने की कृपा करें।

1-पूरे बोधी (पाली) खराब नलकूप संख्या मशीन 157 वि0 खण्ड बाजार शुकुल

2-संसारपुर बाजार मुकुल वि0 ख0

3-कठौरा-39नं0 जगदीशपुर वि0 ख0

4-पूरे भवनी-155 नं0 (माझगांव) वि0 खण्ड बाजार शुक्ल

5-पूरे लोहंगी 179 हविनगांव वि0 खण्ड बाजार शुकुल

6-हरथूमऊ-172 नं0 वि0 खण्ड बाजार शुकुल

7-सौना-175 नं0 वि0 खण्ड बाजार शुकुल

8-सतियन-152 नं0 वि0 खण्ड बाजार शुकुल

9-जौदिल मऊ-129 नं0 वि0 ख0 बाजार शुकुल

10-ग्यासपुर] वि0 खण्ड बाजार शुकुल
11-हुसैनपुर]

12-डोभिपारा (वि0 खण्ड बल्छरिया सुल्तानपुर मशीन नं0 4

ग्राम सहिथन वि0 खण्ड बाजार शुकुल गोमतीनदी में पम्प कैनाल बनवाकर नहर इन्हौना राजवहा में पानी छोड़ा जाय। जिससे किसानों की समस्या समाप्त होगी।

नॉदी पम्प कैनाल को चालू कराया जाय।

1-सुबेहा राजबहा में पानी नहीं पहुंच रहा है।

2-गेरांवा राजबहा में पानी नहीं पहुंच रहा हैं

3-इन्हौना राजबहा में पानी नहीं पहुंच रहा है।

4-देवकली राजबहा में पानी नहीं पहुंच रहा है।

5-कटेहरी राजबहा में पानी नहीं पहुंच रहा है।

6-शंकरगंज से हारी मऊ होते हुए गार्ड मऊ गुगेमऊ अतरौना से नाला तक रजबहा में पानी नहीं है।

(अल्पिका माइनर)

7-गंज गडौली माइनर

8-शेखवापुर माइनर

9-जमुवानी से हसनपुर माइनर

10-अशीषपुर से ग्यासपुर माइनर

उपरोक्त राजबहा एवं अल्पिका माइनर में पानी पहुंचाया जाय शुकुल बाजार वि0 खण्ड में सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन का नव निर्माण कराया जाय जोकि काफी पुराना एवं जर्जर 1942 का बना हुआ है।

कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराये।

श्री गजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद बुलन्दशहर में मेरा विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है जहां पर गंगा होने के कारण अनेक प्राचीन महाभारत कालीन ऐतिहासिक मन्दिर गंगा के किनारे-किनारे स्थित है। बरसात के दिनों में मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांव जो गंगा किनारे बसे हुए है जैसेः- आहार, मेहमदपुर, कल्पानपुर, हसनपुर, सिरौरा, तोरई, बच्चीखेडा नगर अनूपशहर, शेरपुर व रूढ़ बांगर। उपरोक्त सभी ग्राम बरसात में गंगा की बाढ़ में जलमग्न हो जाते है।

उपरोक्त ग्रामों के अतिरिक्त ब्लाक अगौता का ग्राम खेडी की 3000 बीघा जमीन बरसात में जलमग्न हो जाती है। यदि माननीय मंत्री जी 700 मीटर नाला बनवा देवें तो ग्राम खेडी की 3000 बीघा जमीन जलमग्न होने से बच जायेगी व किसान बरसात की फसल पैदा कर लेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त गंगा किनारे बसे ग्रामों में बरसात से पहले बाढ़ से बचाव के उपाय व अगौता ब्लाक के ग्रम खेडी में 700 मीटर नाला खुदवाने हेतु माननीय मंत्री जी से विभाग को निर्देश देने की कृपा करेंगे। जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सकेगी।

सधन्यवाद।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई विभाग के अनुदान संख्या 94 के कटौती प्रस्ताव पर बल देने का अवसर दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद बलिया के तरफ ले चलना चाहूँगा क्योंकि यह बलिया जनपद गंगा घाघरा एवं टोंस नदी अर्थात तीन नदियों से घिरा हुआ है। मान्यवर, यदि हमारे जनपद यदि बाढ़ आ जाय और सरकार यदि तत्काल कोई राहत भी देना चाहेगी तो उसे पहुँचने में 10-12 घंटे लग जायेंगे कारण हमारे जनपद में कोई हवाई पट्टी नहीं है। इसलिए बलिया में हवाई पट्टी बनाए जाने की भी आवश्यकता है।

मान्यवर, हमारे विधान सभा रसड़ा में नरांव माइनर है जिसमें जब भी पानी आता है तो वह नहर इतनी जर्जर है कि उससे लगभग सैकड़ों एकड़ खेत पानी से डूब जाता है इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नरांव नहर को नरांव ग्राम के सामने वाले भाग को पक्का बनाया जाय। मान्यवर मैं आपकी माध्यम से रसड़ा विधान सभा जोकि टोंस नदी के कारण बाढ़ से प्रभावित रहता है इसके लिए मान्यवर मैं आग्रह करूंगा कि टोस नदी के किनारे ग्राम सभा बैजलपुर में पिपरी के सामने टोन्स नदी पर ठोकर निर्माण ग्राम सभा मिर्जापुर जेवेनिया, ग्राम सभा प्रधानपुर के ग्राम सभा अमहरा के चांदपुर के सामने एवं ग्राम सभा तिराहीपुर एवं ग्राम सभा अतरसुआ के सामने टोन्स नदी पर ठोकर निर्माण कार्य कराया जाय एवं प्रधानपुर में लोहारा रेगुलेटर के पास 500 मीटर तक वोल्डर पीचींग का भी कार्य कराया जाय मान्यवर हमारे जनपद में तुर्तीपार पम्प कैनाल है जो अक्सर ब्रेक डाउन रहता है हमेशा उसके कोई न कोई मोटर जला रहता है उसको भी बदलने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करू कि इससे पहले मैं आप के माध्यम से यह भी आग्रह करूंगा कि हमारे विधान सभा की समस्त नहर की सफाई कराते हुए टेल तक पानी पहुंचाने की मांग करता हूँ।

सत्यवीर मुन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी आपने हमें सिंचाई जैंसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट के समर्थन में हमें अपने विचार रखने का मौका दिया इस हेतु हम आपका कोटि-2 धन्यवाद देते है।

मा0 अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से मा0 सिंचाई मंत्री परम आदरणीय शिवपाल जी को सिंचाई विभाग के क्रान्तिकारी और विकासोन्मुखी बजट के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ।

मा0 अध्यक्ष जी खरीफ और रबी की फसल के पहले प्रत्येक वर्ष में दो बार सिल्ट सफाई हेतु धनांवटन किसानों एवं सिंचाई हेतु नई जान फूँकने के समान होगा जिससे कृषि उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय में भी अभिवृद्धि होगी।

मा0 अध्यक्ष जी सरकार द्वारा 3000 नए नलकूप डा0 लोहिया योजना द्वारा और 5000 खराब नलकूप को ठीक करने हेतु बजट में धनावंटन अत्यन्त सराहनीय है।

मा0 अध्यक्ष जी हमारे सोरांव विधान सभा में नहरों का जाल है जिस पर सोलर पैनल लगाकर उसके आस-पास के गाँवों में विद्युत आपूर्ति प्रदेश के कृषि पेयजल एवं विद्युतीकरण के संवर्धन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस हेतु सोरांव वि0 सभा का चयन प्रथम चरण के लिए जाने का आग्रह करता हूँ।

मा0 अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे विधान सभा में स्थित उमरन ताल ड्रेन एवं उससे निकली 20 कि0मी0 लम्बी नहर में सिल्ट सफाई का कार्य अविलम्ब कराया जाए जिससे जल संम्भरण के कारण किसानों की हजारों एकड़ जलमग्न भूमि तथा कृषि क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया जा सकेगा।

मा0 अध्यक्ष जी सोरांव वि0 सभा में रामपुर रजबहा तथा मऊआइमा रजबहा एवं उससे निकली उपनहरों की सिल्ट सफाई अतिशीघ्र कराने का आग्रह करते हुए हम सिंचाई विभाग के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।

धन्यवाद! जयहिन्द!

श्री लक्ष्मीकान्त (पप्पू) निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बोलने का अवसर दिया सिंचाई विभाग एवं बाढ़ खण्ड, लघु उद्योग एवं निर्यात, हथकरघा उद्योग, खानें और खनिज एवं आबकारी विभाग/बजट शानदार हैं।

मा0 अध्यक्ष जी मेरे जनपद में राप्ती नदी एवं सरयू नदी, आमी नदी बांध राप्ती नदी पर पिछली सरकार मरम्मत के नाम लाखों-2 रुपये लूट लिए कोई काम नहीं हुआ वर्तमान समय में भी अभी मरम्मत नहीं हुआ बरसात सर पर है। इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र करमैनी-बेलौली बन्धा को मरम्मत कर बन्धें पर पिच कार्य कराया जाय। जिससे दर्जनों (12) ग्राम के लोगों का आम रास्ता बन जाय आवागमन सुचारू हो जायं क्षेत्र की नहरों में पानी आता तथा बाकी नहरों का काम अधूरा पड़ा है। बने हुए नहरों पर गांवों को जोड़ने के लिए पुल बनना बहुत जरूरी है। तथा मेरे विधान सभा में सरयू नहर है जो चालू नहीं है कुछ काम अधूरा है पूरा कराकर चालू कराने की कृपा करें। तथा बाढ़ विभाग द्वारा करमैनी बेंलौली बन्धे पर बढ़या डाडर गांव है वहां बाढ़ खण्ड विभाग द्वारा बढ़या गांव में गेस्ट हाउस (डाक बंगला) बनवाने की कृपा करें। तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र में लघु उद्योग लगवाने की कृपा करें।

श्री रामपाल यादव-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूँ आपने मुझे मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सिंचाई विभाग के बजट प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया है, मा0 सिंचाई मंत्री जी ने अपने बजट प्रस्ताव में जो व्यवस्था की है। उससे यह सिद्ध हुआ है कि यह किसानों की सरकार है। मा0 मंत्री जो बाढ़ नियन्त्रण एवं सिंचाई में जो प्रस्ताव किया है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र विसवां की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि मेरे यहां शारदा सहायक के रजबहा हैवतपुर पर दो पुल टूट पड़े है। मैंने कई बार विभाग को पत्र लिख चुका हूँ, लेकिन न्याय नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह से विगत पांच सालों में नहरों की सिल्ट सफाई व ड्रेनों व नालों की खुदाई नहीं होने से सिल्ट जमा हो गई है। उसी तरह से नहर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी काफी चर्बी जमा हो गयी है कार्य में पूरी तरह बहाने बाजी एवं टरकाने वाले प्रयास करते है, बार-बार कहने पर भी टाल-मटोल करते हैं। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से हैवत रजबहा पर टूटे पुलों का निर्माण व केवानी नदी पर मदवापुर घाट से सोडा तक वायां लगभग 16 कि0मी0 बांध की आवश्यकता है। इस बांध से लगभग हजारों एकड़ जमीन में उपज एवं बाढ़ से राहत मिलेगी।

धन्यवाद!

श्री बाबू खां-

मा0 अध्यक्ष जी, आप के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो सिंचाई के बजट में मा0 मंत्री जी ने टयूबवेल व रजबहों और नहरों द्वारा टेल तक व खेत-खेत में पानी पहुँचाने का वादा किया आश्वासन दिला और सिल्ट सफाई और नये ट्यूबवेल 3000 स्वीकृत किये है तथा 5000 टयूबवेलों की मरम्मत हेतु धन स्वीकृत किया है। मैं विभाग का आभारी हूँ। स्वागत करता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक वरवन रजबहा और एक गढ़ी शाहाबाद रजबहा है। पिछली सरकार में 3-3 बार सफायी हुई है और पानी एक बार भी नहीं आया। इस समस्या का समाधान का आग्रह करता हूँ।

दूसरी बाढ़ समस्या है मेरी नदी 50 गांवों का कटान करती, ग्रामीण पलायन कर जाते हैं समस्या का निदान आवश्यकता है

धन्यवाद!

श्री गुलाब चन्द-

मा0 अध्यक्ष जी आपने सिंचाई विभाग के बजट प्रस्ताव के अवसर पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देते है। मा0 सिंचाई मंत्री आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव के बजट प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। मा0 अध्यक्ष के माध्यम से मा0 मंत्री जी से

निवेदन करता हूँ कि मेरी विधान सभा केराकत के अर्न्तगत नहर पर सड़क पक्की टूट गयी है तथा नहर पर बने पुल पुलिया टूटे हुए को बनवाने की कृपा करेंगे एवं नहर की सफाई भी करवाने की कृपा करेंगे। सिंचाई बजट प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ।

श्री मनोज कुमार पाण्डे-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा सिंचाई विभाग के बजट का सर्मथन करते हुये कहना चाहता हूँ कि मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा 2012-2013 में सिंचाई का जो बजट रखा गया है यह प्रदेश के सिंचाई में नयी शक्ति लायेगा व निश्चित रूप से किसानों के लिये बहुत ही लाभदायक है, मैं बजट के समर्थन में बोलते हुये अपनी विधान सभा 183 ऊँचाहार-रायबरेली में ब्लाक रोहणियॉ से निकलने वाले बकुलारि नाले से सीपेज की समस्या को रखना चाहते है यह गढी ग्राम सयादपाण से जनपद प्रतापगढ़ जाती है इससे लगभग 5000 एकड़ जमीन किसानों की सीपेज के कारण खराब पड़ी है कोई भी खेती व उपज नहीं हो पा रही है इसकी सफाई कराई जाये, इसी प्रकार से ब्लाक जगतपुर के भीख रजवहा की सफाई न होने से काफी बड़ी समस्या है इसे साफ कराया जाये।

श्री प्रदीप चौधरी-

मान्यवर, जनपद सहारनपुर भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहता है जिसमें गगोंह विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांव हलवाना, दौलतपुर नाईमाजरा, सनौली आदि गांव पहले भी प्रभावित रहे है जिसमें जानमाल की हानि भी हुई है आगे हानि न हो इसके लिए प्रभावी कदम उठाये जाने अति आवश्यक है।

अतः अनुरोध करूँगा कि क्षेत्र के उपरोक्त गांवों में बाढ़ को रोकने के लिए ठोकरे बनवाने की कृपा करें। और कार्यवाही में शामिल कराया जाये।

धन्यवाद!

श्री दलजीत सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी मेरी निम्नलिखित बातें कार्यवाही में शामिल किये जाने की कृपा करें।

मान्यवर, मैं बाँदा जनपद के तिन्दवारी (232) वि0 स0 क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। मा0 अध्यक्ष बाँदा जनपद के वि0 ख0 तिन्दवारी को नये नलकूप लगाने से प्रतिबन्धित कर दिया गया है, तथा नलकूप व विद्युत कनेक्शन में मिलने वाली छूट समाप्त कर दी गयी है, अतः आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ कि नये सिरे से वि0 ख0 तिन्दवारी का सर्वेक्षण कराकर पुनः प्रतिबन्ध हटाकर नलकूप व विद्युत कनेक्शन में मिलनी वाली छूट बहाल कर दी जाय, महान कृपा होगी ?

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाह रहा हूँ कि मेरी तिन्दवारी सभा के तीनों ब्लाकों में सिर्फ नलकूपों व लिफ्ट कैनालों से ही सिंचाई होती है। आज की स्थित यह है कि ज्यादातर नलकूप खराब हैं। लिफ्ट कैनालों की स्थित दयनीय है, किसान परेशान है, आत्महत्याएँ कर रहे है। भूखमरी कगार पर है तालाब सूखे हैं। हैण्ड पाइप फेल हो गये हैं, सिंचाई के साथ-साथ पीने के पानी का भी संकेत है। वाटर लेवल नीचे जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है। यमुना नदी में एक बड़ा डैम बनाकर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराया जाय तथा नलकूपों को लिफ्ट कैनालों को ठीक कराया जाय। महान कृपा होगी।

धन्यवाद!

श्री भाईलाल कोल-

महोदय-सिंचाई विभाग के बजट का स्वागत करता हूँ।

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र छानवे मीरजापुर के अन्तर्गत वाण सागर परियोजना को मेजा बांध व सिरसी बांध में पानी पहुंचाया जाय ताकि मेरे क्षेत्र के किसानों की खेत की सिंचाई हो सके मेजा बांध का पानी मेरे क्षेत्र के किसानों को नहीं मिल पायेगा। ऐसी स्थिति में वाण सागर परियोजना को सिरसी बांध में जोड़ा जाना जनहित में आवश्यक है।

कृष्णपाल सिंह राजपूत-

महोदय जी, अवगत करना है जनपद झाँसी 222 बबीना विधान सभा में पानी की समस्या देखते हुये किसानों को पानी मिल सकता है। जैसे (1) सुकुवा ढुकुवा बांध से लिफ्ट कैनाल द्वारा पानी दे सकते जिससे निम्न 50 गाँव की सिंचाई (2) बबीना तालाब से माईनर निकाली जा सकती जैसे माता टीला पाईप लाइन से जो पानी आता है उसे सुद्धीकरण बबीना में होता और उससे जो वेष्ट पानी तालाब में आता है उसी पानी से माईनर निकलवा कर किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। (3) पारीक्षा बाँध के भराव क्षेत्र से कोलवा एवं तिलैया बीच से एक पम्प कैनाल लगाकर के किसानों को सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था किया जाय जिससे मेरी विधान सभा में सिंचाई की व्यवस्था किया। (4) सिमरधा बाँध-गडमऊ माईनर कि सफाई कराये और टेल तक पानी की व्यवस्था की जाय। (5) वराटा वेशन पम्प कैनाल मोटर की क्षमता विधि बढ़ा दिया जाये और सफाई कराकर टेल तक पानी पहुँचाया जाये। (6) घुसगुवा पम्प की भी मोटर क्षमता विधि की जाय और उस माईनर की सफाई कराकर के टेल तक पानी की व्यवस्था की जाय एवं अन्तिम खेत तक पानी पहुंच सके यही मेरा अनुरोध है। (7) पारीक्षा नहर से वकुवां बुजुर्ग से पसेया पुलगहना खडोवा माईनर की सफाई कराई जाय एवं नहर की पटरी की मरम्मत होकर सड़क मरम्मत हो जाये।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी,

1-थाना भवन क्षेत्र से निकलने वाली कृष्णा नदी में एक दिन सप्ताह में रूड़की से देवबन्द होकर यमुना नहर में मिलने वाली गंग नहर से पानी छोड़ा जाए जिससे प्रदूषण मुक्त होकर पशुओं एवं किसानों को पानी का लाभ मिल सके।

2-उपरोक्त नहर से ही उस क्षेत्र की तडपती जमीन को सिंचाई का पानी मिलने के लिए एक सूजूड राजवाहे जो कि शासन पर प्रस्तावित है को पानी दिया जाए।

श्री त्रिलोकी राम-

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मौका नहीं मिला परन्तु आपके आदेशानुसार मैं अपने विधान सभा क्षेत्र 77 इगलास जनपद अलीगढ़ की नालों की सफाई की समस्या है। सफाई न होने के कारण किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन में धान की फसल नष्ट हो जाती है। अतः मेरे क्षेत्र के नालों की सफाई बरसात से पहले करा दी जाये जिससे की धान की फसल बच जाये। नालों का नाम-

1-ईखू नाला-नगलों विरखू से निबाबरी तक।

2-नाला भूरिया की गढ़ी से नगला बलराम तक।

3-नाला बढ़ीरा से बेलोट तक।

कृपया मेरे प्रकरण को कार्यवाही में जोड़ दिया जाये।

श्री सन्त प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष महोदय सिंचाई विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये आपने अवसर दिया मैं आप के आभारी हैं। यह प्रदेश गांवों का प्रदेश है 75% से 80% लोग गावों में रहते हैं। इनके जीवनयापन का मुख्य साधन खेती है पानी के बिना खेती असम्भव हैं। खजनी विधान सभा में मुखलिसपुर पम्प कैनाल की शाखा आती है परन्तु दुर्भाग्य है कि इन शाखाओं में पानी नहीं आ पाता है मा0 मंत्री जी से आग्रह है कि मुखलिसपुर पम्प कैनाल की खजनी विधान सभा की शाखाओं को भी तत्काल सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की कृपा करें।

मा0 अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आमी नदी की तरफ ले जाना चाहता हूं। आमी नदी का जल दूषित है यदि सरयू नहर परियोजना का पानी आमी नदी में डाल दिया जाता तो हजारों हजार पशु जो नदी का पानी पीने से मर जाते हैं वे नहीं मरते साथ ही पानी सिंचाई के उपयोग में आता महोदय खजनी विधान सभा में शाहपुर-खडगपुर सोपायी बंधा है। जिसकी लम्बाई 26.4 कि0मी0 है जो जर्जर अवस्था में है

महोदय प्रति वर्ष बाढ़ आती है यही बन्धा लोगों के लिए आश्रय होता है मानव पशु पक्षी जहरीले सर्प सबकी शरण स्थली यही बंधा होता है।

मा0 मंत्री जी से आग्रह है कि शाहपुर खडगपुर सोपायी बंधा का चौड़ीकरण कराना नितान्त आवश्यक है तथा बाढ़ से प्रभावित सड़कों की तत्काल मरम्मत करायी जाये। सरयू नहर परियोजना का कुछ भाग खजनी विधान सभा में अर्धनिर्मित अवस्था में है इसे तत्काल पूर्ण कराया जाये।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी आपके निर्देश पर सिंचाई विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर सुझाव के लिए कुछ बिंदू लिख रहा हूँ आशा है आप इन्हें कार्यवाही में शामिल करा देंगे।

1-थानाभवन क्षेत्र से निकलने वाली कृष्णा नदी में एक दिन सप्ताह में रूड़की से देवबन्द होकर यमुना नहर में मिलने वाली गंग नहर से पानी छोड़ा जाए जिससे प्रदुषण मुक्त होकर पशुओं एवं किसानों को पानी का लाभ मिल सके।

2-उपरोक्त नहर से ही उस क्षेत्र की तडपती जमीन को सिंचाई का पानी मिलने के लिए एक सूजूड राजवाहे जो कि शासन पर प्रस्तावित है को पानी दिया जाए।

श्री संजय कपूर-

मुझे आपने कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिनको मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मेरे क्षेत्र में पीलाखार नदी का कहर है प्रत्येक वर्ष सैकड़ों गांव इससे प्रभावित होते हैं और हजारों एकड़ भूमि प्रभावित होती है इसके लिये मेरे क्षेत्र के निम्न ग्रामों में पत्थर की पिचिंग लगवा दे ताकि ग्रामों का कटान बच सके।

1-ग्राम-सनकरा में पिचिंग पीलाखार नदी पर तहसील विलासपुर

2-ग्राम-गजरौला तहसील विलासपुर में बन्दे की मरम्मत कराना आवश्यक है ताकि काफी ग्राम बाढ़ से बच सके।

3-कमुआ नगला तहसील विलासपुर में कटान रोकने के लिये पिचिंग लगना।

4-हरदुआ तहसील मिलक में पिचिंग लगना नितांत आवश्यक सिंचाई विभाग की खाली पड़ी जमीन के पट्टों पर रोक लगा दी इससे राजस्व का घाटा हो रहा है जमीनों के पट्टे भूमिहीन को दिलाया जाय।

बाढ़ रोकने के उपाय बरसात से पूर्व होने चाहिये ताकि सुचारू रूप से कार्य हो सके बरसात के समय कार्य कराने से सरकार का पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और काम भी ठीक नहीं हो पाता है।

आपने मुझे अवसर दिये इसके लिए धन्यवाद।

श्री जयप्रकाश अंचल-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा लाये गये सिंचाई के बजट पर चर्चा करने का मुझे अवसर दिया इसके लिए आपको और सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। चूंकि सबसे पहले अपने सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे व्यक्तिगत अनुरोध पर आपने तुर्तीपार श्रीनगर बन्धे पर पहुंचकर आपने तिलापुर के सामने कटान की स्थिति में खड़ी घाघरा से सैकड़ों गाँवों को बचाने के लिए जहाँ आपने स्थलीय निरीक्षण किया वहीं आपने 14 करोड़ रुपये का बजट देकर काम चालू करा दिये हैं। उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 सिंचाई मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा बैरिया बलिया के तरफ ले जाना चाहता हूँ कि घाघरा व गंगा नदी में अगर छोटी पम्प कैनाल नहर का निर्माण करा दिया जाता है तो नहर विहीन इलाके के किसानों को सिंचाई का पूरा सहयोग किया जा सकता है तथा दूसरी तरफ अधिक से अधिक नलकूपों को लगाकर सिंचाई की सुविधायें मुहैया कराया जाय और बैरिया विधान सभा क्षेत्र में खराब पड़े नलकूपों का मरम्मत अतिशीघ्र कराया जाय।

मान्यवर आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि नलकूपों के खराबी को लेकर नलकूप विभाग के अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही किये और तत्काल बनवाने का आश्वासन दिया इसके साथ ही मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी के बजट का पूरा-पूरा समर्थन करते हुए धन्यवाद देता हूँ।

श्री रामलाल अकेला-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसका समर्थन करते हुए निम्न प्रस्ताव करता हूँ-

1-पुरवा ब्रान्च जो हरदोई से निकली है लगभग 30 वर्षों से पानी नहीं आया। रायबरेली की दो तहसीलों के किसान परेशान हैं।

2-महराजगंज व शिवगढ़ ड्रेन की सफाई तथा पटरी दुरूस्तीकरण एवम् इन्हें शताब्दी ड्रेन से जोड़ा जाय।

3-जौनपुर ब्रान्च से पोषित राजापुर माइनर में झाल बनायी जाय।

4-रायबरेली रजबहा से निकली सेनपुर माइनर के हेड में झाल बनाया जाय।

5-डीह रजबहा में पूरे जोड़ई व सिंहाराम के बीच पुल बनाया जायं।

6-महराजगंज ड्रेन पर नर्वला का पुल बनाया जायं।

7-अमावा तथा कसरांवा ड्रेन की सफाई करायी जाय।

8-राजामऊ रजबहा में पुरहिया के पास हेड पर झाल बनायी जाय।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें भाजपा के नेता सदन श्री हुकुम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत सिंचाई विभाग के प्रस्तुत बजट पर कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ मान्यवर, माननीया सदस्य श्रीमती सादात फातिमा जी जब 'तेरे कूचें से हम निकले' जुमला बोल रही थीं तो हमें लगा वे 2012 की बात नहीं बल्कि 2007 के परिणाम पर बोल रही थीं। हम इतना ही कहेंगे कि चमन को सीचने में पत्तियां कुछ झड़ गयी होंगी यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का, जिन्होंने रौंद डाला समूचे चमन को वो दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। मान्यवर मा0 सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि पिछली बसपा सरकार में बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच होगी और उसमें शामिल लोग जेल जायेंगे। हम मा0. मंत्री जी की बात से सहमत हैं कि अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच करायी जानी चाहिए बस अनुरोध है कि जांच का दायरा का वर्ष केवल 2007 से ही नहीं बल्कि 2003 से 2007 तक के भी विभाग कार्यों की जांच कराकर दोषियों को जेल भेजने का कार्य किया जाय। बल्कि हो सके तो उस मैडम का कार्यकाल भी जोड़ दिया जाये जो लोकदल के कोटे से सिंचाई मंत्री बनी थी।

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है हम ईश्वर से यही कामना करते हैं जितनी अच्छी बातें और दावे उनके मुंह से निकले है, वह पूरा हो जाये। क्योंकि अगर जो कुछ उन्होंने कहा है अगर पूरा हो जाये तो चमत्कार ही कहा जायेगा। मान्यवर, हम आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि गोरखपुर जनपद के गोला तहसील में डीह से सराय खास तक प्रस्तावित बांध का निर्माण शीघ्र कराया जाये। साथ ही नरैना नाले की खुदाई मनरेगा के तहत कराकर दोनों तरफ निकली मिट्टी से तटबन्ध बनवाने का कार्य किया जाये। इसके अलावा गोला के राप्ती तट पर बने बाँधों का आवागमन सुचारू रूप से चलने हेतु पिच रोड बनाने का कार्य करें। साथ ही सरयू नहरों पर क्षेत्र में पुलियों का निर्माण अत्यावश्यक है। मा0 अध्यक्ष जी हमारे यहां एक टेढ़िया बांध जो निष्प्रभावी व बेकार पड़ा है। उस पर कुछ नदी से कटे बेघर लोग बसे हुए हैं जिन्हें सिंचाई विभाग हटा रहा है हम अनुरोध करते हैं कि जब तक उन्हें बसाने की व्यवस्था न हो जाये तब तक उन्हें वहीं रहने दिया जाये साथ ही गोला तहसील के जगदीशपुर मोहन पौलरिया पौलहरिया कोलखास,

कोटियादीप थाह गांव जो राप्ती एवं सरयू नदी से कट रहा है उन गाँवों को बचाया जाये तथा उन्हें बचाने हेतु जो परियोजना शासन को आयी है उसे स्वीकृति प्रदान की जाये। साथ ही जो किसान गरीब बेघर हो गये हैं उन्हें बसाने की व्यवस्था की जाये। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से हम मा0 मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहेंगे कि सरयू नहर को जिस बारानगर पम्प कैनाल से पानी मिलता है वहां तेजी से नदी काट रही है अगर उसे बचाया नहीं गया तो सरकार की एक बड़ी परियोजना को खतरा उत्पन्न हो जायेगा। मा0 मंत्री जी से मांग करता हूं कि सरयू नहर की सिल्ट साफ करायी जाये जिन गांवों के किनारे नहरे कमजोर हैं और बार-बार टूट जाती हैं जिससे गांव भी डूब जाते है। और फसले भी बर्बाद हो जाती है। उन संवेदनशील नहरों की जगह को पक्का कराया जाये। मान्यवर आपसे आग्रह करते हैं कि यह सदन प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजें कि जलकुण्डी योजना पर नेपाल से फिर वार्ता शुरू करे अगर जलकुण्डी योजना आरम्भ हो गयी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ से निजात पा जायेगा और उससे बिजली का भी उत्पादन भी होगा जिससे पूर्वी प्रदेश व नेपाल को भी फायदा होगा।

मान्यवर आपने हमें कटौती प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री रविदास महरोत्रा-

मा0 अध्यक्ष जी,

मैं सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

मान्यवर,

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती के किनारे बसा है गोमती नदी के पानी से पूरे लखनऊ शहर में पानी की आपूर्ति होती है। गोमती नदी का पानी अत्यधिक प्रदूषित है कई बार गोमती के पानी में आक्सीजन की जबरदस्त कमी के कारण मछलियों के भारी संख्या में मरने की घटनायें हुयी है।

मान्यवर,

गोमती नदी में 7 नाले खुलते है और वही पानी जलसंस्थान जाता है और वहीं पानी पूरा लखनऊ शहर पीता है जिस कारण लखनऊ शहर में अत्यधिक गंदा पानी आता है इस अशुद्व एवं गंदा पानी पीने के कारण लखनऊ शहर में पीलिया का प्रकोप फैल रहा है तथा लोग पेट के रोगी हो रहे हैं।

मान्यवर,

सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह उत्तर प्रदेश में खजाने को खोलने का कार्य होता है। इस सरकार ने जनहित में अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस सरकार के बजट से जनता को भारी आशायें हैं। तथा सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है।

मान्यवर,

मैं मा0 सिचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि गोमती नदी में जो नाले खुल रहे है वहाँ सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगा दिये जाये जहाँ नालों में मलबे से खाद बन जाये तथा नदी में वह मैला ना जाने पाये और जनता को शुद्व पीने का पानी मिल सके।

मान्यवर,

गोमती नदी के पानी को प्रदूषण से मुक्त कराया जाये तथा गोमती नदी के तट पर जो घाट बने है उसमें अधिकांश घाट टूटे है तथा वहाँ गंदगी भरी है इन घाटों को नहाने योग्य बनाया जाये जिससे लखनऊवासी गोमती नदी के घाटों पर स्नान कर सकें।

मान्यवर,

मैं सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि गोमती नदी में सफाई अभियान चला कर नदी को शुद्ध कराने की कृपा करें।

सुल्तान बेग-

मान्यवर,

मैं सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का पूर्ण समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सिंचाई मंत्री द्वारा सिंचाई के बजट पर मा0 हुकुम सिंह जी रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय आपके द्वारा दिया गया है मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और सिंचाई विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित समस्यायें रखता हूँ जिनका निराकरण करना नितान्त आवश्यक है।

रोहेल खण्ड नहर खण्ड सिस्टम बरेली जो विधान सभा बहेड़ी तथा विधान सभा भोजीपुरा तथा विधान सभा मीरगंज क्षेत्र में सिंचाई कार्य क्षेत्रीय किसानों द्वारा किया जाता रहा है परन्तु मा0 अध्यक्ष जी इस सिस्टम की नहरों की जो क्षमता है उससे 1/4 क्यूसिक पानी भी नहीं सह पाती है। कारण वश क्षेत्रीय किसानों को समय पर नहरों में पानी न आने के कारण क्षेत्रीय सम्बन्धित किसानों को भारी आर्थिक हानि फसलों के सूख जाने के कारण होती

है यदि सरकार टेल पर पानी किसानों को सिंचाई हेतु पहुँचाना चाहती है तो रोहेल खण्ड नहर खण्ड सिस्टम बरेली की पुनः स्थापना नितान्त आवश्यक है मैं चाहूँगा कि रो0ख0न0 खण्ड सिस्टम बरेली की पुनः स्थापना सरकार कराये ताकि क्षेत्रीय किसानों को सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो सकें। पोलाखार नदी, बहगुल नदी और रामगंगा से ग्राम दिवना व ग्राम पहुँचा बुर्जुग पूरी कटान की चपेट में आ चुका है कारण वश हजारों एकड़ कृषि भूमि कट जायेगी तथा हजारों परिवार बेघर हो जायेंगी अतः मैं चाहूँगा कि मा0 अध्यक्ष दिवना व पहुँचा बुर्जुग पर कटान रोकने हेतु पिचिंग व पत्थर की टोकरें लगाई जाये।

श्री राम मगन-

महोदय,

निवेदन है कि मेरी विधान सभा में पिछले 5 साल के पहले जो सपा सरकार थी तब नहरों में टेल तक पानी पहुँचा और किसान काफी खुशहाल था। परन्तु बसपा की सरकार आ जाने पर 5 सालों में नहरों की खुदाई, सफाई नहीं हुई। जिससे किसान बूँद-बूँद पानी के लिए तरस गये, शिकायत करने पर कोई सुनने वाला नहीं था। चारों तरफ अराजकता व लूट-खसोट का माहौल था। इस बार जब सपा की सरकार आयी मा0 मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव व सिंचाई मंत्री मा0 शिवपाल यादव जी के आदेश पर टेल तक पानी पहुँचाने का प्रयास किया गया। परन्तु नहरों की आधी दूरी तक ही पानी पहुँच पाया। हैदरगढ़ विधान सभा की नहरों का आफिस निर्माण खण्ड तेलीबाग में होने के कारण किसान अपनी समस्या सम्बन्धित विभाग के आफिस तक नहीं पहुँच पाते। मैं चाहता हूँ कि सम्बन्धित निर्माण खण्ड सिंचाई विभाग का आफिस या तो हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर स्थापित किया जाय या इस आफिस का चार्ज खण्ड-28 स्थिति हैदरगढ़ को स्थानान्तरित किया जाय तथा नहरों की खुदाई कराकर ही टेल तक पानी पहुँचाया जा सकता है। इसके अलावा हैदरगढ़ विधान सभा ऐसी विधान सभा है जो गोमती नदी के 50 किमी0 की लम्बाई के दोनों तरफ बस्ती है जहाँ पर 4 किमी0 इधर-उधर नदी के किनारे 50 किमी0 तक नहरे नहीं है और वहाँ पर ऊँचा नीचा होने पर नहरे बनाई भी नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में नदी के किनारे में दोनों तरफ के क्षेत्र में यदि 20 राजकीय नलकूप व 2 लिस्ट कैनाल (पम्प नहर) गोमती नदी से स्थापित करा दिये जाये तो किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि क्षेत्र की समस्या को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की सम्बन्धित नहरों की सफाई-खुदाई व नदी के किनारे क्षेत्र में 20 राजकीय नलकूप व दो गोमती नदी से लिफ्ट कैनाल जनहित में कराये जाने की मेंहरबानी करें।

श्री विजय मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करते हुए मा0 सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देता हूँ ।

मा0 अध्यक्ष जी-

कृषि की सफलता विभिन्न फसलों के लिए जल उपलब्धता पर निर्भर करती है। अतः जल का भण्डारा तथा उसके सदुपयोग राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। प्रदेश के जल स्त्रोत कृषि, उद्योग तथा अन्य उपयोगो की कुल आवश्यकता के लिए अपर्याप्त हैं।

देश के शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत 2007.08 के आंकड़ों के आधार पर 43.40% है। जबकि उत्तर प्रदेश में 78.60% सिंचाई की दृष्टि से प्रदेश चतुर्थ स्थान प्राप्त है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः दिल्ली (104.30%), पंजाब (94.90%), हरियाणा (84.90%) आते है। प्रदेश के वर्ष 2008-2009 के उपलब्ध आकड़ों के आधार पर प्रदेश का यह प्रतिशत 81.10 है।

श्रीमन पूरे विश्व में यह देश केवल एक विशेषता के लिए भिन्न है यह गांव का देश है इस लिए श्रीमन यह किसानों का कृषि मजदूरी पर निर्भर रहने वालों का देश है। जिस प्रकार जीवनधारियों के जीवन के लिए शरीर में रक्त प्रवाह नितान्त आवश्यक है उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वैसे ही कृषि के किसान के लिए कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई के बिना वांक्षित आर्द्रता की उपलब्धता के बिना किसी भी कृषि उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती है।

इस पृष्ठभूमि में मा0 मंत्री जी ने सिंचाई के बजट में जो प्राविधान किए है वे सराहनीय हैं।

मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने की सुविधा हेतु खरीफ एवं रबी फसल से पूर्व सिल्ट सफाई का कार्य कराया जायेगा, जिसके फलस्वरूप नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने में सुविधा होगी तथा टेल क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 3000 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके निर्माण के फलस्वरूप 120.00 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता (पी0पी0ए0) का सृजन होगा। इस परियोजना की कुल लागत रु0 68218.97 लाख है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 17045.27 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिससे लगभग 959 नवीन नलकूपों का छिद्रण कार्य होगा।

डा0 राममनोहर लोहिया राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 1054 असफल राजकीय नलकूपों का पुनः निर्माण वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे 105.40 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी। इस परियोजना की कुल लागत रु0 20306.92 लाख है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 6446.64 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जिससे लगभग 350 नलकूपों का पुननिर्माण कराया जायेगा।

वर्ष 2012-13 में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास कार्यों की प्राथमिकता का संज्ञान लेते हुए बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास कार्यों हेतु रु0 724.75 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

निश्चित रूप से प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

हमारे मंत्री जी ने नहरों और ड्रेनों की सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती बसपा सरकार के फैसले को पलटते हुए इनका विकेन्द्रीकरण कर इसे जिले स्तर पर कराने का फैसला लिया है। मा0 मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र है।

हमारी सरकार का दृष्टिकोण कल्याणकारी है। मा0 मंत्री जी द्वारा विकासशील बजट प्रस्तुत किया है। मंत्री जी ने गंगा नदी को निर्मल करने का जो प्राविधान किया है। वह भी धन्यवाद योग्य है।

श्रीमती नन्दिता शुक्ला-

मा0 अध्यक्ष जी-

मैं आज सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। प्रस्तुत बजट बहुत ही अच्छा तथा जन कल्याणकारी योजनाओं से भरपूर है वर्तमान बजट की व्यवस्था से नहरों का अवश्य ही कायाकल्प होगा। लोक कल्याणकारी भावनाओं से ओत-प्रोत इस बजट में कृपया मेंरी विधानसभा क्षेत्र की रूपईडीह ब्लाक के सरयू नहर खण्ड 5 नानपारा बहराइच आर्यनगर पृथ्वीनाथ मार्ग पर बेलवा नहर पुल से बहराइच बार्डर तक 1200मीटर नहर पट्टी पर पेंटिग अथवा खड़ंजा लगने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में आसानी होगी। दूसरा इटिया थोक ब्लाक में सरयू नहर खण्ड पर बिसुनपुर संगम के पास माइनर पर छोटा पुल बनवाने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

इटियाथोक ब्लाक में मेहनौन ग्रामसभा में माताजी के स्थान पर मेन नहर पर आने जाने के लिए छोटा पुल बनवाने की कृपा करें।

धन्यवाद!

श्री रविन्द्र भड़ाना-

माननीय,

अध्यक्ष जी,

मान्यवर,

बोलने का अवसर मिल ना सका इसलिए सिंचाई विभाग के बजट कटौती पर निम्न विषय दे रहा हूँ जोड़ दें:-

1- मेरठ जिले से गंगा नहर होकर गुजर रही है उसकी पटरी बनाने में पूर्ववर्ती काल में बहुतेरी लूट हो चुकी है वर्तमान में यह छतिग्रस्त होकर पटरी भी टूट गई है गाड़ी की गाड़ी नहर में समा चुकी है ठीक कराया जाय।

2-मेरठ जिले व उ0प्र0 में बम्बे एवं नाली माइनरों की साईडें पक्की कर उनकी तली तक भी पक्की कर दी गई हैं जो सीपेज द्वारा जल स्तर ठीक रहता था लेकिन तली पक्की कराये जाने के कारण जल स्तर नीचे चला गया है इसको रोकने हेतु तली पक्की ना की जायें।

3- मेरठ के दो नाले (सिंचाई विभाग के) कलंजरी से मोइउदीनपुर कादराबाद नाला एवं छजुपुर, इकला, गांवडी, होता हुआ कादराबाद नालों की सफाई अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इनके कारण बरसात में जलभराव रहता है जिससे किसानों की जमीनी, फसलें नष्ट हो जाती हैं आर्थिक हानि एवं जन हानि होती हैं। सफाई हों।

धन्यवाद!

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी कटौती प्रस्ताव में बल देते हुये सरयू नहर योजना में इमामगंज शाखा तथा सरयू पम्प नहर को सिंचाई प्रारम्भ कराने का श्रेय भाजपा सरकार को जाता है जिसे 1996-2002 की सरकार में हुआ था। घाघरा नदी किनारे बने आदमपुर रेवली बांध तथा बलेहा-बहरौली बांध पर पक्की सड़कें बना दी जाय काफी बनी हुई है जो आधूरी है पूरी की जाय। बाढ़ पीड़ितों को स्थायी कालोनी बना कर बसाया जाय। सरयू पम्प नहर को गर्मी में भी चालू कराया जाय तथा टेल तक पानी पहुंचाया जाय। वन वसा बांध का पानी धीरे-धीरे खोला जाय। बाढ़ पीड़ितों को खेत में बालू पटान का मुआवजा जो मिल रहा है कम है बढ़ाया जाय।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बलहा-जनपद बहराइच के विकास खण्ड मिहीनपुरवा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कठपतिया के नालों की सफाई सिंचाई विभाग द्वारा पिछले वर्षों में सफाई कराई गई थी। कई वर्षों से नदी के पानी के कटान से नाला मिट्टी से पट गया है। मिट्टी पट जाने के कारण पानी का निकास नहीं हो पा रहा जिससे गांव और फसल प्रभावित हो जाती है फसल पैदा नहीं हो पाती है।

अतः कृपया उक्त नालों की सफाई हेतु सिंचाई विभाग बहराइच को आदेशित करने का कष्ट करें जिससे की किसानों की फसल बच सके।

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत मिहीनपुरवा जनपद बहराइच के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पड़रिया भादा नदी के कटान को रोकने हेतु पूर्व की सरकार के माध्यम से पत्थरों से रोकने से का कार्य किया जा रहा था किन्तु विगत कुछ माह से उक्त कार्य को रोक दिया गया है। कार्य रोकने से नदी में कटान शुरू हो गया है। किसानों की भूमि तथा गांव बह रहा नदी के कटान से पुरैना रघुनाथ पड़रिया अस्सी पुरवा नाले पुरवा नदया पुरवा सोमई गौटी जालिमनगर मझरा भइया बडखडिया नशैन्यपुर कला-विकास सण्ड बलहा के बंजरिया औसेरी पुरवा सरैया आदि गांव कटान व बाढ़ से हजारों गांव प्रभावित हो रहे हैं।

अतः तत्काल बाढ़ से नाव की व्यवस्था जाने की कृपा करें।

मान्यवर, विधान सभा बलहा के अन्तर्गत पुलों का निर्माण सिंचाई विभाग से कराई गई है। जो दिवाल खड़ी है। छत नहीं पड़ी पैसा पेमेन्ट करा लिया गया है। जो निम्न प्रकार के है।

1-जालिमनगर, गिरगिट्टी, मझाव, भौरहवा बड़खरिया, खैरी समैसा रायबोसा पेटरहा, समई गौढी आदि पुलों का निर्माण अधूरा है जांच करा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री राम चन्द्र यादव-

सिंचाई विभाग के महत्वपूर्ण बजट 2012-13 पर माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार का ध्यान फैजाबाद जनपद की विधान सभा क्षेत्र रूदौली में घाघरा नदी के दायें तट पर निर्मित रौनाही तटबंध जिसका 2.600 किमी0 हिस्सा बाराबंकी की सीमा में है तथा शेष भाग फैजाबाद की रूदौली की सीमा में है। तटबंध के किनारे बसे सैकड़ों गांव हर वर्ष घाघरा नदी की बाढ़ से तबाह होते हैं जिनमें करीब आधे दर्जन गांव नदी की कटान में चले गये। लगभग 107 घर अन्य गांव के बह गये जिनका अभी तक पुनर्वास हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

रूदौली तहसील की करीब 60 हजार एकड़ भूमि की फसल इस भयावह बाढ़ से हर वर्ष प्रभावित होती है। खास तौर से ममरेजनगर, अख्तियारपुर, सराय दौलत, सहवाजपुर, मुतौली, नैपुरा, सड़री, उधरौरा, पस्ता माफी, मानपुर, चैथरी, भौरहरा, रहीमगंज, भेलसर, अहरौली, अल्हवाना, रहीमनगर, हयातनगर, बिचाला, हसनामऊ, कोटरा, कोंपेपुर, परसहूं, चिर्राखजुरी व नकछेदपुर, खैरी आदि गांव बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। जिसके बचाव के लिये रौनही तटबंध के नैपुरा पर बाढ़ पम्पिंग स्टेशन के निर्माण की मांग दशकों से होती रही है और अभी तक उक्त परियोजना की स्वीकृति नहीं हो पायी है। जिसके कारण समय-समय पर किसान आन्दोलन, धरना प्रदर्शन करते रहे। दिनांक 18.04.2011 को 7 मी0 हेड एवं स्राव 90 ली0 प्रति मिनट के लिये आवश्यक पम्प यंत्र एवं संयंत्र का प्राक्कलन लागत रु0 157.24 लाख की योजना बनाकर उत्तर प्रदेश जल निगम के चेयरमैन को प्रेषित की गयी है, जो अभी भी लम्बित है।

मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से मांग करता हूं कि किसानों के हित में नैपुरा बाढ़ पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें साथ ही रूदौली विधान सभा क्षेत्र की फैजाबाद नहर शाखा व सुलतानपुर नहर शाखा से निकलने वाली माइनरों की अधूरी खुदाई एवं सफाई को पूर्ण कराने की व्यवस्था करायें। सिंचाई विभाग द्वारा रूदौली विधान सभा क्षेत्र में एक निरीक्षण भवन भी स्थापित किया गया है, जो दशकों से बंद पड़ा है। इस निरीक्षण गृह का भी पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु धन स्वीकृत करें।

मान्यवर, रूदौली विधान सभा क्षेत्र के किसानों से जुड़ी एक बड़ी समस्या राम शरण दासपुर ड्रेन जिसकी खुदाई अभी तक नहीं हुई जिसे अविलम्ब पूर्ण कराने की व्यवस्था करा दें। मान्यवर, रूदौली विधान सभा क्षेत्र पहले बाराबंकी में शमिल था। 1997 में जनपद फैजाबाद में शामिल किया गया और तब से फैजाबाद में शामिल होने के बाद भी सिंचाई विभाग का चाहे वह नलकूप खण्ड हो, चाहे बाढ़ हो और चाहे ड्रेनेज खण्ड हो, चाहे शारदा नहर सुलतानपुर शाखा हो इन सभी के कार्यालय अभी भी बाराबंकी से संचालित किये जा रहे हैं जिसके कारण रूदौली क्षेत्र के किसानों को, ग्रामीणों को अपने सिंचाई कार्यों से बाराबंकी जाना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सिंचाई विभाग से संबंधित सभी कार्यालय फैजाबाद स्थानान्तरित किया जाय।

अंत में कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

मा0 अध्यक्ष जी मा0 सिंचाई मंत्री जी के बजट पर समर्थन में बोलने के लिये आपने अवसर दिया आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

42 लाख आबादी वाले सीतापुर जिले में हर साल बाढ़ से 10 से 15 लाख की आबादी प्रभावित होती है।

सीतापुर में बाढ़ और जल प्लावन की अलग-अलग बैराजों से छोड़े जाने वाले पानी से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। गिरजापुरी, बनबसा बैराजों से शारदा व घाघरा नदी में पानी छोड़े जाने से 500 से ज्यादा गांव प्रभावित होते हैं, जब भी बैराजों से पानी छोड़ा जाता है, तो लोगों को सूचना नहीं दी जाती है, जिससे अचानक जब पानी गांव में घुसता है, तो भारी तबाही मचता है, इस तबाही को कम करने के लिये अनिवार्य रूप से पहले कम से कम पानी छोड़े जाने की सूचना दी जानी चाहिये। जब गांव में पानी घुस जाता है, और लाखों लोग बाढ़ में कैदी बनकर रह जाते हैं। उनके लिये पर्याप्त नाव की ग्राम पंचायत में व्यवस्था की जानी चाहिये। ग्राम पंचायत को नाव खरीदे जाने के लिये अलग धन मोहय्या कराया जाना चाहिये। बाढ़ प्रभावित इलाके का सर्वे कराकर अधिकांश खराब हुई नावों को निष्प्रयोजन करा देना चाहिये, ताकि होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकें। बाढ़ आने के पूर्व केवटों के साथ बाढ़ अधिकारियों की बैठक अनिवार्य रूप से करनी चाहिये।

जल प्लावन की समस्या से निजात के लिये गांव में कराये गये तेजी से विकास में सड़कों का निर्माण तो करा दिया गया, पर पुलिया न बनाये जाने के कारण सड़कें बन्धे का कार्य कर रही हैं। जिसकी वजह से अधिक वर्षा होने पर पानी का ठहराव हो जाता है, और फिर कच्चे आशियाने गिर जाते हैं। जन हानि होती है। बाढ़ की तबाही को कम करने के लिये यह कदम उठाये जाना चाहिये तथा अधिक से अधिक पुल/पुलियों का निर्माण कराया जाना चाहिये।

1- जो गांव पानी से घिर जाते हैं वहां पेय जल की समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन गांवों में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प और कुएं डूब जाते हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित लोगों को नदी का गंदा पानी पीकर पेट आदि गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इससे निपटने के लिये पानी से घिरने वाले गांवों को चिन्हित कर उन गांवों में पटान कराकर ऊंचाई पर आबादी के अनुसार इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प इतनी ऊँचाई पर लगाना चाहिए जो कम से कम पानी में न डूब सके।

2-पानी के बीच घिरे रहने वाले लोगों को शौच जाने के लिए होने वाली भारी दिक्कत से निजात दिलाने के लिए पानी से घिरने वाले गांवों के ऊँचाई पर पटान कराकर

शौचालय का निर्माण कराया जाना चाहिए। पानी से घिरे गांव में डूबने से होने वाली मौतों को रोकने जंगली जानवरों से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए गाँव में सौर्य ऊर्जा की लाइट लगाई जानी चाहिए।

3-पशुओं के चारे के लिए भूसे की तस्करी पर तत्काल रोक लगानी चाहिए खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों का भूसा नेपाल और गैर जिलों में स्थित पेपर मिलों में भेजा जा रहा है। इस प्रकार तत्काल रोक लग जानी चाहिए क्योंकि कम्बाइन्ड मशीनों के बढ़ते चलन से भूसे पर पहले से ही संकट है, बाढ़ आने पर चारा पानी डूब जाता है।

4-कटान क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर वहाँ के लोगों को विस्थापित कराने की दिशा में पूर्व में कदम उठाये जाने चाहिए। तहसील बिसवां के काशीपुर मल्लापुर समेत आधा दर्जन गांव के अस्तित्व शारदा नदी द्वारा खत्म कर दिये जाने के बाद करीब दस हजार की आबादी सड़कों पर झोपड़ी में जैसे तैसे गुजर बसर कर रही थी। पूर्व बसपा सरकार की उपेक्षा के चलते उन्हें कोई मदद न मिलने से नाराज इन लोगों के द्वारा विधान सभा चुनाव में बहिष्कार किया गया था। इन्हें तत्काल विस्थापित करने और इनके जीवकोपार्जन के लिए रोजगार मुहैया कराये जाने चाहिए। ठीक यही स्थिति वि0खं0 रामपुर मथुरा के गाँवों की है यह सारी व्यवस्था इस वि0खं0 के प्रभावित गाँवों की भी होनी चाहिये।

*बजट प्रस्ताव समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ धन्यवाद!

श्री अनीसुरर्हमान-

मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान सिंचाई विभाग के बजट की ओर ले जाना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं मुरादाबाद जनपद की काठ विधान सभा से निर्वाचित होकर यहाँ आया हूँ। मान्यवर अध्यक्ष जी मेरे विधान सभा क्षेत्र काठ में रामगंगा नदी बहती है। मान्यवर रामगंगा नदी में 2010 से लगातार बाढ़ आने के कारण नदी किनारे बसे गाँवों गोपालपुर, मिश्रीपुर बेगमपुर, भागीजोत व महदद कलमी का कटान होने के कारण जनता परेशान हैं। अब 10 दिन बाद फिर मानसून आने को है। जनता में रोष है तथा त्राही-त्राही है लोग चिन्तित हैं कि पूर्व में प्रशासनिक अधिकारियों से नदी किनारे उक्त गांवों पर पिचिंग निर्माण हेतु कहने के बावजूद आज तक पिचिंग न बनाए जाने के कारण लोगों में भय है। जनता को सरकार की तरफ से यकीन दिलाने हेतु रामगंगा नदी पर आबाद गोपालपुर, मिश्री बेगमपुर, भागीजोत, महदद कलमी पर पिचिंग बनवाने हेतु सिंचाई विभाग के बजट में धन आवंटित कर उक्त पिचिंग बनवाने का सरकार कष्ट करेगी।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ 121 पर)

श्री रविन्द्र भड़ाना-

माननीय,

अध्यक्ष जी,

मान्यवर,

उद्योग बजटपर कटौती के प्रस्ताव पर मान्यवर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ मान्यवर बोलने का समय न मिलने के कारण अपना विषय लिखकर दे रहा हूँ। जो निम्न हैं।

1-मान्यवर मेरठ जिले की दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में उद्योग धन्धों का काफी क्षेत्र आता है परन्तु वहां सड़कें टूटी हैं, विद्युत कनेक्शन मिलने में कठिनाई आती है, विद्युत आपूर्ति ठीक हो।

2-उद्यमियों को सुरक्षा मिले उनके शस्त्र लाइसेन्स अविलम्ब मिले अतिरिक्त सुरक्षा चाहिऐ तो मिले।

3-मेरठ के खेल उद्यमियों एवं सोना चांदी के आभूषणों का निर्माण हेतु उद्योगों को आर्थिक सहायता और इन उद्यमों को टैक्स में छूट दी जानी चाहिए।

4-उद्योग धन्धों हेतु उन्हें सस्ती दर पर विकसित करके उद्योग लगाने हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाये।

धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह-

महोदय,

आप के माध्यम से उद्योग मंत्री से आग्रह है कि हमारी विधान सभा सहनवां, गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापित है, जिसको गीडा भी कहा जाता है, उसमें स्थापित एवं भविष्य में स्थापित यूनिटों को सरकार द्वारा कुछ सुविधा देना आवश्यक है, जिससे कि अन्य उद्योग स्थापित हो सके उसके साथ ही गीडा में, कॉमन ट्रिटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इसकी स्थापना हेतु जरूर आवश्यक कदम उठाया जायेगा।

श्री अजय मिश्रा (टेनी)-

मा0 अध्यक्ष जी,

आपने लघु उद्योग बजट पर अपनी बात कहने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ। कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये बताना चाहता हूँ मेरा जनपद लखीमपुर खीरी लघु उद्योगों के लिये बहुत मुफीद जगह है, चावल शक्कर व गुड़ बनाने की सैकड़ों इकाईयां काम

कर रही हैं तथा उद्योगों हेतु विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लाभ कमा रही हैं उक्त उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जहाँ चावल उद्योग व्यवहारिक रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्रभावित होता है, यहीं कारण है कि सरकारी लेवी खरीद मूल्य व बाजार मूल्य में भारी अन्तर रहता है। अभी लेवी 60% है शेष 40% अपने हिस्से का चावल बेचने में उद्यमी को भारी परेशानी होती है। मेरा अनुरोध है कि उक्त लेवी 80% तक की जाये तथा खण्डा चावल जो तराई क्षेत्र होने के कारण धान में ज्यादा हो जाता है कि सरकारी खरीद में अनुमन्य मात्रा 25% की बजाय 30% किया जाये एवं लेवी चावल भण्डार में भारी भ्रष्टाचार प्राईवेट ठेकेदारों की वजह से होती है यह व्यवस्था समाप्त करके चावल भण्डारण का कार्य भी FCI की तरह प्रदेश सरकार स्वयं करे, इससे चावल उद्योग को स्थापित करने में भारी सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान अपनी वि0 स0 निघासन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ कि जलवायु व जमीन हल्दी, मिर्च सोंठ, मुलेठी, पीपल ऐसे मसालों के लिये मुफीद है उपयुक्त है। अभी लोग मात्र अपने प्रयोग हेतु इनका उत्पादन करते हैं यदि औद्योगिक माहौल बनाया जाये तो लखीमपुर जनपद चीनी, चावल, गुड़ व मसालों के लघु उद्योगों हेतु बड़ी भूमिका निभा सकता है तथा प्रदेश की आर्थिक प्रगति में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि चावल, मसालों, चीनी व गुड़ के लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु इसी बजट में एक विशेष पैकेज देने की कृपा करें इसी अनुरोध के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

धन्यवाद!

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ 121 पर)

श्री रविन्द्र भड़ाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, आबकारी विभाग के बजट पर कटौती में अपनी बात रखते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं।

1-उ0प्र0 में एक ठेकेदार विशेष जो गत पिछली सरकार में इस व्यापार के जरिए उ0प्र0 के लोगों को लूट रहा था तय रेट और अंकित रेट से ज्यादा वसूली करके लूट मचा रखी थी सुना जाता है कि वर्तमान सरकार भी इसी पूर्ववर्ती सरकार के ठेकेदार के द्वारा जनता को लुटवाने का कार्य बन्द कर इस व्यवस्था को भाजपा की सरकार के माडल पर पारदर्शी बनाकर जनता को लुटने से बचाया जा सके।

2-इसे गांव-गांव के स्थान पर इसके विक्रय केन्द्र दूर-दूर खोले जायें।

3-नकली शराब पर अंकुश लगाया जाये क्योंकि इससे निरीह मौतें हो रही हैं।

धन्यवाद।

सुश्री रूबी प्रसाद-

मान्यवर, बसपा सरकार के मंत्री से लेकर संतरी तक सभी इस लूट में सम्मिलित रहे हैं। जिसका परिणाम यह हुआ कि दिनांक 27 फरवरी, 2012 को ग्राम बिल्ली मारकुण्डी में अवैध खनन के कारण टावर सहित पहाड़ी धसकने से लगभग 15 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गयी और सैकेड़ों लोग घायल भी हुए। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद शासन और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों ने खूब बड़ी-बड़ी बातें की व बयान जारी किया कि दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी किन्तु सिर्फ एक निचले स्तर के अधिकारी व छोटे कर्मचारियों को निलम्बित कर मामले को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि जनपद सोनभद्र में हुआ अवैध खनन उच्च स्तरीय सांठ-गांठ का परिणाम है इसमें शासन स्तर के अधिकारियों से लेकर जनपद के आला अधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित रहे हैं। इसलिए शासन स्तर के अधिकारियों की उच्चस्तरीय टीम गठित कर जनपद सोनभद्र के खनन विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए व इनके विरूद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत करा कर जेल भेजा जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार के नापाक गठजोड़ के कारण किसी गरीब को अपनी जान न गवानी पड़े।

यहां यह भी बताना आवश्यक है कि दिल दहला देने वाली इस घटना में मरने वाले व घायलों को अब तक कोई मुआवजा धनराशि भी सरकार की ओर से नहीं प्राप्त हुई है। इसलिए उन्हें उचित मुआवजा भी दिलाया जाय। इसके अतिरिक्त बसपा सरकार में जनपद सोनभद्र में बालू व पत्थर खनन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की जमकर अवहेलना के सम्बन्ध में अपने नीचे के अधिकारियों को मात्र पत्र लिखकर जान बचाते रहे हैं। बालू और पत्थर खनन में मशीनों का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है किन्तु जनपद सोनभद्र में बालू खनन के दौरान मोटर बोट, नाव, जे0सी0बी0 व पोकलेन का जमकर उपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त पत्थर खनन में भी पोकलेन, जे0सी0बी0 व राकब्रेकर का धड़ल्ले से उपयोग किया गया जिसकी वीडियो फुटेज मेरे पास है, इसलिए मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना के सन्दर्भ में दोषी अवैध खननकर्ताओं व अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार का कृत्य न कर सके।

ब0स0पा0 सरकार में जनपद सोनभद्र में जो भी खनन पट्टे स्वीकृत किये गये उसमें भी शासनादेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी है। ब0स0पा0 शासन में जिलाधिकारी द्वारा जो विज्ञप्ति पहले प्रकाशित करायी गयी उस क्षेत्र पर खनन पट्टा बाद में और जिस क्षेत्र की विज्ञप्ति बाद में प्रकाशित करायी गयी उसक्षेत्र पर खनन पट्टा पहले किन परिस्थितियों में

स्वीकृत कर दिया गया। इसका सीधा कारण यह है कि जनपद से लेकर शासन स्तर तक पट्टा स्वीकृत करने हेतु मोल-भाव होता था जिसकी सेटिंग पहले हो जाती थी और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसा देता था उसको पट्टा कर दिया जाता था इसलिए बसपा सरकार में हुए सभी पट्टों की जांच होनी चाहिए।

यहां यह भी बताना है कि बसपा सरकार के बरहज के पूर्व विधायक आर0पी0 जायसवाल के करीबी राकेश जायसवाल को किस आधार पर एक दर्जन से भी ज्यादा गिट्टी/बोल्डर (डोलोस्टोन) के खनन पट्टे स्वीकृत किये गये इसकी भी जांच करायी जाये।

ब0स0पा0 सरकार में जनपद में वन भूमि पर अवैध खनन ही नहीं हुए हैं बल्कि उस पर खनन पट्टे भी आवंटित किये गये हैं। जैसे जनपद सोनभद्र के ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के मिनजुमला नम्बर 4478, 6229, 3567 में ब0स0पा0 सरकार में खनन पट्टे स्वीकृत होना भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन है।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में UPSIDC द्वारा विकास एक 40 वर्ष पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। जिस समय यह औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ था उस समय नोयडा ग्रेटर नोयडा का दूर-दूर तक निशान नहीं था आज नोयेडा ग्रेटर नोयडा प्रदेश के नक्शे पर चमकते हैं लेकिन सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र की कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहां की सड़कें जर्जर हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर रात कोई रोशनी के लिये जो लाइटें है वो टूटी पड़ी हैं। गंदे पानी को बाहर ले जाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में नाली तथा नाले नहीं बनाये गये हैं। आद्योगिक क्षेत्र के गंदे पानी को साफ करने के लिये Common Effulant Treatment Plant नहीं लगाया गया है। क्षेत्र में विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालय नहीं खोले गये हैं। इस क्षेत्र में कजारिया सिरेमिक्स, ओरियेन्ट सिरेमिक्स गुडलक इण्डस्ट्रीज, आदि प्रसिद्ध उद्योग हैं तथा यहां से करोड़ों रुपये का राजस्व प्रदेश तक केन्द्र सरकार को मिलता है। बस की कोई सुविधा नहीं है। अस्पताल की सुविधा नहीं है।

आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये समुचित धन की व्यवस्था की जाय, तथा इस क्षेत्र को पुनजीर्वित करने हेतु विशेष पैकेज की घोषणा की जाय।

श्री दिलनवाज खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी,

मुझे उद्योग विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। आप के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ।

मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर में स्याना विधान सभा क्षेत्र एक फलपट्टी क्षेत्र है। इस क्षेत्र की अधिकांश कृषि भूमि पर आम के बाग हैं, जो यहाँ के किसानों के कार्य का मुख्य आधार है। शेष बची हुया जमीन में किसान आमतौर पर आलू, हरी सब्जियाँ लगाते हैं। कुछ हिस्सों में मेडिसिन प्लाण्ट व फूलों की खेती होती है मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों द्वारा मेहनत करने के बावजूद भी स्थिति तंग होती जा रही है। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। किसानों के बेरोजगार युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं।

खेती में कुछ खास आय न होना चिंता का कारण है। यदि स्याना क्षेत्र में एक फूड प्रोसेसिंग जोन की स्थापना हो जाये तो यहाँ पर अनेकों फूड प्रोसेसिंग यूनिटें लगवाई जायें, जिससे क्षेत्र के किसानों की उपरोक्त फसल रिजर्व रहेगी। तथा इससे अनेक प्रकार के उत्पादकों का निर्माण हो सकता है, जिन्हें बेचकर किसानों का अच्छा मुनाफा होगा। एवं रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे। स्याना क्षेत्र प्रदूषणरहित कृषि आधारित अन्य उद्योगों की स्थापना करायी जाय। जैसे-खाद्य इकाइयाँ, कोल्ड स्टोरेज, फूल संरक्षण आदि। खासतौर से ऐसी इकाईयां लगें, जिससे कि आम के बागों का कोई नुकसान न हो। स्याना क्षेत्र के औद्योगिकीकरण से निकटवर्ती विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर व किठोर, हसनपुर के आम के उत्पादक किसानों, व्यापारियों व बेरोजगार युवाओं को इसका भरपूर फायदा होगा।

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए शुक्रिया।

पी0एस0यू0पी0-एल0 180 विधान सभा (325)-29-8-2012-815 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।